

शाह कमीशन
के आईने मे

शाह कमीशन के आईने में

वीरेन्द्र साघी



सरस्वती विहार

21, दयानन्द भाग, दरियागज
नई दिल्ली-110002

मूल्य सोलह रुपये (16 00)

प्रथम संस्करण 1978

प्रकाशक सरस्वती विहार

21 दयानंद मार्ग दरियागञ्ज

नई दिल्ली 110002

© बीरेन्द्र साघी

मुद्रक चौधरी प्रिंटर्स

ब 32, नवीन शाहदरा

दिल्ली 110032

SHAH COMMISSION KE AAGNE MEIN (Current Affairs) by
Vrendra Sanghi

विषय-सूची

१	आयोग का गन्त और उमरी रिपोर्टें	६
२	श्रीमती गांधी और साह आयोग	३४
३	सागर अर गराह बने	५८
४	गमरदे-जी का पुच्छनूमि—नेताओं की निर्यातियाँ	७१
	(i) रमिनी और बरान	७२
	(ii) लमरदे-जी की पुत्र-गण्डा	७४
	(iii) निर्यातियाँ और गमरदे-जी	८६
५	गमरदे-जी में बरान और निर्यातों नाम निर्यातियाँ और निर्यात	८६
	(i) बरान का बरान की निर्यात का बरान	९०
	(ii) बरान का बरान का बरान— बरान का बरान	१००
	(iii) बरान का बरान की बरान का बरान बरान का बरान	११२
	(iv) बरान का बरान का बरान— बरान का बरान	१२२
	(v) बरान का बरान का बरान	१३०
	(vi) बरान का बरान का बरान— (i) बरान का बरान	११६
	(ii) बरान का बरान	१६१

(iii) बछ गुरदत्त	१४२
(iv) प्रवीरगुरवायस्थ	१४३
(v) बुदनलाल जग्गी	१४४
(vi) डा० बरुणेश शुक्ल	१४५
नजरबदी और सफाई	१४७
नजरबदी और परोल पर रिहाई	१४६
नसबदी और परोल पर रिहाई	१५१
सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन और गृह मंत्रालय के बीच	१५२
जिला म ब्यवहार	१५३
६ छापे या राजनीतिब बदला	१५६
(i) विश्व युवक केन्द्र पर बम्बला	१५७
(ii) अवाड को एमरजेन्सी का अवाड'	१६४
(iii) बजाज उद्योग समूह के प्रतिष्ठानों पर छापे	१७०
(iv) बडौदा रेयन पर छापे	१७२
(v) पंडित श्रद्धा पर छाप	१७६
(vi) दो ट्रेड यूनियन नेताओं के यहां छापे	१८७
(vii) मारुति का मामला दबाया गया	१८८
(viii) रिश्वत का मामला रफा दफा	१९१
७ एमरजेन्सी में सफाई के नाम पर नादिरशाही	१९४
(i) जामा मस्जिद की सफाई सुवमान गट की तबाही	१९५
(ii) कापसहेडा गांव	२०२
(iii) अजुन नगर बनाम अजुन दास	२०५
(iv) अधरिया मोड़	२०७

८	जनप्रचार-साधनों का दुरुपयोग	२१०
	चुनाव घोषणा से पूर्व	२१०
	(i) अखबारों पर शिकजा—विजली काटकर और सेंसरशिप लगाकर	२११
	(ii) अखबारों पर शिकजा—विनापनों के ज़रिये	२१७
	(iii) समाचार का गठन	२१८
	(iv) गीत एवं नाटक प्रभाग	२२१
	(v) किशोरकुमार के गीतों पर प्रतिबन्ध	२२१
	चुनाव घोषणा के बाद	२२२
	(i) त्यागपत्र बनाम 'दल-बदल'	२२४
	(ii) बाबी' का टीवी पर प्रदर्शन	२२४
	(iii) कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र का 'सरकारी' अनुवाद	२२६
	(iv) हमला सजय गांधी और पुरुषोत्तम कौशिक पर	२३१
	(v) चुनावों की घोषणा और सेंसरशिप	२३२
९	अनियमित नियुक्तियाँ	२३८
	(i) इंडियन एयर लाइंस तथा एयर इंडिया निदेशक मंडलों में नियुक्तियाँ	२३८
	(ii) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद पर श्री के० आर० पुरी की नियुक्ति	२४१
	(iii) पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० तुली की नियुक्ति	२४२
	(iv) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० वरदाचारी की नियुक्ति	२४४

(v) भारतीय पयटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर ले० जनरल सतारावाला की नियुक्ति	२४५
(vi) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर एमर माशल एच० सी० दीवान की नियुक्ति	२४६
(vii) दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर श्री यू० एस० श्रीवास्तव की नियुक्ति	२४७
(viii) दिल्ली और बम्बई उच्च न्यायालया के न्यायाधीशों की पदावनति और पुनर्नियुक्ति	२४९
१० ऋण जो चुकाए नहीं गए	२५०
(i) एसोसिएटेड जनल्स	२५१
(ii) ब्रह्मा केमिकल्स	२५६
(iii) मारुति लिमिटेड	२५८
११ गैर-सरकारी हैसियत	२६०
(i) सजय की बागरा यात्रा	२६०
(ii) बोइंग विमानों की खरीद	२६५
(iii) स्वामीजी और विमान	२७०

१ आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट

एमरजेन्सी के दौरान हुई नजरबंदिया और गिरफ्तारिया परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबदी नगरों को सुन्दर बनाने के लिए मकान गिराने की घटनाएँ और ऐसी ही अनेक बातें मार्च, १९७७ में हुए लोकसभा चुनावों में मुख्य मुद्दा रही।

जनता पार्टी ने इन चुनावों में एमरजेन्सी में हुई इन ज्यादतियों की जाँच कराने का वादा किया और उसी वादे के मुताबिक केन्द्र में जनता सरकार बनने के बाद गृहमंत्री श्री चरणसिंह ने ७ अप्रैल १९७७ को इसी जाँच के लिए एक 'याचिका आयोग' के गठन के निश्चय की घोषणा की।

२८ मई, १९७७ को भारत सरकार ने राजपत्र में एक अति विशिष्ट अधिनूचना जारी कर जाँच आयोग अधिनियम की धारा ३ के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जयतीलाल छोटेलाल शाह की अध्यक्षता में एमरजेन्सी के दौरान हुई ज्यादतियों की जाँच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया।

आयोग को जिन जिन कार्यों की जाँच करने का काम सौंपा गया था व इस प्रकार है—

- १ (१) संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अंतर्गत २५ जून १९७५, जब से एमरजेन्सी लागू की गई या उसकी घोषणा के तत्काल पहले के दिनों में की गई कानूनी कारबाइयाँ,

प्रशासनिक कायप्रणाली तथा आचरण अधिकारा का दुरुपयोग उत्पादितिया तथा भ्रष्टाचार आदि के मद्दभ म तम्यो एव परिस्थितियो की जाच ।

- (ii) इस अवधि म गिरफ्तारी व अधिकारा का दुरुपयोग तथा नजरबंदी के उन मामला की जाच जो सम्बद्ध कानूनो स मेल नही खात ।
- (iii) इस दौरान भारत रक्षा कानून के अतगत गिरफ्तार । नजरबंद व्यक्तिओ तथा उनके सम्बन्धियो और निबट सहयोगियो पर किए गए अत्याचार और दुःप्रवहार की जाच ।
- (iv) परिवार नियोजन की अनिवार्यता के नाम पर हुई खार जबरनस्ती की जाच ।
- (v) गंदी बस्तियो की सफाई तथा नगर नियोजन एव सो दय करण के नाम पर मकानो, दुकाना ग्राफडिया तथा अप निर्माण कायों को गिराने व काम की जाच करना ।

२ इसी प्रकार के अन्य मामले जो आयोग की नजर म उत्पादितिया म आने हा ।

२ आयोग को जाच व अतिरिक्त उन उपायो की भी सिफारिश करने का काम सौंपा गया जो एस अधिकारी का दुरुपयोग उत्पादितिया और भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति रोक्न क लिए अप नाए जा सके ।

अधिसूचना म यह प्रावधान भी किया गया कि आयोग की जाच उत्पादितिया भ्रष्टाचार तथा अधिकारा के दुरुपयोग के उ ही मामला स सम्बद्ध होगी जो क्विर रूप म सरकारी कर्मचारियो द्वारा किए गए । इसका साथ ही उन दूसरे व्यक्तिओ व आचरण पर भी विचार करने का प्रावधान रखा गया जिहान उन कामो के लिए निर्देश दिए हा सहयोग किया हो अथवा किसी अन्य तरीके म उसस सम्बद्ध रहे हा ।

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के इडिया गेट इलाके व एक कोने म स्थित पटियाला हाउस की इमारत म स्थापित किया गया जहा पहले दिल्ली उच्च न्यायालय हुआ करता था । आयोग ने ४ जून १९७७ से अपना काय प्रारम्भ किया । आयोग के लिए काय कर रहे केन्द्रीय जाच बूरो (सी० बी० आई०), पुलिस वित्त

तथा आयकर विभाग के एक सौ से अधिक अधिकारियों तथा विभिन्न राज्यों में गठित तथ्या-वेपण समितियों के जरिये तथा सीधे ही आयोग के पास ज्यादातियां की लगभग ८८ हजार शिकायतें जाइ जिनमें से लगभग दो हजार शिकायतों के बारे में जांच करने का फैसला किया गया। इनमें से कुछ संबंधित राज्यों में गठित तथ्या-वेपण समितियों के पास भेज दी गई।

आयोग ने दिल्ली में २६ सितम्बर १९७७ से सावजनिक सुनवाई प्रारम्भ की। आयोग की जो वाय सीपा गया था, वह अपने आपमें एक अलग किस्म का था। आयोग ने इसके लिए एक नई प्रक्रिया अपनायी और कायवाही का दो चरणों में करने का फैसला किया जैसा इससे पहले किसी आयोग ने नहीं किया था।

किसी भी मामले पर विचार से पूर्व सबसे पहले आयोग के जांच अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया मामला आयोग के समक्ष पढ़ा जाता था, जिस 'केस हिस्ट्री' का नाम दिया गया था। यह 'केस हिस्ट्री' आयोग को भेजी गई शिकायतों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के बयान लेकर तैयार की जाती थी।

'केस हिस्ट्री' पढ़े जाने के बाद उससे संबंधित गवाहों के आयोग के समक्ष बयान लिए जाते थे, जो उन्हें शायद लेकर देने होते थे। इसके बाद आयोग द्वारा स्वयं (जस्टिस ग्राह) कुछ प्रश्न किए जाते थे जो तथ्या से संबंधित होते थे। इसके पश्चात् सरकारी वकील अपने प्रश्नों को सुधार के रूप में आयोग की अनुमति से पूछ सकता था। लेकिन वह भी सिर्फ तथ्या की जानकारी तक ही सीमित होता था, जिरह के रूप में नहीं।

आयोग के दूसरे चरण की कायवाही में गवाहों को जांच आयोग अधिनियम की धारा ८ (बी) के अंतर्गत समन देकर बुलाया जाता था और जिसके अंतर्गत वह आयोग के समक्ष अपना वकील लेकर उपस्थित हो सकते थे। इस चरण में संबंधित गवाहों से आयोग के वकील और सरकारी वकील जिरह करते थे। इसके अतिरिक्त गवाह चाहें तो स्वयं अथवा अपने वकील के जरिये दूसरे संबंधित गवाहों में जिरह कर अपनी बात सिद्ध कर सकते थे।

यदि कोई गवाह न तो स्वयं पेश होता और न ही अपना वकील भेजता, तो उसकी अनुपस्थिति में ही जिरह की जाती थी तथा उसके पक्ष में बिना ही मामले पर विचार किया जाता

पा ।

आयोग की कायवाही के दौरान कई अवसरों पर गवाहों द्वारा इसकी प्रक्रिया को चुनौती दी गई । परन्तु जस्टिस शाह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आयोग को दिया गया काय जांच आयोगों के इतिहास में अपनी विम्वर का सम्भवतः पहला है । आयोग को सिर्फ ज्यादातिया का पता लगाने का काम सौंपा गया है जिसके लिए जरूरी था कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाती । उनका कहना था कि यह काय तथ्यावेपात्मक है इसलिए पहले चरण में पता लगाया जाएगा कि ज्यादाती हुई भी है या नहीं और दूसरे चरण में ही संबंधित व्यक्ति को जिम्मेदारी देखी जाएगी ।

जस्टिस शाह ने स्पष्ट किया था कि यदि जांच के लिए यह प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती तो यह काय एक जमान में ही क्या, सफ़ाई जमानों में भी पूरा नहीं हो सकता था ।

आयोग ने ज्यादातियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट में कहा

आयोग की रिपोर्ट

आयोग ने ११ मार्च और २६ अप्रैल को अपनी दो अंतरिम रिपोर्टें सरकार को पेश की । सरकार द्वारा इन दोनों रिपोर्टों को १५ मई को संसद में पेश किया गया । सरकार ने संसद के समक्ष रिपोर्टों के माप-साप इनपर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित पापन भी पेश किया ।

आयोग ने अपनी दोनों रिपोर्टों में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को आंतरिक एमरजेंसी की घोषणा के संबंध में दोषी ठहराते हुए कहा है कि यह एक राजनीतिक फैसला था जो सत्ता में कायम रहने के लिए किया गया था । आयोग ने श्रीमती गांधी के अतिरिक्त श्री सत्य गांधी की दिल्ली में मकान गिराने की कार्रवाई के संबंध में श्री विद्याचरण शुक्ल को कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के अनुवाद के लिए अधिकार का दुरुपयोग करने का तथा श्री प्रणव मुखर्जी को प्रशासनिक प्रक्रिया एवं परम्पराओं का उल्लंघन करने का दोषी पाया है । आयोग ने इनके अतिरिक्त श्री धीरेन्द्र शहाचारी श्री जगमाहन श्री कृष्णचंद्र श्री बहादुरराम टमटा तथा राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी को भी दोषी

ठहराया है। दिल्ली में हुई गिरफ्तारियों के संवध में श्री पी० एस० भिण्डर तथा श्री के० एस० बाजवा को अधिकारों के उल्लंघन का दावा पाया गया है।

आयोग द्वारा अलग अलग मामलों में दिए गए निर्णय इस प्रकार हैं

एमरजेन्सी की घोषणा

‘जिन परिस्थितियों में एमरजेन्सी की घोषणा की गई तथा जिस प्रकार से इस लागू किया गया वह देश के नागरिकों के लिए एक चेतावनी है। देश में पहले से ही एक एमरजेन्सी की घोषणा के बावजूद श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्रपति को आंतरिक एमरजेन्सी की घोषणा के लिए सलाह देने के बारे में न सिर्फ मन्त्रिमंडल तथा सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों से ही विचार विमर्श नहीं किया गया, बल्कि उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया।’

काफी समय था

“श्रीमती गांधी ने काफी समय होने का दावा जूझा अपना मन्त्रिमंडल से सलाह नहीं ली। उनका यह कहना कि वे राष्ट्रपति को पत्र लिखने से पहले मन्त्रिमंडल से सलाह लेना चाहती थी परंतु समय की कमी के कारण ऐसा नहीं कर सकी सिद्ध नहीं हो पाता। जब २६ जून की प्रातः हुई मन्त्रिमंडल की बैठक सिर्फ ६० मिनट के नाटिस पर हो सकती थी तब ऐसा क्या कारण था कि २५ जून की शाम को साढ़े पांच बजे से रात्रि के ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के बीच जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कराए गए ऐसी बैठक नहीं हो सकती थी? चाहे जो भी हो आयोग के पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि श्रीमती गांधी ने २२ जून को ही देश में एमरजेन्सी की घोषणा करने के बारे में विचार कर लिया था। उन्होंने इस संवध में २५ जून की प्रातः ही अपने कुछ विश्वसनीय राजनीतिक साधियों को बता भी दिया था।’

‘उन परिस्थितियों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके कारण देश में एक ओर एमरजेन्सी की घोषणा की ज़रूरत पड़ गई थी। २५ जून १९७५ की रात्रि को समाचारपत्रों के कार्यालयों की बिजली काट दी और भीमा’ में लोगो को नज़रबंद कर दिया

को बारवाई सिर्फ परिस्थितिवश ही की गई मासूम हाती है।"

इस बात व कोई प्रमाण नहीं है कि उस समय देश व किसी भी भाग व कानून और व्यवस्था की स्थिति गिगडी हुई थी अथवा उस समय म र्मिमा प्रकार की आशका थी। उस समय आर्थिक स्थिति भा नियंत्रण म था तथा उस व विगडन का भी काइ डर नहीं था। इस प्रकार री एक भी सूचना नहीं थी कि देश व किसी भी हिस्स म कोई गडबडी हो रही है जिस व कारण मि आंतरिक एमर जमी की घोषणा की जरूरत आ पड। इस व अतिरिक्त इस बात व भी कोई मरत नहीं थे जिनम यह पता चलता हो कि देश की आंतरिक अथवा बाहरी सुरक्षा का खतरा हो गया हो।

सत्ता म बने रहने के लिए

इन सभी बातों म सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्रपति को आंतरिक एमरज सी की घोषणा की जमा माय सनाहू दन का कारण इलाहाबाद उच्च 'यायालय व निणय व बाद सत्तामंड और विपभी दना म हुई गहरी राजनीतिक प्रति प्रिया का नतीजा था जो उन्होंने अपने आपकी सत्ता म बनाए रखने के लिए किया और जिसके कारण अनेकों के हिता की बलि चडा दी गई। आयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक ही है कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने अपने को सत्ता म कायम रखने के लिए एमरज सी लागू करने का निणय किया। उन्होंने यह कठोर कार्यवाई इलाहाबाद उच्च 'यायालय के कमले से हुताश होकर की जिससे हजारों लोगों का अवणनीय कष्ट झेलने पड।"

रिपोर्ट क अनुसार श्रीमती गांधी के समयका द्वारा इलाहाबाद उच्च 'यायालय के निणय के बाद १२ से २५ जून १९७५ के बीच दिल्ली तथा अय स्थाना पर प्रदर्शन रलिया और सभाए आयोजित कर यह लिखाने की चष्टा की गई कि उच्च 'यायालय के निणय के बावजूद व प्रधानमन्त्री पद पर बने रहने के योग्य हैं।

रिपोर्ट क अनुसार इस दौरान इन प्रदर्शनों म भाग लेने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की १७६१ बसों का उपयोग किया गया जिनके किराय के ४ लाख रुपये का आज तक अखिल भार तीय कांग्रेस कमेटी अथवा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक डिपों स ५ बसों के

हिमाचल से प्रतिदिन कुल २५ बसों से अधिक बुक नहीं की जा सकती जबकि इससे कहीं अधिक बसों को इन प्रदर्शनों के लिए लोगों का होना में उपयोग किया गया। दिल्ली की बसों का उपयोग पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से प्रदर्शनकारियों को लाने में जाने में भी किया गया। परंतु उन बसों के लिए अलग से कोई फंड परमिट नहीं बनवाए गए। इसके अलावा राजस्थान से भी ५० ट्रकों में प्रदर्शनकारियों को लादकर लाया गया।”

वायुसेना के विमानों का उपयोग

रिपोर्ट में वायुसेना के विमानों के उपयोग के लिए उचित नियम बनाने को कहा गया है तथा सरकार से इस बात की भी जांच करने का कहा गया है कि २५ जून, १९७५ को वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया था वह नियमों के अनुसार किया गया था अथवा नहीं तथा उनके उपयोग के लिए उचित बिल दिए गए थे अथवा नहीं।

गिरफ्तारियाँ और नज़रबंदियाँ

रिपोर्ट के अनुसार 'अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के निर्देशों पर कई राजनीतिक नेताओं की जो गिरफ्तारियाँ की गईं व न्याय सम्मत नहीं थी तथा अनधिकृत और गलत थी। चूंकि नज़रबंदी का आदेश अधिकारियों की बिना व्यक्तिगत सन्तुष्टि के जारी किए गए थे इसलिए वे अवैध' थे। चूंकि ये सभी आदेश श्रीमती गांधी के निर्देशों पर दिए गए थे इसलिए इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उसीपर है।

इसलिए इन परिस्थितियों में आयाग इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि श्रीमती गांधी कई सम्माननीय नागरिकों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी का आदेश देने के लिए जिम्मेदार हैं। श्रीमती गांधी ने यह निर्देश/आदेश बिना किसी अधिकार के अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए दिए।

प्रमाणों से यह भी साफ है कि सक्थी पी० एस० मिण्डर के० एस० बाबू और नवीन चावला ने एमरजेन्सी के दौरान अपने अधिकारों का बहिर्भाव उपयोग किया, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री निवास तक काफी अच्छी पहुंच थी। अपने अधिकारों का प्रयोग

करते समय उन्होंने यह नहीं देखा कि 'य नतिक है अथवा अनतिक' बंध हैं अथवा 'अवध' । इन लोगो ने सत्ता में पहुँचने के लिए वह सब कुछ किया जो य कर सकते थे । उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग 'पागलपन' की सीमा तक किया । श्री कृष्णचंद ने अपने विभिन्न कार्यों से, चाहे वे नज़रबन्दीया जल महत्त्वपूर्ण कार्य ही क्यों न हों, यह दिखा दिया कि वे दिल्ली प्रशासन के प्रमुख होने का बावजूद नियम लेने में अक्षम हैं । उन्होंने सर्वश्री मिण्टर, घाजवा और चाथना जैसे अतिआकांक्षी लोगों को दस के आगे घुटने टेक दिए ।

आयोग समझता है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों जैसे स्तर के अधिकारियों को उनकी बिना किसी पुष्टि के केन्द्र सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि अमुक व्यक्ति का नज़रबंद कर लिया जाए ।'

सरकार को पुलिस को उनके कृतव्यो और कानून के अनुसार कार्य करने के लिए तथा राजनीतिक अपमान से बचाने पर विचार करना चाहिए । आयोग समझता है कि जो बात पुलिस पर लागू होती है वही अन्य सवाआ पर भी लागू होनी है । जो राजनीतिक अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों को काम में लाते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी स्वयं ही ऐसा करते हैं उस रोक जाना चाहिए ।''

नज़रबन्दी आदेशों की पुष्टि, पुनरीक्षण तथा सम्मति

यद्यपि पुष्टि एवं पुनरीक्षण के समय नज़रबन्दीया के आदेशों के संबंध में विधि विभाग की सहायता ली जाती थी परन्तु वास्तव में कोई कानूनी जांच नहीं की जाती थी । प्रमाणा से पता चलता है कि नज़रबन्दीयो के संबंध में पहले राजनीतिक दल और फिर यह कि अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री के २० दूतों कायक्रम का समर्थन करता है अथवा नहीं मुख्य बात होती थी ।''

पेट्रोल के संबंध में काय विधि

मीसाबंदियों को पेट्रोल पर रीढ़ा करने के संबंध में दिल्ली प्रशासन की कोई एक सी नीति नहीं थी । कई मामलों में प्रशासन द्वारा बहुत ही बड़ा रक़्क़ अपनाया गया तो कई मामलों में बहुत ही

नरमी दिखाई गई।”

जेलों में व्यवहार

‘यद्यपि श्री नवीन चावला की जेल प्रशामन में कोई स्थिति नहीं थी फिर भी वे जेलों के मामलों में अतिरिक्त अधिकारों का प्रयोग करते थे, जिनमें किसी विशिष्ट बंदी से किस प्रकार व्यवहार किया जाए यह सब शामिल है।

आयोग बताना चाहता है कि ‘राजनीतिक नजरबंदी मूलरूप से निवारक किस्म की होती है दण्डात्मक किस्म की नहीं परन्तु एमरजेंसी के दौरान इस बात को बिलकुल अनदेखा कर दिया गया। जेलों में बंदियों के रहने की स्थिति इतनी खराब थी कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से बिलकुल कमजोर हो गए जिनके कारण उनमें माफीनाम लिखवा लिए गए। जेलों में सोगा को ठूम दिया गया। सेनिटरी व्यवस्था में बराबर थी, पानी की कमी, सफाई का स्तर बहुत ही नीचे, बहुत ही खराब खाना तथा चिकित्सा-व्यवस्था भी बहुत ही खराब थी।”

दिल्ली प्रशासन और गृह-मंत्रालय के संबंध

‘मुख्य सचिव श्री जे० के० कोहली की गवाही से पता चलता है कि मोसा के संबंध में उप राज्यपाल गृह मंत्रालय की कोई तरजीह नहीं देते थे। जिन मामलों में उप राज्यपाल सहमत नहीं होते थे उनमें अधिकारी गृह मंत्रालय की सलाह नहीं मानते थे और उप-राज्यपाल की राय मानी जाती थी।

‘श्री कृष्णचंद के बयानों से स्पष्ट है कि गृहमंत्री श्री प्रधान-दरहठी की दिल्ली के मामलों में कुछ नहीं चलती थी। अधिकांश मामलों में गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता के निर्देशों का पालन होता था, जो प्रधानमंत्री निवास में अधिक निकट थे। वास्तव में प्रधान-मंत्री ने दिल्ली का कार्य श्री सत्य गांधी के जिम्मे कर दिया था तथा व चार-पाँच अधिकारी जो उनके काफी निकट थे, उनसे सीधे निर्देश लिया करते थे। श्री कृष्णचंद ने स्वीकार किया है कि जब कभी भी श्री नवीन चावला उन्हें कोई निर्देश दिया करते थे, तो वे उन्हें श्री गांधी के निर्देश समझकर ही पालन करते थे।

सामाय अपराधियों के विरुद्ध मोसा

एमरजेन्सी के दौरान दिल्ली में बहुत-से सामाय अपराधियों को भी मोसा में नज़रबंद कर दिया गया, जबकि उनसे सामाय कानून के अंतर्गत अधिक प्रभावशाली तरीके से निपटा जा सकता था। ऐसा गृह मंत्रालय के विशेष निर्देशों से किया गया।'

मोसा में कृष्णचंद की जिम्मेदारी

“श्री कृष्णचंद ने मोसासहित कई आपात अधिकारों का प्रयोग कर अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग किया जबकि ऐसे मामलों में कानून के सामाय प्रावधानों से ही अच्छी तरह निपटा जा सकता था।’

मामचंद की गिरफ्तारी

श्री कृष्णचंद और श्री मिण्डर दोनों ने ही श्री मामचंद (असह्यार बंधन वाला हाकर) जैसे एक असहाय व्यक्ति की नज़रबंदी के आदेश देकर अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया। मामचंद की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन उन दिनों असहाय व्यक्तियों की आजादी समाप्त करने के लिए कहा तक जा सकता था।’

डॉ० करणेश शुक्ल की नज़रबंदी

जिन आरोपों पर डॉ० शुक्ल को मोसा में नज़रबंद किया गया वह पूर्ण रूप से झूठे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कार्य श्री कृष्णचंद द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग था, जो उन्होंने श्री बाजवा की सलाह पर किया। आयोग समझता है कि श्री बाजवा के पास उन दिनों एस० पी० (सी० आई० डी०) के रूप में बहुत अधिकार थे जिन्होंने अक्सर दुरुपयोग करते थे।

श्री वीरेन्द्र कपूर की नज़रबंदी

‘श्री कपूर की गिरफ्तारी में श्री बाजवा की एक बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। श्री कपूर की गिरफ्तारी के बाद मोसा में उनकी नज़रबंदी एकदम

अवाम्तविव आधारों पर की गई। आयोग का विचार है कि मर कार उन व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कारवाई करे जिनके मौखिक अथवा लिखित आदेशों से ऐसी नज़रबंदिया की गई।”

वद्य गुरुदत्त की नज़रबंदी

आयोग का विचार है कि ‘वद्य गुरुदत्त की नज़रबंदी के आदेश देकर श्री कृष्णचंद ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। लगता है उन्होंने यह बात तत्कालीन प्रधानमंत्री का प्रसन्न करने के लिए किया। वद्य गुरुदत्त जैसे बड़, कमजोर तथा माननीय नागरिक की गिरफ्तारी से लोगों के मन में प्रशासन की ईमानदारी तथा सभ्यता में विश्वास ढिंका है।

श्री प्रवीर पुरकायस्थ की नज़रबंदी

‘श्री भिण्डर द्वारा श्री पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के संबंध में कही गई कहानी, मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया गिरफ्तारी का आदेश तथा उप राज्यपाल की भूमिका, ये सभी कानून के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन हैं। श्री भिण्डर द्वारा मात्र प्रधानमंत्री निवास में किसीको प्रसन्न करने के लिए की गई यह कारवाई काफी दुःखद है। श्री कृष्णचंद द्वारा इस मामले में जिस प्रकार से श्री भिण्डर की बाता पर आखें मूंदकर विश्वास किया गया, वह भी अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग ही है।”

चार अधिकारियों के विरुद्ध झूठी शिकायतें

भारत के संबंध में संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए जानकारी एकत्र करने वाले चार अधिकारियों से संबंधित मामले में आयोग का निष्कर्ष है कि ‘श्रीमती गांधी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। उन्होंने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के चार अधिकारियों के विरुद्ध सिर्फ इसलिए कारवाई करने के आदेश दिए क्योंकि उनकी सूचना से भारत पर प्रभाव पड़ सकता था। उन्होंने श्री सेन से इन अधिकारियों के विरुद्ध घण्टाघर के मामले दर्ज कर उनके घरों की तलाशी लेने को कहा, जो एकदम गलत था तथा जिस बात में वापस भी लेना पड़ा।

श्री सेन ने भी इन अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना

रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दज कर जाच करावे अपने अधिकारो का दुरुपयोग किया है ।'

बारह टक्सटाइल/कस्टम इस्पेक्टरों का मामला

बारह टक्सटाइल/कस्टम इस्पेक्टरों की झूठे आरोपों में गिरफ्तारी और फिर मोसा में नजरबंदी तथा बाद में केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा इनमें से चार के घरों की तलाशी के संबंध में आयोग का मत है कि—

उपलब्ध रिकार्डों से यह कतई बात नहीं होता कि ये अधिकारी भ्रष्ट थे अथवा इन्होंने कोई ऐसा काम किया था, जो गलत था ।'

श्री देवदत्त सेन द्वारा केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा जिस आधार पर यह काम कराया गया वह गलत तथा अपर्याप्त था । उन्होंने ऐसा करके पूर्णरूप से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है ।'

श्रीमती गांधी ने इन बारह इस्पेक्टरों की नजरबंदी के तथा चार अधिकारियों के घरों की तलाशी के आदेश देकर अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग किया ।

श्री भिण्डर ने भी इस मामले में जिस प्रकार से काम किया वे भी श्री सेन के साथ साथ अधिकारों के दुरुपयोग के दोषी हैं ।'

श्री भगलबिहारी तथा श्रीमती शर्मा का मामला

राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने जिस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री के निजी सचिव श्री धवन के एक फोन के आधार पर आई० ए० एस० अधिकारी श्री भगलबिहारी तथा एक अध्यापिका श्रीमती चंद्रावती शर्मा को हटाया उसका संबंध में आयोग का मत है कि—

श्री जोशी ने इस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग कर, स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तोड़कर तथा अधिकारों का गलत लाभ उठाकर श्रीमती शर्मा को बिना किसी भवधानिक प्रावधानों के हटाया ।

' श्रीमती गांधी ने श्रीमती शर्मा को नौकरी से हटाने के आदेश देकर तथा श्री भगलबिहारी को जबरन छुट्टी पर भेजकर अधिकारों तथा पद का दुरुपयोग किया और स्थापित प्रशासनिक प्रक्रि-

याआ को तोड़ा।”

श्री भीमसेन सच्चर तथा सात अय की गिरफ्तारी

‘श्रीमती गांधी ने श्री भीमसेन सच्चर तथा सात अय की मीसा मे नजरबंदी के आदेश देकर अपने पद तथा अधिकारो का दुरुपयोग किया है। श्रीमती गांधी के आदेश श्री घवन के जरिये दिल्ली प्रशासन को दिए गए थे।’

महारानी गायत्रीदेवी की ‘कोफेपोसा’ मे नजरबंदी

जयपुर की राजमाता गायत्रीदेवी और उनका पुत्र बनल भवानीसिंह की कोफेपोसा मे नजरबंदी के पर्याप्त कारण नहीं थे, तथा इस मामले मे यह अधिनियम लागू ही नहीं होता था।’

‘प्रमाणो से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन वर्किंग और राजस्वमन्त्री श्री प्रणय मुखर्जी ने श्रीमती गायत्रीदेवी और बनल भवानीसिंह की अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के आदेश देकर अपने पद तथा अधिकारो का दुरुपयोग किया और वैध तथा प्रशामनिक प्रक्रियाओ को तोड़ा।’

विश्व युवक केन्द्र का अधिग्रहण

‘प्रमाणो से सिद्ध होता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने उप-राज्यपाल श्री कृष्णचंद पर विश्व युवक केन्द्र की इमारत के अधिग्रहण के लिए गलत तरीके से दबाव डाला।’

आयोग का यह भी विचार है कि श्री कृष्णचंद ने अपन पद तथा अधिकारो का दुरुपयोग किया और ऐसा ही विद्याचरण शुक्ल ने भी इस मामले मे किया।”

प्रमाणो से यह भी सिद्ध होता है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये केन्द्र के भवन का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया था।

बजाज उद्योग समूह के प्रतिष्ठानों पर छापे

‘आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १३२ के अंतर्गत बजाज उद्योग पर भारे गए छापा मे वही भी गलत उद्देश्य नहीं मिलता।’

‘पूरे मामले मे सिर्फ तलाशी के खाली वारण्ट पर हस्ताक्षर

करने की बात ही स्पष्ट रूप से सरकारानुनी नजर आती है ।

बड़ोदा रेयन पर छापे

अप्रैल १९७६ में आयकर अधिकारिया द्वारा बड़ोदा रेयन कॉर्पोरेशन पर मार गए छापा के संबंध में जायोग का मत है कि—

आयकर अधिनियम की धारा १३२ के अंतर्गत ली गई तलाशी और जब्ती की कार्यवाही पूर्ण रूप से भलत थी तथा यह कुछ उन दस्तावेजों का प्राप्त करने के लिए की गई थी जिनका आयकर मामले में कोई संबंध नहीं था ।

श्री एस० आर० मेहता द्वारा इस मामले में श्री हरिहरलाल को अधिनियम की धारा १३२ के अंतर्गत कारवाई करने के निर्देश देना कानूनी प्रक्रियाओं को तोड़ना तथा अधिकारों का दुरुपयोग है ।

‘ श्री मेहता द्वारा श्री प्रणव मुखर्जी से कागज वापस लेने की असफलता भी कानूनी प्रक्रियाओं को तोड़ने के समान ही है । ’

श्री मुखर्जी द्वारा जब्त किए गए कागजों को अपने पास रखने की कार्यवाही भी अधिकारों का दुरुपयोग और कानूनी प्रक्रियाओं को तोड़ने के समान है । ’

आयोग के विचार में ‘ इस मामले में श्री हरिहरलाल के लिए सीमित अवसर थे । यद्यपि वे इस अवैध कारवाई के बारे में जानते थे । ’

पडित ब्रदस पर छापे

दिल्ली की एक कम पडित ब्रदस पर मार गए छापे और उसके भागीदार श्री आर० एन० हुक्कर तथा श्री के० पी० मुशरान और उनके मनेजर श्री एल० एस० माथुर की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में जायोग का मत है कि—

फम पर मार गए छापो तथा इन लोगों की गिरफ्तारी में श्री कृष्णचंद की बड़ी भूमिका रही है । ’

प्रमाणों से स्पष्ट पता चलता है कि पडित ब्रदस पर मार गए छापे तथा उसके मालिकों को परेशान करने की कारवाई की सीधी जिम्मेदारी श्री सजय गांधी पर है जो उन दिनों दिल्ली में मकान गिराने की कारवाई के साथ साथ लोगों को परेशान करने

के लिए गिरफ्तार और नजरबंद कराने में भी दिनचस्पी ले रहे थे।”

दो ट्रेड यूनियन नेताओं के यहाँ छापा

बम्बई के दो ट्रेड यूनियन नेता श्री डी० पी० चड्ढा तथा श्री प्रभातकर के निवासों पर श्री देवेन्द्र सेन व निर्दोश पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत भारे गए छापा के संबंध में आयोग का मत है कि—

‘यद्यपि परिस्थितियों के अनुसार तलाशी और ज़रूरी के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में श्री देवेन्द्र सेन की भूमिका पर संदेह होता है परंतु इस मामले में कहीं भी अधिकारों के दुरुपयोग तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ताड़न का मामला नहीं बनता।’

मारुति का मामला

मारुति के बेनामी शेयर होल्डरों के संबंध में चाही गई जानकारी को दबाने के मामले में आयोग का मत है कि “श्री एम० आर० मेहता ने मारुति के संबंध में चाही गई जानकारी में देरी करने के लिए श्री हरिहरलाल को मौखिक आदेश दिए जबकि यह कर-चोरी का एक स्पष्ट मामला था। इस प्रकार से श्री मेहता ने प्रशासनिक प्रक्रिया को तोड़ा तथा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया।’

रिश्वत का मामला

रेलवे के एक क्लक श्री सुशेंन वर्मा के रिश्वत के मामले को रफा-दफा करने के संबंध में आयोग का मत है कि “प्रमाणों से स्पष्ट है कि श्री देवेन्द्र सेन ने प्रधानमंत्री निवास में किसी व्यक्ति के कहने पर सामान्य प्रक्रियाओं का ताड़ा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर श्री वर्मा के मुकदमे में सहायता करने के लिए दबाव डाला।’

गुप्तचर ब्यूरो

आयोग के मत में ‘भारत सरकार द्वारा गुप्तचर ब्यूरो का उपयोग महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं तथा मतियों की कार्यवाहियों की

निराशा रखने में किया गया।'

आयोग सनाह देता है कि 'सरकार द्वारा गुप्तचर ब्यूरो का उपयोग सरकार राजनीतिक जासूसी में जबकि सरकार किसी व्यक्ति के खिलाफ न कर पाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस ओर लोगों का ध्यान गया है तथा इस प्रश्न पर सावजनिक बहस करवाने पर भी विचार दिया जाना चाहिए।'

केन्द्रीय जाच ब्यूरो

आयोग ने जाच ब्यूरो के निदेशक के पद के संबंध में सुझाव दिया है कि भविष्य में निदेशक को अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने से रोकने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। आयोग का विचार है कि केन्द्रीय जाच ब्यूरो के निदेशक को किसी स्वतंत्र संगठन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

प्रमाणों से स्पष्ट है कि श्री सन ने स्वयं को तथा अपने संगठनों को उन कार्यों में लगा दिया था, जो किसी भी हालत में जाच ब्यूरो के अंतर्गत नहीं आते थे।

गुप्तचर संगठन प्रभावशाली तथा ठीक तरह से कार्य करे इसके लिए जरूरी है कि उनके कार्यों तथा उपसब्धियों पर विशेष रूप से छाटे गए एस. लोमा ने एक फोरम द्वारा निगाह रखी जाए, जो जन भावना से कार्य करें। इस सुझाव के पीछे सिर्फ 'राष्ट्र तथा नागरिकों का हित' की ही भावना है।

मकान गिराने की कारवाइया सारी कारगुजारों सजय की

एम. रज. सी. के दौरान दिल्ली के विभिन्न इलाकों में गिराए गए मकानों, दुकानों, झुग्गी झोपड़ियों के संबंध में आयोग का मत है कि—

मकान गिराने की कारवाइ के सूत्रधार श्री सजय गांधी थे। श्री जगमोहन तथा श्री टमटा उनके निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे थे। श्री गांधी के गंदी बस्तियां हटाने, नगर के सौंदर्यकरण तथा पुनर्वास बस्तियों के संबंध में अपने अलग विचार थे। श्री गांधी ने दिल्ली प्रशासन में कोई उत्तरग्राह्यत्वपूर्ण पद नहीं सम्भाल रखा था, फिर भी उनके पास पर्याप्त अधिकार थे। श्री जगमोहन तथा

श्री टमटा जसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी लगभग प्रतिदिन १ सफ़दर-जग रोड स्थित श्री गांधी के निवास पर जाकर उनसे प्रशासन के संबंध में आदेश लिया करते थे।”

आयोग के विचार में, ‘देश भर में एमरजेन्सी के दौरान हुई ज्यादतियाँ भी उस एक ज्यादती के मुकाबले कम हैं, जो सम्पूर्ण रूप से अवैध और असंवधानिक तरीके से हुई है। यहाँ एक युवक है, जो एक के बाद एक आवासीय, व्यावसायिक तथा औद्योगिक इमारतों को बस्ती दर बस्ती गिराता जा रहा है तथा जिसके मन में यह रस्ती भर भी भावना नहीं है कि इससे उजड़े उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कोई साधन नहीं है। इस युवक के पास यह सब काय करने के लिए कोई पद या अधिकार नहीं था। निवाय इसके कि वह प्रधानमंत्री का बेटा था।’

बिना ताज के राजा

आयोग के विचार में “श्री गांधी ने दिल्ली के सावजनिक मामलों में जिस प्रकार से काय किया वह एमरजेन्सी के दौरान हुई सबसे बड़ी ज्यादती है जिसके लिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में न तो कोई दूसरा समान उदाहरण है और न ही अधिकार और सत्ता के इस प्रकार का उपयोग प्रायोचित है। ज्यादतियों के दूसरे काय ऐसे अधिकारियों द्वारा किए गए हैं, जिन्होंने अपने अधिकारों से वही अधिक प्रशक्तियाँ की हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति का मामला है, जिसने बिना किसी अधिकार के सामान्यतः तरीके से असीमित अधिकारों का उपयोग किया। यदि इस देश को भावी पीढ़ियों के लिए बचाना है तो जनता को स्वयं इस काय के लिए अपने आपको आश्वस्त कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की गैर विम्बनाराना और ग़रवानूनी सत्ता का केन्द्रीकरण न हान दे जैसा कि एमरजेन्सी के दौरान श्री सत्य गांधी के चारा आर हा गया था।’

आयोग के मतानुसार श्री कृष्णचन्द की न तो कोई सुनता हा था और न ही कोई उनसे सलाह लेता था। इसकी एवज में सभी आत्म श्री गांधी से लिए जाते थे।’

‘श्री टमटा तथा श्री जगमोहन श्री गांधी को प्रशस्त करने के लिए काय कर रहे थे। श्री गांधी बिना किसी देरी के, बिना किसी शर्तों और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा होने की

परवाह किए जल्दी से जल्दी काम पूरा देखना चाहते थे ।”

‘श्री टमटा ने जहां गलत तथा अवध कायों की जिम्मेदारी अपने ऊपर सेत हुए यह कहने की ईमानदारी दिखाई कि उस समय की परिस्थितियों के कारण ऐसा करना ज़रूरी हो गया था, वहां श्री जगमोहन ऐसा कुछ न स्वीकार करते हुए अभी कहने रह कि जा कुछ शिमा कानून के अनुसार किया और ठीक किया ।’

आयोग द्वारा भूदान गिराने के अलग-अलग मामला में दिया गया निम्नलिखित प्रकार है

भगतसिंह मार्केट

नई दिल्ली नगर पालिका के सदस्य सचिव श्री ऐलीवादी की दख रक म हुआ यह काय अवध तथा बिना कानूनी अधिकार के किया गया । श्री ऐलीवादी ने इस करने में अपने पद तथा अधिकार का दुरुपयोग किया ।

सुल्तानपुर माजरा

इस गांव में डी० डी० ए० द्वारा गिराए गए भूदानों के लिए उनके उपाध्यक्ष श्री जगमोहन तथा कायकारी अधिकारी श्री रणबीरसिंह जिम्मेदार हैं । उनका यह काय अवध है क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा ४ के अंतर्गत कोई अधिभूचना जारी किए बिना भूमि पर कब्जा अवध था ।

सराय पीपलथला

श्री जगमोहन ने इस गांव की भूमि के अधिग्रहण के आदेश देकर अवध काय किया ।

धायसमाज मंदिर

आयोग के विचार में श्री जगमोहन ने पूजा के इस स्थान का गिराने के आदेश देकर अपने पद तथा अधिकार का दुरुपयोग किया ।

तुकमान गेट

‘श्री जगमोहन तथा श्री एच० के० लाल ने बिना प्रशासनिक

कायवाही पूरा किए मकानों को गिराने का जो काय कराया, वह अधिकारों का दुरुपयोग है।'

'श्री भिण्डर ने जिस प्रकार से पुलिस द्वारा गोली चलाने के बाद तथा दगा की गर्मी के बीच बुलडाऊर मगाए उससे सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग किया।

समालखा गांव

समालखा गांव में मकान गिराने की कारवाही में श्री टमटा ने अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग किया।

कापसहेडा

"प्रमाणों से सिद्ध होता है कि सबथो जगमोहन, बहादुरराम टमटा रणबीरसिंह तथा सत्यप्रकाश इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन सभीने अपने पदों तथा अधिकारों का दुरुपयोग किया।'

। 'क्योंकि यह काय थी सजय गांधी के कहने पर किया गया था और अवध था इसलिए वे भी इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।"

अर्जुन नगर

"श्री रणबीरसिंह ने श्री अजु नदास के परिवार के सदस्यों को उनके मौखिक ज्ञापन पर परलट देना स्वीकार किया है।"

एम क्षेत्र में टी० टी० ए० द्वारा गिराए गए कुछ मकानों की कारवाही अवध थी इसलिए सबथो जगमोहन सत्यप्रकाश तथा रणबीरसिंह न इस प्रकार के अवध काय में भाग लिया।'

करोलबाग

"दस क्षेत्र में गिराए गए मकानों की कारवाही 'अवध थी, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी भी टमटा और श्री गांधी पर है, जिनके कहने में यह सब किया गया।"

अघेरिया मोड़

आयोग के मत में 'अघेरिया मोड़ के निवासियों की सम्पत्ति को गिराने के आदेश देने के कारण श्री सजय गांधी उसके लिए

जिम्मेदार हैं तथा वह आदेश भी बिना किसी कानूनी अधिकार के दिया गया।'।

तुर्कमान गेट गोलीकाण्ड

‘प्रमाणों से स्पष्ट है कि श्री सजय गांधी ने श्री भिण्डर को आर से मामला में हस्तक्षेप किया तथा जिला मजिस्ट्रेट, उसके सहयोगियों और जूनियर मजिस्ट्रेटों से पिछली तारीख में गोली चलाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। श्री गांधी द्वारा अपने निवास पर मजिस्ट्रेट को बुलाकर इस प्रकार के गलत तथा अव्यवस्थित कार्य करने का आदेश देने का कार्य अव्यवस्थित तथा बिना चाहा गया हस्तक्षेप है।

जनप्रचार-साधनों का दुरुपयोग

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर बिना कोई टिप्पणी किए आयोग के समक्ष पेश किए गए तथ्यों को उजागर किया है जो इस प्रकार हैं

सामान्य

‘प्रेस के विरुद्ध उठाए गए कदमों का एकमात्र कारण जनता को अधिकार में रखना था। यहाँ तक कि ‘राष्ट्रीय दैनिक’ के सम्पादक भी सरकार के इन कदमों के खिलाफ नहीं बोल सकते थे।’

सेंसरशिप

संसद तथा अदालतों की कार्यवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। समाचारों आदि के प्रकाशन के लिए मौखिक आदेश दिए गए। वास्तव में सेंसरशिप का मुख्य उद्देश्य सरकार के खिलाफ खबरों को दबाना, सरकार समर्थक खबरों को उछालना तथा कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की विरोधी खबरों को दबाना था।

प्रेस पर अत्यधिक दबाव

श्री शुक्ल के निर्देश पर समाचारपत्रों की ‘मित्र’ तटस्थ एवं विरोधी के हिसाब से सूची बनाई गई। इसी ध्येय के हिसाब से

अखबारा को विनापन देने के निर्देश भी दिए गए।”

एमरजेन्सी के दौरान 'समाचार' के प्रशासनिक एवं सम्पादकीय दाना प्रायः सरकार के निरीक्षण में चलते थे।

एमरजेन्सी के दौरान कई सवाददाताओं की मायता समाप्त कर दी गई तथा विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय पत्रकारों को पर-
शान किया गया।

सरकारी प्रचार-साधनों का कार्य

“सरकारी प्रचार-साधना द्वारा एमरजेन्सी के दौरान एक राजनीतिक दल तथा उसके नेताओं की सम्बन्धित उभारने के लिए मुख्य रूप में काम किया गया।”

“न सिर्फ कांग्रेस पत्रिकाओं का अधिकांश विनापन दिए गए बल्कि स्मारिका को दिए गए विनापनों की बाढ़ में धरे तक बढ़ा दी गई।”

“आकाशवाणी द्वारा सरकारी तथा विपक्षी दलों के बीच दिए गए समाचारों का अनुपात ८५ से १ तक कर दिया गया।

‘श्री मजय गांधी को न सिर्फ युवा नेता बल्कि राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारने के लिए कई फिल्में बनाई गई।’

कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र का अनुवाद

“आकाशवाणी तथा डी० ए० बी० पी० के अनुवादकों द्वारा कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र का अनुवाद कराने से संबंधित श्री शुक्ल का कार्य पद का दुरुपयोग तथा जनप्रतिनिधित्व कानून १९५१ की धारा १२३ (७) के अंतर्गत एक अपराध है।”

श्री शुक्ल के चुनाव-पोस्टर

आयोग का मत है कि ‘श्री विद्याचरण शुक्ल ने डी० ए० बी० पी० की डिसाइता द्वारा अपने चुनाव-अभियान के लिए पोस्टर बनवाकर अधिकारियों का दुरुपयोग तथा प्रशासन के मूल उद्देश्यों का उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह कार्य जनप्रतिनिधित्व कानून, १९५१ की धारा १२३ (७) के अंतर्गत एक अपराध है।

विशोरकुमार के गीतो पर प्रतिबन्ध

विशोरकुमार के विरुद्ध कारवाई करने का कारण यह था कि किन्म कलाकारों तथा निर्माताओं ने इच्छा के अनुरूप जवाब नहीं दिया था।

श्री यन्त्री द्वारा लिए गए इस निषेध पर श्री शुक्ल ने सहमति दी थी। श्री शुक्ल ने इसे एक गलत कदम बताया हुए इसकी सम्पूर्ण सवधानिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली।

‘श्री शुक्ल की स्वीकृति न लिया गया मन्त्रालय का यह निषेध अधिकारों का दुरुपयोग था।’

श्री शुक्ल द्वारा इनके लिए अपनी सवधानिक जिम्मेदारी लेने में बावजूद वे अधिकारों के दुरुपयोग की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

नियुक्तियाँ

इंडियन एयर लाइंस तथा एयर इंडिया के निदेशक मंडलों की

निदेशक मंडलों की नियुक्ति के संबंध में सामान्य तथा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। मंत्री श्री राजवहादुर को वस्तुतः यह काम प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के सुझाव पर करने को बाध्य होना पड़ा।

भारतीय पघटन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर

सावजनिक उद्योग धन बोर्ड द्वारा जिस व्यक्ति का इतरम्पू में अध्याय घोषित कर दिया गया था उस ही एक उच्च अधिकारी के पद पर नियुक्त करना एक स्वस्थ परम्परा नहीं मानी जा सकती। बहतर यही होता कि बोर्ड से नया नाम सुझाने को कहा जाता। इस प्रकार एक बंधु निवाय के सुझावों को अनग्न्या कर सरकार इस प्रकार की निवाय की प्रतिष्ठा एवं व्यावहारिकता में घुसपठ कर रही थी।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर

सावजनिक उद्योग चयन बोर्ड द्वारा सुझाए गए किसी व्यक्ति का यदि सरकार किसी विशेष कारण से नियुक्त नहीं करना चाहती तो बोर्ड से नया उम्मीदवार सुझाने को कहा जा सकता है, परन्तु इसका स्थान पर बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति को नियुक्त करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।'

रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर

रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर श्री व० आर० पुरी की नियुक्ति में सामान्य तथा स्थापित प्रक्रियानुसार काय नहीं किया गया तथा वित्तमंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम को अस्तुत यह काय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के सुझाव पर करने की बाध्य होना पड़ा। श्रीमती गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अनदेखा करने का यह एक और मामला है।'

पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर

"इस मामले में भी श्री सुब्रह्मण्यम को श्रीमती गांधी के सुझाव पर बाध्य होकर श्री टी० आर० तुली की नियुक्ति करनी पड़ी। श्रीमती गांधी की इस प्रकार की कारवाई पद का दुरुपयोग तथा स्थापित प्रक्रियाओं को तोड़ना है।'

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर

'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० चरदाचारी की नियुक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा इस संबंध में स्थापित सामान्य प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। श्री प्रणव मुखर्जी ने श्री चरदाचारी की इस पद पर नियुक्ति पर स्थापित प्रशासनिक परम्पराओं तथा प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है तथा अपने पद का दुरुपयोग किया है।

दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर

श्री यू० एस० श्रीवास्तव की नियुक्ति में न सिर्फ सावजनिक उद्योग चयन बोर्ड से ही कोई मलाहली गई बल्कि परिवहन तथा जहाजरानी मंत्री से भी कोई विचार विमर्श नहीं किया गया जबकि यह मामला उनके मंत्रालय में जघीर था। श्री श्रीवास्तव को २५०० ३००० की संयुक्त सचिव वाली वेतन शृंखला में नियुक्त किया गया जबकि वे काफी जूनियर अधिकारी थे। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार से स्थापित नियमों तथा प्रक्रियाओं का ऐसी नियुक्तियों में पालन नहीं किया गया।

‘यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति का मामला

‘दिल्ली उच्च ‘यायालय के अतिरिक्त ‘यायाधीश श्री आर० एन० अग्रवाल तथा बम्बई उच्च ‘यायालय के अतिरिक्त ‘यायाधीश श्री यू० आर० ललित का दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर श्रीमती गांधी द्वारा उनकी पुष्टि करते हुए पुनर्नियुक्ति न करना पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग और स्थापित परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन है।

श्री अग्रवाल के विरुद्ध कारवाई उनके द्वारा श्री कुलदीप नायर का मामला सुन जाने के दंडस्वरूप थी जबकि दोनों मामलों में रायों के मुख्य ‘यायाधीशों तथा भारत के मुख्य ‘यायाधीश की स्वीकृति मिल चुकी थी।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण

एसोसिएटेड जनल्स को

आयाग के विचार में, बैंक के अध्यक्ष श्री तुली ने मसर्स एसोसिएटेड जनल्स लिमिटेड का बिना कोई जांच कर ओवर डाफ्ट दिलाकर स्थापित प्रक्रियाओं का तोड़ा है। इस प्रकार से श्री तुली ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया है।’

ऋस्मा केमिकल्स

‘श्री तुली ने मैसर्स ऋस्मा केमिकल्स को बिना व्याज लिए ६,३० ००० रुपये के ऋण पत्र दिलवाकर सामान्य स्थापित प्रक्रियाओं के विरुद्ध काय किया है ।’

भारुति को रियायत

आयोग का विचार है कि ‘इस मामले में प्रशासनिक प्रक्रियाओं अथवा पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग का कोई मामला नहीं बनता ।’

बोइंग विमानों की खरीद

आयोग के विचार से, ‘इंडियन एयर लाइंस के लिए तीन बोइंग-७३७ विमानों की खरीदों के संबंध में उत्तरों से ज्यादा जल्दबाजी की गई ।’

आयोग ने बोइंग विमानों की खरीद के संबंध में हुई बैठक में श्री राजीव गांधी की असामान्य उपस्थिति पर भी टिप्पणी की है ।

श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा विमान आयात

‘ब्रह्मचारी ने प्रधानमंत्री निवास के साथ अपने संबंधों का पूरा लाभ उठाते हुए एक विमान का उपहार के नाम पर झूठ बोलकर आयात करा लिया । उन्होंने स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तोड़ते हुए तेजी से काम किया । ब्रह्मचारी ने विमान को उपहार-स्वरूप बताकर कस्टम की स्वीकृति भी ले ली । कस्टम बचाने के लिए उन्होंने अपूर्ण आर्थिक का धर्माय संस्था घोषित कर दिया । ब्रह्मचारी ने जम्मू के निकट एक हवाई पट्टी का निर्माण करवाने में भी प्रशासनिक प्रक्रिया को आनन फानन में गंवावानी तरीके से पूरा करवा लिया ।’

जिम तरीके से ब्रह्मचारी की मांगों को पूरा करने के लिए देश की सुरक्षा के विचार को उठाकर ताक पर रख दिया गया, उसके प्रति आयोग ने चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकार ॥ ऐसे गम्भीर मामलों में अपनी स्पष्ट नीति तय करने को कहा है ।

२ श्रीमती गांधी और शाह आयोग

एमरजेन्सी की घोषणा और उस दौरान हुए कार्यों की प्रमुख सूत्रधार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का शाह आयोग ने छ बार बुलाया। चार बार उन्हें आयोग ने सट्टेयों करने के लिए निमंत्रित किया और दो बार उन्हें समन भेजा।

श्रीमती गांधी को पहला आमंत्रण ७ नवम्बर को जाच आयोग अधिनियम के नियम ५ (२) (ए) के अंतर्गत भेजा गया था जिसमें आयोग के समक्ष पेश होकर शपथ लेकर बयान देना होता है। परंतु चूंकि उन दिनों श्रीमती गांधी अपने दौरान में व्यस्त थी इसलिए उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए आगे कोई और तारीख देने का अनुरोध किया। आयोग ने उनकी बात मान ली, और पुनः २१ नवम्बर को आमंत्रित किया।

सोच गए, मगर तमाशा न हुआ

श्रीमती गांधी के २१ नवम्बर को आयोग के सामने पेश होने की सम्भावनाओं को देखते हुए इंडिया गेट इलाके में जहाँ पटियाला हाउस में शाह आयोग की कार्रवाई हो रही है पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो पाए। उस दिन पटियाला हाउस पर भारी सट्टा में जनता पहुँची। इसका अतिरिक्त बड़ी संख्या में देश और विदेश के पत्रकार टी० बी० कमरामैन और फोटोग्राफरों ने प्रातः आठ बजे से ही वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया।

जैसे-जैसे साढ़े नौ बजे का समय नज़दीक आने लगा त्यों-त्यों नागों की उत्सुकता बढ़ने लगी। देखते-देखते साढ़े नौ भी बज गए परंतु श्रीमती गांधी नहीं पहुँची और सारा का सारा बंदोबस्त बेकार हो गया और साथ ही इसपर जो भारी खर्च हुआ, वह अलग।

साढ़े नौ बजे जस्टिस शाह जहाँही बक्ष में प्रविष्ट हुए उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते ही पूछा 'श्रीमती गांधी के बारे में क्या सूचना है?' कुछ क्षणों की खामोशी के बाद एक एडवोकेट श्री मुशीन कुमार जागे आए और बोले 'श्रीमान्, श्रीमती गांधी तो उपस्थित नहीं हुई हैं परंतु मैं उनकी ओर से एक बयान लाया हू'

जिसे अनुमति हो तो पढ़ा जा सकता है।" जस्टिस शाह ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी।

आयोग के जाच अधिकारी द्वारा पढ़े गए श्रीमती गांधी व चयान में कहा गया था कि आयोग की कार्यवाही जिस प्रकार समाचारपत्रों में प्रकाशित और आवाजवाणी तथा दूरदर्शन के जरिये प्रसारित की जा रही है उससे भरी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो रही है और चरित्र-हानि हो रहा है। आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जाच आयोग सबधी कानूनों से संघर्ष पर है। आयोग के समक्ष सबसे पहले आरोपों में संबंधित कहानी पढ़ी जाती है पता नहीं कि कानून के अंतर्गत उस कहानी के निर्माण के लिए सामग्री एकत्र की जाती है और किस कानून के अंतर्गत इसे आयोग के रिकार्ड में शामिल किया जाता है।

आयोग की कार्यवाही जिस प्रकार से चल रही है उससे भरी प्रतिष्ठा पर गहरी आंच आ रही है। संविधान के अनुच्छेद २१ के अंतर्गत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा का मुझे पूरा अधिकार है और मुझे उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मुझे किसी ऐसी प्रक्रिया का शिकार भी नहीं बनाया जा सकता जिसके कारण मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो। यू. कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कुछ भी किया जा सकता है।

प्रश्न मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं प्रतिष्ठा तो देश के एक प्रधानमंत्री की दाव पर लगी हुई है। आयोग के समक्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में मेरी कार्यवाहियां विचाराधीन हैं। आयोग के समक्ष चल रही कार्यवाही के दौरान आयोग द्वारा (जस्टिस शाह) प्रसंगवश की गई टिप्पणियां को आवाजवाणी दूरदर्शन और समाचारपत्रों द्वारा इस प्रकार उछाला जा रहा है माना आयोग ने अपना फैसला दे दिया हो। आयोग ने गवाहों से जिरह करने की छूट नहीं दी है इसके फलस्वरूप अनेक गवाह मनमाने तौर पर गवाहियां दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें जिरह में पकड़े जान का डर नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वयं आयोग द्वारा सभी जिरह की जाती है।

‘आयोग की कार्यवाही हसी मजाक और सौर शराबों के जिस वातावरण में चलती है उसे “यायालय योग्य वातावरण” नहीं कहा जा सकता। आयोग की कार्यवाही के दौरान श्रोताओं

द्वारा ध्वस्त हूँ मजबूत को जिस प्रकार रेडियो पर प्रसारित किया जाता है, उसमें इस आयोग की नियुक्ति के पीछे छिपी राजनीतिक मनोभावना का साफ परित्यक्त मिलता है।”

‘आयोग को विद्वेषपूर्ण राजनीतिक प्रचार का अघाट बनाया जा रहा है जबकि वास्तव में यह एक कानूनी केन्द्र है। ऐसा लगता है, जैसे समाचारपत्रों द्वारा खुली सुनवाई की जा रही हो।’

‘यदि विभिन्न आरोपों पर सबसे पहले भारत सरकार के बयान लिए जाते और उसपर अन्य संबंधित लोगों की गवाही होती तो जनता के सामने सतुलित चित्र प्रस्तुत होता।’

प्रक्रिया को चुनौती

आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा ‘एक ही आरोप पर दो बार जाच की स्थिति पदा हो गई है। जाच आयोग किसीको सजा दान का अधिकारी नहीं है। इसकी कायवाही से मुझे जितनी हानि पहुंच सकती है वह तो इसकी पहले खरण की कायवाही से पहुंच चुकी है। आयोग द्वारा ज्यादाती का सारा मामला निर्धारित किए जाने के बाद सुनवाई के दूसरे दौर में जब उन ज्यादातियों के लिए जिम्मेदार लोग पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कायवाही चलेगी तब उसका मुझे कोई लाभ नहीं होगा। दोहरी जाच ही कोई गुजाइश नहीं थी यदि यह प्रारम्भिक जाच हो रही है तो इसे सावजनिक तौर पर किया जाना उचित नहीं है।’

‘मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा दी गई गवाहियों के दौरान मंत्रिया द्वारा प्रधानमंत्री के नाम लिखे गए पत्रों के उद्धरण पत्र करने से कुछ महत्वपूर्ण सवधानिक प्रश्न खड़े हो गए हैं जिसका संवध मंत्रिमंडल की कायप्रणाली और प्रधानमंत्री पद की गरिमा से संबंधित है।’

स्पष्टीकरण

श्रीमती गांधी ने अपने बयान में अपने द्वारा किए गए कुछ कार्यों का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि जब दो मंत्रालयों के बीच विचारों में परस्पर विरोध उठ खड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में

प्रधानमंत्री अपने विवेक से निणय करता है और ऐसा हो कई मामला में किया गया है। परन्तु उनके द्वारा किए गए इसी प्रकार के निणय को अब आयोग द्वारा ज्यादाती कहा जा रहा है।

इस संबंध में उन्होंने जस्टिस आर० एन० अग्रवाल और जस्टिस यू० आर० ललित के मामलों का उल्लेख किया निम्न गृहमन्त्रालय ने परस्पर विरोधी राय दी थी।

रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर श्री पुरी की नियुक्ति का फसला उन्होंने उनकी योग्यता को देखते हुए किया था तथा पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री तुली की नियुक्ति श्री सुब्रह्मण्यम की सहमति से की गई थी।

टक्सटाइल कमिटी के दस और कस्टम विभाग के दो इस्पेक्टर्स की गिरफ्तारी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी बल्कि बहुत से लोगों ने उसे वाणिज्य मन्त्रालय के कई अधिकारियों के बारे में झूठाचार में लिप्त होने की शिकायतें की थीं जिनके बारे में श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय को अवगत करा दिया था।

समस्त जिम्मेदारी अपने ऊपर

श्रीमती गांधी का कहना था कि शिकायत तो उनके पास थी टी० ए० प के बारे में भी आई थी कि वह तथा उनके परिवार के सम्बन्ध धन बना रहे हैं पर उन्होंने इस ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया था। मर्रा अभिप्राय अपने मन्त्रिमंडल के सदस्यों को दोषी ठहराने का नहीं है। मैं जिन सरकार का नेतृत्व किया है उसकी सभी कार्यवाहियाँ के लिए मैं सम्पूर्ण सवधानिक और राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ।

श्रीमती गांधी के सम्बन्ध १७ पृष्ठों के बयान के बाद जस्टिस शाह ने अपनी व्यवस्था करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि जाच अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग का जिन विषयों की जाच का भार सौंपा गया है वे असाधारण हैं। इस प्रकार की जाच कानून के अंतर्गत पहल कभी नहीं हुई थी। स्वभावतः आयोग के समस्त असह्य शिकायतें पहुँचीं चूँकि उनमें से सभी का निपटाना आयोग के लिए संभव नहीं था इसलिए आयोग ने जाच की एक निश्चित प्रक्रिया अपनायी जो जाच आयोग कानून के अंतर्गत सही है।

जिन आरोपों या शिकायतों में कुछ सत्य नज़र आए हैं उनकी जांच का ही फलला किया गया है। शेष शिकायतों को यही खारिज कर दिया गया है। ज्यादातर के जिन मामलों की जांच का मैंने फलला किया है उनकी अभी प्रारम्भिक जांच ही की जा रही है। सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि वह सबकुछ ज्यादाती का मामला है या नहीं। यदि प्रारम्भिक जांच के बाद यह सिद्ध हो गया कि ज्यादाती का साफ साफ मामला बनता है तो उस मामले की दूसरे दौर में गहराई से जांच की जाएगी और उसके दौरान संबंधित लोगों को समन देकर बुलाया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि उन शिकायतियों के लिए कौन कौन ज़िम्मेदार हैं। जिसपर आरोप होंगे उनको गवाहों से जिरह करने का भी पूरा अवसर दिया जाएगा।

जस्टिस शाह के अनुसार आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने में सक्षम है और अपन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की संवधानिकता या वधता पर उस स्वयं निणय लेने का अधिकार नहीं है। (शायद उनका संकेत था कि जिन्हें यह प्रक्रिया उचित नहीं मालूम होती है व उसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।)

जस्टिस शाह ने स्पष्ट किया कि आयोग की जांच का उद्देश्य किसीको बदनाम करने का नहीं है। जिस निस्तीके विरुद्ध कोई आरोप है उन्हें जवाब देने और निराधार साबित करने के लिए पूरा अवसर दिया जाएगा और दिया भी जा रहा है।

जस्टिस शाह का कहना था कि हमारा समाचारपत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है अतः आयोग के समक्ष चल रही बयानवाही को वे किस प्रकार से छाप रहे हैं उसपर हमारा धम नहीं है और यही बात आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी लागू होती है।

श्रीमती गांधी के बयान के बाद सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लेखी ने कहा कि श्रीमती गांधी ने आयोग के समक्ष स्वयं पेश होने के स्थान पर अपना बयान भेजकर इस न्यायिक आयोग का निरादर किया है।

उनका कहना था कि श्रीमती गांधी ने स्वयं तो न्यायचरण के साथ सिद्धांतों की कथित अवहेलना का आरोप लगाया है परन्तु स्वयं अपने बयान में वर्तमान सरकार के मंत्रियों पर एकतरफा

आरोप लगाकर इस अवसर का नाजायज फायदा उठाया है और जायवरण व प्राथमिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

तीसरे बुलावे का जवाब

आयोग की ओर से २४ नवम्बर को एक बार फिर पत्र लिख कर श्रीमती गांधी से एमरजेन्सी की घोषणा व औचित्य पर विचार करने का समय आयोग के सामने ५ से १० नवम्बर तक उपस्थित हान का अनुरोध किया गया जिस भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आमंत्रण के जवाब में आयोग को २ नवम्बर को अपना बयान भेजा और इसके साथ ही उसकी प्रतिया समाचारपत्रों में प्रकाशन के लिए भी जारी कर दी।

श्रीमती गांधी ने अपन इस बयान में आयोग के समक्ष उपस्थित होने से इकार करते हुए कहा कि एमरजेन्सी की घोषणा के समय में आयोग को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। श्रीमती गांधी ने आयोग से कहा कि नियमानुसार समन भेजने पर ही वह आयोग के सामने उपस्थित होगी।

उन्होंने कहा 'जांच आयोग अथवा किसी भी प्राधिकरण को ससद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम या प्रस्ताव की वैधानिकता अथवा औचित्य पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत किसी मसदीय कार्य की जांच नहीं की जा सकती। यदि जांच आयोग ने ससद की कार्यवाही पर विचार करना शुरू किया तो वह संविधान की व्यवस्था और ससद की सर्वोच्चता पर आघात होगा। एमरजेन्सी की घोषणा की जांच शाह आयोग की जांच की परिधि से पर है। एमरजेन्सी की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक संवैधानिक कदम था, जिसे मन्त्रिमंडल ने अनुमोदित किया था और ससद के दोनों सदनों ने सम्पुष्ट किया था इसलिए उसके औचित्य पर जांच आयोग विचार नहीं कर सकता।'।

श्रीमती गांधी ने एमरजेन्सी के पूर्व की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा, एमरजेन्सी के पूर्व से केन्द्र सरकार को कमजोर करने और निर्वाचित सरकार को अपदस्त करने का उपक्रम किया जा रहा था। एक तरफ लोकतांत्रिक धमनिरूपेण और समाजवादी शक्तियाँ थी और दूसरी ओर प्रतिजियावादी, साम्प्रदायिक और

पूजीवादी तत्त्व थे। जब देश विश्वव्यापी मुद्रा स्फीति की चपेट में था और बगला देश की लड़ाई में उत्तम कठिनाइयों से गुजर रहा था, प्रतिश्रियावादी तत्त्व गर सवधानिक तरीके से केन्द्र सरकार को उलटकर सत्ता हथियान का कुचक चला रहे थे। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया। उससे हमारे विरुद्ध उनका राजनीतिक उन्माद और बढ़ गया। यद्यपि आक्रमण का केन्द्र मैं थी, परन्तु वास्तव में वे कांग्रेस को हटाकर असवधानिक तरीके से सत्ता हस्तगत करना चाहते थे। वसी स्थिति में प्रधान मंत्री के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से वच नहीं सकती थी।"

उनका तर्क था कि सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से लेकर एमरजेंसी की घोषणा तक के घटनाक्रम पर विचार करने से न्याय के बदले अन्याय होगा, क्योंकि केवल उस दौरान की घटनाओं से यह पता नहीं चलेगा कि उस समय स्थिति कितनी विकट हो गई थी।

समाचारपत्रों में बयान के प्रकाशन पर आपत्ति

लगभग दो सप्ताह के अंतराल के बाद ५ दिसम्बर को आयोग की कार्यवाही प्रारम्भ होत ही जस्टिस शाह ने श्रीमती गांधी द्वारा भेजे गए पत्र के समाचारपत्रों पर प्रकाशन पर आपत्ति करते हुए कहा कि जब आयोग ने उक्त पत्र पर विचार ही नहीं किया तब किस प्रकार से उसे समाचारपत्रों में प्रकाशन के लिए दे दिया गया? उनका कहना था कि आयोग को भेजा गया प्रत्येक वागश एक 'याचिका' दस्तावेज है तथा बिना आयोग द्वारा विचार पूरा किए ही उसे प्रकाशन के लिए दे देना उचित नहीं है। आयोग के कार्यालय द्वारा श्रीमती गांधी से समीकृति का ध्यान न रखते हुए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का कहा गया था, परन्तु उन्होंने उपस्थित होने के स्थान पर अपने पक्ष में कई 'याचिकाएँ' एवं राजनीतिक आपत्तियाँ उठाई हैं।

श्रीमती गांधी द्वारा आयोग की प्रक्रिया के सवध में उठाई गई आपत्ति पर अपनी पूर्व व्यवस्था की दोहरात हुए उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया उचित है तथा काफी सोच विचारकर ही उसे अपनाया गया है।

जस्टिस शाह ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई

व्यक्ति आयोग के समक्ष उपस्थित न हाने इसकी कायवाही रोकना चाहता है तो वह इसमें सफल नहीं होगा। 'मैं कई बार आयोग की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण दे चुका हूँ इसलिए उस बार बार दोहराना आवश्यक नहीं है। आयोग की कायवाही जारी रहेगी और दो चरणों में ही होगी।

उनका कहना था कि 'मेरा राष्ट्रपति जयवा गस्त' द्वारा जारी किए गए आदेशों को चुनौती देने का कोई ध्येय नहीं है, तथा ऐसा मोचना एक गलत धारणा है। मुझे जो वाय मीपा गया है मैं सिर्फ उसीके अनुसार काय कर रहा हूँ। एमरजेन्सी में हुई व्यावस्थित तथा एमरजन्सी किन परिस्थितियों में समाप्त गई इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ १२ जून १९७५ कबान की परिस्थितियों पर ही विचार करता हूँ।'

सरकारी वकील श्री लेखी ने जस्टिस शाह की 'यवस्था के बा' कहा कि आयोग के इस मच में श्रीमती गांधी द्वारा जब कुछ राजनीतिक मुद्दों को उठाया गया है तब आयोग की ओर से भी उनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।

जस्टिस शाह ने इसपर कहा आयोग एक राजनीतिक प्रचार मच नहीं है। यदि किसी बात का स्पष्टीकरण करना भी है तो यह काय सरकार का है आयोग का नहीं।

परन्तु श्री लेखी का कहना था कि जब आयोग ने श्रीमती गांधी के पत्र को अपने दिवाइ म रखा है तब इसका स्पष्टीकरण भी इसी मच में होना चाहिए परन्तु जस्टिस शाह ने उसे स्वीकार नहीं किया।

धानूनी लडाइ की शुरुआत

आयोग द्वारा श्रीमती गांधी को तीन बार आयोग के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध करने पर भी न आने के बाद उन्हें जाच आयोग अधिनियम के नियम ५ (२) (ए) तथा धारा ८ (डी) के अनुसार समक्ष देवर ६ १० और ११ जनवरी १९७८ का आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

श्रीमती गांधी को इन दिनों ग्यारह मामलों पर अपना बयान दाखिल करने को कहा गया था। ये मामले इस प्रकार हैं

१ दिल्ली उच्च न्यायालय के 'गांधीश्री श्री ए० एन०

अग्रवाल की पदावनति ।

२ बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यू० आर० ललित की पुनर्नियुक्ति ।

३ केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय में उप-सचिव श्री कृष्णास्वामी, तबनीकी विकास महानिदेशालय में विकास अधिकारी श्री ए० एस० राजन, राज्य व्यापार निगम में मुख्य मार्केटिंग मैनेजर श्री एन० आर० कान्हे तथा इसी विभाग के उप मुख्य मार्केटिंग मैनेजर श्री पी० एस० भटनागर के विरुद्ध कारवाई ।

४ पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० तुनी की नियुक्ति ।

५ रिज़र्व बैंक के गवर्नर पद पर श्री के० आर० पुरी की नियुक्ति ।

६ एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइंस के निदेशक मंडलों के सदस्यों की नियुक्ति में नियमों के पालन न करने का मामला ।

७ टक्काटोइल तथा कस्टम विभाग के इन्स्पेक्टरों की मीसा में गिरफ्तारी ।

८ श्री भीमसन सच्चर तथा सात अन्य की मीसा में गिरफ्तारी ।

९ विश्व युवक केन्द्र का भारत सुरक्षा कानून में अतंगत अधिग्रहण ।

१० राजस्थान के एक आई० ए० एस० अधिकारी श्री मंगल-बिहारी का निलम्बन तथा एक सहायक अध्यापिका श्रीमती चन्द्रेश शर्मा का निलम्बन ।

११ (ए) १२ जून से २२ जून १९७५ के बीच की घटनाएँ ।

(बी) २३ जून से २५ जून १९७५ के बीच की घटनाएँ ।

(सी) २५ और २६ जून १९७५ की मध्य रात्रि का तथा उसके बाद की गई मीसा में मजूरवादिया तथा अन्य गिरफ्तारियाँ ।

उनका आना भी खबर बन गई

६ जनवरी, १९७८ का दिन सवेरे का समय । इडिया गेट इलाके में पटियाला हाउस के आसपास का दृश्य । पुलिस का लगभग वही २१ नवम्बर १९७७ जैसा इन्तजाम । चारों ओर पुलिस के जवानों की भारी भीड़ नजर आ रही थी । आम दिनों की भांति आम आदमी को आयोग कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं थी । आयोग वस में सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों को ही पास से प्रवेश करने दिया जा रहा था । आयोग के मुख्य द्वार पर भारी सड़पा में देश विदेश की टेलीविजन कंपनियों के कैमरामैनों के साथ-साथ बहुत से अन्य फोटोग्राफर भी मौजूद थे । लांगो ने सवेरे आठ बजे से आना प्रारम्भ कर दिया था । विशिष्ट व्यक्तियों के सिवाय अन्य लोगों को पटियाला हाउस के बाहर के लॉज में बल्लियों के सहारे दूर ही रखा जा रहा था । इस भीड़ में श्रीमती गांधी के समर्थक और विरोधी दोनों ही मौजूद थे । सारवात्ता वरण में हलकी सी चहल पहल थी और मनो में यह शक भी कि शायद श्रीमती गांधी आज भी न आएँ । समय के साथ-साथ लोगों की भीड़ भी और उपस्थित लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी । लॉज में एकत्र लोगों के लिए अदर की कायबाही सुनने हेतु साउंडस्पीकरों की व्यवस्था कर ली गई थी ।

आयोग का अदर का कक्ष लगभग नौ बजे ही पूरा भर चुका था । भूतपूर्व रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचंद सेठी तथा श्रीमती गांधी के अतिरिक्त सचिव श्री राजेन्द्र कुमार धवन आ चुके थे । अखानक लांगो में छनवली मंत्री और लगभग सब नौ बजे कम के बीच का दरवाजा विशेष रूप से खोला गया जबकि रोजाना पीछे का ही दरवाजा खोला जाता था । दरवाजा खुलने के साथ ही श्रीमती गांधी के बड़े पुत्र श्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया तथा श्री सचय गांधी की पत्नी श्रीमती मेनका गांधी ने प्रवेश किया । और इसीके साथ लोगों को विश्वास हो गया कि श्रीमती गांधी भी आ रही हैं । धीरे-धीरे श्रीमती गांधी के अन्य भूतपूर्व मन्त्रिमंडलीय साथी भी आने लगे । उनमें प्रमुख थे—भारी उद्योगमंत्री श्री टी० ए० पैं वाणिज्यमंत्री श्री डी० पी०

चट्टोपाध्याय, गृह राज्यमन्त्री श्री ओम मेहता, श्री बी० पी० मोय, श्री ए० पी० शर्मा और श्री एच० के० एल० भगत ।

दस बजते म लगभग दस मिनट पहले श्रीमती गांधी वहां पहुंच गई थी, उनके साथ थे उनके पुराने साथी मीर कासिम । श्रीमती गांधी व पहुंचते ही पटियाला हाउस के लाज में और बाहर एक झेड ने उनके समर्थन और विरोध में बराबर नारे लगाए । श्रीमती गांधी के आयोग के कक्ष में प्रवेश करते ही वातावरण में एकदम हलचल पड़ा हो गई थी । ज्यादा गहरे गुलाबी रंग की साड़ी और उसपर ऊनी क्नाउज पहन के आयोग के कक्ष में पहुंची वहां उपस्थित अनेक लोग और उनके अधिकांश भूतपूर्व साथी उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए । वे कुछ देर तक अपने साथियां और फिर अपने वकीलों से बातचीत कर आगे की पक्ति में रखी कुर्सी पर बैठ गई ।

दस बजते ही जस्टिस शाह ने कक्ष में प्रवेश किया । सभी लोग उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ कर सबको नमस्कार किया । जस्टिस शाह ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही पूछा ' क्या श्रीमती गांधी ने जांच आयोग अधिनियम के नियम ५ (२) (ए) के अंतर्गत अपना बयान दाखिल कर लिया है ? ' और इसके साथ ही कानूनी और राजनीतिक तर्कों का लगभग ढाई दिन तक चलने वाला सिलसिला शुरू हो गया । श्रीमती गांधी की ओर से उनके वकील श्री फ्रैंक एयनी न, जो वर्यो तक संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे थे, परवी की ।

तर्क पर तर्क

श्री एयनी के तर्कों का मुख्य मुद्दा यही था कि शाह आयोग की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य श्रीमती गांधी की प्रतिष्ठा को समाप्त करना है । जो काम आयोग को सौंपा गया है और उसने जिस तरह की कार्यप्रणाली अपनायी है तथा समाचारपत्रों में आरोपों के बारे में एक तम्बे अर्से से जिस प्रकार लिखा जा रहा है उसमें ऐसा लगता है, मानो श्रीमती गांधी और उनके साथी पहले से ही दोषी साबित हो चुके हों । इस समस्त प्रचार से श्रीमती गांधी की प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची है । जब श्रीमती

गांधी के विरुद्ध सबधित गवाहा ने आरोप लगाए, उसी समय आयोग को उन्हें नाटिस देकर बुलाना चाहिए था, तानि बचाव पत्र भी उसके सबध में अपना स्पष्टीकरण दे सकता। इसलिए अब पहले धारा ३ (बी) के अनुसार सबधित गवाहा से जिरह करन का मौका दिया जाना चाहिए और इसके बाद ही वे नियम ५ (२) (ए) के अनुसार अपना बयान देंगे।

जस्टिस शाह ने इसपर बड़े ही शांत और समतल तरीके से उन्हें टोका और समझाने की चेष्टा करते हुए कहा 'जसा आप समझ रहे हैं वसा नहीं है। यह कोई फौजदारी जमानत नहीं है और न ही महा कोई अभियुक्त है। हम सिर्फ सच्चाई जानन की चेष्टा कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जब तक सरसरी नज़र से कोई मामला नहीं बनगा कि उसने एमरजेन्सी के दौरान अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जाएगा।

जस्टिस शाह ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा 'हमने पहले भी श्रीमती गांधी को आमंत्रित किया था कि वे आए और आयोग को सच्चाई का पता लगाने में मदद करें पर श्रीमती गांधी ने इसमें सहयोग नहीं किया। छानबीन के बाद आयोग इस परिणाम पर पहुंचा है कि ऐसे मामले हैं जिनका श्रीमती गांधी से ताल्लुक हो सकता है और जिसके बारे में उनकी जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। इसी कारण उन्हें आयोग में उपस्थित होने के लिए समन जारी किए गए।'

जस्टिस शाह के इस स्पष्टीकरण के बावजूद श्री एघनी ने अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए गृहमंत्री श्री चरणसिंह के उस वक्तव्य पर आपत्ति की जिसमें कहा गया था कि आयोग की प्रारम्भिक कार्यवाही से सिद्ध हो गया है कि श्रीमती गांधी ने एमरजेन्सी के दौरान अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था तथा इस आधार पर उनका विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। उनका कहना था कि श्री चरणसिंह के वक्तव्य से ऐसा लगता है जैसे आयोग उनके इशारे पर कार्य कर रहा हो। इन सब बातों ने स्पष्ट हो जाता है कि जायाग का एकमात्र लक्ष्य श्रीमती गांधी हैं और इसकी कार्यवाही से श्रीमती गांधी जसी विश्व प्रतिष्ठित महिला को काफी धक्का लगा है।

जस्टिस शाह ने इसपर एक बार फिर उह टोकत हुए कहा, 'आयोग के समय जो भी व्यक्ति उपस्थित होता है वह गवाह के रूप में जाता है और मरी नजर में वह सिर्फ गवाह है। उस व्यक्ति की राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार की हैसियत से इसपर कोई अन्तर नहीं पड़ना। जहाँ तक यहमन्त्री और जख़्ख़ारा का प्रश्न है उनसे मुझे कोई सगेकार नहीं है, क्योंकि वे मेरे नियंत्रण में नहीं हैं।'।

एक जन्म दिया, सऊडो जन्म भी कम थे

उनका कहना था कि जहाँ तक आयोग की प्रक्रिया का संबंध है आयोग के समक्ष ज्यातितिया व लगभग ४८ हजार मामल आए थे और यति धारा ८(बी) के अनुसार प्रत्येक गवाह के आरोप पर सब-धित व्यक्ति को बुलाया जाता तो आयोग की कायवाही इस जन्म में तो क्या सऊडो जन्म में भी पूरी नहीं हो सकती थी। आयोग द्वारा जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करने के लिए ही यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

श्री एयनी ने अपनी दसौला में आज कहा कि आयोग द्वारा २३ से २५ जून १९७५ की घटनाओं पर विचार करना तकसगत नहीं है क्योंकि एमरजेन्सी की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी तथा मन्त्रिमल द्वारा उसका अनुमोदन किया गया था और इनकी जाच करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसपर जस्टिस शाह ने फिर टोका और कहा, 'मैं राष्ट्रपति जख़्ख़ारा मन्त्रिमल की कायवाही की जाच नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यह जाच कर रहा हूँ कि एमरजेन्सी त्रिन परिस्थितिया में लागू की गई थी वह वाय सम्मत थी जख़्ख़ारा नहीं। इसपर श्री एयनी ने टिप्पणी करते हुए कहा, यह अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा की जाच करना हो है।'।

श्री एयनी ने कहा कि जब वर्तमान उद्योगमन्त्री श्री जाज फ़र्नांडीस स्वयं ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने तथा उनके साथिया ने अपने वर्नाटक राज्य में एक महीन के दौरान १२ रेल-गाडियों का पटरी से उतारा था तब किस प्रकार से कहा जा सकता है कि एमरजेन्सी गलत परिस्थितिया में लागू की गई थी ?

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'आप यह क्या समझ रहे हैं कि मैं अपना यह दृष्टिकोण बना लिया है कि एमरजेन्सी गलत लागू

की गई थी ?

श्री एथनी का तत्कालीन भाषण जितना कानूनी था, उतना ही राजनीतिक भी। जिस तरह कानूनी तर्कों व माथ-माथ राजनीतिक तर्कों को मिलाकर वे सदन में अपनी बर्निया अग्रेजी में थोताओ को प्रभावित करने की चेष्टा किया करते थे उसी तरह की चेष्टा उन्होंने यहां भी की। उनकी बहस के दौरान उनकी किसी बात पर उत्सहित लोगो ने व्यंग्य भरा ठहाका लगाया तो वे बिगड़ उठे और बाने में जानता हूँ, यहां जानबूझकर एम लोगो को बुलाया जाता है जो वर्तमान सरकार के समर्थक हैं और इसलिए बीच-बीच में हसत और ठहाके लगाते रहते हैं। हा मेरी अग्रेजी पर रीझकर वे हमें तो मुझ कोई एतराज नहीं है। इसपर जस्टिस शाह ने जोर दार हमी व बीच कहा ' मैं दोनों ही तरह की हमी को गर जरूरी समझता हूँ।

श्री एथनी के तर्कों के बाद सरकारी वकील श्री लेखी और आयोग के वकील श्री वास खडालावाला व उनके तर्कों को निराधार बताते हुए आयोग के गठन और उसकी कार्यप्रणाली को उचित ठहराते हुए अनेक तर्क प्रस्तुत किए।

दूसरा दिन पहले जसा

१० जनवरी १९७८ के सबेरे का समय और लगभग पिछले दिन जसा ही वातावरण। आज भी कई भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त श्रीमती गांधी के छोटे पुत्र श्री सजय गांधी उनकी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी तथा उनकी भाभी श्रीमती सोनिया पहले ही आ गए थे। उनके लगभग दस मिनट बाद ही श्रीमती गांधी भी पक्ष में पहुंच गई। आज पक्ष में पहले जिन के मुखावले जरा कम चुस्ती थी, क्योंकि लोगो ने अनुमान लगा लिया था कि आज का दिन भी लगभग श्री एथनी ही लेंगे और श्रीमती गांधी शायद ही अपना बयान दें।

श्री एथनी ने कायवाही शुरू होते ही अपने वही पहल जिन वाले तक रखने शुरू किए जो वे बड़ विस्तार से रख चुके थे। इसके साथ ही वे आयोग के वकील श्री खडालावाला और सरकारी वकील श्री लेखी की बहस का भी उत्तर देते रहे।

कायवाही के दौरान श्री एथनी और श्री लेखी में कई बार गरमा-

गरम झड़पें हुई। एक अवसर पर श्री एयनी द्वारा अपनी दलीलों के दौरान आक्रमण का लक्ष्य बार-बार श्री लेखी की बनान पर उठाने (श्री लेखी ने) कहा 'यदि मेरी उपस्थिति से श्री एयनी को इतनी परेशानी हो रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूँ। आखिर मैं मुझे हवा क्या समय रहे हैं मैं कोई फंक्शन तो हूँ नहीं।' इसपर श्री एयनी ने उसी प्रकार मजाक में कहा 'नहीं नहीं आपको जान की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं स्वयं ही अपनी दलीलें समाप्त करने वाला हूँ और उसके बाद आपको चाय पिलाऊंगा।'

आरोप प्रत्यारोप

एक अन्य अवसर पर श्री एयनी ने श्री लेखी को लक्ष्य करते हुए कहा कि विद्वान मिस किस प्रकार से आपाग के साथ सहयोग कर सकते हैं जबकि उनकी सरकार जिमका व प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पहले से ही श्रीमती गांधी के प्रति पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं और फिर श्री लेखी जिस शस्त्री में घोलत हैं वह उचित नहीं कही जा सकती तथा आरोप भी इसपर आपत्ति नहीं करता।" इसपर श्री लेखी आवाज में आ गए और बोले 'मैं किसीका खरीदा हुआ नहीं हूँ और न ही मैं ससद सदस्य के रूप में कभी मनानियन के लिए ही प्रायना की हूँ।'

इसपर जस्टिस शाह की बीच में टोककर कहना पड़ा 'बेहतर है आप लागू रहा आपसी छोटाकशी न करें।'

श्री एयनी ने इसके जवाब में कहा कि वे अपनी दलील में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तथा श्री लेखी के लिए उठाने एक भी शब्द नहीं कहा है जबकि वे बराबर उनपर व्यक्तिगत आरोप कर रहे हैं। वे ससद में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

लगभग डेढ़ दिन सम्बन्धी वृहत् सुनने के बाद जस्टिस शाह ने श्री एयनी के एतराजों पर अपने फसल में आयोग की कार्यवाही का पूर्णतः उचित और बधानिक ठहराते हुए निष्कर्ष दिया कि 'जैसा आयोग अधिनियम के अंतर्गत श्रीमती गांधी को शपथ लेकर अपना बयान दाखिल करना चाहिए था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया है इसलिए सच्चाई जानने के लिए जरूरी हो गया है कि मैं उनसे जिरत

करू।”

जस्टिस शाह न लगभग ८५ मिनट तक विभिन्न मुद्दा पर अपना निणय दत हुए कहा कि आयोग न जो प्रक्रिया अपनायी है वह उचित है और सही है। अधिनियम व नियम ५(२) (ए) व अनु-भार श्रीमती गांधी शपथ लेकर बयान देन को बाध्य हैं। उह व मूल दस्तावेज या उनकी प्रतिनिधिया भी पेश करनी हानी जिनके आधार पर व जपना बयान दयी। जस्टिस शाह ने स्पष्ट किया कि आयोग की कार्यवाही न तो दीवानी मुकदमा के समान है और न ही फौजदारी मुकदमा व बल्कि उनके द्वारा किया जा रहा जाच काय सच्चा-बपा-मक निम्न का है तथा यह न्यायतंत्र में जीवन की शुद्धता और एकात्मता का बनाए रखन के लिए जरूरी है। उन्होंने इस मद में ट्रिटन व लाइ सानमन की टिप्पणी का जिक्र किया।

उन्होंने कहा जहां तक इस आरोप का सवाल है कि आयोग का गठन राजनीतिक कारणों से और बन्ने की भावना में किया गया है मुझे यही कहना है कि इसपर विचार करना आयोग का काम नहीं है बल्कि उसका गठन करने वाले प्राधिकरण का है। आयोग स्वयं इस मामले पर विचार नहीं कर सकता।

अबबारा और अन्य प्रचार-साधना के बारे में मैं पहले भी कह चुका हू कि उनपर मेरा नियंत्रण नहीं है तथा मेरा कोई भी निणय इनकी आलोचना से प्रभावित होने वाला नहीं है। जहां तक गृहमंत्रा श्री चरणसिंह के बयान का सवाल है मेरे पास उसका कोई अधिकृत निकाह नहीं है। लेकिन उनके या अबबारा की टिप्पणी से मेरे प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं उसी बात में प्रभावित होऊंगा जो मुझे सही और न्यायोचित लगेगी।

जस्टिस शाह ने स्वीकार किया कि उह राष्ट्रपति द्वारा दश में लागू की गई एमरजेन्सी और समद द्वारा उनके अनुमोदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन इससे साफ हो उनका कहना था कि आयोग को इस बात का अधिकार है कि वह उन परिस्थितियों पर विचार कर जिनके कारण राष्ट्रपति को एमरजेन्सी की घोषणा करनी पड़ी थी।

जस्टिस शाह की व्यवस्था के बाद श्रीमती गांधी और उनके वकीला ने आपस में सनाट की और फिर श्री एथनी ने खड़े होकर जस्टिस शाह से उनमें भुवविबल को निणय व अध्ययन के लिए कुछ

समय देने की प्रार्थना की, जिसे जस्टिस शाह ने स्वीकार करत हुए दूसरे दिन मकर दस बजे तक का समय दिया।

सवाल गोपनीयता का

११ जनवरी १९७८ को सुबह आयोग के कक्ष में एब बाहर आशका का एक दातावरण बना हुआ था कि श्रीमती गांधी अपने सचिव बयान देंगी अथवा नहीं तथा जस्टिस शाह क्या फैसला देंगे। दस बजे में पांच मिनट पहले श्रीमती गांधी अपने वकील पुत्र श्री सत्य गांधी और बड़ी पुत्रवधू श्रीमती मोनिका के साथ कक्ष में आई थी। इस अनिश्चित आज समय से पहले ही आयोग का कमरा राजनीतिक नेताओं भूतपूर्व मंत्रियों आमंत्रित गवाह पत्रकारों और वकीलों से भर गया था। सबकी ब्रह्मानन्द रडडी, ज० बेंगल राव निद्राध शर्मा र राजशहादुर जी० ए० ए० चंद्रकुमार गुजरात सी० मुरझाव्यम और दूसरे चित्तन ही नामी व्यक्ति आयोग की बाय बाही की दखन तथा उनमें से कुछ उमम भाग नेन के लिए पहले ही हाजिर हो गए थे।

ठीक दस बजे जस्टिस शाह ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही श्रीमती गांधी के वकील श्री एघनी में सवाल किया 'कहिए श्री एघनी। क्या स्थिति है?' श्री एघनी जवाब देने के लिए छड़े हुए हो थे कि इतने में ही श्रीमती गांधी भी खड़ी हो गई और उन्होंने माइक्रो फोन के पास आकर जस्टिस शाह के सामने अपना पहना सटाप किया हुआ बयान पत्रा शुरू कर दिया।

सरकारी वकील यह देखते ही बोले "श्रीमान श्रीमती गांधी में कहिए कि वे गवाहों की कुर्सी पर जाकर अपना बयान पढ़ें। नियम उनपर भी बस ही लागू होते हैं जैसे दूसरे पर।' परंतु जब जस्टिस शाह ने श्रीमती गांधी को बयान पढ़ने से नहीं रोकता तो वे यह कहकर बैठ गई 'श्रीमान आप देखेंगे कि वे अपना बयान पढ़ेंगी और चली जाएंगी परंतु आदेश का पालन नहीं होगा।'।

श्रीमती गांधी ने अपने बयान में एमरजेन्सा को लागू करने के विषय को उचित ठहराते हुए कहा कि १९७४ में वर्तमान गृहमंत्री ने उत्तरप्रदेश विधानसभा के उद्घाटन पर चुनावी दावा थी कि यदि मैं सरकार नहीं हूँ तो हम हटा देंगे। भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री व० कामराज के मकान की गोस्ता आंदोलन के ताल पर जनान

का प्रयत्न किया गया। भूतपूर्व रेलमंत्री श्री सलिलसारायण मिश्र की हत्या कर दी गई और दिल्ली में भूतपूर्व मुख्य-यायाधीश श्री ए० एन० र पर हमला किया गया। इन सबके अतिरिक्त पुलिस तथा सना के जवानों से सरकार के आदेशों का मानन का आह्वान किया गया, जो बिलकुल भी उचित नहीं था। कोई भी सरकार इस प्रकार की कार्यवाहियाँ नहीं कर सकती थी तथा हम समझते थे कि इस प्रकार की कार्यवाहियाँ देश को नुकसान होंगी और इसी आधार पर एमरजेंसी लागू करना उचित था। हो सकता है, उनका नियम उचित नहीं रहा हो परन्तु उन्होंने जो कुछ किया जनता के हित में किया।

श्रीमती गांधी ने कहा कि जो भी नियम लिए गए थे सब सम्मति से लिए गए थे। यदि किसी सहयोगी को कुछ आपत्ति थी भी तो उसका उह पता नहीं। यदि उह आपत्ति से अवगत नहीं कराया गया तो उसकी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वे सामूहिक उत्तरदायित्व में विश्वास करती हैं परन्तु आयोग के समक्ष उनका कुछ साक्ष्य नहीं है। हममें बचना चाहता है।

उन्होंने कहा कि बका क राष्ट्रीयकरण के मामले में संविधान सभाधन का सर्वोच्च न्यायालय ने अवधि करार दिया था क्योंकि हमने बका का मुआवजा देना स्वीकार नहीं किया था। जब न्यायालय की बैठक में बैठे सदस्य ही बका के शेयर होल्डर हैं तो किस प्रकार से न्याय की आज्ञा की जा सकती थी? (उल्लेखनीय है कि बका राष्ट्रीयकरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की जिस बैठक द्वारा नियम दिया गया था उसमें जस्टिस शाह भी शामिल थे।)

इसपर जस्टिस शाह ने आपत्ति करने हुए कहा कि वे उसी समय स्पष्ट कर चुके थे कि वे किसी बका के शेयर होल्डर नहीं थे। श्रीमती गांधी ने कहा मैंने आपका नाम नहीं लिया है। जस्टिस शाह जाने परन्तु इशारा भरी ओर ही है। श्रीमती गांधी ने जवाब दिया भला जानिये यह नहीं था और यदि हममें आपकी चोट पहुँचा है तो मुझे इसका खेद है।

श्रीमती गांधी ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि गृह-मंत्री ने अपनी पसंद का आयोग नियुक्त किया है तथा इसका उपयोग उनका विरोध किया जा रहा है।

उनका कहना था कि एक ओर तो आप कहते हैं कि आपका

समाचारपत्रों पर कोई अधिकार नहीं है इसलिए आप उन्हें कुछ भी प्रकाशित करने से रोक नहीं सकते, जबकि दूसरी ओर जाकाशवाणी और दूरदर्शन पर तो पूर्णरूप से रोक का नियन्त्रण है जहाँ से उनका चरित्र हनन किया जा रहा है इसपर तो आप रोक लगा सकते हैं।

श्रीमती गांधी ने कहा 'आप उन परिस्थितियों पर विचार नहीं कर सकते, जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति को एमरजेंसी लागू करने की सलाह दी गई थी। मसद का अपना स्वतंत्र प्रभाव है तथा आप संविधान के अनुच्छेद ७८ (२) के अंतर्गत उसके कार्यों पर विचार नहीं कर सकते।'।

उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा उन्हें जा नाटिस दिया गया है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि उन्हें किन किन आरोपों का उत्तर देना है। जब उसपर कोई आरोप ही नहीं लगाए गए हैं, तब किस प्रकार से उन्हें समझाकर बुलाया गया?

श्रीमती गांधी का ध्यान समाप्त होत ही सरकारी बसील श्री लेखी खड़े हुए और बोलने लगे। तबपर जस्टिस शाह ने कहा 'श्री लेखी! मैं पहले ही एक राजनीतिक भाषण सुन चुका हूँ और दूसरा नहीं सुनना चाहता।' परंतु श्री लेखी बोलते रहे और उन्होंने लगभग आधे घंटे के अपने भाषण में श्रीमती गांधी के बयान का उत्तर दिया।

श्री एथनी और श्री लेखी में एक बार फिर चड़पड़ा गई। श्री एथनी ने एक अवसर पर श्री लेखी के खिलाफ कुछ कहा तो श्री लेखी उबल पड़े और बोले 'श्रीमान श्री एथनी क्या राजनीति की बात करेंगे? मैं जब १५ वर्ष की उम्र में लाहौर के किले में बंदी बना पड़ा था उस जमाने में भी श्री एथनी 'गांडी सेव दि किंग' के तराने गाने में मशगूल थे, और दंग के आजाज होत ही वे संविधान बनाने वाला में शामिल हो गए और अब उसी संविधान में किए गए गणतंत्रसोधनों की परवी कर रहे हैं।'।

श्री लेखी के जवाबी भाषण के बाद वह निर्णायक समय आया, जब जस्टिस शाह इस ढाई दिन की कायवाही का पटाक्षेप करने वाले थे। जस्टिस शाह ने कहा कि श्रीमती गांधी और श्री लेखी दोनों ही की ओर से राजनीतिक भाषण हुए हैं जो इस आयोग के सामने नहीं हान चाहिए थे परंतु अंतिम मुद्दा यह है कि क्या

श्रीमती गांधी मने वन व निणय व अनुमार शपथ लेजर वयान दे रही हैं ?

कुछ क्षणा का रामोशी वृ बाग श्री एथनी ने कहा कि हम यहां याय की आशा नहीं है इसलिए हम आयोग में बिना ल रह है। एनता महंजर श्री एथनी और श्रीमती गांधी जान लग तो जस्टिस शाह ने उन्हें राका और कहा आयाग व साथ महयाग न परन का तो वानूनी परिणाम निक्ता है वह भी मैं आपको बता एना चाहता हूँ। मैं तही चाहता कि आयाग व समग प्रविष्य में कोई और एम प्रकार का समाशा बनाए। यदि आपको वयान नहीं देना था तो आपको एम बार में पढ़ा में ही बता देना चाहिए था। आपन वयान व कारण ही दूर दूर से गयाहा को बुलाना पना है इनमें से आप तो मणिपुर से आए हैं।

जस्टिस शाह ने अपना पमला गुनान से पूछ एक बार फिर श्रीमती गांधी ने पूछा क्या आप आपन वयान दे चुकी हैं इसपर श्रीमती गांधी ने कहा मैं पढ़ने भी कह चुकी हूँ कि मैं संवधानिक जोर वानूनी रूप से वयान देने व लिए बाध्य नहीं हूँ क्योंकि एमग वन की गोपनीयता भंग होन का गुतरा है।

श्रीमती गांधी व इबार करने पर जस्टिस शाह ने अपना पमला लिया कि श्रीमती गांधी द्वारा आयोग के मम में शपथ लेकर वयान देने में इबार करने पर उनने खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा १७६ व अलगत मामला बनता है और व आदेश देने हैं कि उनने खिलाफ न्तिनी की किसी उपयुक्त अदालत में मुकदमा चलाया जाए।

जस्टिस शाह का पमला गुनजर जटा दसवा में स्तघता छा ग" यही श्रीमती गांधी और उनने वकील आपस में सलाह मग घरा करने वने। श्री एथनी ने जस्टिस शाह का ध्यान उनको भज गण जोनिस की जोर दिलाया जिसमें मामला नम्बर ११ में यह गहा लिया था कि श्रीमती गांधी का १२ से २६ जून १९७५ की तित घटनाओं पर अपना वयान देना है। एमपर आयाग की जोर से उन्हें सूचित किया गया कि इस सत्रघ में दोजारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इसक बाद श्रीमती गांधी और उनके वकील आयाग के वन से उठकर चले गए। श्रीमती गांधी व आयाग में चले जाने पर जस्टिस शाह ने उन सभी शूनपूव मतिया और अय

गवाहा का जो श्रीमती गांधी से संबंधित मामला पर अपनी गवाही देने आए थे जान की अनुमति दे दी।

आयोग के निर्देशानुसार दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री पी० के० जन की अदालत में श्रीमती गांधी पर मुरदमा दज किया गया।

श्री एयनी की आपत्ति के अनुसार श्रीमती गांधी को एक बार फिर १६ जनवरी को मामला नम्बर ११ पर विचार करने के लिए बुलाया गया। उस दिन भी श्रीमती गांधी की जोर में एयनी ने वही पहले जसा तर्कों का लम्बा सितसिना शुरू किया और उसका अंत भी उसी प्रकार हुआ। आयोग की ओर से इस मामले में भी श्रीमती गांधी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १७६ के अंतर्गत मुकद्मा चढ़ाने के आदेश दिए और यह मुकद्मा भी श्री जन की अदालत में दायर किया जा चुका है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १७७ के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग या अधिकारी के समक्ष उससे द्वारा चाहे गए अनुसार ब्याज न से इकार कर देता है तो यह एक अपराध है जिसके अंतर्गत उसे छ महीने के कारावास अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दाना ही सजाए भुगतनी पड़ सकती है।

बारी वकीलों की

जायाग की ओर से एक बार फिर श्रीमती गांधी से २५ फरवरी का जायाग के समक्ष उपस्थित होकर सहयोग करने को आमंत्रित किया गया और उसका दिनांक १५ फरवरी तक जायाग के कार्यालय में जवाब देना कहा गया। जायाग के नोटिस के उत्तर में श्रीमती गांधी के वकीला भवथी फक एयनी डी० आर० सेठी और श्री मुशीलकुमार ने जवाब भेजा और उनकी प्रतिनिधिया समाचारपत्रों में प्रकाशनाथ दे दी।

इन वकीलों ने आयोग का यह पत्र स्वयं हस्ताक्षर कर भेजा था। वकीला ने अपने इस पत्र में आयोग द्वारा उन्हें तथा श्रीमती गांधी का २५ तारीख को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के आदेश को गलत और गलतानुनी बताया था। इसके अतिरिक्त पत्र में वही सब तक दोहराए गए थे जो पहले ही कहे जा चुके हैं।

आयोग द्वारा हम पत्र के जवाब में कहा गया कि श्रीमती गांधी की एक्ट में उनके वकीलों द्वारा भेजा गया पत्र आयोग की अवमानना है। आयोग ने वकीलों के बयान को पूर्ण रूप से अनुचित बताया हुआ कहा कि क्या न उनपर अधिनिर्णय की धारा १० (ए) और हमारी उपधारा (२) के अंतर्गत आयोग की मान-हानि का मुकदमा चलाया जाए। हम संबंध में आयोग की आर स डम संबंध में ताना वकीलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।

जस्टिस शाह का कहना था कि जहाँ तक वकीलों द्वारा सरकारी वकील द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का शिष्ट किया गया है उन्होंने (सरकारी वकील) प्रथम चरण की कामवाही में सिर्फ प्रश्न किए हैं जिरह नहीं। वह अवसर पर स्वयं उन्होंने सरकारी वकील या एस प्रश्न पूछने में रोका है जो प्रश्न नहीं बतौर तक लगने दे।

जस्टिस शाह ने कहा कि अब भी समय है जब श्रीमती गांधी २५ फरवरी का आयोग के मामले उपस्थित होकर उन ११ मामलों में अपने बयान देंगे जो उत्तर पूछे गए हैं। जस्टिस शाह का कहना था कि श्रीमती गांधी हम तरह-दार बार इबार कर अपने आपको आयोग की बारबाई में नहीं बचा सकती।

उन्होंने आयोग के वकील श्री बाल खडालावाला के इस सुझाव के प्रति सहमति व्यक्त की कि श्रीमती गांधी द्वारा आयोग के साथ सहयोग करने में द्वार करने पर अब उनकी अनुपस्थिति में उन ६ मामलों में आगे की कामवाही प्रारम्भ की जा सकती है जो सिर्फ उनमें सम्बंधित हैं। वे छ मामलों में प्रचार हैं।

पञ्चम नेशनल बक के अध्यक्ष पत्र पर श्री टी० आर० तुली की नियुक्ति रिजर्व बक के गवर्नर पद पर श्री के० आर० पुरी की नियुक्ति एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडलों कि नियुक्ति में नियमा का पालन न करना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए० एन० अग्रवाल की पदावनति सम्बद्ध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यू० आर० ललित की पुनर्नियुक्ति तथा १२ जून से २६ जून १९७५ के बीच हुई घटनाएँ।

समस्त जिम्मेदारी श्रीमती गांधी की

आयोग के वकील श्री बाल खडालावाला न इन छ मामला में सप्रधित गवाहा द्वारा दिए गए बयानों से निष्कर्ष निकालत हुए कहा कि श्रीमती गांधी के पास इतना समय था कि वह एमरजेन्सी लागू करने से पूर्व अपने मन्त्रिमंडल के सहयोगियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उसपर विचार विमर्श कर सकती थी। परन्तु उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया क्योंकि कुछ भविष्य द्वारा इसका विरोध करने की सम्भावना थी।

श्री खडालावाला का कहना था कि एमरजेन्सी की घोषणा का एकमात्र उद्देश्य श्रीमती गांधी द्वारा अपनी मतांश वश की बचाना था।

उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी ने एमरजेन्सी लागू करने के लिए जिन कारणों का जिक्र किया है, वे गलत हैं तथा किसी भी गवाह ने उनका इस बात का भरोसा नहीं किया है कि उस समय स्थिति असामान्य थी।

श्री खडालावाला ने कहा कि श्रीमती गांधी द्वारा बैंको और 'यापानिया' में अपनी इच्छा के व्यक्तिगत नी नियुक्ति महो दशांती है कि वे उच्च पदों पर अपने विरोधी विचार बाल व्यक्तियों का रखना ही नहीं चाहती थी। उन पदों पर अपने दृष्टिगत व्यक्तियों का नियुक्ति करने के पीछे एक ही भावना थी कि वे उनसे अपने मन मान अनुसार काम करा सकें।

वहीं भी नियुक्ति के समय श्रीमती गांधी ने त्रिभुवन श्री सुब्रह्मण्यम की राय नहीं मानी तथा उच्च 'यापानिया' के 'यापानिया' के मामले में उन्होंने विधिमन्त्री की राय को अनदेखा कर दिया।

इसी तरह उन्होंने इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडियन के निदेशक मनना की नियुक्तियों में भी किया।

वकीलों का भी नम्बर

आयोग द्वारा लिए गए मान हानि के नोटिस के उत्तर में श्रीमती गांधी के तीनों वकील-सचिव श्री फ्रैंक एचनो, श्री० आर०, सेठी और श्री सुशीलकुमार वाट् में २७ मार्च, १९७८ को आयोग के सामने पेश हुए।

बकीला की आर स प्रमिद बेसा श्री अगाव मन १ कहा कि उनक मुवन्निलान जो कुछ किया उनका उद्देश्य विमा भा तरह स आयाग की मान हानि करना नहीं था तथा उन्होंने जो कुछ किया, अपनी मुवन्निलान श्रीमती गांधी व हिता का ध्यान में रखकर किया। श्री मन का कहना था कि उनक मुवन्निलान आयाग को बयान भेजेन व वात ही उस प्रम व लिए जारी किया गा।

गमिस शाह न तीना बकीला व स्पष्टीकरण का स्वीकार करने हुए किया गया गमिस वापस लेने व आदेश दिए।

३ शासक जब गवाह बने

भारतन में सभी बराबर हान हैं शासक भी और जनता भी। जो बल तब शासन करने र उ हैं भी एक दिन अपने कार्यों व लिए जनता व सामन अपनी सफाई दनी पड़ सकती है विमी न साक्षा नहीं था। नकिन ऐसा हुआ और एमरजमी व दौरान अपने लिए गए कार्यों के लिए किस प्रकार स इन शासका का शाह आयोग व समन उपस्थित हाकर अपनी सफाई दनी पड़ी वह भी स्वतंत्र भारत व इतिहास की एक अनायी घटना बन गई है।

आयोग व समन भूतपूर्व व द्रीय मंत्री राया व भूतपूर्व मुख्य-मंत्री तथा उनक सगिया का पश होन व लिए कहा गया था और इनमें न कई आयोग का पूरा सहयोग भी दत रहे। कुछ लोग कुछ दिन जाए लकिन वात में गोन हो गए और कुछ तितपुन ही नहीं आए।

आयोग व समन उपस्थित होन वान भूतपूर्व मंत्री हैं—वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम विधिमंत्री श्री एच० आर० गाखल धाणिज्यमन्त्री श्री डी० पी० चट्टापाध्याय पयटन एव नागरिक उद्घुपनमन्त्री श्री राजबहादुर रक्षामन्त्री श्री जगजीवनराम सूचना और प्रसारणमन्त्री श्री इद्रकुमार गुजराल थम एव आवासमन्त्री रघुरमया गृहमन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रणे भारी उद्योगमन्त्री श्री टी० ए० व गृह राज्यमन्त्री श्री जोम महता बकिंग और राजस्वमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी तथा सूचना और प्रसारणमन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल।

दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद और भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में मध्यप्रदेश के श्री पी० सी० मेठी उत्तरप्रदेश के नारायणदत्त तिवारी, राजस्थान के श्री हरिद्वज जोशी, आंध्रप्रदेश के श्री जे० बेंगनराव वर्मा के श्री देवराज अंस और पश्चिम बंगाल के श्री मिट्ठाथ शर्मा के श्री आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

इनके अनिरीक्षित दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री बहादुरराम दमटा तत्कालीन उप राज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन चावला, दिल्ली विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री जगमोहन और तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनिरीक्षित सचिव श्री राजेन्द्रकुमार धवन को भी आयोग ने बुलाया। श्रीमती गांधी के पुत्र श्री सत्य गांधी और परिवार नियोजन कार्यक्रम में उनकी सहायिनी श्रीमती रघुमाना मुलतान को भी आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया था।

हम तो बस उनके इशारे पर

आयोग के समक्ष मंत्रस पहले गवाह के रूप में पेश होने वाले थे श्री सुब्रह्मण्यम जिन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर श्री क० आर० पुरी की तथा पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री पी० आर० तुली की नियुक्ति में संवर्धन गवाही दी। श्री सुब्रह्मण्यम ने इसकी मारी जिम्मेदारी श्रीमती गांधी पर डालते हुए कहा कि यद्यपि श्री पुरी एवं श्री तुली की नियुक्ति श्रीमती गांधी के निर्देशानुसार की गई थी परन्तु वे स्वयं उसमें सतुष्ट नहीं थे।

विधिमंत्री श्री गोखले को बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यू० आर० ललित की पुनर्नियुक्ति और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए० एन० अग्रवाल की पदोन्नति के मामले में बुलाया गया था। उन्होंने भी उनकी जिम्मेदारी श्रीमती गांधी पर डाल दी। उन्होंने कहा कि वे चाहती थीं कि इन लोगों की सेवाएं आगे जारी न रखी जाए और उसीके अनुसार कार्य किया गया। उन्होंने इस बात में भी इन्कार किया कि एमरजेंसी की घोषणा के संवर्धन विधि मंत्रालय में कोई राय ली गई थी।

पयटन एवं नागरिक उद्वेगनमंत्री श्री राजवहादुर का दो तीन मामलों के लिए बुलाया गया था। पहला मामला था पयटन विकास

निगम के अध्यक्ष पद पर ले० जनरल श्री सतारावाला की नियुक्ति का । उन्होंने इस मामले की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली । दूसरा मामला था इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया व निष्पक्ष मंडला में नियुक्तियाँ का । श्री राजवहादुर का कहना था कि इन मण्डला में था अप्पा स्वामी का नाम श्रीमती गांधी व निर्देशानुसार ही हटाया गया था और उन्होंने ही कुछ अर्थ नाम भी सुझाए थे । इसके अनिश्चित बाइंग विमानों की खरीद व सबंध में भी उनसे पूछ साछ की गई । इस मामले में उनका कहना था कि श्रीमती गांधी के निर्देशानुसार ही इन विमानों की सिस्टम स्टडी नहीं कराई गई थी । इस मामले में श्री क० रघुनमया की भी गवाही हुई क्योंकि उन्होंने श्री राजवहादुर के पद-त्याग के बाद हम मंत्रालय का काम संभाला था ।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर एयर माशेल एच० सी० दीवान की नियुक्ति को उचित बताते हुए उनकी पूरी जिम्मेदारी श्री राजवहादुर ने अपने ऊपर ले ली ।

श्री राजवहादुर ने आयोग के समय उपस्थित होकर अनुरोध किया कि उन्हें कुछ लोगों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है उन उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए । इसपर सरकार की ओर से उन्हें पूरा संरक्षण देने का आश्वासन दिया गया । श्री राजवहादुर के आयोग के समय गवाही देने के लिए उपस्थित होने के समय कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध नारेबाजी की थी ।

रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम और तत्कालीन सूचना और प्रसारणमंत्री तथा इन दिनों सोवियत संघ में भारत का राजदूत श्री इन्द्रकुमार गुजराल का कहना था कि एमरजेन्सी की घोषणा के बारे में उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं थी तथा दूसरे दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मात्र सूचना दी गई थी । बैठक में किमीने अमहमति व्यक्त नहीं की थी जाप चाह तो उस मौन स्वीकृति नले ही मान लें ।

भारी उद्योगमंत्री श्री टी० ए० प तथा वाणिज्यमंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय को कुछ अधिकारियों को तंग करने और गिरफ्तार करने से संबंधित मामला में बुलाया गया था ।

इन दोनों मंत्रियों ने माहति व सबंध में संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के लिए जानकारी एकत्र करने वाले चार अधिकारियों

के विरुद्ध बन्दोबस्त जाच ग्युरा द्वारा की गई कारवाई से संबंधित मामला के बारे में गवाही दी। उनका कहना था कि इन अधिका-रियों के विरुद्ध कारवाई करने के निर्देश श्रीमती गांधी ने दिए थे। वह स्वयं तो इन अधिकारियों की महायत्ना करने चाहते थे, परन्तु उस समय के हालात ही ऐसे थे जिनके कारण कुछ नहीं किया जा सका।

श्री सत्य गांधी की मास से संबंधित एक घम की जाच करने वाले वाणिज्य मन्त्रालय की टक्कराइल कमटी के दम और बस्टम विभाग के दो इम्पबन्टों की मौमा में गिरफ्तारी के संबंध में भी श्री चट्टोपाध्याय को अपनी मफाइ इन के लिए बुलाया गया था। इस मामले में उनका कहना था कि उन्हें स्वयं इन गिरफ्तारियों की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि यह सब कारवाई प्रधानमंत्री निवास से सीधे की गई थी।

श्री ओम मेहता तथा श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी का एमरजेन्सी की घोषणा और उसके बाद की गई नजरबन्दियों और गिरफ्तारियों के संबंध में बुलाया गया था। श्री रेड्डी का कहना था कि उन्हें २५ जून की रात को एमरजेन्सी की घोषणा के बारे में चलन चलत जानकारी नहीं थी और इसपर उन्होंने श्रीमती गांधी से यह कहकर छुट्टी पा ली थी कि 'आप बेहतर जानती हैं कि देश के लिए क्या अच्छा होगा।' जबकि श्री मेहता का कहना था कि उन्हें एमरजेन्सी की घोषणा के बारे में कोई पूरा जानकारी नहीं थी।

भूतपूर्व सूचना तथा प्रसारणमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने जरा अपनी मन्तवगी का परिचय देते हुए उन सभी कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली जो उन्होंने किए थे। उनका कहना था कि उन्होंने जो कुछ किया मंत्री की हैसियत से किया और उचित समयपर ही किया। अब यह अलग बात है कि उन्हें उचित नहीं समझा जा रहा है। उन्होंने कुछ मामला से साफ इकार भी कर दिया। इस संबंध में उनका कहना यही था कि संबंधित गवाह झूठ बात रहा है। उनका तब था कि जो व्यक्ति नौकरी के डर में पहले इस प्रकार के कार्य कर सकता था उसके संबंध में अब क्या शरटी है कि वह यहाँ भी उसी नौकरी के डर से गवाही देने नहीं आए हैं? इस मिलमिले में उन्होंने आकाशवाणी समाचार-सेवा के निदेशक श्री शंकर भट्ट का विशेष रूप से उल्लेख किया।

वैरिंग तथा राजस्वमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी को एक नहीं, बल्कि कई मामला में गवाही के लिए बुलाया गया। श्री मुखर्जी ने आयाग व समग्र कुछ आपत्तियाँ उठाई। उनको एक आपत्ति यह भी थी कि उनको द्वारा गवाही देने से उनको पद की आपसीपता की शपथ भंग हो सकती है जिस जस्टिस शाह ने अस्वीकार कर दिया। उन्हें पञ्जाब नेशनल बैंक व अध्यापन पत्र पर श्री टी० आर० तुली, स्टेट बैंक आफ इंडिया व अध्यापन पद पर श्री टी० आर० धरणाचारी की नियुक्ति तथा जयपुर की राजमाता श्रीमता गायत्रीदेवी और ग्वालिपर की राजमाता श्रीमती विजय राजे सिधिया की भीमा में गिरफ्तारी व संबंध में गवाही देने के लिए बुलाया गया था।

श्री प्रणव मुखर्जी को बाद में जाच आयाग अधिनियम व नियम ५ (०) (ए) तथा धारा ८ (बी) व अनुसार गमन देकर बुलाया गया और शपथ लेकर बयान देने को कहा गया परंतु उन्होंने भी श्रीमती गांधी का रास्ता अस्वीकार करते हुए शपथ लेकर बयान देने में इन्कार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप आयाग ने उनको बिस्फुट भी दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री पी० व० जन की अदालत में दण्ड प्रक्रिया महिना की धारा १७६ के अंतर्गत मुकद्मा दायर कर दिया।

हम तो बस नाम के थे

दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने कई मामला में संबंध में आयाग के समग्र बयान लिए। श्री कृष्णचंद ने एमरजेन्सी की पूर्व संध्या और उसके बाद हुई गिरफ्तारियाँ, अखबारों की निजली काटने व आदेश मिली परिवहन नियम व अध्यापन पत्र पर श्री यू० एस० आवास्तव की नियुक्ति टक्सलाइन इस्पिटल की गिरफ्तारी विश्व युवक केन्द्र पर कब्जा श्री भीमसेन सच्चर तथा मात अर्थ की गिरफ्तारी और दिल्ली में मरानात गिराए जाने में संबंधित मामला में आयोग को मध्योक्त किया।

श्री कृष्णचंद ने इस बयान पर विशेष रूप से जोर दिया कि एमरजेंसी के दौरान बसिफ एक खबर स्टाम्प बनकर रह गई थी। दिल्ली शासन का कायभार तो श्री साय गांधी को सौंप दिया गया था तथा उनको नियंत्रित व वचार या पांच अधिकारी ही सत्र काय कर रहे थे। इन लोगों में उनको निजी सचिव श्री नवीन चावला, उप

महानिरोधक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर, पुलितम अधीनक (मुक्त घर विधायक) श्री बाजवा आदि शामिल थे। उनसे ता सिर्फ उन्ही कार्यों के बारे में पूछा जाता था जहाँ वैधानिक रूप में उनकी ज़रूरत आ पड़ती थी। उनका कहना था कि श्री चावला श्री गांधी के काफी नज़दीक थे और श्री गांधी के सभी निर्देश उनके जरिये आया करते थे।

उन्होंने कहा कि उन्हें एक सूची देकर कहा गया था कि इसमें बताए गए लोगों को गिरफ्तार करना है जिसका उन्होंने पालन किया। अखबारों की विजली भी प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही काटी गई थी। दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पट्ट पर नियुक्ति के संबंध में भी श्रीमती गांधी की अनुमति थी। इसी प्रकार टकमगादल रूस कटरा की गिरफ्तारी घाणक्यपुरी स्थित विश्व युवक केंद्र की इमारत पर कब्जा और श्री भीमसेन मच्छर तथा मात अय की गिरफ्तारिया भी प्रधानमंत्री निवास से मिल निर्देशों के अनुसार की गई थी।

श्री पी० एम० रजसी के दौरान मकानात गिराए जान की घटनाओं के संबंध में श्री कृष्णचंद का कहना था कि ये सब कार्य श्री सत्य गांधी के निर्देशों पर हुए थे। उन्होंने बताया कि एक तरीके से एम० रजसी के दौरान श्री प्रशामन का कार्य भी गांधी बना रहा था। बताया था कि जब उन्हें किमा उच्च पर नियुक्त करने के लिए प्रशिक्षण के रूप में दिल्ली प्रशामन का कार्य सौंपा गया है। उन्होंने आयोग का बताया कि श्री प्रशामन की कार्यपद्धति में यदि एन० जी० (उप राज्यपाल) के स्थान पर एस० जी० (सत्य गांधी) कर दिया जाए, तो सभी बातें स्वतः समय में आ जाएगी।

आभ्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जे० बेंगलराव ने इस बात से इनकार किया कि एम० रजसी में लागू करने से पूर्व मुख्यमंत्रियों से कोई सलाह ली गई थी। लेकिन इसके विपरीत कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवराज अम ने आयोग को बताया कि एम० रजसी की घोषणा के बारे में सूचना उन्हें सबसे पहले स्वयं श्री बेंगलराव ने २५ जून की दोपहर में बंगलूर बुलाकर दी थी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पी० सी० सठो ने बताया कि उन्हें एम० रजसी की घोषणा के बारे में तो नहीं बताया गया था परंतु २५ तारीख की मध्य रात्रि को की जाने वाली गिरफ्तारियों के

सबध म जम्बर कहा गया था। उन्होंने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिद्व जोगी का वामबाइल जाकर ऐसा ही संदेश दिया था।

श्री जोगी को इस मामले में अनिश्चित एवं आई० ए० एम० अधिकारी श्री मन्मथिहारी व निमन्धन व मामले में भी गवाही देने को बुलाया गया था। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री-निवास पर दानत हुए कहा कि श्री धवन ने उन्हें फोन कर ऐसा करने को कहा था।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायणचन्द्र तिवारी ने इस बात से डरकर किया कि उन्होंने आगरा-यात्रा में श्री सत्य गांधी का कोई विषय नहीं किया था। श्री गांधी का युवक व एक दहे वगैरे प्रति निधि के रूप में आगरा बुलाया गया था। उनका कहना था कि श्री गांधी ने वहां कोई आदेश या निर्देश नहीं दिए। उन्होंने तो सिर्फ मुस्ताव लिए थे जिन्हें अच्छा समझा गया और बताया कि किया गया।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थ मुखर्जी का कहना था कि एमरजेन्सी की घोषणा के संबंध में उन्हें तो सिर्फ साहूरा बनाया गया था जबकि समस्त कार्य श्रीमती गांधी द्वारा ही किए गए थे। उन्होंने बताया कि एमरजेन्सी की घोषणा के संबंध में उनसे राय जम्बर ली गई थी परंतु अब व समझत है कि इसमें श्री सत्य गांधी तथा अन्य लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी।

राज सचिवों का

जापान के समस्त राजनीतिक नेताओं व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के भी बयान हुए जिनमें कुछ प्रमुख हैं—श्रीमती गांधी के अतिरिक्त सचिव श्री राजेंद्रकुमार धवन दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन सावना दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री बहादुरराय टमटा और दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जगमोहन।

एमरजेन्सी के दौरान सबसे अधिक चर्चित व्यक्ति थे श्री धवन। एमरजेन्सी में अधिकारिया तथा महिला आदि को श्रीमती गांधी के संदेश श्री धवन के माफन ही जाया करने थे और इसी कारण उनका महत्व बढ़ गया था। जायाग के समस्त देश सभी मामलों में जिनमें प्रधानमंत्री निवास का जिम्मा था श्री धवन का जिम्मा अधिक

था, श्रीमती गांधी का कम ।

श्री धवन न बहुत ही तब-तरीर तरीक स जवाब दिए । अधिक-काश मामलो म उनका यही कहना था कि उन्होंने वही किया, जो श्रीमती गांधी ने उनसे कहा । कुछ मामला म उन्होंने सवधित गवाहो को झूठा ठहराते हुए कहा कि वे लोग उन्हें पमाना चाहत हैं । उनकी नजर म ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसपर समस्त इतजाम थोपा जा सके । इसपर जस्टिस शाह ने कहा, "आखिर म लाग आप ही को क्या फसाना चाहते इससे इन्हें क्या मिलने वाला है ?" श्री धवन न जवाब दिया "श्रीमान् यही वे लोग थे, जो एमरजेसी के दौरान प्रधानमंत्री निवास तक गलत सूचनाएं भिजवाकर अपना उल्लू सीधा करत रहे और अब भी वही कर रहे हैं ।"

एक अवसर पर श्री धवन का कहना था कि मुझे हर मामले म बेकार म घसीटा जा रहा है जबकि वास्तविकता तो यह है कि उन दिनों हालात ऐसे थे, जिसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता था । श्री सत्य गांधी और श्री नवीन चावला के आपसी संबंधों की ओर इशारा करत हुए उन्होंने कहा कि श्री चावला हम चेष्टा म थे कि किसी तरह मुझे हटाकर वे स्वयं इस पद पर पहुंच जाए । वे मेरी उपस्थिति बरनाशत नहीं कर सकते थे । श्री धवन ने कहा कि श्री चावला बहुत ही महत्ववादी व्यक्ति थे । उन्होंने जस्टिस शाह से पूछा, 'श्रीमान क्या आप उन दिनों दिल्ली म थे ?' जस्टिस शाह ने जब इसका जवाब नकारात्मक दिया तो श्री धवन बोले 'तभी श्रीमान आप चावला के शिक्कर होने से बच गए ।'

श्री धवन ने कहा कि यदि उनकी तथा उनके परिवार की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए तो वे बता सकते हैं कि अब भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपना सारा अपराध उनके सिर मढ़कर बचना चाहत हैं । उन्हें इस बात की बराबर धमकी दी जा रही है कि उन्होंने अपना मुंह खाल दिया तो बड़े बुरे परिणाम हाने ।

लेफ्टिनेंट मनाम गवनर

एक अत्यंत बहुचर्चित सचिव थे श्री चावला । श्री धवन की ही तरह दिल्ली के मामला म इनकी चर्चा ज्यादा थी और उनका बास श्री कृष्णचंद की कम । दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री जे० व० कोहली का उनके संबंध म कहना था कि एमरजेसी के

दौरान अधिवारियों को कह दिया गया था कि प्रत्येक मामले में पहले श्री चावला से बात की जाए। बाद में श्री कृष्णचंद से। उनके अनुसार श्री कृष्णचंद तो सिर्फ सेप्टिनेण्ट थे, मगर तो श्री चावला ही थे जबकि श्री चावला का कुछ और ही रहना था। उन्होंने कहा मैंने अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया। उस राज्यपाल ने मुझे जो निर्देश दिए मैंने सिर्फ उनका पालन किया।' उन्होंने यह बात भी इवार किया कि श्री गांधी के साथ उनकी मैत्री के कारण उन्होंने मल्लत बदल उठाए थे।

वही किया जो उन्होंने कहा

दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री बहादुरराम टमटा का भी यही कहना था कि एमरजेंसी के दौरान दिल्ली के मामलों में जैसा उन्होंने करने का कहा गया उन्होंने वसा ही किया, चाहे वह मामला मकानों को गिराए जान का हो या कोई और। मकान गिराए जान की कायदाही सिर्फ श्री मजबूत गांधी के जहम को पूरा करने के लिए थी गई थी। उन्हें धमकी दे दी गई थी कि यदि उनके आदेशों का पालन नहीं किया गया तो उन्हें भीसा में गिरफ्तार किया जा सकता है। नौकरी से हटाने की धमकी तो अक्सर ही दी जाती थी। उनके सामने इन आदेशों को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था।

कुत्तों के भौंकने पर भी रोक

श्री टमटा का कहना था कि उन दिनों इतने घुर हासात थे कि श्री राजय गांधी यह भी पसंद नहीं करते थे कि जब कसबका से गुजरें तो कुत्ता या अन्य जानवर उनके रास्ता बाट दे या उन्हें दिख जाए। और उनकी इच्छा में इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे कि सफरजग इलाके से सभी कुत्तों को हटा दिया जाए।

दिल्ली के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्री भवानीमल माथुर ने भी श्री टमटा के इस बयान की पुष्टि करते हुए कहा कि इस प्रकार के आदेश दिए गए थे कि सफरजग इलाके में तथा उसके आसपास के क्षेत्र में जावारा कुत्ता तथा अन्य जानवरों को पकड़ लिया जाए ताकि वे भौंक नहीं सकें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन आयोग

के सम्मुख यही सिद्ध करने की चेष्टा करते रह कि प्राधिकरण द्वारा जा कुछ किया गया, वह जाता की भलाई के लिए ही किया गया था। चाहे वह काम तुकमान गट इलाके में मकानों को गिराने का रहा हो या फिर अजुन नगर की पूरी बमो-बसाई बस्ती का उखाड़ देना। श्री जगमाहन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए घंटा एक ही बात को दोहराते रह और एक बार तो जस्टिस शाह को भी बन्ना पड़ा कि आप जिस तरह प्रश्न का घुमा फिराकर उत्तर देते हैं, उसमें अच्छा है आप भी उसे ही उत्तर देना स इकार कर दें।

एक जमाने के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति केन्द्रीय जाच-धुरी के निदेशक श्री देवदत्त मन की इस सन्दर्भ में चर्चा के लिए जान में यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। श्री मन के जस्टिस शाह आयोग और सरकारी वकील के संवादा के जवाब देने के तरीके से ऐसा अनुमान लगाना कठिन था कि वे कभी एक ऐसी मन्कमे के प्रमुख रह चुके हैं, जिसका नाम सुनते ही आम आदमी घबरा जाता है। चाहे वह मामला मारुति की जाच कर रह चार अधिकारियों को तग करने का रहा हो या फिर बहोदा रयन के स्तर पर मार गण छापा का। वे प्रत्येक कास के जीविम पर प्रकाश डालते हुए यही बताते रह कि उन्होंने जा कुछ किया सही किया और कानून तथा नियमों के अनुसार किया। वह न तो यह बात मानने को तयार थे कि उन्होंने जा कुछ किया वह सब ऊपर के निर्देशों से किया और न ही फिर यह मानने को तयार थे कि उन्होंने वे कार्य करते समय अपने अधिकारों की भी सीमा लाघ दी थी।

श्री सजय गांधी तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में उनकी सहयोगिनी श्रीमती रत्नसुखाना सुलतान को भी आयोग के समक्ष उपस्थित होकर तुकमान गट इलाके तथा दिल्ली के अल्प-स्तरों में मकानों को गिराए जान का घटनाक्रम पर आयोग के साथ सहयोग देने की बुलाया गया था, पर दोनों ही अपना समयानुसार उपस्थित नहीं हुए।

घाए भी वे और गए भी वे

आयोग द्वारा भेजे गए समन के जवाब में श्री सजय गांधी ने

अप्रैल को आयोग के सामने पेश तो हुए परन्तु उन्होंने वहाँ यह बन्कर सनसनी फला दी कि दो बार तारीखें बदले जाने के बाद तीसरी बार भेजे गए जिस समन का अख्खाग में जिक्र किया गया है वह उन्हें मिला ही नहीं।

जस्टिस शाह ने आयोग के रिवाजों को जांच करने के बाद स्वीकार किया कि ८ अप्रैल को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए भेजा गया समन श्री गांधी को स्वयं अथवा उनके परिवार के किसी व्यक्ति सदस्य के स्थान पर उनके डाइवर को दिया गया था।

श्री गांधी ने समन ठीक से जारी न होने के तक के आधार पर आयोग के सामने कुछ कहने से इन्कार कर दिया तथा माग की कि उन्हें समन दोबारा से जारी किए जाए वे तभी कुछ कहेंगे। जस्टिस शाह ने इसपर उन्हें वही प्रतीक्षा कर समन लेने को कहा ताकि बाट की परेशानियों से बचा जा सके। श्री गांधी लगभग आधे घंटे तक तो इंतजारी करते रहे फिर अचानक यह कहकर उठकर चले गए कि 'मुझे आप कानूनन यहाँ रोक नहीं सकते हैं तथा समन मेरे घर भेजा जा सकता है।' आयोग ने बाद में उसी दिन श्री गांधी को उनके घर पर समन भेजकर २२ अप्रैल को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए। जस्टिस शाह ने यह स्पष्ट किया कि वे श्री गांधी की सुविधा के कारण ही शनिवार का दिन तय करते रहे हैं क्योंकि श्री गांधी जय शिवा एक अत्यंत मुकदमे में (किस्मा कुर्सी का) व्यस्त रहते हैं।

आयोग की ८ अप्रैल की कायदाही के दौरान श्री गांधी के मध्यका द्वारा बार बार ताली बजाने तथा हसी मजाक करने पर जस्टिस शाह को कई बार चेतावनी देनी पड़ी। कायदाही के दौरान कई बार श्री गांधी तथा सरकारी वकील श्री लेखी में तोड़ी तफारें हुई जा कई बार तो व्यक्तिगत छाटावशी तक पहुंच गई। एक बार तो जस्टिस शाह को इसमें हस्तक्षेप कर श्री लेखी को रोकना पड़ा।

श्री गांधी का पहला ८ अप्रैल को और बाद में २२ अप्रैल को दिल्ली की एक फर्म पंडित ब्रदस पर छाप मारे जाने तथा उनके मालिकों को परेशान करने की कारवाई और अधेरिया मांड कापमहेडा गांव तथा करौल बाग क्षेत्र में मकान गिराने की कारवाई से संबंधित मामलों पर बयान देने के लिए बुलाया गया

हंगामे के बीच सफाई

२० अप्रैल का दिन आयाग के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन रहेगा । उस दिन की कायवाही भारी हंगामे के बीच अपने सामान्य समय से (सबरे दस बजे) दस मिनट देर में प्रारम्भ हुई । उसमें पूर्व थी गांधी के समर्थकों और उनके विरोधियों में आयाग के कक्ष में और बाहर जमकर हाथापाई और नारवाजी हुई । आयाग के कक्ष में तो मोना पन्ना की ओर से एक दूधर पर बुनिया फेंकी गई जिससे कुछ खिड़कियाँ और दरवाजा बंशीर भी टूट गए । पुनिस द्वारा प्रश्नकारियों को घसीटकर बाहर निवाला गया और बाद में आयोग के कक्ष में सिर्फ प्रेम बाला की ओर सादी बर्तों में पुनिस बाला को रहने दिया गया । पुनिस द्वारा इस तरह हंगामे के आरोप में आयोग के कक्ष और बाहर में ३३ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद में शाम की यूहा या फिर बेनाबनी देकर रिहा कर दिया गया ।

२२ अप्रैल की रात घटना पर लोकमभा में भी अच्छी-बुराई खर्चा हुई जहाँ सरकारी पक्ष के सदस्यों ने इस घटना की सारी जिम्मेदारी श्री गांधी के समर्थकों पर थोपी वहीं विरोधी पक्ष के सदस्यों का कहना था कि यह सारा काय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कराया गया था, तब ही श्री गांधी का बर्तनाम किया जा सके । कुल मिलाकर सन्त में इस प्रकार की कारवाई की निन्हा ही हुई और सभी सदस्यों का मत था कि इस प्रकार की कारवाई आगे न हो, इस बात के प्रयत्न किए जाए ।

आयोग की २० अप्रैल की पूरी कायवाही का अंतिम निष्पत्ति यही रहा कि श्री गांधी पर शपथ लेकर बयान न देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा १७८ और १७९ के अंतर्गत लिनी के मुख्य मद्रोपोनिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया गया ।

उससे पूर्व श्री गांधी ने शपथ लेकर बयान देने के स्थान पर तीन अलग अलग आपत्तियाँ की जिन्हें जस्टिस शाह न अस्वीकार कर दिया ।

श्री गांधी की पहली आपत्ति यह थी कि आयोग की आज की

कायवाही प्रारम्भ हान से पहले आयोग के कमरे और बाहर उठने समयका के साथ जनता पार्टी के किराये के लोग द्वारा जिन प्रकार ग मारपीट की गई तथा पुलिस वाले उनको प्रोत्साहन दे रहे उनमें से ऐसी मन स्थिति में नहीं हैं कि अपना वयान दे सकें। उन्होंने आयोग की कायवाही स्थगित कराने की मांग की।

श्री गांधी की दूसरी आपत्ति यह थी कि जिस प्रकार स श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा अपनी सफाई में कुछ न कहने पर जायाग द्वारा उनको छूट दी गई थी उसी प्रकार उन्हें भी छूट दी जाए क्योंकि वे भी उसी मुकदमे में (किस्सा कुर्सी का) "यस्त है" को अदालत में चल रहा है। सरकारी वकील श्री सेधी का कहना था कि श्री गांधी की आपत्ति का स्वीकार न किया जाए क्योंकि जहां श्री शुक्ल ने आयोग के प्रत्येक चरण की कायवाही में पूरा सहयोग दिया है वहीं श्री गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि हर स्तर पर आयोग की कायवाही को रोकने का प्रयत्न ही किया है।

श्री गांधी ने अपनी तीसरी आपत्ति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में श्रीमती नन्दिनी सत्यधी के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें भी उसी प्रकार वयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद २० (३) का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी अभियुक्त को उसका स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

जस्टिस शाह ने सभी आपत्तियां रद्द करत हुए कहा कि श्री गांधी और श्रीमती सत्यधी का मामला अलग अलग है। संविधान के अनुच्छेद २० (३) के संदर्भ में उनका कहना था कि उनके सामने कोई भी गवाह अभियुक्त के रूप में पेश नहीं हुआ है और न ही उन्हें किसीको अभियुक्त करार देने का कोई अधिकार ही है। ऐसी स्थिति में किसी भी गवाह के वयान लेने से अनुच्छेद २० (३) का उल्लंघन होने का संवात ही नहीं उठता।

कायवाही के दौरान श्री गांधी की जस्टिस शाह से भी कई बार तकरार हुई और श्री गांधी द्वारा की गई उनसे मन की वार्ता से एक बार तो जस्टिस शाह भी थोड़े से रोप में आ गए। एक अवसर पर श्री गांधी के साथ आए वकील द्वारा ताली बजाने पर जब जस्टिस शाह ने डाटकर उनसे जायोग की प्रतिष्ठा बनाए

रखन को कहा तब श्री गांधी बोले 'आयोग की प्रतिष्ठा ता
में सवर उस समय से देख रहा हूँ जब मर समयका को जनता
पार्टी के किराये के मुँहा द्वारा मारा पीटा गया और पुलिस खड़ी
की खड़ी देखती रही।'

एक अथ अवसर पर जब श्री लखी न श्री गांधी के लिए कुछ
कहा और श्री गांधी न भी सहे हाकर उसका जवाब देना प्रारम्भ
किया, ता जस्टिस शाह न उह टाककर बैठ जाने का कहा। श्री
गांधी इसपर बोले "पहले जाय श्री लेखी को बटाइए उसका बाद
में बठूंगा।" जस्टिस शाह द्वारा तान चार बार चेतावनी दन पर
भी जब श्री गांधी नही बठे तो जस्टिस शाह का कहना पडा,
"आप बठ जाइए, अथवा आपके खिलाफ मान हानि का मुकदमा
चलाया जा सकता है।" श्री गांधी उसका बाद बठ गए।

४ एमरजेन्सी की पृष्ठभूमि नेताश्री की गिरफ्तारिया

१२ जून १९७५ की दापहर को आकाशवाणी के समाचार
बुलटिन में प्रसारित इस समाचार ने सभीको स्तब्ध कर दिया कि
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका
को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया है कि उन्होंने अपने चुनाव
में सरकारी साधना का दुरुपयोग किया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जगमोहन लाल
मिश्रा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के १९७१ में राय-
बरती लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनकर आन के विरोध में श्री राज-
नारायण द्वारा दायर की गई याचिका को स्वीकार करल हुए इनके
चुनाव का अवध घोषित कर दिया। न्यायाधीश श्री मिश्रा ने
श्रीमती गांधी के चुनाव का अवध घोषित करने हुए उच्च न्यायालय
के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में इस निषेध के विरुद्ध अपील करने
की भी अनुमति दे दी।

१२ जून का यही ऐतिहासिक दिन उन वाले दिन की पृष्ठ-
भूमि है जिसके कारण भारत के नागरिकों को १८ महीने तक एक
निरंकुश शासन में जाना पडा। यही वह दिन था जिस दिन में देश में
अपन प्रधानमंत्री के प्रति आस्था प्रकट करने वाला का हाड लगी

उह हटाने के लिए जुलूसों और रलियाँ की बाढ़ आ गई समाए हृद् और न जाने कितने बयान जारी हुए, समथन और विराघ दान' म जोर अंत म २५ जून की मध्य राति को देश म आतरिक एमरजेन्सी की घोषणा कर दी गई । एमरजेन्सी की घोषणा के साथ ही गिरफ्तारियाँ और नजरबन्दियाँ ना एक अटूट सिलसिला भी शुरू हो गया । समाचारपत्रा पर सेंसर लग गया, व्यक्ति की अभि व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन गई । किसीकी मालूम नहीं कि उमे बब किम आराप म जेल के अंदर डाल दिया जाए । सबर घर से निकलने वाले का यह पता नहीं था कि वह ग्राम की धर पर वापस पहुँचगा या जेल म टांगा ।

(1) रलियाँ और प्रदर्शन

१२ जून १९७५ के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निणय के बाद सरकारी स्तर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के समथन म रलियाँ और प्रदर्शनों की आयोजित कर उनके समथन म एक लहर उत्पन्न करने की चेष्टा की गई थी ।

इन रलियाँ और प्रदर्शनों म लोगों के भाग लेने के लिए दिल्ली परिवहन निगम और अन्य सरकारी संगठना की सहायता ली गई । महा तब कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा १७६१ बसों की व्यवस्था की गई जिनके किराये के रूप मे समग्र चार लाख रुपयों का आज तक किसीन भी भुगतान नहीं किया । इन बसों का उपयोग न केवल दिल्ली के ही बल्कि आसपास के राज्या से भी प्रदर्शनकारियों का लाने-ले जाने म किया गया और उसके लिए कोई परमिट भी जारी नहीं किए गए ।

इन रलियाँ म न सिर्फ दिल्ली प्रभावित हुआ ही बल्कि पंजाब हरियाणा उत्तरप्रदेश और राजस्थान सरकारा ने भी बसा और टुका की व्यवस्था की । २० जून को दिल्ली म बोट क्लब पर आयोजित रैली म श्रीमती गांधी के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए आसपास के राज्या से भारी संख्या म प्रदर्शनकारियों को लाया गया । उम दिन दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ४६७ बसों की व्यवस्था की गई जबकि निजी संस्थाओं को आम तौर पर एक दिन के लिए ६५ रता से अधिक लिए जाने का प्रावधान नहीं है ।

माग अधिक थी—वस कम

दिल्ली परिवहन निगम के तत्कालीन यातायात व्यवस्थापक श्री जे० आर० आनन्द का एक ही दिन में इतनी वसा की व्यवस्था के बारे में कहना था कि यह सब 'असामान्य' ज़रूर था परन्तु वह अवसर भी कम असामान्य नहीं था क्योंकि माग बहुत अधिक थी और जनता प्रधानमन्त्री में अपनी अधिक से अधिक आस्था प्रकट करना चाहता थी।

इसी सन्दर्भ में पंजाब तथा हरियाणा के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि श्रीमती गांधी के प्रति समर्थन व्यक्त करने हेतु दिल्ली में आयोजित रलिया में जनता के भाग लेने के लिए सरकारी मशीनरी का खूबकर उपयोग किया गया।

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री मंगल बिहारी ने इस अवसर में बताया कि जयपुर में प्रदर्शनकारियों को लाने के लिए राजस्थान विद्युत मंडल के ५८ ट्रका का उपयोग किया गया था और उनका किराया का सम्भवतः आज तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों ने इस रैली में भाग लिया था, उन्हें तीन दिन का आकस्मिक अवकाश की सुविधा भी गई थी और कारण में कहा गया था कि विद्युत मंडल दूर पर्यटन की बैठक में भाग लेने के लिए कर्मचारी दिल्ली जा रहे हैं तथा ट्रका की भी इसीके लिए माग की गई थी।

धारा १४४ के बावजूद रलिया

दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन चावला ने इस मामले में अपनी मफाई दत्त हुए कहा कि उप राज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की थी कि दहशतिया सहिता की धारा १४४ के लागू रहने के बावजूद श्रीमती गांधी के निवास के बाहर प्रशासन और रलिया आयोजित कराई जाए। उनका कहना था कि रलिया और प्रशासन आयोजित करा के लिए वसा की जा व्यवस्था की जाना थी व सब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के नाम बुक की जाती थीं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक हरियाणा में लागू का लाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की वसा की व्यवस्था करने की बात है तो वे सभी श्री वसीनाम के अनुरोध पर भेजी गई थीं

और इसका लिए श्री बमीलाल न श्री कृष्णचन्द स अनुरोध किया था।

यसे ही नहीं, रेलगाडिया भी

उत्तरप्रदेश में लखनऊ बानपुर और वाराणसी से प्रदशन-कारिया को लाने के लिए सिर्फ बत्ता की ही नहीं बल्कि तीन विशेष रेलगाडियो की भी व्यवस्था की गई थी। ये गाडिया १८ जून को रवाना होकर २० जून को दिल्ली पहुची थी। प्रदशनकारियों की वापसी के लिए भी दो विशेष रेलगाडिया की व्यवस्था की गई थी।

जहा एक ओर श्रीमती गांधी के प्रति समयन व्यक्त करने हेतु प्रदशनकारिया का लाने के लिए विशेष रेलगाडिया तक की व्यवस्था की गई वही श्री जयप्रकाश नारायण को जिन्हें २२ जून को पटना से दिल्ली आना था दिल्ली न जाने देने के लिए विमान पटना हवाई अड्डे पर उतारा ही नहीं गया। यह विमान बलकत्ता पटना दिल्ली की उड़ान पर था। परन्तु पटना नहीं रोके जान के बारे में इसके स्पष्टीकरण में बताया गया कि तत्कालीन गन्वडी के कारण विमान को पटना में रोकने के बजाय सीधा ही बलकत्ता से दिल्ली ले जाना पडा।

(11) एमरजेन्सी की पूर्व-सन्ध्या

२५ जून की मध्यराति को घोषित की गई एमरजेन्सी के लिए प्रमुख कारण यह बताया गया था कि देश में जन जीवन असामान्य हो गया था हिंसा की घटनाएँ बढ़ गई थी और आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही थी। इन सबसे निपटने के लिए ही इसे लागू करना जरूरी हो गया था। एमरजेन्सी की घोषणा न सिर्फ जनता के लिए बल्कि प्रधानमंत्री के कुछ सहयोगियों के अतिरिक्त सभीके लिए आवश्यक जनक खबर थी। उनमें से अधिकांश के लिए तो २५ जून की राति आम राता की तरह हो थी, परन्तु सवेरा आम नहीं था।

भूतपूर्व कबिनेट सचिव श्री बी० डी० पाण्डे का एमरजेन्सी की घोषणा सबसेप्रथम उस समय मालूम पडी जब वे २६ जून को

प्रातः छ बजे १ अक्बर रोड पर मल्लिमडल की बठक में भाग लने गए। इससे पूर्व उन्हें २५ जून की रात्रि तक इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। रात्रि के लगभग साढ़े चार बजे उनके निवास पर प्रधानमंत्री निवास से फोन आया था, जिसमें सवेरे छ बजे की बैठक के बारे में सूचित करते हुए आन को कहा गया था।

श्री पांडे जब प्रातः १, अक्बर रोड पहुंचे तो वहां कुछ मंत्री आ चुके थे और कुछ आ रहे थे। उसी समय एक मंत्री आए (जिनका अब उन्हें नाम याद नहीं है) और उन्होंने पी० टी० आइ० का एक समाचार लिखते हुए बताया कि रात्रि में श्री जय-प्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई तथा कई अन्य विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री पांडे का कहना था कि बठक में एमरजेन्सी की घोषणा के बारे में तथा प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी गई और इसपर वहां बैठे हुए सभी मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की। ये सब सूचनाएं उनके लिए बड़ी आश्चर्यजनक थी।

तत्कालीन गृह-सचिव श्री सुंदरलाल खुराना का कहना था कि एमरजेन्सी लागू किए जाने के बारे में उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं थी तथा गृह-सचिव होने के बावजूद उनमें इनके किसी भी पहलू पर विचार विमर्श नहीं किया गया था और न ही राय ली गई थी। वे इस पर एमरजेन्सी की घोषणा ने दो-तीन दिन पहले ही निपुक्त किए गए थे और इससे पूर्व वे राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। गृह सचिव का पद ग्रहण करने के बाद गृह राज्यमंत्री श्री आम महता ने उनसे १६७१ में घोषित की गई बाहरी एमरजेन्सी की अधिसूचना की एक प्रति देने को कहा था जो उन्होंने संबंधित अधिकारियों में प्रेषित के बाद प्रधानमंत्री निवास पहुंचा दी थी।

दाल में बाला

श्री खुराना ने बताया कि २५ जून की रात्रि को लगभग साढ़े दस या दस बजे किसी के उस राजस्थान में उनसे फोन कर अनि-रिक्त पुत्रिम की मांग की थी क्योंकि उनका अनुमान राजधानी में साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ने का आशंका थी। जब उन्होंने इस बारे

म अतिरिक्त गृह-सचिव को फोन किया तो उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रात्रि को ही लगभग तीन बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनसे फोन कर कुछ गिरफ्तारियां के बारे में स्पष्टीकरण चाहा, परन्तु उन्हें स्वयं इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही इसी प्रकार का फोन चंडीगढ़ में आया। इन सब बातों से उन्हें लगा कि जम्मू स्थान में कहीं बला है। उनके बाद तो उनकी सवेरे अगले सोरा की तरह ही इस बारे में मालूम पड़ा।

श्री खुराना को शिकायत थी कि सरकारी अधिकारियों के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि एमरजेन्सी में पहले और बाद में दोनों समय उनके साथ दुःखवहार हुआ, जबकि उन लोगों ने सिर्फ अपने राजनैतिक बासा के आदेशों का ही पालन किया था।

उनका कहना था कि एमरजेन्सी की समाप्ति के तुरंत बाद समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं ने जो सनसनीखेज सामग्रियां प्रकाशित की हैं उनसे उनके जैसे अनेक अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर फट पड़ा है। उन्होंने इस संबंध में उदाहरण देते हुए बताया है कि एक समाचार पत्रिका में प्रकाशित किया गया कि मुझे राजस्थान में दिल्ली इसलिए भेजा गया, क्योंकि मैं सजय गांधी की समुराल बाला का रिश्तेदार था। रिमांड देखकर मान्य किया जा सकता है कि उनकी सजय के समुराल बालों से क्या रिश्तेदारी रही है। वे दिल्ली आने को विलकुल भी उत्सुक नहीं थे क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव का पद और केन्द्र में किसी मंत्रालय के सचिव का पद एक ही स्तर के हैं और इसके अतिरिक्त दिल्ली आने पर उनकी परेशानी के साथ साथ धन का जो नुकसान उठाना पड़ा वह अलग में।

प्रधानमंत्री सचिवालय में तत्कालीन समुक्त सचिव श्री पी० एन० वल्लभ का कहना था कि २६ जून १९७५ को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे जाकाशवाणी के सम्पर्क में रहने को कहा था ताकि कोई सनसनीखेज समाचार प्रसारित न होने पाए। वे इस निर्देश के बाद दो या तीन दिन तक ही वहां गए थे और बाद में वहां के समाचार निष्प्रेषक को इसी प्रकार के निर्देश दे दिए थे।

श्री बहल ने, जो बाद में नई दिल्ली नगरपालिका के आयुक्त भी बना लिए गए थे, बताया कि एमरजेन्सी की घोषणा के तुरंत बाद नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र के समाचारपत्रों के कार्यालयों की बिजली काटने के लिए दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल ने कहा था। उन्होंने जब प्रधानमंत्री में इसकी पुष्टि की तो जात हुआ कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। इसके बाद नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र के किसी समाचारपत्र की बिजली नहीं काटने दी गई।

चंडीगढ़ के तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री एन० पी० माधुर और उप आयुक्त श्री एच० जी० देवश्याम का कहना था कि उन्हें आदेश दिए गए थे कि ट्रिब्यून समाचारपत्र में किसी भी तरह से बिपक्षी दला के नेताओं की गिरफ्तारी की खबर नहीं छपनी चाहिए और इसके लिए उसके कार्यालय की बिजली काट देने के आदेश दिए गए थे।

हरियाणा के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्री एस० एस० बाजवा ने बताया कि श्री बसीलाल ने जो उस समय बहा के मुख्य-मंत्री थे उन्हें २५ जून की रात्रि को साठे दम ग्यारह के बीच अपने घर बुलाया। जब वे बहा पहुंचे तो उस समय श्री बसीलाल श्री सत्य गांधी से फोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बहा अपने आपको बर्किल समझता है जबकि आता जाता कुछ नहीं है। इसे बाहर निकाल फेंको और पहले विमान से ही बिदा करो।' यह बात श्री मिट्ठाय शर्कर के बारे में कही जा रही थी।

श्री बाजवा का कहना था कि फोन से बातचीत करने के बाद श्री बसीलाल काफी उद्विग्न लग रहे थे। वे कमरे में इधर से उधर घूमने-फूटने कर रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। इसके बाद उन्हें उस रात्रि के गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की एक सूची दी गई।

सामान्य नहीं तो असामान्य भी नहीं

भूतपूर्व केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा आजकल सीनियर सभ में भारत के राजदूत श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने बताया कि एमरजेन्सी लागू किए जाने से पूर्व देश में स्थिति सामान्य तो नहीं कही जा सकती थी परन्तु ऐसी असामान्य भी नहीं थी जिसके

कारण एमरजेसी लागू करना जरूरी था। उन्होंने बताया कि १२ जून से पहले गुजरात और बिहार में आंदोलन हो चुका था तथा बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर श्रीमती गांधी सत्याग्रह की मांग की जा रही थी तथा प्रदर्शन आदि किए जा रहे थे। एक निर्वाचित प्रधानमंत्री ने सत्याग्रह की मांग का लेकर प्रदर्शन आदि करने की स्थिति को सामान्यता नहीं कहा जा सकता परंतु इतना जरूर था कि इन सब बातों से एमरजेसी लागू किए बिना भी निपट जा सकता था और वैसे भी प्रदर्शन आदि तात्कालिक ढाँचे में एक सामान्य बात है। इसपर जस्टिस शाह ने जानना चाहा कि स्थिति यदि सामान्य नहीं थी तो क्या ऐसा कहा जा सकता है स्थिति असामान्य भी नहीं थी? श्री गुजराल ने प्रत्युत्तर दिया कि असामान्य शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता परंतु स्थिति सामान्य नहीं थी ऐसा मैं कह सकता हूँ।

श्री गुजराल ने बताया कि २६ जून को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद श्री मजबूत गांधी ने उनसे कहा था कि रडियो से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिन पहले उद्घोषित किए जाएँ। इसपर उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर श्री गांधी ने उनसे कहा था कि आकाशवाणी द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण सभी चैनलों पर प्रसारित नहीं किया गया है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ठीक तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इसपर उन्होंने श्री गांधी से कहा था कि 'मेरा मंत्रालय मैं क्या हो रहा है यह मेरा मोक्ष की बात है और यदि वह उनसे भविष्य में बात करना चाहें तो शिष्टता एवं नम्रता से बात करें। प्रधानमंत्री और कांग्रेस से मेरा संबंध तब से है जब तुम पंगा भी नहीं हुए थे।

चलते चलते

तत्कालीन गृहमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेडडी का एमरजेसी लागू करने के बारे में कहना था कि एक तरीके से उनसे चलते चलते इस संबंध में राय मांगी गई थी। उन्हें २२ जून की रात को साढ़े दस बजे प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि दश में एमरजेसी लागू करना जरूरी हो गया है। इसपर उन्होंने कहा था कि आप भली प्रकार जानती हैं कि देशहित में क्या अच्छा

है और क्या बुरा उसीन अनुसार निणय ले लें।" इसने बाद वे घर वापस चल गए थे।

मौन स्वीकृति

रभामंत्री श्री जगजीवनराम का कहना था कि २० जून की प्रातः दृढ़ बैठक में सिर्फ एमरजेंसी की घोषणा की सूचना दी गई थी तथा उसपर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ था। इस मामले में मन्त्रिमंडल की स्वीकृति सिर्फ इन्हीं अर्थों में मानी जा सकती है कि किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था, एक तरीके से यह मौन स्वीकृति मानी जा सकती है।

श्री जगजीवनराम ने आयोग को यह भी बताया कि एमरजेंसी के दौरान मन्त्रिमंडल के सदस्य एक के विरुद्ध गुप्तचर विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही थी।

बाद में इन बातों की पुष्टि गुप्तचर विभाग के भूतपूर्व मुखिया श्री जयराम ने भी की कि प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार की रिपोर्ट भेजी गई थी कि कौन कौन सदन सदस्य किम किम नेता के अनुयायी हैं तथा कौन कौन उनका कफादार।

तत्कालीन विधिमंत्री स्वर्गीय एच० आर० गाखल का कहना था कि एमरजेंसी के वार में विधिमन्त्रालय की राय न लेना एक अमान्य बात थी। राय लेना को दूर, उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी गई। बाद में दूसरे दिन मन्त्रिमंडल की बैठक में जानकारी दी गई। वह बात अलग थी।

पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सिद्धाथ शर्मा ने कहा कि उन्हें २१ जून को मवेरे प्रधानमंत्री निवास से फोन कर बुलाया गया था। जब वे वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर बाद श्रीमती गांधी आईं उनका हाथ में कुछ कागज थे। उन्होंने आतशी कहा शुरु कर दिया कि देश में गुजरात की घटना के बाद स्थिति बदतर हो गई है। यद्यपि हम लोग सटिष्णु और शांत रहें हैं लेकिन हमारी सटिष्णुता और धर्म को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। कीमते नियंत्रण से बाहर चली गई है अतः इन सबके लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। इसपर उन्होंने (श्री र. न.) पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा था कि इस प्रकार की स्थिति में तो वर्तमान कानूनों से ही निपटा जा सकता है।

श्री र ने बताया कि जब वे लोग इस मामले पर विचार विमर्श कर ही रहे थे तभी एक व्यक्ति ने श्रीमती गांधी को बागड़ का एक टुकड़ा लाकर दिया। श्रीमती गांधी ने उस बागड़ का पत्र कर बताया कि आज शाम दिल्ली की सावजनिक सभा में श्री जयप्रकाश नारायण एक दो दिन में जन-आंदोलन का आह्वान करेंगे स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने तथा पुलिस और सना को आदेशों का उल्लंघन करने का कहेंगे। श्री रे ने कहा कि सम्भवतः यह रिपोर्ट भी गुप्तचर विभाग से आई थी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद श्रीमती गांधी ने कहा कि सरकार के पास इस प्रकार की कारवाइया में निपटने के लिए कुछ सबटकालीन अधिकार होने चाहिए और एमरजेंसी जैसी कोई घोषणा होनी चाहिए। इसके बाद वे अपने घर चले गए और पूरे मामले पर पुनर्विचार किया। उन्होंने कहा मैं इतना बुरा कहना चाहूंगा कि उन्होंने तथ्या को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया उसमें मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। मैंने इसके पूर्व उन्हें कभी इतना चिन्तित और परेशान नहीं देखा था।

काफी चिन्तन और मनन के बाद वे इस परिणाम पर पहुंचे कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद ३५२ का उपयोग कर देश में आंतरिक एमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। इस अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान है कि यदि आंतरिक उपद्रव का होना निश्चित प्रायः है, तो भी एमरजेंसी लागू की जा सकती है।

श्री रे ने बताया कि इसके बाद मात्र चार या पांच बज पुनः प्रधानमंत्री निवास गए तथा इस बारे में श्रीमती गांधी को अवगत कराया। श्रीमती गांधी इतना सुनते ही बोली आप तुरंत मेरे साथ राष्ट्रपति के यहां चलिए। राष्ट्रपतिजी ने पूरी बात सुनकर कहा 'ठीक है आप फिर अपनी सिफारिश तैयार करिए और मेरे पास भी आएं। श्री रे ने कहा कि उन्होंने श्रीमती गांधी से इस बारे में अंतिम बातचीत की भी विज्ञापन में लेने को कहा था और इस अवसर में कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकात बरआ का नाम विशेष रूप से लिया था। जब वे प्रधानमंत्री निवास वापस पहुंचे और मसविदा तैयार किया तो श्री बरआ भी वही आ गए। श्रीमती गांधी ने उन्हें एमरजेंसी की घोषणा करने के बारे में सूचित किया।

इसके बाद वे तीनों दूसरे दिन आकाशवाणी पर प्रसारित किए जाने वाले संदेश को तैयार करने बैठ गए। उह इस काम में लगभग तीन घंटे का समय लगा क्योंकि बीच-बीच में थी सजय गांधी दर बाजा खटखटाकर अंदर आ जाते थे और अपनी मम्मी का लेकर बाहर चले जाते थे। श्रीमती गांधी दस-पंद्रह मिनट बाद फिर लौट आती थीं। इस बीच उनके कनिष्ठ सचिव भी कमर में आते रहे थे। श्रीमती गांधी बाहर जाकर क्या बातें करती थीं इसकी उह जानकारी नहीं है परन्तु अगले समय में जान लगा है कि 'श्रीमती गांधी समूचे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। सम्भवतः इस बड़े कदम के लिए हम मोहरा बनाया जा रहा था।

श्री रे ने बताया कि तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता ने इसके बाद उन्हें बताया था कि उच्च न्यायालय को दो या तीन दिन के लिए बंद कर देने और समाचारपत्रों के कार्यालयों की बिजली काट देने का फैसला किया जा चुका है। उनके विचार में यह एक बहुत ही बेतुका सुझाव था अतः उन्होंने आधी रात बीत जाने के बावजूद श्रीमती गांधी से मिलने का फैसला किया और उन्हें ऐसा न करने का सुझाव दिया। श्रीमती गांधी ने इस सुझाव को मान लिया था।

श्री रे ने बताया कि २५ जून को सवेर जब वह प्रधानमंत्री-निवास पर श्रीमती गांधी का इंतजार कर रहे थे, तब श्री गांधी बड़े आवेश और गुस्से की हालत में उनसे मिल और बोले 'आप नहीं जानते कि देश को किस तरह चलाया जाता है।

सजय को चाटा मारने की बात गलत

उह ठीक तरह से तो याद नहीं कि उन्होंने इसपर श्री गांधी को क्या जवाब दिया था परन्तु इतना जरूर कहा था कि 'आप अपना काम संभालिए और जा कुछ हो रहा है, उसमें दखल नहीं दीजिए।' श्री रे कहा कि जमाबंदी समाचारपत्रों में छपा था कि उन्होंने इस अवसर पर श्री गांधी को चाटा मार दिया था गलत है। उन्होंने अपना समय नहीं घोसा था।

श्री रे का कहना था कि वे ऐसा नहीं मानते कि किसी कांग्रेस-जन ने श्रीमती गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद त्यागपत्र देने की सलाह दी हो। वास्तव में अनेक कांग्रेस

नेताजी न उनसे अपने पद पर बने रहने का आग्रह करते हुए वक्तव्य जारी किए थे। श्री रेड्मन् बात से भी सहमत नहीं थे कि एमरजेन्सी की घोषणा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रेरित होकर की गई थी।

मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रवासचन्द सेठी ने बताया कि २५ जून १९७५ का जब वे १ सफ्दरजग राड स्थित आयोग का प्रधानमंत्री के बगले पर प्रातः साढ़े नौ और दस बजे के बीच गए तो वहाँ के द्वायमहुराज्यमंत्री श्री ओम महता भी उपस्थित थे। श्री महता ने श्रीमती गांधी की उपस्थिति में उन्हें कुछ निर्देश दत्त हुए २५ जून का मध्यरात्रि को उन लोगों को गिरफ्तार करने को कहा जा प्रतियुद्धित संगठना तथा साम्प्रदायिक संगठना के सदस्य थे या फिर सम्बर थे तथा जिनका रिवाज अच्छा नहीं था। श्री सेठी का कहना था कि उस समय इन गिरफ्तारियों के बारे में उनके दिमाग में यही बात थी कि यह भारत भरवार के आदेश हैं तथा समाज विरोधी तत्वा को गिरफ्तार किए जाना के संबंध में ही यह सब कुछ किया जा रहा होगा।

श्री सेठी ने बताया कि उसी दौरान जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने सम्पर्क करने की चेष्टा की गई परन्तु वह वहाँ नहीं थे तथा अपने पुत्र के विवाह में बासबाड़ा गए हुए थे। बाद में उनसे वायुमना के विशेष विमान से बासबाड़ा जाकर आ जाशी से भी यही संदेश देने को कहा गया। यह दिल्ली में हलबाड़ा और वहाँ से बार द्वारा बासबाड़ा गए जहाँ श्री जाशी को यह संदेश देकर भाषान चले गए।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवराज अम्मा का इस संबंध में कहना था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जे० बंगलराव ने २५ जून के मध्याह्न उन्हें बंगलूर बुलाकर सूचित किया था कि एमरजेन्सी की घोषणा की जा रही है।

मुख्यमंत्रियों से सलाह-मशवरा नहीं

श्री जे० बंगलराव ने इस बात को गलत बताया कि एमरजेन्सी की घोषणा में पहले राज्या के मुख्यमंत्रियों से सलाह-मशवरा किया गया था जस्ताकि श्रीमती गांधी ने एक पत्रिका का लिए इन्टरव्यू में दावा किया था।

राष्ट्रपति की मन स्थिति

एमरजंसी की घोषणा के बाद में स्वर्गीय राष्ट्रपतिजी ने जिस मन स्थिति में हस्ताक्षर किए थे, इसके बारे में बताया है कि उनके सचिव श्री क० बालचंद्रन ने जायाग को बताया कि २५ जून की रात्रि को लगभग सवा ग्यारह बजे राष्ट्रपतिजी ने उन्हें बुलाकर श्रीमती गांधी द्वारा लिखा गया एक अत्यंत गोपनीय पत्र पढ़ने को दिया और उसपर राय मांगी। इस पत्र में श्रीमती गांधी ने अपनी ज्ति की मुद्राकात का जिक्र करते हुए एमरजंसी की घोषणा करने के बारे में लिखा था। पत्र में कहा गया था कि देश में आतंरिक गड़बड़ियाँ से आंतरिक सुरक्षा खतरा में पड़ रही है और यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हों तो संविधान के अनुच्छेद ३५२ (१) के अंतर्गत एमरजंसी की घोषणा कर दें। उन्होंने लिखा था कि घोषणा का मसौदा सन्नद्ध किया जा रहा है, जयंति शांतिवत् में यह सलग्न नहीं था।

श्रीमती गांधी ने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि वे मंत्रिमण्डल के सदस्यों की इस बारे में राय लेना चाहती थीं परन्तु समय की कमी के कारण ऐसा सम्भव नहीं है और मामला इतना जल्दी कि कारवाइ होना चाहिए, इसलिए सरकारी नियमांकी १२वीं धारा के अनुसार वह सीधे ही राष्ट्रपति से प्रार्थना कर रही हैं।

श्री बालचंद्रन ने राय दी थी कि संवैधानिक रूप में यह कार्य उचित नहीं होगा तथा सारी जिम्मेदारी आपपर आएगी। इसपर राष्ट्रपति ने फोन पर प्रधानमंत्री से बात की। इस बीच वे अपने कमरे में चले गए थे। लगभग दस मिनट बाद जय व वापस आए तो पता लगा कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव श्री धवन आए थे और हस्ताक्षर कराकर लौट आए।

राष्ट्रपति के विशेष सहायक श्री अष्टर जालम का कहना था कि राष्ट्रपति ने कभी मानसिक स्थिति में उसपर हस्ताक्षर किए थे इसका पता तो उनकी व्यक्तिगत डायरी से ही लग सकता है जो शायद अब उनके परिवार के सदस्यों के पास है।

(iii) गिरफ्तारिया और नज़रबंदिया

२५ जून की मध्य रात्रि को एमरजन्सी की घोषणा के साथ साथ सम्पूर्ण देश में गिरफ्तारिया का ताता लग गया। इनमें से कुछ गिरफ्तारिया भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत की गई और कुछ बीसा के अंतर्गत।

उस दिन अकेले दिल्ली में ६७ लोगों का गिरफ्तार किया गया, जिनमें सर्वश्री जयप्रकाश नारायण मोरारजी देसाई चरणसिंह चंद्रशेखर रामधन सिक्ंदर बख्त राजनारायण पीलू मोदी और बीजू पटनायक शामिल थे। श्री जयप्रकाश नारायण का जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय रात्रि के ढाई बज रहे थे और वह सो रहे थे तथा अस्वस्थ भी थे।

२५ जून की शाम को दिल्ली की गमलीला मदान में बिपक्षी दला की ओर से एक आम सभा का आयोजन किया गया था जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण सहित कई प्रमुख बिपक्षी नेताओं ने सम्भा धित किया था और यह सब गिरफ्तारिया इस सभा के समाप्त होने के बाद जादी रात के आसपास की गई थी।

इन गिरफ्तारियों के संबंध में दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद का कहना था कि गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की सूची प्रधानमंत्री निवास से उपलब्ध की गई थी। सूची बनाने के काम की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक (सी० आई० डी०—विशेष ब्रांच) श्री के० एस० बाजवा को सौंपी गई थी तथा उसमें श्री जाम महता और श्री घबन ने सहायता की थी। गिरफ्तारिया चाय सम्मत थी अथवा नहीं इसके बारे में उनका कहना था कि उस समय यह सोचन का समय नहीं था क्योंकि प्रधानमंत्री निवास से बार-बार फोन कर इन गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी मांगी जा रही थी।

गिरफ्तारियों की सूची में मंत्री भी

श्री कृष्णचंद ने बताया कि एमरजन्सी की घोषणा से पूर्व ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जान के बारे में सूची तैयार कर ली गई थी परन्तु बाद में उस सूची में कई परिवर्तन हुए। उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक सूची में भूतपूर्व वन्द्रीय मंत्री श्री केशवदेव

मानवीय का भी नाम था परन्तु परिवर्तित सूची में उनका नाम नहीं था ।

हम तो 'ओझार' थे, काम कोई और ले रहा था

उन्होंने स्वीकार किया कि तत्कालीन उप आयुक्त श्री सुशील कुमार ने इन गिरफ्तारियाँ और नजरबंदियों का इस आधार पर विरोध किया था कि वारंटों में गिरफ्तारी के कोई कारण नहीं बताए गए थे । श्री कृष्णचन्द ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने तो आदेशों का पालन भर किया था । "हम तो सिर्फ 'ओझार' मान थे काम तो उन्हें कोई और ले रहा था । उनके अतिरिक्त श्री सुशीलकुमार के सामने भी इन आदेशों को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था ।

निल्दा के उप आयुक्त जीर जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशीलकुमार ने बताया कि २५ जून की रात्रि को उन्होंने अपना दफ्तर खुलवाया और लगभग २०० वारंट तयार करने के काम में मदद करने के लिए ए० डी० एम० वगैरह की सहायता ली । इस बीच उप राज्यपाल और प्रधानमंत्री निवास से बराबर फोन आते रहे और उस वारे में शीघ्रता करने को कहा जाता रहा । उनपर इतना अधिक दबाव पड़ रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री निवास पर जाकर यह बताने का निश्चय किया कि भीमा में गिरफ्तारी का यह तरीका गलत होगा और सही तरीका अपनाना होगा । परन्तु श्री धवन ने उनमें बहुत ही घमकी भर अन्तर्ज में यह काम करने को कहा । उनके बात करने के तरीके से साफ लग रहा था कि यदि उन्होंने कुछ और अधिक कहा तो स्वयं खतरे में पड़ जायेंगे ।

खाली वारंटों पर हस्ताक्षर

उन्होंने बताया कि चूंकि २०० वारंटों को इतनी शीघ्रता में टाइप नहीं कराया जा सकता था और फिर सभीकी चार-पांच प्रतिलिपियाँ भी करनी पड़ती थीं इसलिए अस्थायी तौर पर वारंट फॉर्मों को साइकिलोस्टाइल कराने का निश्चय किया गया । उन्होंने स्वीकार किया कि शीघ्रता के कारण उन्होंने कुछ वारंटों पर खाली हस्ताक्षर भी किए थे ।

निल्ली के अतिरिक्त उस रात्रि की हरियाणा में ५० लोगों को

नज़रबन्द किया गया। आध्रप्रदेश में २६ तारीख की शाम तक २६ व्यक्तिगता का नज़रबन्द किया जा चुका था। बर्नाटिक में बगलौर में, २६ जून को ही सब्जी लातृष्ण आन्वानी अन्तर्विहारी वात्र पयो श्यामनदन मिश्र और श्री मधु दडवत सहित कई नताआ को गिरफ्तार किया गया।

इन गिरफ्तारिया के सबध में विभिन्न राज्या के उच्चवाधिका रिया का कहना था कि उहाने गिरफ्तारिया सबधित मुन्यमत्रिया ने आन्वानी से की थी। उहाने भी यही वान दोहराई कि यह सब कुछ इतना जल्दी करना था कि उम समय यह सोचन का समय भी नहीं था कि यह पायसम्मत है अथवा नहीं।

गृह मंत्रालय का इन गिरफ्तारिया के सबध में क्या हक था उसका पता २६ जून को सभी राज्यों के मुख्य सचिवा को भेजे गए वायरलेस संदेश में दिए गए निर्देश से लगता है। संदेश में कहा गया था कि आज सबेर घोषित की गई एमरजेंसी को देखते हुए एहतियात तथा अत्यवस्था के रूप में सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी प्रभावशाली और सक्रिय पायकर्ताओं को नज़रबन्द/गिरफ्तार कर लें।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न निर्देशों के अंतर्गत २४ जून से ३ जुलाई के बीच कुल ८८१२ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से १२७३ लोगों को भीसा के अंतर्गत नज़रबन्द किया गया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ३ जुलाई १९७५ का एक गिरफ्तारिया के सबध में अपनी नमनीयता दिखाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक अत्यंत गोपनीय पत्र में दिशानिर्देश देते हुए लिखा था कि—

हमने अभी हाल ही में भीसा अधिनियम में संशोधन किया था उससे अनुसार राज्य सरकारों का बिना कारण बताए लोगों को गिरफ्तार करने का बहुत बड़ा अधिकार मिला है। यहां तक कि ऐसे मामलों को सत्ताहत्तर मंडल तक का भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अधिकार का उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक और बड़ी सावधानी में करेंगे। संशोधित किए गए अधिनियम के अंतर्गत यह आवश्यक है कि यदि नज़रबंदी का आदेश

किसी अन्य अधिकारी न दिया है ता राज्य सरकार को पंद्रह दिन में उसकी पुष्टि कर देनी चाहिए। इस बात का देखत हुए यह आवश्यक है कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी इस प्रकार के आदेशों की स्वीकृति दे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग स्वयं इन मामलों को देखें और ऐसे सभी आदेशों में आपकी द्वारा स्वीकृत हो अथवा फिर आपके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी से।

यह भी देख लिया जाए कि किसी भी प्रकार से इस मशायित अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जाए। यह जरूरी है कि इस अधिनियम में मिली शक्ति का उपयोग सिर्फ एमरजेन्सी में उत्पन्न हुए हालातों से निपटने में ही किया जाए।

एमरजेन्सी के दौरान देश भर में मौसा के अंतर्गत कुल ३६ - ०२६ व्यक्तियों का गिरफ्तार किया गया, जिनमें से ६,२४४ का मौसा की सामान्य धारा में और शेष २८,७६५ का मौसा की धारा १६ (ए) के अंतर्गत। इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है।

सबसे अधिक गिरफ्तारियाँ उत्तरप्रदेश में हुई जहाँ ७,०४६ लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरा नम्बर मध्यप्रदेश का था जहाँ ६,२१२ लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे कम गिरफ्तारियाँ सिक्किम में हुई। इस राज्य में सिर्फ चार व्यक्तियों का ही गिरफ्तार किया गया था। अरुणाचलप्रदेश लक्ष द्वीप तथा दार्जिली और नागपुर हवेली में एक भी व्यक्ति का एमरजेन्सी के दौरान मौसा के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया। इस दौरान दिल्ली में १,०११ लोगों को मौसा में गिरफ्तार किया गया।

एमरजेन्सी के दौरान देश भर में मौसा के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए लोगों की थोड़ेवार सख्या इस प्रकार है

राज्य/विदेश/प्रदेश जिसके अन्तर्गत से गिरफ्तारी की गई	मौसा की सामान्य धारा में गिरफ्तारी	मौसा की धारा १६ (ए) में गिरफ्तारी	कुल
१. आंध्रप्रदेश	२६	१०५२	१०७८
२. असम	१६०	३८३	५४३
३. बिहार	—	२३६०	२३६०
४. गुजरात	२७	१८०१	१८२८
५. हरियाणा	—	२००	२००

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश जिसके अन्तर्गत से निरपराधी की गई	बीसा की सामान्य घारा में निरपराधी	बीसा की घारा १६ (ए) में निरपराधी	कुल
६ हिमाचल प्रदेश	—	३४	३४
७ जम्मू तथा कश्मीर	१३८	३६७	५०५
८ नागालैण्ड	—	४८३	४८३
९ केरल	—	७८६	७८६
१० मध्य प्रदेश	३६३	५८१६	६१७९
११ महाराष्ट्र	—	५४७५	५४७५
१२ मनीपुर	१८	१३७	१५५
१३ मेघालय	—	३६	३६
१४ नागालैण्ड	६६	३४	१००
१५ उड़ीसा	—	४५३	४५३
१६ पंजाब	३२१	६०	३८१
१७ राजस्थान	—	५४२	५४२
१८ सिक्किम	—	४	४
१९ तमिलनाडु	—	१०२७	१०२७
२० त्रिपुरा	—	७७	७७
२१ उत्तर प्रदेश	३८	७०११	७०४९
२२ पश्चिम बंगाल	४००६	३११	४३१७
२३ अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
२४ अण्डमान निकोबार	१	४१	४२
२५ चण्डीगढ़	—	२७	२७
२६ दादरा नागर हवेली	—	—	—
२७ दिल्ली	—	१०११	१०११
२८ गाँजा दमन और दीव	—	११०	११०
२९ लक्षद्वीप	—	—	—
३० मिजोरम	१४	५६	७०
३१ पाण्डिचेरी	—	५४	५४
३२ केन्द्र सरकार	—	६	६
कुल	६२४४	२६७६५	३२००९

५ एमरजेन्सी में कर्तव्य और शिकायते बनाम गिरफ्तारिया और निलम्बन

क्या एक सामान्य देश में कृत-अपराधिता के लिए भी लोगो को जेल भेजा जा सकता है? यकीनन इसका जवाब है 'नहीं'। परंतु एमरजेन्सी में ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों का जेल में ठूस दिया गया जिन्होंने एक सरकारी अधिकारी के नाते या फिर इस देश के नागरिक के नाते अपराध कृत्यों का पातन किया। जेल में ठूस जाने वाले ऐसे सरकारी अधिकारियों में वे लोग शामिल थे, जिन्होंने कुछ गलत काम करने से इन्कार कर दिए थे, और नागरिकों में ऐसे लोग थे, जिन्होंने किसी गलत काम की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। इन सब गिरफ्तारियों और नजरबन्दियों के पीछे जो एकमात्र कारण नजर आया, वह था राजनीतिक।

इसी सन्दर्भ में जायाग के समक्ष कुछ मामले पेश हुए। एक मामले में श्री सत्य गांधी की फर्म मार्घत के सबंध में ससंद में पूछे गए प्रश्नों की जानकारी एवम् करने वाले चार अधिकारियों का निलम्बित कर दिया गया। इसी प्रकार के एक अन्य मामले में श्री सत्य गांधी की भाग में मयघित एक फर्म की जांच करने वाले टकमटाइन नगरी के दम और रस्टम विभाग के दो इस्पेक्टरों को भी जेल में डाल दिया गया। कुछ गलत काम करने से इन्कार कर देने की हिम्मत दिखाने वाले राजस्थान के डर के एक आई० ए० एस० अधिकारी का निलम्बित कर दिया गया।

इन सब मामलों के अनिश्चित एक मामले में एमरजेन्सी की आलोचना करने पर एक नहीं मान करिष्ठ राजनीतिज्ञों को भीसा मवाद कर दिया गया। इनमें से एक था—८० वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी श्री भीमसेन मच्चर (जिनका जनवरी, १९७८ में निधन हुआ)।

सरकारी अधिकारियों और अन्य नागरिकों के साथ-साथ राजनीतिक पूर्वाग्रह के नाम पर दो भूतपूर्व रजवाडों की राज-माताओं तथा पत्रकारों और छात्रों को भी जेल में हवा खिलाई

(1) मारुति की जाच की हिमाकत का फल

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र श्री सचय गांधी की बहुचर्चित फम मारुति लिमिटेड के मरघ म ममद म पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर १६ अप्रैल १९७५ को दिया जाना था । यह प्रश्न मारुति द्वारा कुछ आयातित मशीनें प्राप्त करने के बारे में था । साइमंस की शर्तों के अनुसार उस मशीनें आयात करने की अनुमति नहीं थी ।

सूचना एकत्र कराने के सिनमिल में भारी उद्योग मन्त्रालय में उप-सचिव श्री आर० कृष्णास्वामी तन्नीवी विराम मन्त्रालयालय के विवास अधिकारी श्री ए० एस० राजन प्रोडक्ट एंड प्रिविपमट कार्पोरेशन के मुख्य मार्केटिंग मनेजर श्री एल० आर० वाहन तथा उप मार्केटिंग मनेजर श्री पी० एम० भटनागर ने मारुति लिमिटेड और उस मशीनें सप्लाई करने वाली फम वायली आई कम्पनी में सम्पर्क किया था । बाद में इनपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जाच के नाम पर इन फर्मों को तग करने की कारवाई की थी । इससे परिणामस्वरूप इन चारों अधिकारियों के घरो पर तलाशी ली गई और वाहन में उन्हें नौकरी से भी निलम्बित कर दिया गया । इनमें से एक अधिकारी ने तो बाद में नौकरी से ही त्यागपत्र दे दिया ।

भारी उद्योग मन्त्रालय में भूतपूर्व मंत्री श्री टी० ए० प का इस मरघ में कहना था कि श्रीमती गांधी ने उन्हें अप्रैल १९७५ के किसी समय प्रधानमंत्री विराम बुलाकर नाराजगी प्रकट करत हुए कहा था कि कुछ अधिकारियों ने अपने निजी वार्तालाप में राजनीतिक भ्रष्टाचार पर बातचीत की है । श्रीमती गांधी का यह भी कहना था कि ये अधिकारी स्वयं भ्रष्ट हैं तथा फर्मों को जाच के नाम पर तग करत रहत हैं । श्रीमती गांधी ने उनसे बातचीत के तुरन्त पश्चात अपना अतिरिक्त निजी सचिव श्री राजेन्द्र कुमार घवन को बुलाकर केन्द्रीय जाच युरो के निदेशक श्री दत्त सन से इन चारों अधिकारियों के विरुद्ध मामला दज कर उनसे निवासा की तलाशी लेने के आदेश देने का कहा ।

वाणिज्य मंत्रालय में तत्कालीन मंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने बताया कि श्रीमती गांधी न उन्हें १५ अप्रैल १९७५ की शाम को अपने निवास पर बुलाकर कहा कि श्री वात्से के खिलाफ काफी गम्भीर शिकायतें आई हैं इसलिए उन्हें तत्काल निलम्बित कर पूरी जांच कराई जाए। श्रीमती गांधी ने श्री भटनागर के सबध में आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ फर्मों को तग किया है। श्री चट्टोपाध्याय का कहना था कि श्रीमती गांधी ने इस तरह की बातें उनमें पत्नी वार नहीं थी इसलिए वे इसकी गम्भीरता से संतुष्ट हो गए। वे नहीं समझते थे कि श्रीमती गांधी ने बिना कुछ माचे समझे पता लगाए ही यह निष्पत्ति लिया होगा।

श्री चट्टोपाध्याय का कहना था कि इस प्रकार की अफवाह उनके विभाग में सुनने में आई थी कि कुछ अधिकारी फर्मों के साथ ठीक तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस सबध में मिक अनुशासनात्मक कारवाई के आदेश दिए थे। केंद्रीय जाच ब्यूरो से किसी तरह की कोई जांच कराने की नहीं सोची थी और न ही इस विषय में उन्हें कोई जानकारी थी कि इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है। उन्हें यह बात तो बाद में मालूम पड़ी कि ऐसी जांच हो रही है।

चार अधिकारियों में से एक श्री कृष्णास्वामी के अनुसार उन्होंने कभी किसी पार्टी को तग करने जैसी कोई कारवाई नहीं की थी न तो उन्होंने कभी मारुति फक्ट्री ही देखी थी और न ही इस सबध में कभी किसीसे बातचीत की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने समद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जानकारी एकत्र करन का काम तो शुरू कर लिया था परन्तु यह मालूम हात ही कि यह एक नाबुर मामला है इसके बारे में अपने मयुक्त सचिव का सूचन कर लिया था।

श्री कृष्णास्वामी का कहना था कि केंद्रीय जाच ब्यूरो द्वारा उन पर तथा नार्थानय पर ५ मई १९७५ को छापा मारा गया। छापा मार जान के बाद उन्हें काफी परेशान किया गया और २ अगस्त को उन्हें चार महान की छुट्टी पर भेज दिया गया तथा कहा गया कि वे आग भी आधे वेतन पर अपनी छुट्टियां बटाते रहें।

एन सर्वे वाता न अतिरिक्त जाच ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध एवमाइड अधिनियम के अंतर्गत मामला दज किया गया, जिस बाद

मे 'यायालय न समाप्त भी कर दिया। उनके ७० वर्षीय पिता का तय किया गया और उनकी पत्नी के खिलाफ विदेशी मुद्रा के उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया गया। इतनी परेशानियों से जूझने के बाद व सिर्फ इतना करा सके कि उन्हें वापस उनके पुराने विभाग रेलवे में भेज दिया गया।

एक अन्य अधिकारी श्री कान्हे ने बताया कि वे १५ अप्रैल १९७५ का एक दिन के आक्स्मिथ अवकाश पर थे, जबकि तत्कालीन वाणिज्यमंत्री व विशेष सचिव श्री एन० के० सिंह ने उनमें फोन पर मारुति की जांच के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने श्री सिंह को बताया था कि श्री भटनागर उनके निर्देश पर जांच कर रहे हैं। जब व दूसरे दिन कार्यालय गए तो उन्हें मद्रास स्थानांतरण का आदेश मिला। अपने अध्यक्ष श्री विनोद पारीख से उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने सलाह दी कि इस समय उचित यही है कि इस मान लो, अथवा आगे और भी गड़बड़ हो सकती है।

श्री कान्हे का कहना था कि उन्होंने मद्रास जाने के स्थान पर कार्यालय से लम्बी छुट्टी ले ली परंतु वे मई को ही उनमें मकान की तलाशी ली गई। उन्होंने जब इस मामले में अपने उच्चाधिकारियों से हस्तक्षेप करने को कहा तो श्री पारीख ने उन्हें सलाह दी कि 'बेहतर यही है कि तुम किसी और जगह काम तलाश कर लो। तुम्हें काम ढूँढने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा अनुभव और योग्यता है।' श्री पारीख के सुझाव पर उन्होंने १५ जून को अपने पत्र में त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद से आज तक उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। इस बीच उन्हें एक निजी संस्था में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काय भी मिल रहा था परंतु ज्यादातर फर्म को यह मालूम पड़ा कि वे भी सचिव के सताए हुए हैं। उन्हें इकार कर दिया गया। परेशान न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पत्नी को भी किया गया। उनकी पत्नी को जो एक विनायक एजेंसी में काय करती थी, नौकरी से हटा दिया गया। उनकी जावन बीमा की एक पॉलिसी समाप्त हो गई थी परंतु उस लिए नवीनीकृत नहीं किया गया क्योंकि जांच ब्यूरो ने फोन कर ऐसा करने से मना कर लिया था।

इतने घबके खाने के बाद जब उन्होंने पुन प्राजक् एण्ड

इविषयमें म आना चाहता तो यह कहकर इकार कर दिए गए कि उनका मामला जाच आयोग के विचाराय है इसलिए यह सम्भव नहीं है।

जाच रोकने के लिए घवन ने फोन किया

श्री भटनागर और श्री राजन न बताया कि श्री घवन न उन्हें फोन कर कहा था कि वे मारुति व सवध म जाच न करें। श्री भटनागर को ता सोलह महीने तक निलम्बित रखा गया और जब श्री राजन जाच ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध की जा रही जाच के सवध म श्री मजय गांधी से मिलन गए तो उन्होंने कहा कि 'व मारुति व सवध म जानकारी एक्स क्या कर रहे हैं ?'

आयोग म जिरह के दौरान श्री घवन व वकील श्री के० जो० भगत ने दोनों अधिकारिया से जानना चाहता था कि क्या फोन वाशई म श्री घवन ने ही किया था ? वहीं एसा तो नहीं कि किसी और ने श्री घवन के नाम से फोन कर दिया हो। उनका यह भी कहना था कि जब श्री घवन इन दोनों अधिकारिया का जानन तक नहीं थे, उहे फोन करने की क्या आवश्यकता पड गई थी ? इसपर अधिकारिया का कहना था कि यदि श्री घवन ने उन्हें फोन नहीं किया होता तो व श्री घवन का नाम क्या लेत ? परंतु इसके साथ ही इन दोनों अधिकारिया ने स्वीकार किया कि म तो श्री घवन हमने पहले कभी उनम मिले थे और न ही हमने याद ही उनकी कभी बात हुई थी।

श्री भटनागर ने आयोग के वकील श्री काल खडालावाला व एव प्रश्न व उत्तर म बताया कि उनकी बीस वष की मवा म आज तक किसीने यह शिकायत नहीं की कि उन्होंने किसीको तग किया है। परन्तु जब श्री भगत ने उनसे जानना चाहता कि क्या उनका विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कारवाई की गई थी तो श्री भटनागर ने कहा कि हा, एक बार उह चेतावनी दी गई थी।

श्री राजन न भी श्री खडालावाला और श्री भगत के प्रश्न के उत्तर म बताया कि उनमें आज तक कभी यह शिकायत नहीं की गई कि उन्होंने किसीको तग किया है। उन्होंने श्री भगत के प्रश्न व उत्तर म स्वीकार किया उन्हें २५ वष पूव घोषाघटी में दण्डित गया था, जिसके कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया था।

जस्टिस शाह तथा श्री भगत न श्री राजन से जानना चाहता कि उहान किस तरह यह पहचान लिया कि फोन करने वाले श्री धवन ही हैं ? इसपर श्री राजन ने कहा 'बोलने वाले न कहा था कि मैं प्रधानमंत्री निवास में आर० के० धवन बोल रहा हूँ।' इस पर श्री धवन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, 'यह गलत है। मैं हमेशा फोन पर कहता हूँ—मैं पी० एम० हा उस में धवन बोल रहा हूँ न कि आर० के० धवन।'।

मैंने फोन नहीं किया

श्री धवन न जिरह के दौरान इससे साफ इफार किया कि उहान कभी भी श्री राजन अथवा श्री भटनागर का फोन कर कोई निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति ने उनके नाम से फोन कर दिया हो। उहाने कहा कि जब व उनसे पहले कभी मिले ही नहीं थे और न ही उन्हें जानने थे तब वे किस प्रकार से उन्हें फोन कर कोई निर्देश दे सकते थे ? इसपर जस्टिस शाह न कहा 'फिर इन लोगों को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है जो उहाने आपसे विरुद्ध वयान दिया ?' श्री धवन ने कहा

इस बार मैं क्या कह सकता हूँ। श्री खडालावाला के एक प्रश्न में उत्तर में श्री धवन न कहा कि हो, सकता है उनके नाम से आटलीआई वाला न ही फोन कर दिया हो ताकि उनके विरुद्ध हो रही जांच रुक जाए परंतु यह सिर्फ उनका खयाल ही है जरूरी नहीं कि यह बात सही ही हो।

श्री धवन का कहना था कि इन जस वरिष्ठ अधिकारियों से यह तो अपेक्षा की ही जाती थी कि वे इन निर्देशों के बारे में प्रधानमंत्री निवास फोन कर कम से कम इसकी पुष्टि तो कर लें। उहोंने बताया कि सामान्यतः इस प्रकार के निर्देशों की इसी तरह पुष्टि की जाती थी।

श्री धवन द्वारा इस प्रकार के मामले को बहुत ही मामूली मामला की सजा देना पर श्री खडालावाला ने पूछा 'यदि यह मामला इतना ही मामूली था तो प्रधानमंत्री को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि उहाने अपने निवास पर श्री प तथा श्री चट्टोपाध्याय को बुलाया ?' इसपर श्री धवन यही कह सके कि 'प्रधानमंत्री ने क्या साचकर इन्हें बुलाया था इस बारे में मैं क्या

वह मक्ता है। उन्होंने कहा कि यह कहना मत है कि प्रधान मंत्री न श्री प की उपस्थिति में उन्हें श्री सन के लिए कोई निर्देश दिए थे, जसाकि श्री प द्वारा अपने वयान में कहा गया है। दूसरी ही बात

श्री धवन ने इस अवधि में एक दूसरी ही बात बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि कुछ ममद सदस्या तथा अन्य लोग न इन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की हैं आप इनके वायकलापों की जांच कराइए। उन्होंने बाद में जांच पूरी के निर्देश श्री दत्त सन को इन शिकायतों से अवगत करा दिया था, इसके बाद क्या हुआ उन्हें मालूम नहीं।

सिफ सदेशवाहक

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री धवन ने बताया कि उनका काम सिर्फ लोगों तक प्रधानमंत्री के सदेश पहुंचाने का था। एक तरीके से वे सिर्फ एक 'सदेशवाहक' थे।

श्री धवन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सिर्फ इन लोगों के जातिपूचक उपनाम बताए थे और उन्होंने श्री सन से यही नाम बताए थे (राजन भटनागर, कृष्णास्वामी कावै) पूर नहीं। उन्होंने इस बात में भी इकार दिया कि उन्होंने श्री सन को इन लोगों के विभाग या पद भी बताए थे। इसलिए श्री खड्गनावाला ने कहा, आपने प्रधानमंत्री से इन लोगों के पूर नाम जानने की चेष्टा क्या नहीं की?"

श्री धवन बात 'वे मेरी बात थी मैं उनसे ऐसा करने को कैसे कह सकता था। क्या आपका संबंध आपसे ऐसी कोई बात पूछ सकता है जो उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं है?'

श्री धवन ने इस उत्तर पर श्री खड्गनावाला मुस्कराए बिना नहीं रह सके।

सचिव श्री खड्गनावाला फिर भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, उन्होंने पूछा जब आपने श्री सन से इन अधिकारियों के वायकलापों की जांच के लिए कहा, तो उन्होंने किस समय लिया कि वे लोग अपनी आय से वही अधिक अच्छी तरह रह रहे हैं और घट रहे हैं? इसलिए श्री धवन ने एक बार फिर उसी चतुरता से जवाब देते हुए कहा, वायकलापों के बारे में अनन्त-अनन्त

क्षेत्र का व्यक्ति अलग अलग अथ लगाएगा, साधारणतया पुलिस और सी० बी० आर्द० वाल इसका यही एक अथ लगात है ।'

श्री सेन ने आयाग को बताया कि श्री घवन के निर्देशानुसार ही उन्होंने इन अधिकारियों के विरुद्ध जाच कराई थी । उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बिना जाच-पड़ताल के ही उनकी बातों पर विश्वास करते हुए मौखिक रूप से उप महानिरीक्षक श्री यागत्र राजपाल से जाच कराने को कहा था ।

श्री राजपाल का कहना था कि श्री सन ने उन्हें १५ अप्रैल को अपने कमरे में बुलाकर श्री कृष्णास्वामी के विरुद्ध इस आधार पर जाच कराने का कहा था कि वह एक भ्रष्ट अधिकारी हैं । साम का उनसे श्री भटनागर और श्री राजन के बारे में भी जाच कराने का कहा गया । उन्होंने प्राप्त सूचना के आधार पर श्री सन को बताया था कि श्री कृष्णास्वामी अच्छी प्रतिष्ठा वाले अधिकारी हैं और काफी ईमानदार भी हैं परन्तु बाट में जिस प्रकार से जाच-काय पूरा होने से पहले ही फाइलें मंगा ली गई और मामला भी दफ़्त कर लिया गया उससे लगा कि यह सब कुछ राजनीतिक दबाव से हो रहा है और इनके पीछे माफ़ि का हाथ हो सकता है । उन्होंने बताया कि श्री कान्ते का मामला बम्बई शाखा को भेज दिया गया था ।

जाच ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक श्री व० विजया के अनुसार, जाच ब्यूरो के समूक्त निदेशक श्री ए० पी० चौधरी ने उनपर दबाव डालकर रिपोर्ट लिखवाई थी और इन अधिकारियों की तलाशियाँ लाने की सिफारिश कराई थी । श्री चौधरी द्वारा डाले गए दबाव के बारे में उन्होंने उप महानिरीक्षक श्री राजपाल को सूचित कर दिया था ।

श्री चौधरी ने श्री विजयन के आराप का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने श्री चौधरी पर कोई दबाव नहीं डाला था । उन्होंने तो सिर्फ निदेशक के आदेशों को जाग लगाया था । २० अप्रैल को श्री सन ने उन्हें बुलाकर इन अधिकारियों के विरुद्ध मामले दफ़्त करने को कहा था ।

सजय का ख़ला व्यवहार

श्री सन ने शपथ लेकर दिए अपने बयान में बताया कि वे

कभी भी श्री सत्य गांधी से मिलने नहीं गए क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि वे लोग व साथ बड़ा दया व्यवहार करते हैं। उन्होंने इसका एक उदाहरण देने हुए बताया कि एक बार जब वे प्रधान मंत्री निवास में थे तो श्री गांधी एक कमरे में घुस और वहां उपस्थित लोगों से बड़े दृष्टपन में कमरे से बाहर निकल जाने को कहा।

परन्तु इससे साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ सचता है, वे श्री गांधी से कभी प्रधानमंत्री निवास में आते-जाते टकराए हाँ, परन्तु दोनों के बीच दुआ सत्ता में अधिक कुछ बात नहीं हुई।

श्री मेन का कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन अधिकारियों द्वारा मारुति के संघ में तत्काल एकत्रित करने के कारण आज करने को कहा गया है। उनसे न तो कभी श्री से ने और न ही इनमें से किसी अधिकारी ने ऐसी शिकायत की। यदि शिकायत की गई होती तो वे प्रधानमंत्री के पास सीधे जाकर जांच द्यूरो का इस मामले में न घसीटन की प्रार्थना करते।

उन्होंने कहा कि श्री भटनागर और श्री काळे के संघ में श्री राजपान की रिपोर्ट के बाद उन्होंने विश्वास कर लिया था कि ये अधिकारी झूठे होंगे। उप महानिरीक्षक जैसे स्तर के अधिकारी की बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था।

श्री काळे द्वारा श्री वाटनीबाई से रिश्ते लेने तथा अम्बई में एक पनट खरीद जान के संघ में श्री खडालावाला ने पूछा 'जब दाना ही घातें गसत थी, तब आपने किम प्रकार में इस सही मान लिया?' श्री सन ने कहा 'इस दाना बाना के बारे में जांच के बाद ही पता लगा था कि यह सही नहीं है और एमीलिए रिश्ते के मामले का एफ० आई० आर० में खिन्न नहीं किया गया था।'

श्री खडालावाला द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आपका जानकारी थी कि काळे का दावा हज़ार रुपया मामिन में अधिक वतन मिलता था और उनकी पत्नी का भी जा नौकरी करती थीं नगमग दा हज़ार रुपये मामिन वतन मिलता था? ऐसा स्थिति में आप किम प्रकार में यह कह सकते हैं कि वे अपने माघना से वही अधिक अम्बई तरह से रहे रहे थे? इसपर श्री सन ने कहा 'उस समय मुझे यह जानकारी नहीं थी कि श्रीमती काळे का क्या वेतन है। उस समय सिर्फ यह जानकारी थी कि वे वही नौकरी करती हैं। इस-

पर जस्टिस शाह न कहा 'आप जैसे अनुभवही आदमी के निमाण में उस समय यह बात जरूर आनी चाहिए थी कि उनको आखिर कुछ न कुछ बताना तो मिल ही रहा होगा व वही अवतनिक नौकरा तो बर नहीं रही होगी। श्री सन इसका कुछ भी जवाब नहीं दे सक।

शान शौकत की परिभाषा

यदि आपका पाम रफ़िज़िटर टलीविज़न और छापी कार है तो उसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि आप बहुत शान शौकत से रह रहे हैं। इस बात का रहस्यार्थ टाटन श्री सन न किया। उनका कहना था कि एक अधिकारी की जाच करन पर उसके पास में यह सब मिला था और उसका आधार पर उन्होंने समझा था कि वह अपनी जाच में वही अधिक अच्छी तरह और शान शौकत से रह रहा है।

इसपर जस्टिस शाह न कहा 'क्या सालह-सत्रह सौ रुपये महीना बताने वाले सरकारी अधिकारी के पाम टलीविज़न रफ़िज़िटर या पुरानी कार का हाना उनकी आय से बहुत अधिक धन होने का प्रमाण है ?

श्री सन न मुस्कराने हुए कहा 'मुझे साढ़े तीन हजार रुपये मासिक बताना मिलता था लेकिन मेरे पाम टलीविज़न नहीं था।' इसपर जस्टिस शाह न हमी के बीच कहा 'इसमें क्या होता है। मेरे पाम टलीविज़न नहीं है लेकिन मेरे स्टेनो के पास तो है।'

जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में श्री सन न बताया कि जाच रिपोर्ट से पता चला था कि श्री कान्हे का बम्बई में एक फ्लट है। हो सकता है श्री कान्हे न इसकी अपनी सम्पत्ति में घोषणा नहीं कर रखा हो और इसके बनावी मानिक हों। श्री सन ने यह बात सब कहा जब जस्टिस शाह न उनसे कहा कि श्री कान्हे के फ्लट तो है नहीं उन्होंने इसे किस प्रकार मही समझ लिया था।

एक अन्य अधिकारी श्री कृष्णास्वामी के संबंध में श्री सन ने स्वीकार किया कि वे औमत तरीके से रहते थे तथा उनकी गोपनीय रिपोर्ट में भी कोई विपरीत टिप्पणी नहीं निघी हुई थी।

उनका कहना था कि श्री कृष्णास्वामी के नाम पर ३० हजार रुपये के धायर थे जिनमें से २५ हजार के डेयर १९७२ में उनके

पिता ने उनके नाम हस्तान्तरित किए थे और शेष पांच हजार के शेषर उद्धान स्वयं खरीदे थे।

जस्टिस शाह ने पूछा "क्या आपको पता है कि श्री कृष्णास्वामी एक रिटायर्ड अकाउंटेंट जनरल के पुत्र थे इसलिङ्ग पांच हजार के शेषर खरीदना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी?"

श्री सेन बोले, "१९७२ में पांच हजार रुपये की राशि बहुत अधिक होती थी तथा उन जैसे स्तर के अधिकारी के हिसाब से यह अधिक ही थी और इसके अतिरिक्त उनके पास बहुत मा अल्प सामान भी था। उन्होंने बताया कि मुक्तचर यूनिट के अनुसार, श्री कृष्णास्वामी के कुछ लोग व साथ सदिग्ध सबध भी थे।"

जस्टिस शाह ने उनसे पूछा "क्या आपको पास कुछ शेषर हैं?"

"जी हाँ, लगभग दो हजार रुपये मूल्य के।"

"क्या आपने उन्हें उचित तरीके से खरीदा है।"

"जी हाँ।"

"तब आप किस प्रकार से वह सक्ते हैं कि श्री कृष्णास्वामी ने पांच हजार रुपये मूल्य के शेषर गलत तरीके से खरीदे थे?"

श्री सेन इसका जवाब नहीं दे सके।

श्री खडालावाला ने इस मामले के सबध में पूरी बहस पर विचार करने के बाद कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सभी बायदे कानूनों की उपेक्षा करके कानून अपने हाथ में ले लिया था। श्रीमती गांधी नहीं चाहती थीं कि उनके पुत्र की फक्टरी के बारे में संसद में कोई जानकारी दी जाए।

उन्होंने कहा "जहां सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है वही निरंकुश सत्ता उस पूणतया भ्रष्ट कर देती है।"

उनका कहना था कि इन सत्तों के देखते हुए श्रीमती गांधी पर भारतीय दंड मंहिता के अंतर्गत अभियोग बनता है। इसपर जस्टिस शाह ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई संशय नहीं है कि अभियोग बनता है या नहीं उनका काम सिर्फ ग्यान्था का पता लगाने तक सीमित है अभियोग बनाने तक नहीं।

(॥) चले थे फर्म की जाच करने— पहुँचे भीसागार मे

हडलूम व वस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसक नियामक शुल्क में छूट मिली हुई है और हडलूम के नाम पर मिल में बने कपड़े के वस्त्रों का निर्यात कर यह छूट पाना एक अपराध है। इस अपराध का पता लगाना कोई अपराध नहीं बल्कि देश के राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए अच्छा कदम भी है। परंतु एमरजन्सी के दौरान इस अच्छे कदम के लिए अधिकारियों को जो पुरस्कार मिला वह भी विचारणीय है।

कुछ अधिकारियों को उनके कार्यालय से घर लौटने से पूर्व ही और कुछ को जाघी रात को उनके घरों से उठाकर भीसा के अंतर्गत नजरबंद कर देना ही वह पुरस्कार था। यह पुरस्कार किसी एक अधिकारी का नहीं बल्कि बारह अधिकारियों को मिला। इन अधिकारियों की गलती सिर्फ यही थी कि जाच से पहले उन्होंने इस याच की जाच नहीं की थी कि यह फर्म किससे सम्बद्ध है। यह फर्म थी इंदिरा इंटरनेशनल जिसका संबंध था तत्कालीन प्रधान मंत्री के पुत्र श्री सजय गांधी की सास श्रीमती जमेश्वर आनंद से।

वाणिज्य मंत्रालय में टेक्सटाइल कमिटी की सूचना मिली थी कि इस फर्म द्वारा हडलूम के स्थान पर मिल में बने कपड़े के वस्त्रों का निर्यात कर निर्यात शुल्क में छूट प्राप्त की जा रही है। जाच के लिए इस कमिटी में भी इस्पेक्टरों की संख्या एक सौ बीस थी। वाणिज्य मंत्रालय में भी इस्पेक्टरों की संख्या बीस थी। इनमें से बीस इस्पेक्टरों को दो इस्पेक्टरों की संख्या में घटा दिया गया। उधर कस्टम विभाग में दो इस्पेक्टरों की संख्या में घटा दिया गया और दो इस्पेक्टरों की संख्या में घटा दिया गया। उधर कस्टम विभाग में दो इस्पेक्टरों की संख्या में घटा दिया गया और दो इस्पेक्टरों की संख्या में घटा दिया गया।

इन सभी इस्पेक्टरों को इस जाच-काय में हाथ डालने पर दंड प्रक्रिया महिता की धारा १०८/१५१ के अंतर्गत गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड जल में डाल दिया गया। बाद में इन लोगों का भीसा के अंतर्गत गिरफ्तारी के आदेश समा लिए गए। सिर्फ एक इस्पेक्टर

श्री वालिया के अतिरिक्त जिन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया था, शेष सभी इस्पेक्टरों को लाजम्मा चुनाव घोषणा के बाद रिहा किया गया।

इन गिरफ्तारियां व पीछे सरकार का कथन था कि प्रधानमंत्री के पास कुछ शिकायतें आई थी कि वाणिज्यमंत्री श्री टी० पी० चट्टोपाध्याय टैक्मटाइल कमेटी में बगालिया ही बगानिया को भर रहे हैं और इनमें से कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तथा फर्मों का सग कर घन बना रहे हैं। श्रीमती गांधी के अनुसार, इस बार में श्री चट्टोपाध्याय को सूचित करने के निर्देश लिए। श्री चट्टोपाध्याय के उपलब्ध न होने पर श्रीमती गांधी के अतिरिक्त निजी सचिव श्री राजेन्द्रकुमार घबन ने उनके विशेष सहायक श्री एन० के० सिंह को इस बात से अवगत करा दिया। कुछ ही दूर बाद श्री सिंह ने इस्पेक्टर आफ़ीसर श्री एस० सी० सूरी से बगाली अधिकारियों की सूची प्राप्त कर प्रधानमंत्री निवास भिजवा दी और प्रधानमंत्री के अनुसार यह मामला बंदी समाप्त हो गया।

परंतु यात यही समाप्त नहीं हुई थी जाच ब्यूरो के उपमहा निरीक्षक श्री० ए० पी० मुखर्जी के अनुसार दिल्ली पुलिस के महा-निरीक्षक (रैंज) श्री पी० एस० मिश्र ने उन्ह मई १९७६ के अंत में सूचित किया था कि प्रधानमंत्री निवास में शिकायत मिली है कि टैक्मटाइल कमेटी के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चूंकि श्री मुखर्जी के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसकी जाच करने के आदेश दिए। परंतु अभी जाच पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सूचना मिली कि दिल्ली पुलिस ने इन अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

श्री मुखर्जी का यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तक सभी अधिकारियों के खिलाफ जाच पूरी भी नहीं हो पाई थी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ तो आरोप भी सही नहीं पाए गए थे। बाद में पता चला कि श्री मिश्र ने जून के पहले सप्ताह में ही सवधित पुलिस अधीक्षक को इन अधिकारियों के नामों की सूची पत्रागते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए थे और कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट स्वयं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को इस संघ में सूचित कर देंगे।

कम्टम इस्पेक्टर मानव तथा मलिन का १ जून, १९७६ को

दोपहर में उनके कार्यालय में ही गिरफ्तार कर लिया गया। टकन टाइन इस्पेक्टर सवथी वालिया भाम्भरी, रंगराजन तथा सहायक इस्पेक्टर श्री चटर्जी को उसी रोज़ आधी रात को उनके घर में गिरफ्तार किया गया और अगले इस्पेक्टर सवथी घोष गुप्ता वकटघ चनवर्ती, जन तथा मुखर्जी को २ और ५ जून के बीच गिरफ्तार किया गया।

यादव तथा मलिक का इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने एमरजेंसी के विरोध में नारे लगाए हैं तथा सरकार का तत्त्वा उलटने की योजना बनाने का प्रयास किया है। इस्पेक्टर भाम्भरी को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उसने २ जून १९७६ को सायं साढ़े पांच बजे अजमल खा रोड पर जनता को भड़काने वाला भाषण दिया था। वहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्री भाम्भरी को एक जून को रात को ही गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस का चूँकि भीसा के अलग-अलग गिरफ्तारी के लिए उचित कारण नहीं मिल पाए थे इसलिए एक बार फिर जाच ब्यूरो की सेवाएँ जन का फसला किया गया। जाच ब्यूरो के निष्पक्ष श्री सेन ने आठ जून को उपमहानिरीक्षक श्री योगेश राजपाल को बुलाकर कहा कि वे श्री भिण्डर के सम्पर्क में रहकर इन अधिकारियों से तिहाड़ जन पूछताछ की व्यवस्था करें। यह सब इन लिए किया गया, ताकि इन अधिकारियों के विरुद्ध आप से कहीं अधिक सम्पत्ति रखने का मामला बनाया जा सके।

इन आदेशों के बाद जाच ब्यूरो के इस्पेक्टर श्री दरियाबसिंह ने दिल्ली पुलिस के इस्पेक्टर श्री वदप्रसाथ के सहयोग से यह पूछताछ की। इन दोनों इस्पेक्टरों द्वारा की गई यह पूछताछ टेप रिकार्डर पर रिकार्ड की गई थी। पूछताछ के बाद इन अधिका के साथ कोई विशेष बात मालूम नहीं हो सकी और एक दूसरी ही बात बात हुई कि इस्पेक्टर आफिसर श्री सूरी ने जिन्होंने श्री सिंह को इन इस्पेक्टरों को सूची दी थी, जानबूझकर उन अधिकारियों के नाम दिए थे जिनमें उनके अच्छे संबंध नहीं थे। बाद में जस्टिस शाह के आदेश पर वह रिकार्डर आयाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें यह सब पूछताछ रिकार्ड की गई थी।

बाद में ११ जून को श्री सेन के कमरे में हुई एक बैठक में श्री भिण्डर ने कहा यद्यपि इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई दस्तावेजी

प्रमाण नहीं मिल सके हैं परंतु व इस बात से शत प्रतिशत विश्वस्त हैं कि ये अधिकारी भ्रष्ट हैं।

इस वठक में चार अधिकारियां सदथ्री चटर्जी, मुखर्जी, यादव और मलिक के विरुद्ध मामले दज करने का निणय किया गया। इसके बाद इन अधिकारियों के विरुद्ध १६ जून का मामले दज कर लिए गए और इन अधिकारियों के घरों की तलाश ली गई। मुखर्जी के घर की तलाशी के समय उनकी पत्नी बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी थी।

जहां इन चार अधिकारियों के विरुद्ध मामले दज कर लिए गए वही श्री सूरि और श्री आर० डी० भटनागर के विरुद्ध कोई मामला दज नहीं किया गया जबकि गुप्तचर यूनिट ने इन दोनों के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री एकत्र कर मामला दज करने की सिफारिश की थी। २६ जुलाई को श्री राजपाल ने एक नाट लिखत हुए कहा था कि कम से कम इन लोगों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के मामले तो दज किए ही जा सकते हैं और इसपर संयुक्त निदेशक श्री ए० डी० चौधरी ने भी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए नियमित मामले दज करने का सुझाव दिया था। परंतु श्री सन ने ३ अक्टूबर को श्री चौधरी से बातचीत करने के बाद कहा कि एक्ट की गई सामग्री पर्याप्त नहीं है। इसके बाद में आगे और जांच कराई जाए। २७ अक्टूबर को अघीसक ने फिर इन दोनों के विरुद्ध मामले दज करने की सिफारिश की, परंतु यह निश्चय किया गया कि इन लोगों के विरुद्ध जांच ब्यूरो द्वारा जांच न कराई जाए बल्कि ये मामले विभागीय कारवाई के लिए भेज दिए जाए।

ये सब गिरफ्तारियां इतनी अचानक और बिना कोई कारण बनाए की गई थी कि ये लोग स्वयं तथा इनके परिवार वाले बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सके। गिरफ्तार इस्पेक्टरों की पत्नियां ने न सिर्फ दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल श्री कृष्णचंद से भेंट की बल्कि गृह राज्यमंत्री श्री आनंद मेहता और वाणिज्य मंत्री श्री चंद्रोपाध्याय और उनके विशेष सहायक श्री सिंह से भी मुलाकात की, परंतु कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सका। हा बातों से ऐसा जरूर लगा कि श्री सिंह इन गिरफ्तारियों से प्रसन्न नहीं थे।

पाठ पढ़ाने की आवश्यकता

कस्टम इस्पेक्टर यादव की पत्नी श्रीमती ओमवती यादव ने गुडगावा न एक निवासी श्री कदमसिंह की सहायता से श्री भिडर से मुलाकात की। परंतु श्री भिडर ने कहा कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गिरफ्तारों के आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न लिए थे। श्री कदमसिंह द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से मिलने पर उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि आप श्री भिडर से ही मिल क्योंकि उनके कहने पर ही ये गिरफ्तारियां की गई थीं। बाद में श्री भिडर से दुबारा मिलने पर उन्होंने कहा कि श्री राजय गांधी व अतिरिक्त कोई और व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि वे यादव से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उसने उनकी सास की कम के वस्त्रों की गांठ की जांच करने की हिमाकत ना थी। श्री कदमसिंह ने श्री गांधी से भट करने की काफी कोशिश की और बाद में एक सुरक्षा कर्मचारी के सहायक से वे उनसे मारुति फक्टरी में मिलने में सफल भी हो गए। श्री गांधी ने सारी बात सुनने के बाद कहा कि उस (यादव को) पाठ पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। श्रीमती यादव ने श्री कदमसिंह के अतिरिक्त अपने पति व साथी कस्टम इस्पेक्टर श्री सुरेंद्रमोहन बोहरा द्वारा भी श्री भिडर से कहलान की चेष्टा की परंतु काम नहीं चला।

काफी जांच पड़ताल के बाद भी उन चारों अधिकारियों के खिलाफ साधन में वही अधिक संपत्ति रखने का प्रमाण नहीं मिल सका जिसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। बाद में इन सभी अधिकारियों को जिन्हें बिना किसी उचित कारण व भीष्मा में गिरफ्तार कर लिया गया था परबरी १९७७ में जेल में रिहा किया गया।

हृदयविदारक विवरण

गिरफ्तार इस्पेक्टरों की पत्नियों ने आयाग के समक्ष अपनी कठिनाइयां का ज्ञा हृदय विदारक वर्णन किया, उस सुावर जस्टिस शाह भी अपने को नहीं रोक सके और कहा इसान की इसान के प्रति अमानवीय व्यवहार की कोई सीमा नहीं है। हमारे अधिकारियों में यह अभी भी विद्यमान है। मैं जो कुछ सुना है वह

रागटे खड़े कर देने वाला है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।"

श्रीमती बालिया न फफफ फफफ रोते हुए अपनी बरणाजनक गाथा सुनाई कि किस प्रकार से उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका फलस्वरूप उनके बच्चे समुद्र बीमार हो गए, जो अभी भी बिस्तर नहीं छोड़ सके हैं।

'मीसा' नहीं होना चाहिए

श्रीमती बालिया ने सुबकते हुए कहा कि 'मीसा' जसा बालून होना ही नहीं चाहिए। इसमें लागा को जानवरों की तरह गिरफ्तार किया गया। हम लोग ने सपह-सड़पकर बहुत काटा है। हम लोगों की इतनी बर्णामी हुई कि हमारे मने-सबधिया न हमसे मिलना तक छोड़ दिया। हमारे बच्चे से दूसरे बच्चे कहा करते थे कि तुम्हारा पापा जेल में है। मीसा के भय और आतंक के कारण लोगों ने हमारा बच्चा जाना भी छोड़ दिया।

श्रीमती बालिया यह कहते हुए इतनी जोर से रो पड़ी कि उनकी पूरी बात तक सुनाई नहीं दी। आशोक के बस में एक बरणाजनक दृश्य पड़ा हो गया। वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आँखें यह हृदय विचारक गाथा सुनकर भर आई।

इसमें पूरा एक अर्थ इस्तेव्वर की पत्नी श्रीमती चटर्जी ने अपनी बरणाभरी गाथा सुनाते हुए कहा कि उनके पति को क्यों गिरफ्तार किया गया वह बात नहीं जान पाई। उन्होंने कहा, 'मैं एक गृहिणी हूँ मैं कभी जेल से बाहर नहीं निकली थी, परन्तु उस दिन अपनी दाना बच्चिया को छोड़कर अकेले पुलिस स्टेशन गई। मुझे दर दर की ठाकरें पानी पड़ीं, मैं गह रायमल्ली श्री आम मेहता से भी मिली, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।'

श्रीमती चटर्जी का कहना था कि जाच व्यूरो द्वारा उनके मकान को तलाशी ली गई और वे अपनी दोनों छोटी बच्चिया के साथ रात के समय बाहर आगन में खड़ी रहीं। भर पति अभी तक उस आघात में प्रभावित हैं।

एक अर्थ इस्तेव्वर की पत्नी श्रीमती घोष ने कहा कि उनके पति की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके सास और समुद्र बीमार पड़ गए। बस लोग बसबसा मैं से और समुद्र की हालत बहुत

धराव हो गई थी। उनका कहना था कि सरकार बदलन के बाद उनके पति की नौकरी तो वापस मिल गई, परंतु उनका तबादला बम्बई कर दिया गया और इस कारण अब भी वे अपने बीमार माता पिता की सेवा भी नहीं कर सके।

सभी महिलाओं की ओर से फरियाद

श्रीमती रंगराजन न महिलाओं की ओर से अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसा समय फिर कभी नहीं आए और महिलाओं को आतंकित और अपमानित न होना पड़े। उन्होंने बताया कि वे उन दिनों रात में भी नहीं पाती थीं। उन्होंने कई नेताओं के दरवाजे खटखटाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मैं श्री सिंह से मिलने भी गई थी परंतु उन्होंने मिलने से ही इकार कर दिया। उन्होंने कहा कि व श्रीमती गांधी से भी मिलने गई थी परंतु उन्हें बताया गया कि श्रीमती गांधी इस मामले में सबध में किसीसे मिलना नहीं चाहती।

गिरफ्तारी की खबर से शम आई

तत्कालीन वाणिज्यमंत्री श्री चट्टोपाध्याय ने अपने बयान में बताया कि उन्हें बसटाइल कमेटी के दस इस्पेक्टरों की गिरफ्तारी की बात सुनकर बहुत ही शम महसूस हुई। इन गिरफ्तारियों के बारे में तो उन्हें कोई जानकारी ही दी गई थी और न ही कोई राय ली गई। उन्हें इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी कि श्रीमती गांधी के परिवारजनों की इंदिरा इंटरनेशनल नामक फर्म में कोई दिलचस्पी है। श्री चट्टोपाध्याय का कहना था कि उनपर आरोप लगाया गया था कि वे इन छप्ट इस्पेक्टरों को बचा रहे हैं। इस बात की गलत ठहराने के लिए ही उन्होंने इन सभी इस्पेक्टरों की सूची प्रधानमंत्री के पास भिजवा दी थी। ये सभी इस्पेक्टर बंगाली थे तथा इनमें से कुछ तो उनके इस मंत्रालय में आने से पूर्व ही काम कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि १० इस्पेक्टरों की गिरफ्तारी में सबध में उन्हें कोई 'याचिका' औचित्य नजर नहीं आया था तथा यह सब उनके लिए धक्का पहुंचाने वाला और शर्मनाक था। उन्होंने इन लोगों के बारे में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री मेहता से भी बात

की थी, परन्तु उन्होंने यही कहा कि वे इस सबध में दिल्ली प्रशासन
 में बात करेंगे ।

श्री चट्टोपाध्याय ने जस्टिस झाह के एक प्रश्न के उत्तर में
 बताया कि श्रीमती गांधी वस तो हमेशा उनसे सीधे ही सम्पर्क
 रखा करती थीं परन्तु इसी मामले में उन्होंने अपने अतिरिक्त
 निजी सचिव व जरिय सदेश भिजवाया था ।

जस्टिस झाह बाले ' आप मन्त्रानय के प्रमुख थे, एक तरीके से
 अपने अधीनस्थ लागा व पिता के समान, फिर भी आप इस मामले
 में नौ महीने तक साते रहे ? "

श्री चट्टोपाध्याय ने जवाब दिया, ' मैं साता नहीं रहा, जो
 कुछ सम्भव था, मैंने किया । परन्तु उन दिना हालात असामान्य
 थे । "

उन्होंने बताया कि उह बाद में पात हुआ कि इन अधिका
 रियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय जाच
 ब्यूरो में प्रतिस्पर्धा-सी चल रही थी, जिसमें विजय दिल्ली प्रशासन
 की हुई ।

बच्चे भी सम्पत्ति

यथा किमी सरकारी अधिकारी का पानियों आदि में हिस्सी
 पीना नौ बच्चे होना घर में दा कितना दूध प्रतिदिन मगाना
 सम्पत्ति है ? हमारे अनिर्दिष्ट बच्चे घर में रहियो मित्र, हम कूलर
 मोटे की अलमारी तथा रिक्वाड-प्लेयर का होना भी सम्पत्ति में
 शामिल है ?

यह ममान आयोग व समस्त उम समय पता हुआ, जब जाच
 ब्यूरो व भूतपूर्व निदेशक श्री सेन ने बताया कि श्री मलिक की
 जाच करान व बाद इन इन सम्पत्तियों का पता लगा था । श्री
 मलिक की सम्पत्ति में इन मय बातों को शामिल किया गया था ।
 श्री मन प्राप्ताग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में इस बात का
 उचित उत्तर नहीं दे सक वस यही कहन रहे कि जाच के बाद
 इन मय बातों का पता लगा था ।

उनका कहना था कि श्री मलिक का १०४३ रुपया मामिक
 पन्ना मित्रता था और व हमम में घर पर मिफ ८५० रुपया ही
 में जा पात दे । हमारे पासबू उनक बैंक में १२ हजार रुपये जमा
 १०७

थे।

श्री यादव न सवध म श्री सेन न बताया कि उनका वेतन १२०४ रुपये मासिक था। उनकी गुठगाव में जमीन भी थी तथा इनके अतिरिक्त उनके दो बकां म खाने थे, जिनमें से एक में २८ हजार और दूसरे में पांच हजार रुपये जमा थे। ये आंकड़े यादई चौकाने बात थे।

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इस बात की कोई जांच नहीं कराई थी कि इनकी पत्निया कमाती थी अथवा नहीं। परन्तु यह सही है कि उनके रहने रहने का हक उनकी आय से बही अधिक अच्छा था।

जांच पुरो के तत्कालीन उपमहाधिवक्ता श्री ए० पी० मुखर्जी ने अपने बयान में बताया कि एमरजेन्सी के दौरान जो कुछ हुआ, उसके कारण उन लोगों को भी मर्यादा पीड़ा है। उनका कहना था कि निरपराध सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच-पताला करना उन्हें भी बुरा तो बहुत लगा था, परन्तु क्या करते, विवश जो थे।

जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोगों के कार्यालय का दुरुपयोग किया जा रहा था। हम लोगों ने इस विषय में आपस में विचार विमर्श भी किया, पर कोई और रास्ता भी नहीं था।

जस्टिस शाह ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा "उस अवधि में ऐसे काय हुए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एमरजेन्सी के दौरान किसीकी प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं थी किसीको भी घसीटकर मनमाने तौर पर पकड़कर मारबंद किया जा सकता था। किसीकी भी सम्पत्ति जब्त की जा सकती थी।" उन्होंने आगे कहा "एमरजेन्सी में अधिकारी अपनी बुद्धि विवेक की ताक पर रखकर किस प्रकार से काम करते थे आश्चर्य होता है।"

श्री मुखर्जी ने आयोग से प्रार्थना की कि ऐसी उपयुक्त कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी सरकार भविष्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जसी प्रतिष्ठित संस्था को ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सके जिससे उसकी प्रतिष्ठा नष्ट न हो।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'जब तक नागरिकों और सर

वारी अधिकारियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक इससे भी खराब बातें होती रहेंगी।”

सूची लुप्त

श्री धवन न जिरह के दौरान स्वीकार किया कि श्री एन० के० सिंह न उन्हें सूची तो भजी थी, परंतु बाद में उन्होंने वह सूची प्रधानमंत्री को दे दी थी। इसके बाद उस सूची का क्या हुआ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

इसपर आयोग के वकील श्री खडालावाला ने कहा, ‘प्रधान मंत्री न उस सूची का क्या किया?’

श्री धवन बाले ‘मुझे मालूम नहीं।’

श्री खडालावाला ता क्या फिर वह नहीं लुप्त हो गई?

श्री धवन मैं क्या कह सकता हूँ।

श्री खडालावाला कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वह सूची श्री सत्य गांधी के पास पहुंच गई हो?

श्री धवन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे मालूम नहीं कि सूची का क्या हुआ।

श्री खडालावाला न जानना चाहा कि जब यह मामला इतना महत्वपूर्ण था, तो प्रधानमंत्री सचिवालय में इसकी फाइल तो खोल रहा होगी। इसपर श्री धवन ने कहा ‘मैं फाइल का काम नहीं देखा करता था।’

श्री खडालावाला परंतु आपको प्रधानमंत्री सचिवालय की कार्य-पद्धति की तो जानकारी होगी?

श्री धवन भर ख्यान से यह मामला उसी समय समाप्त हो गया था जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें आरापों का कोई सत्यता मंदर नहीं आती।

इसमें पूछ श्री धवन ने आयोग का बताया था कि प्रधानमंत्री के पास कुछ रिपोर्टें आई थीं कि वाणिज्यमंत्री श्री चट्टोपाध्याय टक्करान् बनने में योगदान का भर रहे हैं और उनमें से कुछ घृणाचार में निपट हैं और अनियमितताएं बरत रहे हैं। उन्होंने इस बारे में था चट्टोपाध्याय के विशेष सहायक श्री सिंह को सूचित कर दिया था और उन्होंने बाद में इन इस प्रकार की एक सूची भी भेजा था।

श्री सिंह न आयोग को दिष्ट अपने बयान में बताया कि श्री धवन ने उन्हें फोन कर इन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की थी। उन्होंने टेक्सटाइल आफिसर श्री सी० एस० सूरि का फोन कर इस्पेक्टरों के सूची भेजने का कहा और कुछ देर बाद ही उनका पास सूची भेज दी गई, जो उन्होंने प्रधानमंत्री निवास भेज दी थी। इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें पता हुआ कि कुछ टेक्सटाइल इस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भिण्डर ने जिम्मेदारी ली

दिल्ली के तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक (रैंज) श्री पी० एम० भिण्डर ने इन अधिकारियों की गिरफ्तारी की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेत हुए कहा कि बहुत से वस्त्र निर्माता न उनसे शिकायत की थी कि कुछ इस्पेक्टर उन्हें बर्बरता परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इसके बाद दिल्ली प्रशासन में पुलिस अधीक्षक (घण्टाचार निरोधक) श्री बलवत्सिंह से इस मामले का पता लगाने का कहा था।

श्री भिण्डर ने इन अधिकारियों की गिरफ्तारी में उनके परिवारजनों का हुई परेशानियों पर खेद प्रकट किया परन्तु उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने कभी किसी इस्पेक्टर की पत्नी से श्री सजय गांधी के पास जान को कहा था। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि इस मामले में कुछ कर पाने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। उन्होंने उस बात से भी इन्कार किया कि उन्होंने श्री मुखर्जी से कहा था कि यह सूचना प्रधानमंत्री निवास से आई है।

श्री भिण्डर का कहना था कि एमरजेंसी की घोषणा के बाद दिल्ली प्रशासन में एक अपेक्स कमेटी का गठन किया गया था और उसमें हुई एक बैठक में निणय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की भांति दिल्ली प्रशासन भी सरकारी कर्मचारियों को मोसा क अतगत गिरफ्तार कर सकता है।

उन्होंने बाद में जिरह के दौरान स्वीकार किया कि यह इस्पेक्टर दिल्ली प्रशासन के अतगत नहीं आते थे परन्तु अपेक्स कमेटी की बैठक में यह नहीं कहा गया था कि यह आदेश सिर्फ दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर ही लागू होगा केन्द्र सरकार के कर्म

चारियों पर नहीं। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी अधिका-
रिया का यह आदेश नहीं दिया कि इन लोगों को पहले दंड
प्रक्रिया महिना की धारा १५१ के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाए।
उन्होंने ता इन लोगों का सीधे ही मौला में गिरफ्तार करने को
कहा था।

श्री भिण्डर ने इस बात का गलत बताया कि उन्होंने श्री कृष्ण
बन से कहा था कि उच्चाधिकारियों ने इन इस्पेक्टरों को मौला
में गिरफ्तार करने को कहा है। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि
उन्होंने इस मामले पर गृह राज्यमंत्री श्री मेहता से विचार विमर्श
किया है और आप भी आगे कोई कार्रवाई करने से पहले श्री मेहता
में मिलावट कर लें।

मिल्ली प्रशासन के गृह विभाग में तत्कालीन विशेष गृह सचिव
श्रीमती शलजा कट्टा ने स्वीकार किया कि प्रशासन में एक अपेक्षा
कमिटी का गठन किया गया था और उसमें सरकारी कमचारियों की
मौला में गिरफ्तारी पर भी विचार विमर्श किया गया था, परन्तु
उन्हें यह पता नहीं है कि वठन में केन्द्र और मिल्ली प्रशासन के
कमचारियों के बीच में विवाद रूप में कोई झिझक किया गया था
अथवा नहीं।

गुरु म फम इन्दिरा इन्दिरनेशनल की एक भागीदार श्रीमती
इन्दिरा बोडी ने आपीन को भेजे एक वक्तव्य में इन आरोपों को
गलत बताया था कि श्री गांधी की सात श्रीमती आनन्द इस फम
की कोई भागीदार थी अथवा उनका इसमें कोई मानिकाना स्वाध
था।

परन्तु एक आखिरी अधिकारी श्री एस० व० भारद्वाज ने बाद
में आपीन के समक्ष कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कर सबको चौंका दिया।
इन दस्तावेजों में पता चलता था कि श्रीमती आनन्द को इस फम
द्वारा १ अक्टूबर १९७६ में मकर ३१ मार्च १९७७ के बीच १७
हजार रुपये से अधिक की धनराशि कमीशन के रूप में दी गई
थी। श्रीमती आनन्द को यह राशि नियम के बाम के लिए कमी-
शन के रूप में दी गई थी।

श्री गणनावाता ने विरह के बाद निष्पक्ष निकासने हुए कहा
कि इन अवधि निष्पक्षियों के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती
इन्दिरा गांधी उत्तरदायी हैं क्योंकि इस सब में समझौते कार्रवाई

श्रीमती गांधी की पहल पर ही की गई।

उनका कहना था कि इन इस्पेक्टरों ने इन्फिरा इटरनेशनल फम के सिलेसिलाए वस्त्रों को राक दिया था ता फम के एजेण्टों ने इस्पेक्टरों को धमकी दी थी कि इसकी कीमत चुकानी होगी, और बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री खडालावाला ने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अतिरिक्त निजी सचिव श्री घवन यह कह चुके हैं कि उन्होंने वह सूची श्रीमती गांधी को दे दी थी। उसके बाद से ही वह सूची गायब है। यदि श्रीमती गांधी यहाँ गवाही देने आती तो यह मालूम हो सकता था कि उस सूची का क्या हुआ और क्या उसका क्या चाहती थी।

(iii) आनन्द माग की आड में राजनीतिक प्रतिशोध

एमरजेन्सी के दौरान राजस्थान के एक आई० ए० एस० अधिकारी को अपनी कृतव्यनिष्ठा के कारण नौकरी से निलम्बित होना पड़ा। उनपर आरोप लगाया गया था कि वे आनन्द माग से सम्बद्ध हैं।

आनन्द माग की आड में ही जयपुर के एक एडवोकेट की भीसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था और उनकी पत्नी को भी नौकरी से हटा दिया गया था।

राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने २० अगस्त १९७५ को राज्य के मुख्य सचिव का एक नाट लिखा था जिसमें कहा गया था

‘प्रधानमंत्री ने अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० घवन ने मुझे फोन कर निम्नलिखित संदेश दिया

१ जयपुर में सरोजनी माग पर रहने वाले एक एडवोकेट श्री एस० एन० शर्मा के बारे में जात हुआ है कि उन्होंने स्वयं के तथा अपनी पत्नी के आनन्द माग से संबंधित होने के कुछ कागजात जलाए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जार० एन० गौड इन कागजातों के जलाए जाने की सूचना मिलने के बाद भी वहाँ समय पर नहीं पहुँचे और कागजों को जलने दिया। यहाँ सूचित

किया जाता है कि श्री शर्मा का मोसा के अतगत गिरफ्तार कर लिया जाए।

७ उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रा शर्मा को जा जयपुर के महा राज, विद्यालय में अध्यापिका हैं, नौकरी में हटा दिया जाए।

८ श्री गौड़ के इस प्रकार की काय की तुरत जाच कराई जाए।

९ आई० ए० एस० अधिकारी श्री मंगलबिहारी का भी नौकरी से हटा दिया जाए।

दुपचा हम धारे में तुम्हें कारवाई करें।

हस्ताक्षर/—हर्षिनेव जोशी

२० द ७५

मुख्यमंत्री, राजस्थान

मुख्य सचिव न मुख्यमंत्री ने उक्त नाट के आधार पर अपनी कारवाई प्रारम्भ कर दी। उन्होंने उसी दिन यानी २० अगस्त १९७५ को तीन अत्यंत गोपनीय पत्र लिखे। यह पत्र जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को लिखा गया जिसमें श्री गमा का मुख्य-मंत्री की निष्पत्ती के आधार पर मोसा में गिरफ्तार करने को कहा गया। दूसरा पत्र शिक्षा आयुक्त को लिखा गया, जिसमें श्रीमती शर्मा का इस आधार पर हटाने को कहा गया कि उनका संबंध आनन्द माग स है। तीसरा पत्र पुलिस महानिरीक्षक को लिखा गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री गौड़ के विरुद्ध तुरत कारवाई करने का कहा गया था।

आई० ए० एस० अधिकारी श्री मंगलबिहारी को, जो उस समय राजस्व महल के सदस्य थे २० अगस्त स छुट्टी पर जान को बना गया। बाद में २ सितम्बर का मुख्य सचिव न प्रधानमंत्री सचिवालय में समुक्त सचिव श्री बहल तथा केंद्र सरकार में पसनल विभाग के सचिव से बात कर था मंगलबिहारा का एक महीने के अवकाश पर भेज दिया।

मुख्य सचिव ने पत्र के आधार पर श्री गमा को उसी दिन मोसा में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति में राज्य सरकार ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार श्री शर्मा १९६३ में आनन्द माग में शामिल हुए थे तथा उसका बाद स लगातार उमरे सम्पर्क में रहे थे।

श्री शर्मा का इही आधार पर गिरफ्तार किया गया ।

सरकारी रिवाजों व अनुसार यह मन्त्रालय में संयुक्त सचिव ने १४ अगस्त का लिख एक पत्र में उन लोगों की सूची भजी थी, जो आनन्द माग सहित अन्य प्रतिबंधित दला से सम्बद्ध थे । इस सूची में श्री शर्मा का तो नाम था, परन्तु उनकी पत्नी का कोई जिक्र नहीं था ।

मुख्य सचिव द्वारा भेजा गए पत्र के आधार पर शिक्षा आयुक्त ने अपने संयुक्त निदेशक (महिला) की श्रीमती शर्मा की नौकरी से हटाने का निश्चय लिखा था । उन्होंने उसके कारण वही बताया थे, जो मुख्य सचिव ने उद्धृत किए थे । शिक्षा आयुक्त ने इसी पत्र के आधार पर संयुक्त निदेशक ने २३ अगस्त का ही श्रीमती शर्मा की नौकरी से हटा देने के आदेश दिए ।

श्री गौड़ के मामले में राजस्थान पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद बताया गया कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने में कोई देर नहीं की थी । इसलिए उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है । जांच के अनुसार प्रोफेसर बी० बी० गुप्ता के मकान के एक हिस्से में श्री शर्मा रहते थे तथा एक हिस्से में एक डाक्टर कुमारी पुष्पा खाना रहती थी । डा० खाना ने ही आनन्द माग व संबंध में कुछ पागलता जताए जाने की पुलिस की सूचना दी थी । सूचना मिलते ही श्री गौड़ जब वहां पहुंच तो डा० खाना ने उन्हें एक डायरी व कुछ जले हुए पृष्ठ दिखाए थे जो उनके अनुसार शर्मा दम्पती ने जलाए थे । जले हुए अधिकांश पृष्ठ खाली थे लेकिन छ-पृष्ठों में अध्यात्म के बारे में कुछ बातें लिखी थी । लेकिन डा० खाना वह स्थान नहीं बता पाए, जहां यह कागज जल जाते हुए थे और न ही उन्हें उस गोरुर से मिलवा सकी जिसने उन्हें जलते हुए देखा था ।

झगडा मकान खाली कराने का

श्रीमती शर्मा ने आयोग को बताया कि उनके पति की मकान मालिका श्री गुप्ता से रही बनती थी क्योंकि वह मकान खाली कराना चाहते थे । श्री गुप्ता मकान खाली कराने के लिए उनपर कई तरह से दबाव डाल रहे थे । डॉ० (कुमारी) खाना का मकान मालिक से अच्छा मेल जाल था और उम्मीन पुलिस को गतत रिपोर्ट

दी थी।

श्रीमती गर्मा ने स्वीकार किया कि व १९६३ तक आने-माग की समस्या थी परंतु बाद में उनका उससे कोई संबंध नहीं रहा था, हालांकि उनके पनि उससे सम्बद्ध रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात को बिलकुल गलत बताया कि उनके मकान में आने-माग से संबंधित कोई वागजात जलाई गए थे। उनका कहना था कि उनसे कम मद्रघ में पूछताछ करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी भी नहीं आया था।

उन्होंने बताया कि नौकरी से हटाए जाने का समाचार उनके लिए बहुत ही अप्रत्याशित था, क्योंकि तीन दिन पूर्व ही उनकी प्रमोशन में उनसे कहा था कि आपको तरक्की के चांस हैं। इससे पूर्व उन्हें १९७३ में थ्रेष्ठ अध्यापिका का पुरस्कार मिल चुका था। नौकरी से हटाए जाने के बारे में प्रिंसिपल से मालूम करने पर कहा गया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है बेहतर है मुद्रमन्त्री से मिलो। मुद्रमन्त्री से मिलने पर उन्होंने कहा 'इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वारदात ठीक से नहीं जानती'। श्रीमती गर्मा ने कहा कि वे इस संबंध में शिकायत जमावत में भी मिली थी। उन्होंने कहा था कि 'हो सकता है कि आपके संबंध में किसी केन्द्र सरकार में शिकायत की हो।'

निलम्बन के कारण

श्री मंगलविहारी को मितम्बर, १९७४ में तीन बर के लिए राजस्थान विद्युत् मंडल का अध्यापक बनाया गया था परंतु जवानक ही उन्हें ३० जून १९७४ को अत्रमर में राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया। श्री मंगलविहारी ने बताया कि उन्हें निरन्तरित किए जाने के मुख्य कारण में हा संवत् है।

१ उन्होंने मार्च १९७४ में राजस्थान राज्य मंडल परिवहन के अध्यापक के रूप में 'निलम्ब' में वापस द्वारा जयप्रकाश आशालन के विरोध में आयोजित एक विज्ञापन रत्ती में निगम की वसा को काम मन की अनुमति नहीं दी थी।

२ विद्युत् मंडल के अध्यापक के रूप में उन्होंने जयपुर में श्रीमती मन्तराज कपूर द्वारा आयोजित एक प्रमोशन के लिए रियायती दर पर बिजली देने में इस्तेमाल किया था।

३ विद्युत् मंडल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद दिल्ली में श्रीमती गांधी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के अवसर में आयोजित की जान वाली २० जून की रैली के लिए मंडल के १०० टूका तथा दस हजार श्रमिका को बहा भेज जान की व्यवस्था करने से इन्कार कर दिया था। 'मुझ में राजनीतिक बाधा द्वारा मौखिक रूप से निर्देश दिए गए थे कि श्रमिका को बिना छुट्टी ही जान की अनुमति दी जाए तथा टूका के लिए कुछ भी भिराया न लिया जाए।

४ बाद में उन्होंने दिल्ली भेज गए ५८ टूका के लिए मामाय निजी दरें वसूल करने के लिए आदेश दिए थे।

श्री मंगलबिहारी ने आयोग को बताया कि सम्भवतः आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी अधिकारी को सिर्फ प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव द्वारा किए गए फोन के आधार पर हटा दिया गया हो और वह भी बिना कोई कारण बताए अथवा नोटिस दिए। यह भी आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री ने बिना कोई जांच कराए मुख्य सचिव को कारवाई करने के भी आदेश दिए।

उन्हें निलम्बन की १६ महीने की अवधि के दौरान कोई बैतन नहीं दिया गया। चिकित्सा शुल्क का पसा नहीं दिया गया, फोन काट दिया गया तथा भविष्य निधि तक में से धन नहीं लेने दिया गया।

मन्त्री भी आनन्द मार्गी

श्री मंगलबिहारी ने बताया कि उनका १९६९ में आनन्द मार्ग से अवध था परन्तु १९७० के बाद से उससे कोई संबंध नहीं रहा था। जब वह इस संस्था में थे उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री गुलजारी लाल नन्दा श्री पुनाचा श्री गुरुमया तथा एक विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे प्रमुख लोग तक उसके सदस्य थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक-दो ऐसे विवाह समारोहों में जरूर शामिल हुए थे, जिनमें विवाह आनन्द मार्ग के उच्चारणा से हुआ था परन्तु १९७१ के बाद तो उनसे इस संस्था का कोई सदस्य तक नहीं मिला था। उन्होंने बताया कि वे निलम्बन के अवधि में श्री घराने से भी मिले थे।

उनका कहना था कि एमरजेसी के दौरान दो स्थानों से निर्देश मिला करते थे, एक प्रधानमंत्री घराने से और दूसर आधिकारिक स्तर से। इसमें प्रधानमंत्री घराने से आए निर्देशों का आधिकारिक स्तर के निर्देशों पर प्रभुत्व होता था।

जाच में प्रमाण नहीं मिले

श्री मंगलबिहारी पर लगाए गए आरोपों की जाच स पता चलता है कि इस बात के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि १९७४ में जयप्रकाश आदोलन विरोधी रेली के लिए रोज़ाना की बसा का उपयोग किया गया था। श्रीमती मंगलपाल कपूर द्वारा आयोजित प्रदर्शनी 'क्राफ्ट्स इंडिया' को रियायती दरा पर बिजली देने का संबंध भी श्रीमती कपूर ने अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर प्रदर्शनी के लिए औद्योगिक दरों पर बिजली देने का लिखा था परन्तु उन्होंने आम प्रदर्शनियों के लिए दी जाने वाली दरा पर ही मंजूरा दी। २० जनवरी की रेली के संबंध में प्रांतिय विद्युत मजदूर संघ की ओर से जो प्रार्थना की गई थी कि २० तारीख को आसपास उनका संघ को दिल्ली में एक बैठक है अतः उसमें भाग लेने के लिए मजदूरों का छुट्टी दी जाए तथा ट्रेका की व्यवस्था की जाए। बोर्ड की ओर से संघ को डब रफ़ा प्रति किनोमीटर की दर से ट्रेको की व्यवस्था का गई तथा उनसे कहा गया कि वे स्वयं ही स्ट-परमिटों की व्यवस्था करें परन्तु बाद में पता चला कि इस प्रकार के परमिट बनाए बिना ही ट्रेका को दिल्ली ले जाया गया था। यन् श्री माल ठूना कि संघ की इन दिनों दिल्ली में कोई बैठक नहीं हुई थी। याद द्वारा संघ के महासचिव श्री दामोदर शर्मा को उन ट्रेका का बिना भेजे जाने पर उन्होंने लिखा कि इन ट्रेका का उपयोग दिल्ली में आयोजित रेली के लिए किया गया था तथा यह एक प्रवक्ता के माध्यम से यात्राचीन के नाम ही उपन्यास कराए गए थे। इसलिए इनके जिले में भी कोई अपवाद भ्रष्टाचार की भेजे जाए।

यह सरकार और राज्य सरकार के रिवाजों का उल्लंघन के पना चलता है कि इस प्रकार के कोई पूरे प्रमाण नहीं थे कि श्री मंगलबिहारी का आनन्द माय से बाद में भी संबंध रहा था। रिपोर्ट में यह पता चला चलता था कि वे आनन्द मायियों से सम्बन्ध बनाए रखने के विवाह-समारोहों में शामिल हुए परन्तु उनमें एक ही दिनांक

वात नहीं थी। जाच ब्यूरो के एक पत्र में यह भी कहा गया था कि श्री मंगलबिहारी का आनंद माग से संबंध सिर्फ अध्यात्म तथा सगठनात्मक क्षेत्र तक ही सीमित है। हो सकता है कि वह आनन्द माग के बारे में सत्य का पता नहीं हो और वे इसका अध्यात्म पाठों में भाग लेते रहें हैं।

मंचिव का यह नोट ३ फरवरी, १९७६ को प्रधानमंत्री के पास भेजा गया, जिसपर उद्धाने काफी दिना बाद ८ दिसम्बर १९७६ को नोट लिखा कि हा—परंतु उनपर समय समय पर निगाह रखी जाए। श्रीमती गांधी के इस निषेध के बाद राज्य सरकार का इस बारे में १५ दिसम्बर को सूचित कर दिया गया और उसीके अनुसार श्री मंगलबिहारी ने २० अगस्त १९७५ से १५ दिसम्बर १९७६ तक छुट्टी पर रहने के बाद २० अगस्त से अपनी सवाण पुन प्रारम्भ की।

राजस्थान के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री मोहन मुखर्जी ने आयोग का बताया कि जहां तक उनका संबंध है किसीको गिरफ्तार करने का संबंध में और किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कारवाई करने के बारे में किसी से आए निर्देश काफी थे।

जस्टिस शाह क्या गिरफ्तारी का कारण पर्याप्त थे ?

श्री मुखर्जी चुनि आदेश प्रधानमंत्री से आए थे इसलिए हमने समझा कि उन्होंने इस बारे में अपनी सतुष्टि कर ली होगी।

प्रधान-मंत्रीनिवास के आदेश सरकारी आदेश

श्री मुखर्जी ने बताया कि कोई मामला में गिरफ्तारी का आदेश पान पर ही नहीं बल्कि गायरलस के जरिये भेजे गए थे। इसपर जस्टिस शाह ने कहा आप अधिनियम की धारा १६ (ए) पढ़िए, क्या इसमें प्रधानमंत्री अथवा उनके अतिरिक्त निजी सचिव का कहीं इस प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं ? श्री मुखर्जी बोले, 'हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री निवास से आया प्रत्येक आदेश का सरकारी पार में आया आदेश है।'

रैलियों का कोटा

प्रातीय विद्युत् मंडल मजदूर फंडेशन के महासचिव श्री दामोदर मोय ने आयोग का बताया कि दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस

म १६ जून, १८७५ को हुई एक बैठक में २० जून की रती के लिए राजस्थान से एक लाख व्यक्तियों के भाग लेने का कोटा निश्चित किया गया था। उनका कहना था कि इन एक लाख व्यक्तियों में से विद्युत् मंडल का बेटा १० हजार का था। उन्होंने यह प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया था कि कमचारियों को परिवहन तथा छुट्टी की सुविधा दी जाएगी।

एक प्रश्न के उत्तर में श्री मौय ने बताया कि ५८ टर्कों में लगभग पांच हजार कमचारी दिल्ली आए थे। उन्हें सिर्फ परिवहन और छुट्टी की ही सुविधा दी गई थी। खान-पान का समस्त खर्चा स्वयं कमचारियों ने उठाया था।

राजस्थान के भूतपूर्व सिंचाई तथा विजलीमंत्री श्री हीरालाल देवपुरा ने बताया कि उन्हें इस बात का पता एक दो महीने बाद तक चला, जब टर्कों के भुगतान के विषय में सबंधित मामला उनके सामने आया। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने कमचारियों को आबस्मिक अवकाश की सुविधा देने की कहा था।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वे सरकारी कमचारियों का इस प्रकार राजनीतिक प्रदर्शना में भाग लेना उचित समझते हैं श्री देवपुरा ने कहा 'मैं उस समय इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया था।'

राज्य के तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री माहन छगणी ने आयोग का बताया कि श्री जोशी ने उन्हें दिल्ली में फान कर श्री मौय की सहायता करने को कहा था। एक दो दिन बाद श्री मौय उनमें मिले तथा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का कहा।

बेचारे मृत्युमंथ्री

उनका कहना था कि यह वह समय था जब प्रत्येक व्यक्ति श्रीमती गांधी श्री सत्य गांधी अथवा किसी और गांधी के निर्देश पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा, 'न सिर्फ वह बलि बेचारे' मुख्यमंत्री भी उनके निर्देश पर काम कर रहे थे।'

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आपको यह गलत नहीं लगा कि यह सावधानी भ्रम का दुरुपयोग होगा? उन्होंने कहा कि 'मैं अनुचित नहीं कहूँ नहीं था यह पहले भी

होता रहा था। उन दिना एक नही कई रलिया निकाती जा रही थीं।

भाड मे जाए महात्मा गाधी

श्री छगाणी न कहा कि एमरजन्सी के दौरान राजस्थान की स्थिति का वणन इन शब्दों में किया जा सकता है

देश की नेता इन्दिरा गाधी,
युवका के नेता—सजय गाधी,
महिताआ की नेता—मेनका गाधी,
बच्चा के नेता—राहुल गाधी
भाड में जाए महात्मा गाधी।'

(श्री छगाणी के इस वचन पर आयोग का कक्ष कई मिनटों तक ठहाका में गुंजता रहा।)

राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जोशी न स्वीकार किया कि २० जून १९७५ को इनाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का विरुद्ध श्रीमती गाधी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के संबंध में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए राजस्थान से आए लोगों को राजस्थान विधुत मंडल के ट्रका में लाया गया था। उन्होंने कहा लगता है उस समय कुछ अधिकारियों ने अधिक उत्साह में आकर यह काय किया।'

श्री जोशी ने इस बात से इकार किया कि राजस्थान हाउस की बैठक में २० जून का रैली के लिए राजस्थान का कोई कोटा निश्चित किया गया था। उन्होंने कहा कि श्री मोय के वचन के अनुसार यदि एक लाख व्यक्तियों को राजस्थान से लाया जाता तो पांच से सात हजार के बीच ट्रकों की आवश्यकता पड़ती। उनका अनुमान था कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के लगभग पांच हजार व्यक्तियों ने रैली में भाग लिया था।

श्री जोशी ने प्रारम्भ में जस्टिस शाह के प्रश्नों को टालने का प्रयत्न किया परंतु जब बार बार उन्होंने उनसे घुमा फिराकर प्रश्न किए तो उन्होंने स्वीकार किया 'कुछ मामलों में गलतिया हुई हैं। ये गलतिया किसी भी मंत्री का लेकर हुई हो, मैं अपने उत्तरदायित्व से स्वयं का मुक्त नहीं करना चाहता।'

‘घबन, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि

उनका कहना था कि श्री घबन ही तत्कालीन प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करते थे। वह जो कुछ कहते थे, उसे श्रीमती गांधी का आदेश समझकर तुरंत कारवाई की जाती थी।

श्री जोशी न बताया कि श्री घबन ने उन्हें फोन कर इन लोगों के खिलाफ कारवाई करने को कहा था और यह भी बताया था कि श्री मंगलबिहारी का सबध आनन्द भाग से है और एडवोकेट श्री शर्मा और श्रीमती शर्मा के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री गोड को भी उन्होंने नौकरी के प्रति लापरवाही बरतने के कारण गिरफ्तार करने को कहा था परन्तु कोई प्रमाण न होने के कारण उन्होंने श्री घबन का दोबारा फोन किया तब उन्होंने श्री गोड के खिलाफ सिर्फ जांच करने की ही बात कही।

श्री घबन ने इस बात से साफ इन्कार किया कि उन्होंने श्री जोशी का फोन कर इस मामले के सबध में यह सब कारवाई करने के आदेश दिए थे।

श्री घबन ने कहा, मैं फोन पर सिर्फ यह कहा था कि प्रधानमंत्री को कुछ विधायकों द्वारा उक्त ‘यन्त्रियता’ के सबध में शिकायतें मिली हैं कि इन लोगों का आनन्द भाग से सबध है।’ उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही इन शिकायतों से श्री जोशी के साथ-साथ गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता को भी अवगत करा दिया था। उन्होंने श्री जोशी को इस सबध में केन्द्रीय जाच ब्यूरो का नोट पढ़कर सुनाया था कोई आदेश या निर्देश नहीं दिए थे तथा इस सबध में उनसे श्री मेहता से सम्पर्क करने को कहा था।

श्री घबन ने कहा कि कुछ विधायकों ने प्रधानमंत्री से शिकायत की थी कि आनन्द भाग से संबंधित कुछ कागजात जलाए गए हैं तथा राज्य सरकार ने सूचना मिलने के बाद भी कोई कारवाई नहीं की है। प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले में केन्द्रीय जाच ब्यूरो से जानकारी प्राप्त करने पर उसने इसकी पुष्टि की थी।

श्री घबन ने एवं प्रश्न के उत्तर में बताया मैं श्री मंगलबिहारी के सबध में श्री जोशी से बात की थी। श्री जोशी ने तो श्री बिहारी को तुरंत ही नौकरी से हटा देने को कहा था, परन्तु मैं

कहा था कि यह ठीक नहीं होगा। आप सिर्फ उह छुट्टी पर भेज दें।” उन्होंने स्वीकार किया कि श्री मंगलविहारी उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उह श्री महता से मिलने को कहा था।

श्रीमती गांधी दोषी

इस मामले पर जिरह के बाद आयोग व वकील श्री काल खडालावाला ने कहा कि पूरे मामले से स्पष्ट हो जाता है कि यह सब कुछ श्रीमती गांधी के निर्देशानुसार किया गया। श्री जोशी ने श्रीमती गांधी के निर्देश से यह किया जो उह श्री धवन के जरिये मिले थे।

श्री खडालावाला का कहना था कि यह सही है कि श्री धवन ने इस मामले में सिर्फ एक मददवाहक की ही भूमिका निभाई थी, परंतु यह भी सगता है कि उन्होंने अपनी क्षमता से कहीं अधिक किया। उन्होंने अपनी रजाइ से अधिक ही पर फलाने की चेष्टा की थी। श्री खडालावाला ने कहा इन गिरफ्तारियों और निलम्बना के लिए श्रीमती गांधी ही जिम्मेदार हैं।

(iv) आजादी के स्वतंत्रता-सेनानी एमरजेन्सी के देशद्रोही

समय समय की बात है आजादी से पहल नागरिक-अधिकारों तथा प्रेस की स्वतंत्रता का परखी करना एक सम्मानजनक बात समझी जाती थी वही एमरजेन्सी के दौरान इन सब बातों का शिक करना भी एक अपराध हो गया था।

२३ जुलाई १९७५ को ८२ वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी श्री भीम सेन सच्चर (जिनका १८ जनवरी १९७८ को रात्रि को निधन हो गया) तथा उनके सात अन्य साथियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एक पत्र लिखा। पत्र में एमरजेन्सी लागू करने और प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का विरोध करते हुए कहा गया था कि यदि इनपर से नियंत्रण नहीं हटाया गया तो आगामी ६ अगस्त से सावजनिक रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।

श्रीलंका में भारत के भूतपूर्व उच्चायुक्त आध्यात्म और उडीसा के भूतपूर्व राज्यपाल तथा एकीकृत पंजाब के मुख्यमंत्री

श्री सच्चर के अनिरिक्त जिन सात व्यक्तिगता न इस पत्र पर हस्ताक्षर किये थे वे थे—सिटीजन आफ डेमोक्रेसी के कायनारी सचिव श्री विष्णुदत्त सर्वेण्ट्स आफ पीपुल्स सोसायटी की दिल्ली शाखा के अध्यक्ष श्री मेहनाराम एडवाकेट श्री बी० के० सिंहा इंडियन मर्विस मिशन के श्री एस० डी० शर्मा, हसराम बालेज मफिलोसफी विभाग के प्रमुख श्री जे० क० शर्मा सर्वोदय कायकर्ता श्री कृष्ण-लाल वैद तथा अध्यात्म साधना मन्दिर के श्री जे० आर० साहनी । ये सभी हस्ताक्षरकर्ता ६० वर्ष से अधिक की आयु के थे । इस पत्र की साइक्लोस्टाइन् प्रतिमा राजनीतिक, धार्मिक और प्रेस सेवा के प्रमुख प्रतिनिधियों को भेजी गई थी ।

श्री सच्चर तथा उनका सात साथियों ने इस पत्र में लिखा था कि ' पंडित नेहरू को हम भारतीय स्वतन्त्रता का मुख्य निमित्त मानते हैं । वे कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति वह चाह कितना ही बड़ा क्या न हो आलाचना से परे नहीं है । ब्रिटिश राज में उन्होंने कहा था कि स्वतन्त्रता संकट में है, अपनी पूरी शक्ति से हम बचाओ । उसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि इस समय वे जीवित हों तो कहते ' लोकतन्त्र संकट में है, अपनी पूरी शक्ति से इस बचाओ । '

' कानून के विरुद्ध कार्य करने वाला संनिपटने के लिए सरकार के पास पटले से ही बहुत-से अधिकार हैं फिर भी हम आपके द्वारा इन संनिपटने के लिए और अधिक अधिकार लाने का धनौती नहीं देते ।

संसद की कार्यवाही का बिना पूर्व संसरक्षिप के प्रसारित करने में राबना संसदीय लोकतन्त्र पर कुठाराघात होगा । हम इस बात की पूरी आशा है कि गिरफ्तार किए गए समद-मदस्था को संसद के इस सत्र में अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा । "

' आज आपके राजनीतिक समर्थकों के अतिरिक्त दिल्ली का आम आदमी काफी हाउस और बस स्टैंड पर अपनी कोई राय तक प्रकट नहीं कर सकता । डर का एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है कि आपके विरोधी विचार वाला व्यक्ति कुछ कहने के स्थान पर चुप रहना ही पसंद करता है क्योंकि उनके मन में यह डर है कि क्या मालूम आधी रात को दरवाजा खटखटाकर उस जेल में डाल दिया

जाए। पंडित नहुन न इस प्रकार के डर को भारत का नम्बर एक का दुश्मन बताया था।”

“वर्तमान स्थिति ने प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है खास तौर पर जीवित बचे स्वतंत्रता सेना नियो पर। इसीलिए हमने सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए अति विशिष्ट अधिकारों के गुणों और दोषों पर विचार करने के लिए आगामी ६ अगस्त १९७५ से सावजनिक भाषणा और जन सगठनों के जरिये प्रेस की स्वतंत्रता की परी करने का निश्चय किया है इसके लिए हमें चाहे जो परिणाम ही क्या न भुगतन पड़ें। हमारा यह सब काय करने का पीछे किसी भी तरह अनावश्यक रूप से अधिकारियों को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है।”

पल्ल लियन के तीन दिन के भीतर ही इन आठों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और २६ जुलाई को श्री बद के अतिरिक्त अन्य सभी को २६ जुलाई को अम्बाला की सप्टेंस जेल में स्थानांतरित भी कर दिया गया। इन लोगों को गिरफ्तारी मीसा की धारा ३ (I) (F) II के अंतर्गत की गई। इनमें से श्री सच्चर व वारंट पर २५ जुलाई को नई दिल्ली की ए० डी० एम० श्रीमती मीनाक्षी दत्त न २५ जुलाई को ही दक्षिण दिल्ली के ए० डी० एम० श्री पी० घोष ने श्री दत्त श्री सबकराम, श्री सिंहा श्री साहनी तथा श्री एस० डी० शर्मा के वारंटों पर और उसी दिन श्री जे० के० शर्मा के वारंट पर उत्तरी दिल्ली के ए० डी० एम० श्री एस० एल० अरोड़ा ने हस्ताक्षर किए। श्री बद के वारंट पर २६ जुलाई को मध्य दिल्ली के ए० डी० एम० श्री अशोक प्रधान ने हस्ताक्षर किए थे।

गिरफ्तारी के कारण

श्रीमती दत्त ने श्री सच्चर की गिरफ्तारी के कारणों में बताया था कि उन्होंने तथा उनके साथियों ने सरकार का विरोध करने के अपने कार्यक्रमों के बारे में जनता में प्रचार किया है तथा ६ अगस्त से इस संबंध में पूरा प्रचार प्रारम्भ किए जाने वाला है।

श्री घोष ने सब्बरी विष्णु दत्त सबकराम जे० आर० साहनी, के० व० सिंहा और श्री एस० डी० शर्मा की गिरफ्तारी के लिए भी इसी प्रकार के कारण बताए थे।

श्रीमती दत्त तथा श्री घोष के अनुसार यह आदेश जिला

मजिस्ट्रेट के इस निर्देश पर दिए गए थे कि प्रधानमन्त्री की इच्छा में यह किया जा रहा है तथा गिरफ्तारियां के पूरे आधार सी० आई० डी० अधीक्षक द्वारा बाद में प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्री अरोड़ा ने श्री जे० के० शर्मा की नजरबंदी के कारणों में वही बातें लिखी जो श्री सच्चर तथा अन्य का में लिखी गई थी। श्री अरोड़ा के भी अनुसार, उन्होंने यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के कहन पर दिए थे। उत्तरी क्षेत्र के जिसके श्री अरोड़ा ए० डी० एम० थे अधीक्षक श्री प्रकाशसिंह ने इस मामले में श्री भिण्डर (उप महानिरीक्षक रेंज) द्वारा बताया गए कारणों पर ही अपनी रिपोर्ट दी थी।

श्री प्रधान ने श्री बद की गिरफ्तारी के कारणों में लिखा था कि वह सगठन कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं तथा उन्होंने १२ फरवरी १९७५ को नजफगढ़ के मुख्य बाजार में आयोजित एक सभा में बिहार जैसा आंदोलन चलाने की बात कही थी तथा लोगों से श्री जयप्रकाश को ६ माच को होने वाली रली में भाग लेने का आह्वान किया था। श्री बद ने बाद में २४ फरवरी को नजफगढ़ में एक विशाल सभा आयोजित की, जिसे श्री जयप्रकाश ने भी सम्बोधित किया। सी० आई० डी० स्पेशल ग्राच के रिवाइडों से पता चलता है कि श्री बद ने १९६८ और १९६९ में तीन सभाओं में भाग लिया तथा उनमें पुलिस की असमता और भ्रष्टाचार तथा गांधीजी के विचार और गोवध पर अपने विचार व्यक्त किए थे।

श्री सच्चर की घमपत्नी श्रीमती ललिता सच्चर ने ६ अगस्त को जिल्ला उच्च न्यायालय में अपने पति की गिरफ्तारी का धुनौती देने हुए रिहा करने के लिए एक रिट माचिवा दायर की। न्यायालय द्वारा इसे विचाराय स्वीकार करने का नोटिस देने पर सरकार को न्यायालय में अपना पक्ष बमजार लगने लगा और उमन उह २१ अगस्त को न्यायालय का फैमला आन से पूव ही रिहा भी कर दिया।

श्री सच्चर के अनिरिक्त श्री सक्कराम को भी उसी दिन रिहा कर दिया गया। उधर श्री विष्णु दत्त की अम्बाला की जेल में हालत बिगड़ने लगी और उह १४ अगस्त १९७५ को जिल्ला का दोहा पठा। उह पहले अम्बाला के सिविल अस्पताल से जाया

गया परन्तु वहा आराम न मिलने पर चढीगढ के पी० जाई० जी० अस्पताल भेजा गया । परन्तु जब उनकी हालत म कोई सुधार होना नजर नही आया, इसपर सरकार न उह रिहा करना ही उचित समझा । उह १६ सितम्बर को रिहा किया गया ।

इन तीना "यक्तियो के अतिरिक्त शेष पांचो सबथी वै" मिहा साहनी और श्री जे० के० शर्मा तथा श्री एस० डी० शर्मा का २ अप्रैल १९७६ तक रिहा नही किया गया । यहा ध्यान दन योग्य बात यह है कि सभी आठा व्यक्तिया को एक ही आरोप म नजरबंद किया गया था परन्तु शेष पांचा को इतने महीने बाद छोडा गया । यहा एक बात का उल्लेख करना और भी आवश्यक है कि इन लोगा की गिरफ्तारी पी पुष्टि इनके रिहा होने के बाद की गई ।

रिट याचिका सुनने वाले भी स्थानांतरित

श्री एस० डी० शर्मा ने आयोग को भेजे अपने वयान म बताया कि एमरजे सी म नजरबंदी के दौरान उनपर ओ ज्यादातिया की गई उमीके कारण उनकी कोहनी की हडडी म काफी दर्द है । उनका कहना था कि उहे बिना कोई कारण बताए ही नजरबंद कर लिया गया था । जिन "यायाधीशा न रिहाई के संबंध म पेश की गई रिट याचिकाए सुनी उहे भी स्थानांतरित कर लिया गया ।

छोडने में भी भेदभाव

श्री सेवकराम न बताया कि यह कितना आश्चर्य की बात थी कि २४ जुलाई को प्रधानमन्त्री को पत्र दिया गया और २५ तारीख की राति को उह गिरफ्तार भी कर लिया गया । उनको तथा श्री सच्चर को एक महीना चार दिन तक नजरबंद रखा गया जबकि उनके अन्य साथिया को इमसे अधिक समय तक । उन्होंने कहा कि जब सभीको एक अपराध म गिरफ्तार किया गया था तो उह जल्दी क्या छोडा गया और अन्य लोगा को इतनी दर स क्या ? वह समय कितना खराब तथा शमनाक था कि देश का नाग रिक् अपन प्रधानमन्त्री तक को पत्र नही लिख सकता था । वास्तव म प्रधानमन्त्री लोगा के मन म डर बिठाकर उह उरपोके बना दना चाहती थी ।

श्री सिन्हा ने बताया कि वे १९६६ तक कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहें थे और बाद में कांग्रेस विघटन के समय से संगठन कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद सिर्फ एक मूक दशक मात्र रह गए थे। उन्होंने आवश्यक प्रवृत्त किया कि प्रधानमंत्री ने ६ अगस्त तक को इतजारी करना उचित नहीं समझा और उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह हमसे यह भी कह सकती थी कि यह काम नहीं किया जाए लेकिन वह तो विरोध सुनना ही नहीं चाहती थी।

श्री सिन्हा ने कहा कि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी पहले देशवासी है, बाद में सरकार का सेवक। देश के भविष्य के लिए जरूरी है कि वह स्वतंत्रता की रक्षा का विरोध करने वाला कोई आदेश नहीं माने। उन्होंने बताया कि तत्कालीन अटार्नी जनरल श्री निरेन डे ने उनके लड़के से, जो वकील भी है, कहा था कि यदि मैं राजनीति में भाग नहीं लू तो मुझे रिहा किया जा सकता है। ऐसी ही बात मेरी पत्नी से भी कही गई थी।

आसू ही कहानी कह सकते हैं

श्री जे० व० शर्मा ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार का उनका कोई आ पता नहीं बताया गया। उन्हें कानून से निलम्बित कर दिया गया तथा पांच छ महीना तक उनका बतन भी नहीं भेजा गया। उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार जना को जिन परेशानी का सामना करना पड़ा है, वह तो वही जानते हैं। उन्होंने कहा 'यह सब एक दटना कहानी है जिसमें हुई क्षति धारा से कहीं अधिक गहरी है। सिर्फ आसू ही हमारी कहानी कह सकते हैं शब्द नहीं।'।

उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को अम्बाला जेल में काफी परेशानी होती थी और एक बार तो वे अम्बाला के लिए बस पकड़ने समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उन्हें विस्तर पकड़ना पड़ा परंतु उमरु बाबजूद उनके पेराल के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। उनके ससुर का १६ मितम्बर को निधन हो गया तब उन्हें सिर्फ चार घंटे के लिए पराल पर रखा किया गया। एक पुलिस जवान ने उनके परिवार वाला का उनके पेराल से रिहा होने की

बात बताई और कहा कि मैं तिहाड़ जल में आ गया हूँ जबकि उस समय तक मैं अम्बाला में ही था। यह उनके परिवारजनों के साथ एक झूठ मजाक था।

गिरफ्तारी प्रधानमंत्री के निर्देश पर

इन आठों 'यनितया' की गिरफ्तारी के आदेश दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने दिए थे। उनका कहना था कि उन्होंने गिरफ्तारियों के ये आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के निर्देशों पर दिए थे। यह निर्देश उन्हें उनके अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन के जरिये मिले थे। उन्होंने इस बात से भी इकार किया कि उन्होंने श्री भिण्डर से इन सातों लोगों को हरियाणा की जेल में स्थानांतरित करने के लिए मुख्य सचिव से मिलने को कहा था। इससे पूर्व श्री भिण्डर ने बताया था कि उप राज्यपाल ने उनसे कहा था कि इन बंदियों का अम्बाला स्थानांतरित करने के संबंध में वे मुख्य सचिव से मिल लें।

दिल्ली के तत्कालीन उप-आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशीलकुमार ने श्री कृष्णचंद के वयान का समयन करते हुए बताया कि श्री धवन ने उन्हें फोन कर प्रधानमंत्री निवास बुलाया था तथा डी० आई० जी० (रेंज) श्री भिण्डर की उपस्थिति में यह आदेश दिए थे। वहां कुछ देर बाद ही श्री सत्य गांधी भी आ गए थे और श्री धवन ने यह आदेश फिर दुहराए थे। श्री धवन ने यह भी कहा था कि वे इस बात से श्री कृष्णचंद को सूचित कर रहे हैं।

आयोग द्वारा यह पूछे जान पर कि आपने मौखिक आदेशों का पालन क्या किया श्री सुशीलकुमार ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं था जब किसी मौखिक आदेश का पालन किया गया था, इससे पूर्व भी श्री कृष्णचंद ने उन्हें ६७ 'यनितया' की गिरफ्तारी के आदेश मौखिक ही दिए थे और उनका पालन किया गया था।

दूसरी ही कहानी

परंतु श्री धवन दूसरी ही बात कह रहे थे। उनका कहना था कि श्री सुशीलकुमार स्वयं प्रधानमंत्री निवास गए थे और प्रधानमंत्री से इन गिरफ्तारियों की अनुमति मांगी थी। श्री सुशील-

कुमार ने बताया था कि मलकागज पास्ट आफिस में श्री मन्वर तथा उनके साथियों का एक पत्र पकड़ा गया है, जिसमें ८ अगस्त से आंदोलन करने की बात कही गई है। श्री मुशीन कुमार ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या इन लोगों को भीमा में गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि यह एक राष्ट्र विरोधी कारवाइ है। इसपर श्रीमती गांधी ने कहा था कि "यह मामला दिन्नी प्रशासन से संबंधित है मैं इसमें दखल देना नहीं चाहती।"

मुझे फसाने के लिए

श्री धवन ने इन अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जो लोग एमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री सचिवालय तक गलत सूचनाएं देने रहें वही लोग आज आयोग के सामने स्वयं को बचाने के लिए झूठी गवाहियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय भी कुछ लोगों की यही आदत थी और आज भी वे यही कर रहे हैं।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि ये लोग आप जैसे छोटे 'जीव' को क्यों फसाना चाहते हैं श्री धवन ने कहा कि उस समय भी उनका नाम काम निकालने के लिए सबका बड़ा उपयोगी लगता था और आज भी ये लोग अपना काम निकालने के लिए उसी नाम का उपयोग कर रहे हैं।

दिन्नी के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर विशेष ब्रांच) श्री के० एम० बाजवा आयोग द्वारा बार-बार पूछे जाने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि किस आदेश के अंतर्गत विशेष लोगों के पत्रों का मँसूर करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था।

उन्होंने आयोग के समक्ष इस संबंध में दो आदेश प्रस्तुत किए। इनमें से एक की अवधि ३० जून, १९७५ को ही समाप्त हो गई थी, जबकि दूसरा ८ अगस्त को जारी किया गया था परंतु इस प्रमाणी एवं जुलाई से ही मान लिया गया था। श्री बाजवा यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें किस तरह से २४ जुलाई को ही यह मानलुम हा गया था कि ४ अगस्त को एमा आदेश जारी किए जाने वाला है और उन्होंने उसका आधार पर पहले ही कारवाई भी कर ली। श्री बाजवा बार-बार यही कहते रहे कि यह सब सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया गया। परंतु सामान्य प्रक्रिया

बात बताई और कहा कि मैं तिहाड़ जल में आ गया हूँ जबकि उस समय तब मैं अम्बाला में ही था। यह उनके परिवारजनों के साथ एक क्रूर मजाक था।

गिरफ्तारी प्रधानमंत्री के निर्देश पर

इन आठों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के आदेश दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने दिए थे। उनका कहना था कि उन्होंने गिरफ्तारियों के ये आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के निर्देशों पर दिए थे। यह निर्देश उन्हें उनसे अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० क० धवन के जरिये मिले थे। उन्होंने इस बात से भी इकार किया कि उन्होंने श्री भिण्डर न इन सानो सायो को हरियाणा को जेल में स्थानांतरित करने के लिए मुख्य सचिव से मिलने का कहा था। इससे पूर्व श्री भिण्डर न बताया था कि उप राज्यपाल ने उनसे कहा था कि इन बदिया को अम्बाला स्थानांतरित करने के संबंध में वे मुख्य सचिव से मिल लें।

दिल्ली के तत्कालीन उप-आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट था सुशीलकुमार ने श्री कृष्णचंद के वयान का समर्थन करते हुए बताया कि श्री धवन ने उन्हें फोन कर प्रधानमंत्री निवास बुलाया था तथा डी० आई० जी० (रेंज) श्री भिण्डर की उपस्थिति में यह आदेश दिए थे। वहां कुछ देर बाद ही श्री सजय गांधी भी आ गए थे और श्री धवन ने यह आदेश फिर दोहराए थे। श्री धवन ने यह भी कहा था कि वे इस बात से श्री कृष्णचंद को सूचित कर रहे हैं।

आयोग द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपने मौखिक आदेशों का पालन क्या किया श्री सुशीलकुमार ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं था जब किसी मौखिक आदेश का पालन किया गया था। उससे पूर्व भी श्री कृष्णचंद ने उन्हें ६७ व्यक्तियों की गिरफ्तारी के आदेश मौखिक ही दिए थे और उनका पालन किया गया था।

दूसरी ही कहानी

परंतु श्री धवन दूसरी ही बात कह रहे थे। उनका कहना था कि श्री सुशीलकुमार स्वयं प्रधानमंत्री निवास गए थे और प्रधानमंत्री से इन गिरफ्तारियों की अनुमति मांगी थी। श्री सुशील-

कुमार ने बताया था कि मलकागज पोस्ट आफिस में श्री सच्चर तथा उनके साथियों का एक पत्र पकड़ा गया है जिसमें ६ अगस्त से आंदोलन करने की बात कही गई है। श्री सुशील कुमार ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या इन लोगों को भीसा में गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि यह एक राष्ट्र विरोधी कारवाही है। इसपर श्रीमती गांधी ने कहा था कि 'यह मामला दिल्ली प्रशासन से संबंधित है, मैं इसमें दखल देना नहीं चाहती।'

मुझे फसाने के लिए

श्री धवन ने इन अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जो लोग एमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री सचिवालय तक गनत सूचनाएं देते रहे हैं, वही लोग आज आपाग के सामने स्वयं को बचाने के लिए झूठी गवाहिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय भी कुछ लोगों की यही आदत थी और आज भी वे यही कर रहे हैं।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि 'ये लोग आप जैसे छोटे जीव' को क्यों फसाना चाहते हैं, श्री धवन ने कहा कि उस समय भी उनका नाम काम निवाहन के लिए सबका बड़ा उपयोगी लगता था और आज भी ये लोग अपना काम निवाहन के लिए उसी नाम का उपयोग कर रहे हैं।

श्रीमती के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर विशेष द्वाच) श्री के० एम० बाजवा आयोग द्वारा बार-बार पूछे जाने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि किस आदेश के अंतर्गत विशेष लोगों के पत्रों का सेंसर करने के लिए अधिकारियों का नियुक्त किया गया था।

उन्होंने आयोग के समक्ष इस सबब में दो आदेश प्रस्तुत किए। इनमें से एक की अवधि ३० जून, १९७५ को ही समाप्त हो गई थी, जबकि दूसरा ४ अगस्त को जारी किया गया था, परंतु इसे प्रभावी एवं जुलाई से ही मान लिया गया था। श्री बाजवा यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें किस तरह से २६ जुलाई को ही यह मालूम हुआ गया था कि ४ अगस्त को ऐसा आदेश जारी किए जाने वाला है और उन्होंने उसके आधार पर पहले ही कारवाही भी कर ली। श्री बाजवा बार-बार यही कहते रहे कि यह सब सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया गया। परंतु सामान्य प्रक्रिया

क्या थी व इस स्पष्ट नहीं कर सके ।

वाद में सर्वोष्ठम आफ पीपुल्स आफ सासायटी व एक सदस्य श्री आय भूषण भारद्वाज न आयोग के समक्ष वह पत्र पेश कर सनसनी फना दी, जिसपर प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा २४ जुलाई के पत्र पर उम तारीख की प्राप्ति रसीद दी गई थी । रसीद वाकई पुरानी लगती थी क्योंकि उसपर लघु आलपीन में अंग लग गया था और वह कागज पर भी फन गया था । आयोग के वकील श्री काल खडालावाला न पत्र का ध्यान से देखन के बाद यह कहकर और भी सनसनी फना दी कि इस पत्र पर प्राप्ति-तारीख २४ जुलाई से काटकर २८ जुलाई करने की चेष्टा की गई है ।

बाद में प्रधानमंत्री सचिवालय में निजी सहायक श्री एम० एम० शर्मा न भी इस रसीद की पुष्टि करत हुए कहा कि इसपर उनके ही हस्ताक्षर हैं तथा इसपर प्राप्ति-तारीख को २४ जुलाई से काटकर २८ जुलाई १९७५ करने की चेष्टा की गई है ।

दूसरी कहानी बाद में गढी गई

आयोग के वकील श्री खडालावाला का कहना था कि इस रसीद से मिट्ट हा जाता है कि श्री सच्चर तथा उनके साथियों की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री का भेजे गए पत्र के आधार पर की गई न कि पकड़े गए पत्र के आधार पर । उनका कहना था कि पकड़ा गया पत्र तो मिफ एक कहानी थी जिसे प्रधानमंत्री का बचाने के लिए बाद में गना गया ।

(५) राजमहलों से कैदखाने तक

आजादी से पहले दश के भूतपूर्व रजवाडों की शान शौकत अब इतिहास की बात रह गई है । शान शौकत के साथ-साथ राज प्राप्त करने के लिए युद्ध और फिर राजा महाराजाओं का जल में डाल देन के किस्से भी अब उसी इतिहास का एक अंग बन गए हैं ।

दश की आजादी के बाद इन भूतपूर्व रजवाडों को मिनाकर भारत गतनत्र की स्थापना हुई । विलय के एवज में इन राजा महाराजाओं को जेब-खर्च दिया जान गया और कुछ विशेषाधिकार भी जिनमें यह भी था कि उन्हें किसी आरोप में बिना राष्ट्रपति

की अनुमति व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। परन्तु कुछ वर्षों बाद सस" एव बिल क जरिये इन राजा महाराजाजी के व जब खच और विशेषाधिकार समाप्त कर लिए गए।

जाजाजी के बाद दश की प्रमुख रियासतों के राजा महाराजा राजनीति में आ गए और उनमें से कई लोकसभा और राज्यसभा में जरिये सस" में अपनी भूतपूर्व प्रजा का निधित्व करने लग। इही रजवाड़ा में सदा प्रमुख जयपुर और ग्वालियर विरोधी दला की ओर से उभरकर आई—जयपुर के महाराजा मानसिंह की दूसरी महारानी श्रीमती गायत्रीदेवी और ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजयराने सिधिया।

जयपुर के भूतपूर्व महाराजा मानसिंह का देश के आजाद हान के बाद ऐसे पहले महाराजा थे, जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी रियासत को भारत में विलय करने की इच्छा प्रकट की थी। स्वर्गीय मानसिंह पोना के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाडी थे तथा उन्हें १९६३ में स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। २४ जून १९७० को इंग्लैंड में पोली सेलत हुए उनका निधन हो गया था।

श्रीमती गायत्रीदेवी जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से १९६२ १९६७ और १९७२ के चुनावों में स्वतंत्र पार्टी की ओर से चुनकर आती रही थीं और इसी तरह ग्वालियर की श्रीमती विजयराने सिधिया ग्वालियर स जनसभा के उम्मीदवार के रूप में।

परन्तु समय क्या रंग दिखा दे, कोई नहीं जानता। देश में जून, १९७५ में एमरजेन्सी लागू की गई और ३० जुलाई को जयपुर की राजमाता गायत्रीदेवी और उनके बड़े पुत्र (सोतेले) ले० बनल भवानीसिंह को निदेशी मुग़ा संरक्षण और तस्करों की विधि निवारण अधिनियम (कोफ़ेपोसा) के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के आदेश तत्कालीन वकिल एवं राजस्वमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी ने दिए थे यद्यपि इन लोगों के विरुद्ध जांच के बाद भी तस्करों का कोई भागला नहीं बन पाया था। इसके अनिश्चित प्रवर्तन निदेशालय अथवा राजस्व गुप्तचरी और जांच महानिदेशालय की ओर से भी उन्हें नज़रबंद करने का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था।

ले० बनल भवानीसिंह जो जयपुर के महाराजा मानसिंह के

चार पुत्रों में सबसे बड़े थे, १९७४ तक सेना में पूणकालिक सेवा में थे तथा नवम्बर १९७४ में व्यक्तिगत कारणों से सेना से रिटायर हो गए थे। १९७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम के लिए सरकार की ओर से उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया था।

श्रीमती गायत्रीदेवी न सिर्फ संसद सदस्य ही थी, बल्कि रेड क्रॉस तथा अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक संगठनों से भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध थी। वे विश्व वन्य जीव जन्तु काय से भी सम्बद्ध रहो तथा अपनी गिरफ्तारी के समय तो संसद सदस्य के रूप में कार्य कर ही रही थी।

आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा १३२ के अंतर्गत जयपुर तथा दिल्ली में ११ फरवरी, १९७५ को श्रीमती गायत्री देवी, श्री भवानीसिंह और उनके भाई श्री जयसिंह, श्री पृथ्वीसिंह तथा अन्य लोगों के विरुद्ध तलाशी की कारवाइया की गई। इन तलाशियों के दौरान कुछ विदेशी मुद्रा अमेरिकी डालर ट्रेवलर्स चेक जब्त किए गए। रोम स्थित श्री भवानीसिंह के एक साकर की खाती भी बरामद की गई। बाद में पूछताछ के दौरान श्री भवानीसिंह ने स्वीकार किया कि उनका इंग्लैंड में भी एक मकान है जिसका प्रबंध एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

इन दाना व्यक्तियों के यहां जयपुर तथा दिल्ली में मारे गए छात्रों की सूचना मिलते ही संसद में प्रश्नांतर किए गए। बहुसंख्यक के दौरान दो तीन सदस्यों द्वारा इन लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग की गई।

राज्यमंत्रि मंत्र २५ फरवरी १९७५ को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि प्रश्न किसीको गिरफ्तार करने का नहीं है प्रश्न है तथ्य मालूम करने का, और इसमें समय लगगा। पहले यह पता लगाया जाएगा कि कोई गलत काम हुआ है या नहीं। इसलिए उन्हें गिरफ्तार किए जाने संबंधी मुद्दा जिम्मेदारपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

आयकर विभाग द्वारा श्रीमती गायत्रीदेवी के जयपुर स्थित मोती झूगरी महल पर मारे गए छात्रों में निम्नलिखित तथ्य सामने आए

श्रीमती गायत्रीदेवी के नाम से एक स्विस बैंक क्रेडिट कार्ड
१३२

मिला, जिससे यह सबैत मिलता था कि उनका या तो वहाँ कोई बक खाता है अथवा फिर उनका किसी बैंक से लेन देन है।

छापे के दौरान १६ ब्रिटिश पाँड, १० स्वीस फ्रक तथा ५० पनी के दो सिक्के मिले। इसके अतिरिक्त २०० डालर का एक ट्रेडलर बक भी मिला।

ले० कनल भवानीसिंह के दिल्ली स्थित निवास पर मारे गए छाप से मालूम पड़ा कि भूतपूर्व स्वर्गीय महाराजा श्री मानसिंह द्वारा इंग्लंड में तीन ट्रस्ट बनाए गए थे जिनकी आय श्री मानसिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती गायत्रीदेवी तथा उनके पुत्रों को देने की बात थी।

इन ट्रस्टों से होने वाली आय के बारे में यहाँ रिजर्व बैंक आफ इंडिया को सूचित नहीं किया गया था। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा आयकर विभाग को एक पत्र लिखकर सूचित किया गया कि ले० कनल भवानीसिंह तथा श्रीमती गायत्रीदेवी ने रिजर्व बैंक से म्यूचुअल के चार्ज में हेटन बैंक तथा स्विट्जरलैंड के सोसायटी डी बैंक में अपने खाते रखने के बारे में अनुमति नहीं मांगी है।

इनके अतिरिक्त श्री भवानीसिंह के निवास से में हेटन बैंक की एक बैंकबुक, २२० अमेरिकी डालर के ट्रेवलिंग चैक, ७६ पाँड दो हजार इटेलियन लीरा ३० स्विस फ्रैंक तथा १२० अमेरिकी डालर नकद मिले। इन सबके अतिरिक्त रोम के एक बैंक के साकर की चाबी भी बरामद हुई।

विदेशों में चिन्ता

श्रीमती गायत्रीदेवी की गिरफ्तारी ने विदेशों में भी पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के पास किंग्सविले, टेक्सास की श्रीमती केशरिन लॉकिस तथा श्रीमती पटेरा लॉकिस का एक नेबन आया जो इस प्रकार था

श्रीमती गायत्रीदेवी की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में ढालने की घटना भारत सरकार के लिए इतनी दुर्भाग्यपूर्ण, भयंकर रूप से बदनामी भरी और घातक होगी जिसकी प्रतिश्रिया विश्व भर में सुनी जाएगी। इससे किसीका भला नहीं होने वाला है। उनको (गायत्रीदेवी) जानने वाले सभी क्रोधित और दुखी हैं। कृपया मेरी ओर से इस महिला की रिहाई के लिए प्रार्थना करें और यदि

आवश्यक हो तो उस मेरे सरक्षण में छोड़ दें।

राजदूत ने इस प्रकार के आपन पर जवाब देने के लिए सरकार से इस मामले की पृष्ठभूमि चाही। इसपर प्रधानमंत्री के सचिव श्री पी० एन० धर ने टिप्पणी लिखी

प्रधानमंत्री भी इसे देखना चाहेंगे। मैं नहीं जानता कि श्रीमती लालिन कौन है परंतु मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता जिसके कारण राजदूत को इस प्रकार के सुझाव का जवाब देने की आवश्यकता है।

जब यह फाइल श्रीमती गांधी के पास गई तो उन्होंने लिखा

परंतु राजदूत को निश्चित रूप से अपनी स्वयं की सूचना के लिए यह जानकारी होनी चाहिए। यह कोई राजनीतिक गिर पतारी नहीं है।”

इन दोनों व्यक्तियों द्वारा कई बार अपनी नजरबंदी को समाप्त करने के लिए आपन दिए गए परंतु श्री मुखर्जी ने उस स्वीकार नहीं किया। परंतु इन दोनों द्वारा की गई परोल की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। श्री भवानोसिंह को १ नवम्बर १९७५ को और श्रीमती गायत्रीदेवी को ६ जनवरी, १९७६ को परोल पर रिहा करने के आदेश दिए गए।

श्रीमती गायत्रीदेवी को परोल पर रिहा करने से पूर्व उनसे एक पत्र पर ११ सितंबर १९७५ को हस्ताक्षर कराए गए, जिसमें श्रीमती गांधी को संबोधित कर लिखा गया था कि—

पत्र पर रिहाई

माननीया अन्तर्राष्ट्रीय महिला दंपति समाप्त होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं व्यक्तिगत रूप से तथा आपके द्वारा देश के हित और अच्छाई के लिए किए जा रहे योगदान का समर्थन करने का विश्वास दिनाती हूँ। मैं यह और कहना चाहूँगी कि मैंने राजाजी के निधन के बाद ही राजनीति से संन्यास लेने का निश्चय कर लिया तथा आगे भी राजनीति में कोई भाग नहीं लूँगी। वैसे भी स्वतंत्र पार्टी समाप्त हो चुकी है। मैंने भविष्य में भी किसी राजनीतिक दल में प्रवेश न करने का निश्चय किया है।

‘मैंने ऊपर जो कुछ कहा है उसको देखते हुए तथा उपनयन कराई गई चिकित्सा-मुविद्या के बावजूद मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है मैं

आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे रिहा करन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। यदि आप कोई शर्त लगाना चाहती हैं तो मैं उनका पालन करूँगी।'

बाद में १६ मार्च, १९७७ को पुनरीक्षण कमेटी की निफारिशा पर विचार करते हुए श्री मुखर्जी ने श्री भवानीसिंह को रिहाई के आदेश देने हुए लिखा

प्रारम्भ में ले० कनन भवानीसिंह को रिहा किया जा सकता है तथा उनकी गतिविधियों पर पूरी निगाह रखी जाए। श्रीमती गायत्रीदेवी के मामले पर कुछ समय बाद निणय किया जाएगा।'

श्रीमती गायत्रीदेवी को पेरों पर रिहा करन से पूर्व उनसे यह आश्वासन ले लिया गया था कि वे निल्ली उच्च न्यायालय में उनके द्वारा 'कोफेपोसा' के अंतर्गत अपनी गिरफ्तारी व विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका वापस ले लेंगी।

श्रीमती गायत्रीदेवी को गिरफ्तारी व शुरू के पाँच महीनों में जेल के बरक में सी बत्तास में रखा गया था। पाम में ही दंडित अपराधियों के लिए दो सल थ जिनमें से एक में ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजयराजे सिंधिया को रखा गया था। सभी के सेल में एक शौचालय था जिसका उपयोग दोनों भूतपूर्व महिला रानिया करती थीं। बरक के सेल में महिला कनियों को रखा गया था, जो हत्मा जैसे जघन्य अपराध से लेकर अनैतिक आचरण निवारण संबंधी कानून के अंतर्गत तक गिरफ्तार की गई थी। दिन के समय ये सभी श्रीमती गायत्रीदेवी के कमरे तक घूम फिर सकती थी।

गिरफ्तारी, राजनीतिक बदले से

दोना राजमाताओं ने आयोग को लिए बयानों में आरोप लगाया कि उनसे विरुद्ध कारवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई थी। उनका कहना था कि निल्ली की तिहाड़ जेल में उन्हें महीना अथवा दो महीने विरोधपूर्ण स्थिति में रखा गया। उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद उनका साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आयोग के कक्ष में उपस्थित लोग शोक और दुःख से नतमस्तक उनकी व्यथापूर्ण कहानी सुनते रहे। 'शेम शेम' की आवाज़ों के बीच उन्होंने बताया कि उन्हें जेल में पागला तथा कठोर अपरा

धिया और हत्यारा के साथ रखा गया।

श्रीमती गायत्रीदेवी ने बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधान-मन्त्री श्रीमती गांधी, वित्तमन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम तथा बैंकिंग और राजस्वमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी का अनेक नापन भेजे, परन्तु उनका कोई जवाब तक नहीं दिया गया।

उन्होंने बताया कि जेल में न तो पछा था और न ही सफाई की कोई विशेष व्यवस्था। लोग खुले में उनके सेल के सामने मल त्याग किया करते थे। जेल की चिकित्सा व्यवस्था इतनी खराब थी कि एक कदी को तो शौचालय में बच्चा हुआ। कदियों का अस्पताल अतिम बर्ही में ही भेजा जाता था। श्रीमती गायत्रीदेवी ने बताया कि एक महिला तो हमेशा नगी रहती थी तथा जिनमें भुन भुन किया करती थी और लोगों पर पत्थर फेंका करती थी।

उन्होंने बताया कि लगभग साठे पाँच महीने के दौरान उनका वजन दस किलो घट गया था लेकिन पेट्रोल पर छोड़े जाने के लिए उनके सामने शर्तें रखी गई थी कि वे उच्च न्यायालय में दायर उम रिट याचिका को वापस लें, जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में दायर कर रखी थी। उनसे यह भी कहा गया था कि वे श्रीमती गांधी के प्रतिशोध कायन्त्रमा का समर्थन करते हुए राजनीति से त्याग लेने-सम्बन्धी पत्र लिखें। यद्यपि वह इसे तीन सप्ताह तक टालती रहीं लेकिन बाद में अपने पुत्र जयसिंह के कहने पर इस प्रकार के पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और उसके पश्चात् ही उन्हें पेट्रोल पर छोड़ा गया।

उन्होंने बताया कि पेट्रोल पर छूटने के बाद की स्थिति और भी खराब थी। जिन परिचिता से मिलना चाहती थी उनसे मिल नहीं सकती थी। हर दूसरे महीने पेट्रोल के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी और हजारों रुपये का बाड भरना पड़ता था।

श्रीमती गायत्रीदेवी का कहना था कि उन्हें जेल में रखने का सात्पय केवल राजनीतिक बदला था क्योंकि पिछले चुनावों में वे काफी बोटों से विजय होती आई थी और आगामी चुनाव में भी सफलता मिलने की पूरी सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई मामला नहीं बन रहा था जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। पिछले एक वर्ष से उनकी सम्पत्ति का मामला चला आ रहा था और उसपर सरकार का कोई फसला नहीं हुआ

सुबह की शुरुआत गालियों से

रवानियर की राजमाता श्रीमती सिंधिया ने बताया कि तिहाड़ जेल के जिन कमरे में उन्हें तथा श्रीमती गायत्रीदेवी का रखा गया था, वहां दिन रात दुगंध जाती रहती थी। भयंकर अपराधों में सजा काट रही जिन महिलाओं के साथ उन्हें रखा गया था व सुबह की शुरुआत ही गालियों के उच्चारणों से करती थीं और जेल की हासत भी बड़ी खराब थी। वहां न तो शौचालय ही था और न ही स्नानघर का प्रबंध।

उन्होंने बताया कि जेल में महिलाओं के साथ जेल के अधिकारी बड़ा ही रूखा व्यवहार किया करते थे। श्रीमती सिंधिया का कहना था कि उन्हें गिरफ्तारी के शुरू के दिनों में पचमढी के एक बगले में रखा गया और उसके बाद तिहाड़ जेल लाया गया। उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बदला इतना विकट होगा।

"मुझे गिरफ्तार करने के अतिरिक्त पुणे दिल्ली और ग्वालियर स्थित मकानों पर छापा मारा गया और तलाशी के नाम पर वहां की बेसकीमती और पुरानी चीजों को तोड़ फोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त मरी पुत्रियों और कमचारियों को काफी परेशान किया गया। किसी भी सभ्य देश में नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता यह सब और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक बर्ताव था।'

कारवाई मुखर्जी के निर्देश पर

राजस्व गुप्तचरी एवं जाच विभाग के तत्कालीन महानिदेशक श्री जी० ए० साहनी ने बताया कि २४ जुलाई १९७५ को श्री मुखर्जी के बमरे ॥ त्रिना पूव सूचना के आयोजित एक बैठक में श्रीमती गायत्रीदेवी और से० वनस भवानीसिंह को 'कोफेपोसा' के अधीन नजरबंद किए जाने पर विचार हुआ था। उनके छयाल से इस मामले में काफी तेजी बरती जा रही थी।

उनका कहा था कि आयकर विभाग द्वारा श्रीमती गायत्रीदेवी के जयपुर स्थित निवास मांती दूरी महल पर मारे गए छापा में जो दस्तावेज तथा मान जन्त किए गए थे, उसमें उनपर सम्बन्धी

का मामला नहीं बनता था। उन्होंने इस बात से श्री मुखर्जी को अवगत करा दिया था कि श्रीमती गायत्रीदेवी और श्री भवानीसिंह पर सिर्फ विदेशी मुद्रा से सबधित ही मामला बन सकता है।

श्री साहनी के अनुसार यद्यपि ज्ञान की गई किन्ती मुद्रा की मात्रा अधिक नहीं थी परन्तु विदेशों में स्थापित तीन 'यासो' से होने वाली आय के बारे में रिजर्व बैंक का सूचित किया जाना जरूरी था। श्रीमती गायत्रीदेवी ने इस सबध में रिजर्व बैंक की अनुमति नहीं ली थी और इसी आधार पर कोर्पोरेट के अतगत मामला बनाया गया।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछा जाने पर कि जब श्री भवानीसिंह की पेट्रोल पर रिहाई कर दी गई थी तब किस आधार पर श्रीमती गायत्री को पेट्रोल पर रिहाई की अनुमति नहीं दी गई प्रवक्तन निदेशक श्री एस० बी० जैन ने कहा कि 'यासो' का सबध श्रीमती गायत्री से था और इसीलिए उन्हें रिहा न करने का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि नियमानुसार विदेशों में स्थित 'यासो' से होने वाली आय के बारे में रिजर्व बैंक को ३० दिन के भीतर सूचना दे दी जानी चाहिए परन्तु श्रीमती गायत्रीदेवी ने ऐसा नहीं किया था।

मुखर्जी की यापसो

तत्कालीन वर्ग तथा राजस्वमन्त्री श्री मुखर्जी भी इस मामले के सबध में जायोग के समक्ष उपस्थित हुए थे परन्तु ज्यादा उहाने अपना बयान पटना प्रारम्भ किया वहां उपस्थित लोगों ने जोरा से 'शेम शेम' के गारे लगाए और कुछ लोगों ने तो उह 'चमचा' तक कहा।

इसपर श्री मुखर्जी यह कहकर जायोग से उठकर चले गए कि गवाहियों की सावजनिक मुनवाई से मेरी इज्जत को गम्भीर हानि हो सकती है।

जस्टिस शाह ने इसपर कहा जायोग के साथ सहयोग करने के लिए आपपर कोई प्रतिबध नहीं है। यदि आप मेरे साथ सहयोग नहीं करना चाहते तो यह ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए मैं चिन्तित हूँ।

बाद में इस मामले पर जिरह के बाद सरकारी वकील श्री प्राण-

नाथ लेखी और आयोग के वकील श्री काल पडालावाला ने कहा कि यह समस्त काय श्रीमती गांधी के निर्देशानुसार हुआ था। श्रीमती गायत्रीदेवी और से० बनल भवानीसिंह की गिरफ्तारी का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक था क्योंकि उन्हें जिन ट्रस्टों के मामलों में गिरफ्तार किया गया था उनके बारे में पहले ही उन्हें अगस्त तक जवाब देने को कह दिया गया था, परंतु सरकार द्वारा अगस्त तक इंतजार किए बिना ही गिरफ्तार करना इनके पीछे छुपी इच्छा को साफ जाहिर करता है। उनका कहना था कि दोनों की गिरफ्तारी का मामला पड़ताल कमेटी (स्त्रनिंग कमेटी) के समक्ष न रखने से भी यही इच्छा चलवती है।

(११) नजरबंदिया कुछ गैर-राजनीतिकों की

एमरजेन्सी के दौरान राजनीतिक बंदियों की मीसा में गिरफ्तारों के अतिरिक्त जिन गैर राजनीतिक व्यक्तियों की नजर बंदी की गई उनमें से कुछ इस प्रकार हैं प्रसिद्ध पत्रकार श्री कुलदीप नायर एक अन्य पत्रकार श्री बीरेंद्र कपूर प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री गुरुदत्त, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र श्री प्रवीर पुरवायस्थ एक व्यवसायी श्री कुन्दलाल जंगी तथा डा० बदंगेश शुक्ल। इन लोगों के अतिरिक्त अखबार बेचने वाले एक हाकर मामूली चोर भी नहीं बचता था।

(१) कुलदीप नायर

श्री नायर को २५ जुलाई १९७५ को सबरछ बजे इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उनकी कार्यवाहियां स देश में शांति और व्यवस्था को खतरा है। इसके अतिरिक्त उनपर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने संगठन कांग्रेस तथा श्री जयप्रकाश के नेतृत्व वाले गैर कम्युनिस्ट विरोधी मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक में गैर पत्रकार के रूप में भाग लिया तथा उन्हें प्रेस के खरिय पूरा प्रचार दिलाने का आश्वासन दिया। श्री नायर पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जामा मस्जिद के इमाम सय्यद बुखारी से मिनकर ६ मार्च को वोट बनव कर आयोजित की जाने वाली विरोधी मोर्चे की रली में अधिक से अधिक सभ्यता में

मुसलमान स्वयंसेवका को भजने की बात कही थी ।

गिरफ्तारी, सेंसरशिप का विरोध करने पर

जहां सरकार की ओर से उनकी गिरफ्तारी के लिए यह आरोप लगाए गए, वही श्री नायर का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी का एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने समाचारपत्रों पर लगाई गई सेंसरशिप का विरोध किया था तथा उसके लिए एक बार प्रेस क्लब में और दूसरी बार प्रेस परिषद में एक प्रस्ताव पारित कराने की चेष्टा की थी । इसके अतिरिक्त उन्होंने सेंसरशिप के विरोध में श्रीमती इंदिरा गांधी को भी एक पत्र लिखा था जिसके कारण वह भीसा में गिरफ्तार कर लिया गया ।

जब शुक्ल रोए

श्री नायर का कहना था कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने प्रेस क्लब वाले प्रस्ताव में बार में उनसे पूछताछ की थी । श्री शुक्ल से उनकी काफी निकटता रही थी तथा उनको वह अवसर अब भी याद है जब वे रक्षा उत्पादन मंत्रालय छिन्ने पर उनके पास आए थे और उनके कंधे पर सिर रखकर रोए थे । श्री शुक्ल ने प्रेस क्लब वाले प्रस्ताव के बारे में उनसे कहा था 'कुलदीप ! वह प्रेम पत्र कहा है ?'

उन्होंने पूछा, कौन-सा प्रेम पत्र ?

श्री शुक्ल बोले, 'वही जिसपर ११७ पत्रकारों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं । मैं उन पत्रकारों के नाम जानना चाहता । क्योंकि मुझे उन्हें गिरफ्तार करने को कहा गया है ।' परन्तु उन्होंने वह प्रस्ताव उन्हें दिखाया नहीं ।

श्री नायर की गिरफ्तारी के सबब में दक्षिण दिल्ली के ए० डी० एम० श्री पी० घोष का कहना था कि उन्होंने जिना मजिस्ट्रेट श्री सुशीलकुमार के कहने पर भीसा वारंट पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि दूसरी ओर श्री सुशीलकुमार का कहना था कि उन्होंने तत्कालीन उप राज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन चावला के कहने पर श्री घोष को ऐसे निर्देश दिए थे और श्री चावला का कहना था कि उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री के निवास से मिले निर्देशों के अनुसार किया था ।

इन सब बातों से देखकर श्री कृष्णचंद का कहना था कि 'उन्हें तो श्री नायर की गिरफ्तारी न बरे में मालूम ही दूसरे दिन पड़ा था, जबकि वे दिल्ली के मुखिया कहे जाते थे।'

श्री नायर की गिरफ्तारी के विरोध में बाद में उनकी पत्नी श्रीमती भारती नायर न दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद याचिका पर निम्न १५ सितम्बर, १९७५ तक के लिए सुरक्षित रखा गया और इसी बीच सरकार द्वारा ११ सितम्बर १९७५ को श्री नायर को रिहा करके मौसा आदेश रद्द करने के आदेश भी दे दिए गए।

(11) श्री बीरेन्द्र कपूर

एक अन्य पत्रकार दिल्ली के फाइसियल एक्स्प्रेस ने सवाद दाता श्री बीरेन्द्र कपूर को १ नवम्बर १९७५ को लालकिले में आयोजित एक समारोह की रिपोर्टिंग के समय गिरफ्तार कर लिया गया। यह समारोह उन दिनों दिल्ली में आए राष्ट्र मंडलीय प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में लालकिले के दीवाने आम में आयोजित किया गया था। उक्त समारोह में अचानक ही कुछ छात्रों ने नारा-बाजी करना और पच्चे फेंकना प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच उन दिनों युवक कांग्रेस की महासचिव श्रीमती अम्बिका सोनी ने एक छात्र को पकड़ लिया तथा उनके दो साथियों ने उसकी मरम्मत प्रारम्भ कर दी। श्री कपूर द्वारा श्रीमती सोनी को ऐसा करने में रोकने पर पुलिस वाला ने श्री कपूर को गिरफ्तार कर लिया।

रिहाई मौसा में नजरबंदी के लिए

श्री कपूर को बाद में ६ नवम्बर को जमानत पर रिहा कर दिया गया और बाद में फिर १७ नवम्बर को मौसा में नजरबंद कर लिया गया। लगभग एक वर्ष बाद पांच नवम्बर १९७६ को मौसा आदेश रद्द किए गए। इस बीच उन्हें २६ जुलाई १९७६ को पेरों पर रिहा कर लिया गया था।

इन सारे कांडों के बारे में श्रीमती सोनी का कहना था कि यह सब कुछ गलतफहमी के कारण हुआ। पुलिस वाला ने जाने क्या सोचकर श्री कपूर को गिरफ्तार किया था, जबकि उन्होंने

स्वयं श्री सजय गांधी तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० मिण्डर से मिलकर कहा था कि श्री कपूर को बेकार न ही गिरफ्तार किया गया है। वे स्वयं इस मामले में श्री कपूर से मिलकर अपना अपमोक्ष प्रकट करना चाहती थी परन्तु श्री कपूर न मिलना उचित नहीं समझा था। उह इस बात का भी कोई जानकारी नहीं थी कि श्री कपूर को एक बार रिहा करने का वाद में फिर भीसा में नजरबंद कर लिया गया था। उह वाद में लोकसभा चुनाव के बाद एक दिन ससद सदस्य श्री सुब्रह्मण्य स्वामी ने बताया था कि उनका साझा श्री कपूर की गिरफ्तारी मेरे कारण हुई थी। उसमें पहले उन्हें यह भी पता नहीं था कि श्री कपूर श्री स्वामी के रिश्तेदार हैं।

जबकि दूगरी जोर दिल्ली प्रशासन का कहना था कि श्री कपूर का श्रीमती सोनी से हुई तकरार के कारण नहीं बल्कि उनके जनसम तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से निकट के संबंध होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री कपूर के रिहाई के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद दिल्ली प्रशासन ने उह रिहा करना स्वीकार नहीं किया था।

(iii) बच्चू गुरुदत्त

गुरु राजनाथिक व्यक्तियों की भीसा में गिरफ्तारी का एक महत्वपूर्ण मामला प्रसिद्ध उपन्यासकार ८२ वर्षीय श्री गुरुदत्त का है जिन्हें २२ नवम्बर १९७६ को रात्रि के दस बजे गिरफ्तार किया गया। उनपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने २२ नवम्बर की ही रात्रि को दस बजे गली के बाहर एक जलस में लोगों को भड़काया था जबकि उनके अनुसार उस दिन कोई जलसा हुआ ही नहीं था।

तीस हजारी अदालत में संबंधित मजिस्ट्रेट ने स्वयं आश्चर्य चकित होकर पूछा था कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है वह किस प्रकार से लोगों का भड़काएगा। इसपर पुलिस को जोर से कोई जवाब नहीं दिया गया तथा सिर्फ इतना कहा गया कि उह ऐसा करने के आदेश दिए गए थे।

पंजाबी बाग दिल्ली के जिस इलाके में श्री गुरुदत्त रहा करते थे तत्कालीन ए० डी० एम० श्री ए० के० पटण्डी का कहना था

कि उन्होंने श्री गुरुदत्त की गिरफ्तारी का विरोध किया था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के कारण मजबूरन मानना पड़ा। इस बार में उस समय के जिला मजिस्ट्रेट श्री बी० के० गोस्वामी ने बताया कि श्री पटवर्दी ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया था, परन्तु बलाचार थे, क्योंकि उस राज्यपाल ने कहा था कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

२२ नवम्बर का गिरफ्तार करने के बाद श्री गुरुदत्त को ३० नवम्बर तक के लिए पुलिस रिमांड में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हम बीच उह २५ नवम्बर का भीसा में बनी वनान का आदेश समा दिया गया और ३ नवम्बर को रिहा भी कर दिया गया।

व्यक्तिगत ईर्ष्या

आयाग के वकील श्री खडालावाला ने गुरुदत्त की गिरफ्तारी को 'तुच्छ' व्यक्तिगत ईर्ष्या का परिणाम बताया जो किसीको प्रसन्न करने के लिए की गई थी।

(iv) श्री प्रवीर पुरकायस्थ

इसी प्रकार की गिरफ्तारियों में एक नाम है—जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र श्री प्रवीर पुरकायस्थ का, जिन्हें २५ अगस्त १९७५ को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वे अपने कुछ साथियों के साथ विश्वविद्यालय के भाषा विभाग के बाह्य लॉन में बैठे थे। इससे पहले दिन सयानी २४ तारीख से तीन दिन के लिए कक्षाओं के बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा था और उसीके अनुसार कक्षाओं में कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी।

श्री पुरकायस्थ की गिरफ्तारी का मुख्य कारण यह बताया गया कि उन्हें गलतफहमी का शिकार होना पड़ा। पुलिस वास्तव में गिरफ्तार करना चाहती थी विश्वविद्यालय यूनियन के अध्यक्ष श्री देवीप्रसाद त्रिपाठी का परन्तु उनकी एक्जाम गिरफ्तार कर लिया गया श्री पुरकायस्थ को। इस बार में श्री पुरकायस्थ का कहना था कि हम मटना के पटन श्रीमती मेनरा गांधी को, जो विश्वविद्यालय में जमान भाषा पढ़ने आती थी, कक्षा में जाने से कुछ छात्रों ने रोका था और इस बारे में हो सकता है, श्री मेनरा ने श्री मजय गांधी को कहा था। परन्तु उह यह जानकारी नहीं थी कि श्रीमती

या कि श्री करणेश को तुरंत मौसा में गिरफ्तार कर लिया जाए। इस सबध में जाणस भेजे जा रहे हैं।

श्री अशाक प्रधान का कहना था कि दिल्ली के उप-आयुक्त श्री बी० वं० गास्वामी ने उनमें बातचीत के दौरान कहा था कि उप राज्यपाल चाहते हैं कि श्री करणेश शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि उन्होंने उप राज्यपाल को दिए पापन में गलत तथ्य बताए।

श्री वाचवा ने स्वीकार किया कि उनके पास श्री करणेश के सबध में कोई सूचना नहीं थी परंतु जमाकि उप राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने तथ्या को गहन तरीके से प्रस्तुत किया है गिरफ्तारी के आदेश लिए गए।

बाद में उप राज्यपाल ने २८ सितम्बर, १९७६ को श्री करणेश की मजरबती के आदेशों की पुष्टि की और ६ फरवरी, १९७७ को उन्हें रिहा कर दिया गया।

भिण्डर की भी मजदूरी

दिल्ली के तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (रैंज) श्री भिण्डर ने न अग्रस की कायवाही में आयोग के सामने अपना पक्ष रखने में असमर्थता प्रकट की। उनका कहना था कि जहां एक ओर प्रत्येक सरकारी अधिकारी को उस विभाग द्वारा अपने बचाव के लिए कानूनी मदद दी जा रही है वहां उच्च न्यायालय सरकार ही कोई मदद दे रही है और न ही हरियाणा सरकार जहां से वे डेपूटेशन पर दिल्ली आए थे। ऐसी स्थिति में वे बिना किसी कानूनी मदद के अपना पक्ष ठीक तरह पक्ष नहीं कर सकते।

श्री भिण्डर का यह भी कहना था कि वे इस समय एक अन्य मुकदमे में (मुंदर डाकू-हत्याकांड के मामले में जिसमें वे मुख्य अभियुक्त हैं) फस हुए हैं तथा उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है इस कारण उन्हें आयोग का संबंधित मामला पर विचार करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आयोग से उनके मामले में कायवाही स्थगित करने की भी प्रार्थना की।

जस्टिस शाह ने श्री भिण्डर के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अपनी व्यवस्था में कहा कि आयोग का इसमें कोई सबध नहीं है कि सर्वाधिक गवाह का सरकार की ओर से कानूनी मदद मिल

रही है या नहीं। ऐसी स्थिति में इस आधार पर कायवाही को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग न पहन ही श्री भिण्डर को काफी समग्र किया है, इसलिए अब जीर समय देना सम्भव नहीं है।

जस्टिस शाह ने श्री भिण्डर द्वारा अपना पक्ष न रखने पर उनका पक्ष सुने बिना ही मामले पर विचार पूरा करने के आदेश दिए।

नजरबंदी और सफाई

एमरजेंसी के दौरान मीसा जीर भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार/नजरबंद किए जाने वाला की सूचिया तयार किए जाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देते हुए पुलिस अधीक्षक सी० आई० डी० (विशेष ब्रांच) श्री के० एस० बाजवा ने बताया कि उन्होंने बनी बनाए जाने वाले लोगों की सूची तयार करके केवल अपनी इच्छा पूरी की थी। यदि इसमें कोई गलती हुई हो तो वे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तयार हैं।

उनका कहना था कि पहलू और दूसरे स्तर के सभी नतीजा को गिरफ्तार किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस श्रेणी के लोगों को मीसा में जीर शेष सभीको डी० आई० बार० जीर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने की कहा गया था।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र माहान का कहना था कि जिन लोगों का श्री बाजवा अवकाश भी भिण्डर ने मीसा में बना बनाने पर सहमति दी उन्हें बनी बनाने के आदेश जमानत हान में पहले ही जेल में दे दिए गए थे।

श्री ओट्टरी ने बताया कि उन दिनों कई तरह के नोट और सूचनाएं मिलती थी जिनमें कहा जाता था कि अमुक व्यक्ति को उठाना है। उठाने से मतलब होता था, एकदम जेल में बंद करना। उन्होंने बताया कि जितनी भी राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई, वे या तो श्री बाजवा के कहने पर हुई या फिर श्री भिण्डर के कहने पर।

एक अन्य पुलिस अधीक्षक श्री के० डी० नैयर का कहना था, कुछ कुछ लोगों के भूमिगत होने का संदेह था, इसलिए पहले उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १०० के अंतर्गत गिरफ्तार करने

को कहा जाता था और उसके बाद से मीसा का वारंट थमा दिया जाना था । '

एमरजेन्सी में घोर मदाघता और पागलपन

उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने इस अवधि में स्वीकार किया कि एमरजेन्सी में घोर मदाघता का वातावरण कायम था और सम्पूर्ण सत्ता प्रधानमंत्री निवास में सिमट गई थी तथा सारा काय श्री सत्य गांधी के निर्देशानुसार चलता था ।

श्री कृष्णचंद और उनके सचिव श्री नवीन चावला ने स्वीकार किया कि एमरजेन्सी की घोषणा के बाद एक अजीब पागलपन की स्थिति कायम हो गई थी । इस दौरान किसीको भी नजरबंद कर दिया जाना एक साधारण बात हो गई थी ।

श्री चावला ने जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि एमरजेन्सी के समय राजनीतिक विरोधियों की नजरबंदी सरकार की नीति के अनुकूल स्वाभाविक थी परंतु अनक लोग की नजर बंदी अघाघुध की गई । इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता । इसपर सरकारी वकील श्री लखी ने शट पूछा 'उस पागलपन के माहौल में आपकी क्या भूमिका थी ? ' श्री चावला ने जवाब दिया "यह निणय करना आयोग का काम है । मैं स्वयं अपना मूल्यांकन नहीं कर सकता ।

श्री चावला का कहना था कि यह कहना जरूरत से ज्यादा होगा कि नजरबंद लोग के मामला की समीक्षा समिति की बैठक में श्री बाजवा की ही चलती थी । वास्तविकता यह थी कि नजर बंदी का छोड़ने की जिम्मेदारी कोई भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था । उहान आरोप लगाया कि जो लोग अब श्री बाजवा पर आरोप लगा रहे हैं वे उस समय क्या नहीं बोलते थे ?

परंतु इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस समिति का गठन केवल औपचारिकता थी । उस समय भय का ऐसा वातावरण बना हुआ था तथा प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही डरा हुआ था और एक दूसरे का सहारा चाहता था ।

जिम्मेदारों तो है ही

जस्टिस शाह ने आयोग के अंतिम चरण की कार्यवाही के

दौरान दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद और उनके वकील तथा प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने जो कुछ किया, ऊपर स मिले आदेशों के कारण किया तथा वे उसके जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते क्योंकि उस समय के हालात में उनके सामने उपरवाला के आदेश मानने के सिवाय कोई और चारा नहीं था।

जस्टिस शाह का कहना था कि कोई भी अधिकारी सिर्फ यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि वह असहाय था, इसलिए उसने ऐसा किया। क्योंकि प्रत्येक अधिकारी को नियमों तथा अपने विवेकानुसार कार्य करना होता है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह जिम्मेदारी उसकी है।

आयोग के वकील श्री खडालावाला का कहना था कि एमरजेंसी के दौरान की गई गिरफ्तारियाँ एक 'मजबूत' थी तथा यह इतनी अचानक की गईं ताकि लोगों को बचन और छुपने का अवसर भी नहीं मिला सके।

नजरबंदी और पेरौल पर रिहाई

दिल्ली प्रशासन की ओर से नजरबंद किए गए कुछ बदमाशों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा पेरौल पर रिहाई की सिफारिश किए जाने के खतरा नज़र नहीं दिखा मया। इनमें से कुछ नाम हैं—सर्व श्री बबरनाल गुप्त श्रीमती प्रमीला ललित, प्रवीर पुरकायस्थ, हंस राज गुप्त और श्री टी नरुला।

इन सभी लोगों के मामले में यह मंत्रालय द्वारा रिहा करने की सिफारिशें की गई थी, परन्तु दिल्ली प्रशासन की ओर से उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। जहाँ एक ओर इन लोगों को पेरौल पर रिहा नहीं किया गया, वहाँ दूसरी ओर कुछ बदमाशों को थोड़े से समय के लिए ही रिहा किया गया था, परन्तु बाद में वे काफी समय तक बाहर रहे और इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया गया। इनमें से कुछ थे—सर्व श्री विशम्भरदत्त शर्मा रजितसिंह के ० एम० राधाकृष्ण बलीराम शर्मा रमेश कुमार रखेजा और श्री वृजमोहन शर्मा।

श्री बबरनाल गुप्त के संबंध में उनकी पत्नी ने पेरौल पर रिहाई के लिए प्रार्थना की थी क्योंकि उनकी दो भतीजियाँ का

विवाह होने वाला था परन्तु उप राज्यपाल ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद एक प्राथना उनका बीमार होने के आधार पर की गई, परन्तु उस भी स्वीकार नहीं किया गया। इन दोनों मामलों में गृह मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी थी।

इस संवध में उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद का कहना था कि गृह मंत्रालय की सिफारिश के साथ साथ वे भी श्री गुप्त को रिहा करने को इच्छुक थे परन्तु श्री ओम मेहता की इस मामले में अनुमति नहीं थी और श्री मेहता उन दिनों प्रधानमंत्री निवास से निकट से जुड़े हुए थे। उन्होंने अंत में स्वयं अपने निणय से भी गुप्त को रिहा भी कर दिया था परन्तु इससे प्रधानमंत्री उनपर बहुत विगड़ी थी और कहा था कि जब और लोग अंदर हैं तब इन्हें ही रिहा करने की क्या आवश्यकता थी? इसपर जस्टिस शाह ने खुटकी लते हुए कहा आपका कह देना चाहिए था कि उन्हें भी रिहा कर दिया जाए।

संवर्षी जार० प्रसाद श्री हसराम गुप्त टी० नरुला और श्री एम० एन० तलवार को बीमारी के आधार पर गृह मंत्रालय की ओर से रिहा करने की सिफारिश की गई परन्तु इन्हें भी नहीं माना गया।

नजरबंदी में मृत्यु

उल्लेखनीय है कि श्री तलवार के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद उप राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान नहीं की जबकि उनकी हालत काफी खराब थी और वे पत नसिग-होम में भरती थे। इसी बीच श्री तलवार की मृत्यु हो गई। श्री तलवार की मृत्यु के बाद उप राज्यपाल चाहते लगे कि किसी भी तरह रिवाइडों में यह तबदीली कर दी जाए कि श्री नरुला को मृत्यु से पहले ही रिहा कर दिया गया था परन्तु अधिकारियों के असहयोग से ऐसा हो नहीं सका।

श्रीमती प्रमीला निविस के बारे में भी जिन्हें प्रधानमंत्री के फाम पर काम कर रहे मजदूरों को यूनतम वेतन देने के लिए भंडकान के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था गृह मंत्रालय की सिफारिश को नहीं माना गया।

इन सब मामलों के अतिरिक्त जहाँ कुछ बन्धियों का रिहा कर

दिया गया उनके बारे में कहा जाता था कि वे तत्कालीन अर्थ-
 कार्य में लिप्त थे तथा उन्हें इसी प्रकार के आरोपों में भी शामिल
 कर दिया गया था, परन्तु उसके बावजूद उन्हें रिहा कर दिया गया।
 इन लोगों की रिहाई के बारे में भी उप-राज्यपाल ने श्री अम
 मेहता पर हिम्मेतारी डाली। उनका कहना था कि श्री मेहता तथा
 प्रधानमंत्री निबाम के निर्देशानुसार ही ऐसा किया गया।

नसबदी और पेरौल पर रिहाई

एमरजेन्सी के दौरान स्वेच्छा से नसबदी कराकर पेरौल पर
 छोड़ने के आदेश देने से संबंधित रोचक मामला भी आयाग के सामने
 आया। प्रशासन की ओर से आदेश दिए गए थे कि जहाँ भी मोसा-
 बदी स्वेच्छा से अपनी नसबदी करा लेगा, उस तुरन्त पेरौल पर छोड़
 दिया जाएगा।

इस आदेश के संबंध में उप-राज्यपाल से लेकर अर्थ अधिकारिणा
 तक ने सारी हिम्मेतारी श्री नवीन चावला पर डाली। जबकि श्री
 चावला ने बड़ी ही मातृमयित से यह कहकर बचना चाहा कि 'नस-
 बदी शब्द जो आजकल इतना धुरा लगता है उन निम्न परिवार
 नियोजन कार्यक्रम का एक आवश्यक भाग था। चूंकि जेलों में नित्य
 प्रशासन के अंतर्गत ही आती थीं इसलिए वहाँ भी परिवार नियोजन
 कार्यक्रम का प्रचार किया जा रहा था। श्री चावला ने यह भी
 स्वीकार किया कि श्रीमती खड्गसानी सुलतान की भी दस-तीन बार
 रिहाई जेल भेजने की व्यवस्था की गई थी।

पेरौल और परीक्षा

निहाई जेल में बंदी कुछ छात्रों की जो परीक्षा में बैठना चाहते
 थे, गृह मंत्रालय की मजूरी के बाद पेरौल पर रिहा न कर परीक्षा
 देने की अनुमति नहीं दी गई। जिन छात्रों ने इस प्रकार की अनु-
 मति मांगा थी वे थे—मधुजी जिनेंद्र सरिन, अशाककुमार दागरा
 सुभाष नागपात्र, गुरुमुख दाग, प्रवीर पुरजायस्थ और श्री अरुण
 जन्नी।

श्री जेन्नी ने इस संबंध में नित्य उच्च न्यायालय में एक रिट
 याचिका प्रस्तुत कर नित्य प्रशासन को आदेश देने की प्रार्थना की
 थी। मुंबई के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि यदि विश्व-

विद्यालय तिहाड़ जेल में ही एक परीक्षा केंद्र खोल दे, तो सरकार को आपत्ति नहीं होगी। इस संबंध में 'मामालय' ने उसका अनुसार अपने आदेश दे दिए परंतु दिल्ली प्रशासन द्वारा इस संबंध में विश्व विद्यालय से कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया गया और छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सका।

संबंध—दिल्ली प्रशासन और गृह मंत्रालय के बीच

पैरोन पर रिहा करने और अन्य मामला में दिल्ली प्रशासन की गृह मंत्रालय के सुझावों पर बरती गई नाराजगी के बारे में श्री कृष्ण खन्ना का कहना था कि 'एमरजेंसी' के दौरान दिल्ली के मामलों में श्री ओम मेहता को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो थे तो मंत्रालय में राज्यमंत्री परन्तु मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के मुकाबल उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि इसका कारण यही हो सकता था क्योंकि श्री ओम मेहता प्रधानमंत्री निवास से सीधे जुड़े हुए थे। इसका मतलब यह था कि श्री ओम मेहता के निर्देश या सुझाव एक तरीके से प्रधानमंत्री निवास के ही आदेश या निर्देश होते थे।

श्री कृष्णखन्ना ने बताया इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी श्री सजय गांधी को दे दी थी। अतः हम लागू कोई कारवाई श्रीमती गांधी या सजय गांधी के निर्देश के विपरीत नहीं करते थे।

प्रधानमंत्री निवास में शक्ति केंद्रित

उन्होंने जस्टिस शाह के प्रश्न के उत्तर में बताया कि वास्तव में पराल और बर्दिया को छोड़ने के बारे में मेरी मर्जी कुछ भी नहीं थी इसका निणय तो प्रधानमंत्री निवास से होता था जहां सत्ता केंद्रित थी।

सत्कालीन मुख्य मंचिव श्री ज० क० काहली के अनुसार दिल्ली में मौला के अंतर्गत बर्दिया को पैरोन पर रिहा करने के लिए कोई नियम नहीं था। इस प्रकार के नियमों की अनुपस्थिति में कुछ नियमों का प्रावधान किया गया था और उनपर उप राज्यपाल की सहमति से निणय लिया जाता था। उन्होंने बताया कि कुछ अवसरों पर उप राज्यपाल और गृह मंत्रालय के दृष्टिकोणों में अंतर पाया

गया। अधिकांश मामला म उप राज्यपाल के निणय की ही मायता मिलती थी। इसी प्रकार की बातों को देखते हुए दिल्ली प्रशासन विभिन्न मामला म गृह मन्त्रालय के सुझावों को ठुकराने म हिक्कता नहीं था।

तत्कालीन विशेष गृह सचिव श्रीमती शलजा चट्टा के अनुसार गृहमन्त्रालय ने कभी मुख्य सचिव को और कभी उप राज्यपाल को हम बारे म पत्र लिखना चालु कर दिया था कि भीसा म की गई कुछ गिरफ्तारियां उचित नहीं हैं अथवा उन्हें भीसा के अंतगत नहीं किया जाना चाहिए था। कितने ही अवसरों पर मन्त्रालय ने पेरोल पर रिहा किए जाने के बारे म भी सिफारिशें की थी। अधिकांश समय उप राज्यपाल द्वारा मन्त्रालय की सिफारिशें नहीं मानी गई। हम बारे म वे बराबर उप राज्यपाल और उनके सचिव से बात किया करती थी कि वहां मे पत्र भी आ रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से वे लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन उनकी राय नहीं मान रहा है। इसपर उप राज्यपाल उनसे कहा करते थे कि गृहमन्त्रालय की सिफारिशों से वह निपट लेंगे, हम लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली के ही तत्कालीन उप आयुक्त श्री सुशीलकुमार तथा भूतपूर्व विधि सचिव श्री राजनीकांत के अनुसार गृह मन्त्रालय ने कई बार दिल्ली प्रशासन को लिखा था कि जिन आचार्यों पर अमुक व्यक्ति की गिरफ्तारी भीसा म की गई वह उचित नहीं है, परंतु उप राज्यपाल ने उनकी राय कभी नहीं मानी।

श्री कृष्णचंद के निजी सचिव श्री नवीन चावला का कहना था कि उप राज्यपाल ने इन मामलों म शायद ही कभी गृह मन्त्रालय के निर्देशानुसार काम किया हो। चाहे वह मामला श्री कवरलाल गुप्त की रिहाई का रहा हो या फिर श्रीमती लिविस का। उन्होंने कभी गृह मन्त्रालय के निर्देशों के अनुसार काय नहीं किया। अब यह एक अलग बात है कि वह यह काय किसी और के निर्देशानुसार कर रहे हों।

बंदियों के साथ जेल में व्यवहार

एमरजेंसी के दौरान जेलों म राजनीतिक बंदियों तथा अन्य बंदियों म किया गया व्यवहार काफी खचित रहा है। चाहे बंदिया

मे कोई आम मजदूर रहा हो पत्रकार रहा हो या फिर भूतपूर्व महारानिया ही क्या न रही हा, कोई भी इन जेल अधिकारियों के दुर्यवहार से नहीं बच सका था।

जेल अधीक्षक श्री आर० एन० शर्मा ने स्वीकार किया कि जयपुर की राजमाता श्रीमती गायत्रीदेवी को तिहाड़ जेल की ऐसी कोठरी में रखा गया था जो फासी की सजा पाने वाली महिलाओं के लिए नियत थी, यद्यपि उसमें ऐसी सजा पाने वाली कोई महिला नहीं रखी गई थी। उन्होंने कहा कि श्रीमती गायत्रीदेवी के अतिरिक्त ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजयराज सिन्घिया और श्रीमती गायत्रीदेवी के पुत्र ल० बनल भवानीसिंह को भी इसी प्रकार की कोठरियों में रखा गया था।

श्री शर्मा का कहना था कि उच्चाधिकारियों को बताया दिया था कि ये कोठरियाँ इन लोगों के उपयुक्त नहीं हैं परन्तु पुलिस वाले माने नहीं। जेल के कई अधिकारियों ने बताया कि तिहाड़ जेल में श्री मन्मलाल खुराना (हिन्दी के वरमान कायकारी पापद) और श्री प्राणनाथ लेखी (शाह आयोग में सरकारी वकील) और एक अन्य नजरबंद को जेल के पागलों के बाड़े में रखा जाने के निर्देश दिए गए थे। श्री लेखी ने स्वयं बताया था कि उन्हें जेल में झुलसा देने के उद्देश्य से सीमेण्ट की चादर वाली छत की कोठरी में बन्दी गर्मी में रखा गया था।

एक अन्य जेल-अधीक्षक श्री एस० के० बत्ता का कहना था कि श्री नवीन चावला ने इन नजरबंदों को पागलों के साथ बाड़े में रखे जाने का निर्देश दिया था।

श्री चावला ने स्वीकार किया कि उन्होंने उप राज्यपाल के निर्देशानुसार इन तीनों को जेल में रखने का सुझाव अवश्य दिया था परन्तु पागलों के साथ बंद किए जाने की बात झूठी थी।

उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने किसी राजनीतिक नजरबंदी को सेल में रखने के आदेश दिए थे।

चर्चा रखसाना की

जेलों में व्यवहार पर विचार के दौरान आयोग के समक्ष एक रोचक संस्मरण भी पेश हुआ और वह था श्री सजय गांधी की परि-

बार नियाजन कायक्रम म सहयोगी श्रीमती रुखसाना सुलतान के सबध म । चर्चा के दौरान बताया गया कि श्रीमती सुलतान के लिए राजनिवास और तिहाड जेल, दोनों के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे ।

श्री कृष्णचंद ना कहना था कि श्रीमती रुखसाना अक्सर श्री चावला के पास आती रहती थी और उनके कमरे म तीन-तीन घंटे बठती थी । कभी-कभी मुसस भी भेंट कर लेती थी और परिवार नियाजन कायक्रम की प्रगति के सबध म कुछ सूचनाएं दे जाती थी ।

उनके इस बयान पर श्री चावला न उत्तेजित स्वर म कहा, 'कुछ तो मच सोलिए आपन उनके (श्रीमती रुखसाना) साथ कितनी बार भोजन किया था ?'

इससे पूर्व श्री चावला स्वयं कह चुके थे कि श्रीमती रुखसाना को दो-तीन बार तिहाड जेल भेजने के लिए उन्होंने स्वयं व्यवस्था की थी । श्रीमती रुखसाना वहा परिवार नियाजन कायक्रम के मिलमिल म गई थी ।

जला में किए गए व्यवहार पर जयपुर और ग्वालियर की राजमाताएं पहले ही शिकायत कर चुकी थी । उनका कहना था कि उन्हें जिन सेलों म रखा गया था वह एकदम गंदी थी तथा उनका आम पास गंदी बंदी महिलाएं धूमती रहती थीं और गालिया बकती रहती थीं ।

श्री कुलजीप नायर न भी अपने बयान म बताया था कि जलों की हालत बड़ी खराब थी और वहा क एन दा अधिकारिया को छाडकर अन्य का व्यवहार बड़ा ही खराब था । उन्होंने बताया था कि ६३ बंदिया के बीच सिर्फ दो मुख् शौचालय थे तथा पूरी जेल म एक हैंडपंप । इसके अतिरिक्त सला के चारों ओर की घास को काटा नहीं जाता था जिसम वर्षा म कीड़े मकोड़े और कभी कभी साप भी अंदर आ जाते थे ।

पैसे देने पर सब कुछ हाजिर

उन्होंने बताया था कि जेल म खाना भा ठीक नहीं था । चपा-निया ता जितनी मांगी मिल जाती थी परन्तु दात एक ही बार मिलती थी । इसका अतिरिक्त कभी भी कोई सजा नहीं दी जाती

थी। इन सब बातों के अतिरिक्त यदि बंदी स्वयं धन खर्च कर तो उसके लिए चिक्कन करी और 'तदूरी' तक बाहर से भोजन दी जाती थी।

श्री नायर न बताया था कि जेल में जब भी अधिक बंदी हो जाते थे तो सड़कों पर इधर उधर घूमने वाले लड़कों को यही पकड़कर ले आया जाता था और उनसे काम कराया जाता था और उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाता था, जब तक कि दूसरे सड़के नहीं आ जाते थे। श्री नायर जब तिहाड़ जेल में थे तब एक मकैर एक लड़के को उन्होंने रोते देखा और उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपने मालिक के लिए पान लेने जा रहा था, तब उसे पकड़ लिया गया। जेल वाइन ने बाद में उन्हें इस प्रकार भी जानकारी दी।

६. छापे या राजनीतिक बदला

किमी उद्योगपति, व्यवसायी राजनीतिज्ञ अथवा साधारण व्यक्ति को परेशान करने का एक अप्रत्यक्ष किंतु सबसे अच्छा तरीका यह भी हो सकता है कि उससे संबंधित फर्मों, ट्रस्टों और अन्य स्थानों अथवा ये न हो तो उसके घर पर ही किसी न किसी बहाने आयकर विभाग बिप्री कर विभाग या फिर किसी अन्य विभाग के जरिये छापे पकड़ाए जाएं और फिर जब देश में एमरजेन्सी लागू हो तो यह काम और भी आसान हो जाता है—यानी सोने में सुहागा।

एमरजेन्सी के दौरान इसी प्रकार की परेशान करने की कारवाइयों के जतमश दिल्ली के विश्व युवक केन्द्र पर किया कर लिया गया अवाड (ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन) पर छापे मारकर उसकी तथा दो अन्य गांधीवादी संस्थाओं की सरकारी सहायता बंद कर दी गई। बजाज उद्योग समूह के प्रतिष्ठानों की देशव्यापी तलाशी ली गई तथा बन्नीदा रेयन के दफ्तरों और दिल्ली की एक फर्म पंडित ब्रह्म पर छापे मारे गए।

इस दौरान इन मामलों में जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई वह भी उल्लेखनीय है। जहाँ एक ओर अवाड पर एक

समद-सदस्य व कुछ पत्रों व आधार पर तथा बजाज उद्योग समूह पर कुछ अनात व्यक्तियों की सूचना पर बिना किसी उचित आधार के छापे मारे गए वही मारुति लिमिटेड के ५५ हजार रुपये मूल्य के शेयरों के दो बेनामी लन देनो के मामले को बिना जांच ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। बात यही समाप्त नहीं हुई एक मामले में तो प्रधानमंत्री निवास से मिले निर्देशों पर २०० रुपये की रिश्वत व मामले को भी रफा दफा कर दिया गया।

(1) विश्व युवक केन्द्र पर कब्जा

नई दिल्ली में राजनयिका की एक आजीशान बस्ती है— चाणक्यपुरी। यहाँ विश्व युवक केन्द्र की एक बहुमजिली इमारत है। इस केन्द्र में देशी तथा विदेशी पर्यटकों को ठहराने की व्यवस्था व अतिरिक्त युवकों में नृत्व की भावना पैदा करने और उनके कल्याण के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। परन्तु एमरजेंसी के दौरान ३० अगस्त १९७५ को दिल्ली प्रशासन द्वारा भारत रक्षा कानून की धारा २३ के अंतर्गत इस इमारत पर बन्ना कर दिया गया। बन्ना करने के कारणों में बताया गया था कि केन्द्र राष्ट्रविरोधी कारवाइयों में सलग्न है।

युवक केन्द्र पर निगाह

केन्द्र का संचालन कर रहे 'यास' व प्रबोध 'यासी' तथा प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रामकृष्ण बजाज व अनुसार, भूतपूर्व रक्षा उत्पादन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल की (जिन्होंने बाद में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था) १९७३ से ही केन्द्र पर निगाह लगी हुई थी तथा वे मौक की तलाश में थे और उन्होंने यह मौका एमरजेंसी के दौरान मिल ही गया। श्री शुक्ल केन्द्र का प्रमुख स्वयं करना चाहते थे। उनका कहना था कि वे इसका प्रबोध श्री सजय गांधी की महायत्ना से करेंगे। था युवक प्रबोध मंडल के सचिव श्री मनमोहन अमरजिया, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित श्री वी० वी० जॉन और चरतराम का हटाना चाहते थे। उन्हें श्री नवल टाटा सहित अन्य समस्या व बने रहने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसपर उन्होंने श्री शुक्ल से कहा था कि इस बात पर 'यास' मंडल के

सविधान में कोई प्रावधान नहीं है तो उन्होंने कहा 'यदि प्रावधान नहीं है तो सविधान को ही बदल दो।' परन्तु बाद में प्रवध मंडल ने भी श्री शुक्ल के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

श्रीमती गांधी से भेंट

श्री बजाज का कहना था कि श्रीमती गांधी जब नवम्बर १९७५ में आचार्य विनाया भावे से मिलने बर्धा गई थी तब वे भी वहाँ मौजूद थे। श्रीमती गांधी के बर्धा से दिल्ली लौटते समय उनकी अनुमति से वे भी उनके विमान में ही दिल्ली आए। विमान में श्री बजाज ने केन्द्र पर कांग्रेस के सबध में उनसे बातचीत करनी चाही परन्तु ऐसा नहीं लगा कि श्रीमती गांधी ने इस मामले में कुछ उत्सुकता दिखाई हो। श्रीमती गांधी की श्री बजाज से हुई बातचीत के कुछ अंश इस प्रकार हैं

श्री बजाज ने कहा 'आपकी मुझसे कोई नाराजगी है क्या केन्द्र के सबध में आपको पास कोई शिकायत आई है ?'

श्रीमती गांधी ने इसपर कहा 'हाँ इस तरह की खबर तो बीच बीच में आती ही रहती है।'

यदि केन्द्र राष्ट्र विरोधी कायवाहियों में सलग्न है तो आप अपने विश्वास का आदमी नियुक्त कर दें और इसकी जांच करा लें।'

श्री बजाज का कहना था कि श्रीमती गांधी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। श्री बजाज ने बताया कि उनके भाई १९६६ में कांग्रेस विभाजन के समय संगठन कांग्रेस में चले गए थे। उनके परिवार वालों का और उनका श्री मोरारजी देसाई श्री जयप्रकाश नारायण और सर्वोदय वाला से निकट का सबध रहा था और शायद इसीलिए श्रीमती गांधी के समर्थक उन्हें अपना विरोधी मानते थे और उनका विरुद्ध शिकायतें करते रहते थे।

कृष्णचंद से भी भेंट

श्री बजाज ने बताया कि नवम्बर १९७५ में दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने उनसे कहा था कि 'यदि वे अपने प्रवध मंडल का पुनर्गठन स्वीकार कर लें तो केन्द्र की इमारत को वापस दिलवाया जा सकता है। श्री कृष्णचंद ने इस सबध में

श्रीमती अम्बिका सोनी को मंडन में शामिल करने का सुझाव दिया था। बाद में एक अर्थ मुलाकात में श्री कृष्णचंद के सुझाव पर उन्होंने कहा था कि प्रबन्ध मन्त्र में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन उनका प्रवेश व्यक्तिगत दृष्टियत में होगा, उपराजपाल के पत्र में संस्थ के रूप में नहीं, क्योंकि इससे प्रत्येक बार उपराजपाल के बदलने के साथ-साथ उनको भी अपना मन्त्र बदलना होगा। परन्तु श्री कृष्णचंद ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

श्री बजाज का कहना था कि उन्होंने वर्षों से आन के बाद तीन बार बार श्रीमता गांधी तथा तत्कालीन गृहमंत्री श्री ब्रह्मा नन्द रेड्डी को केंद्र पर से सरकारी बच्चा समाप्त करने तथा उम्र पर लगाए गए भारों की जांच कराने के बारे में पत्र लिखे, परन्तु होना नहीं उनके एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया।

आदेश न मानने पर जेल में डालने की धमकी

बाद में जनवरी, १९७६ में एक बार श्रीमती गांधी के विशेष दूत श्री मोहम्मद युनुस में मिल और उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया। इनपर श्री युनुस ने उनसे बात में फांस करने को कहा। बात में फांस करने पर श्री युनुस ने उनसे कहा 'बेहतर यह है कि आप श्री प्रुसल के साथ सहयोग करें। वस भी आज कल एमरजेंसी है और सरकार का काफी अधिकार मिल गए हैं। यदि दृष्टिगत न उनके साथ सहयोग नहीं किया तो उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है।'

श्री बजाज का कहना था कि श्री युनुस ने यह बात उनसे कोई गंभीर भावना से नहीं कही थी। श्री युनुस उनके मित्र थे और अब भी हैं। उन्होंने उनसे जो कुछ कहा, वह एक सुझाव के रूप में था, कोई धमकी नहीं थी।

श्री युनुस में हुई इस वार्ता के बाद बम्बई में प्रबन्ध मंडल की एक बैठक हुई जिसमें पूरे मामले पर तत्कालीन विचार विमर्श किया गया। बैठक में एक दृष्टिशील नवन टाटा ने सरकार के इस रवये पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी संस्था से त्यागपत्र देने को कहा और बाद में अपना त्यागपत्र भिजवा भी दिया।

इसके पूर्व श्री टाटा ने किसी भी श्री सजय गांधी से बातचीत

की थी। श्री गांधी न बताया था कि उनकी पहले इस इमारत में जहर दिलचस्पी थी परन्तु अब नहीं है। इमारत पर कच्चे कदारे में उनका कोई लेना देना नहीं था तथा यह कार्य उप राज्यपाल द्वारा किया गया था। श्री वजाज ने इस बात में श्री शुक्ल को बम्बई में अवगत करा दिया था।

श्री वजाज न बताया कि केंद्र का एक अग्र दृष्ट्या श्री वी० वी० जान ने प्रवचन मंडल की बम्बई में हुई बैठक में कहा था कि 'यासियो द्वारा त्यागपत्र देना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे सरकार आसानी से केंद्र का दुरुपयोग कर सकेगी। उन्होंने कहा था कि 'जेन में डाल देने की धमकी का उनपर कोई असर नहीं होने वाला है। जो लोग पहले से ही जल में है वह हममें काफी अच्छे हैं।'

केंद्र का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए

श्री वजाज न बाद में जिरह के दौरान बताया कि केंद्र पर कच्चे के बावजूद उसका उपयोग उसका मूल उद्देश्यों के अनुरूप नहीं किया गया बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया, जो उचित नहीं था। उनका कहना था कि केंद्र पर कच्चा इस आधार पर किया गया कि यह राष्ट्रविरोधी कामवाहियों में सतर्क है परन्तु इस बारे में कभी भी जांच नहीं कराई गई।

केंद्र को सी० आई० ए० से घन

उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्र को शुरू में कठिन में भवन निर्माण के समय बाहर से कुछ धन अवश्य मिला था, परन्तु ज्योंही यह बात हुई कि यह धन सी० आई० ए० में सम्बद्ध है उसे तुरन्त वापस कर दिया गया और बाद में ऐसा कोई धन स्वीकार नहीं किया गया। श्री वजाज ने यह भी स्वीकार किया कि केंद्र का भवन का एक भाग एक भूतपूर्व ट्रस्टी को विरासत में दिया गया था तथा वे वहाँ इंटरनैशनल असम्बली आफ यूथ की भारत स्थित शाखा का कार्यालय चलाया करते थे परन्तु बाद में उनसे यह भाग खाली करा लिया गया था।

श्री वजाज ने बताया कि उप राज्यपाल से हुई बातों से लगता था कि वे केंद्र की समस्या तो सुलझाना चाहते हैं परन्तु अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि

श्री कृष्णचंद किसी और के ब्यारे पर काम कर रहे थे। बम्बई में श्री शुक्ल ने उनसे भेंट के दौरान उनके साथ जो व्यवहार किया वह बहुत ही धक्का पहुँचाने वाला था जबकि स्वतंत्रता संग्राम में श्री शुक्ल व पिता और उनके पिता मित्र रह चुके थे और वे दोनों भी आपस में अच्छे मित्र थे।

इमारत पर कब्जा श्रीमती गांधी के निर्देश से

श्री कृष्णचंद ने आयोग को बताया कि केन्द्र की इमारत पर कब्जा श्रीमती गांधी के निर्देशों पर किया गया था। श्रीमती गांधी ने उन्हें बताया था कि केन्द्र राष्ट्र विरोधी कारवाइयाँ में सलग्न है। इसके अतिरिक्त पुलिस जमीन (सी० आई० डी० विशेष शाखा) श्री के० एस० बाजवा ने भी सरकारी तन्त्र में जायकत श्री सुशीलकुमार को इस संबंध में एक पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सदन सदस्य श्री शशिभूषण ने भी उन्हें एक पत्र लिखकर इस बात का जिक्र किया था कि केन्द्र को सी० आई० ए० से धन मिलता है।

उन्होंने जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री बी० बी० राजू ने उनसे केन्द्र की इमारत का दो महीने के लिए भागा था। इससे पूर्व इस इमारत का उपयोग दिल्ली प्रशासन के एक विभाग दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जा रहा था। श्री राजू का यह प्रस्ताव उक्त विभाग को भेज दिया गया था और उसने इमारत का एक भाग कांग्रेस के देने पर सहमति प्रदान की थी। उन्होंने इस बारे में श्रीमती गांधी को भी सूचित कर दिया था।

श्री कृष्णचंद ने स्वीकार किया कि वाद में सूचना मिली थी कि कांग्रेस द्वारा इमारत का उपयोग चुनाव प्रचार मामलों के लिए करने तथा अन्य कामों में किया गया।

आपत्ति इमारत पर थी, ट्रस्ट पर नहीं

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इमारत पर कब्जे के बावजूद ट्रस्ट के कार्यालय जारी थे। ट्रस्ट ने विरोध व किसी भवन में अपनी गतिविधियाँ जारी रखी थी। इसपर आयोग ने

चकील श्री काल खडालावाला ने कहा, “ इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को आपत्ति केंद्र की इमारत पर थी, ट्रस्ट के काय कलापा पर नहीं।’ श्री कृष्णचंद ने जवाब में कहा ‘हो सकता है, परंतु मैंने तो सिर्फ वही किया, जो मुझसे कहा गया।’

दिल्ली प्रशासन में तत्कालीन मुख्य सचिव श्री जे० के० कोहली का कहना था कि बंबे के बाद विश्व युद्ध केंद्र का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं किया गया। हालांकि वे स्वयं भी इस परसंद नहीं करते थे, परंतु उस समय वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इस मामले में जो कुछ भी हो रहा था, वह सब ‘राजनिवास’ की ओर से हो रहा था।

कृष्णचंद लेफ्टिनेंट, चावला गवर्नर

उन्होंने बताया कि उस समय के हासनात ही ऐसा था और उप राज्यपाल स्वयं भी असहाय थे, क्योंकि उस समय ऐसी धारणा थी कि उनके निजी सचिव श्री नवीन चावला जिस मामले में रक्षित रहे हैं उसमें श्री सत्य गांधी की भी दिलचस्पी होगी। श्री कृष्णचंद तो सिर्फ ‘लेफ्टिनेंट’ थे गवर्नर तो श्री चावला ही थे। और इन मंत्रियों को देखते हुए ही उन्हें श्री चावला जैसे जूनियर अधिकारी से निर्देश देने होते थे।

केंद्र को विदेशों से घन

भूतपूर्व मसद सदस्य श्री शशिभूषण ने आयोग के समक्ष यह सिद्ध करना चाहा कि केंद्र को विदेशों से घन मिलता था तथा वह राष्ट्रविरोधी कारवाइयों में सलग्न था।

जस्टिस शाह के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि केंद्र को इटरनेशनल असेम्बली आफ यूथ के जरिये सी० आई० ए० से घन मिलता था। जस्टिस शाह द्वारा इस संबंध में प्रमाण मागे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा अमेरिका से प्रकाशित होने वाले दैनिक ‘यूथफ़ टाइम्स तथा पत्रिका ‘टाइम’ में पढ़ा था। इसपर जस्टिस शाह ने कहा ‘जब तक दस्तावेजी प्रमाण या निकट के बोर्ड प्रमाण नहीं पेश किए जाते तब तक किसी भी आयोग अथवा भाषातंत्र द्वारा उसपर विश्वास करना मुश्किल है।’

सजय गांधी भी सी० आई० ए० के एजेण्ट

श्री शशिभूषण ने जब यह कहा कि ये लोग भारत आकर केन्द्र में गांधियों के नाम पर समाज विरोधी कारवाइयाँ करते रहते थे और इसी आधार पर केन्द्र भी इस प्रकार की कारवाइयों में शामिल था, सरकारी धनील श्री लेखी ने पूछा 'सी० आई० ए० के एजेण्ट श्री कुलदीप नारंग श्री सजय गांधी के मित्र थे क्या इसका मतलब हुआ कि श्री गांधी भी सी० आई० ए० से सम्बद्ध हैं?' इसपर श्री शशिभूषण ने कहा, 'हो सकता है, तभी तो मेरे कागजात पर कारवाई नहीं हुई।' (उनके इस कथन पर भाषण के अन्त में देर तक ठहाके लगते रहे।)

शुक्ल द्वारा खडन

भूतपूर्व सूचना और प्रसारणमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने जिरह के दौरान इस बात से साफ़ इकार किया कि उनका श्री सजय गांधी के साथ मिलकर युद्ध केन्द्र को चलाने का कभी कोई इरादा था। उन्होंने इस बात से भी इकार किया कि उनकी इस केन्द्र पर कोई बुरी नज़र थी। उनका कहना था कि केन्द्र के मामले में दखल-दाजी उ होने केवल एक दोस्त के रूप में की थी किसी सरकारी हैसियत से नहीं।

श्री खडालावाला के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक मामले पर उनके विचार श्री बजाज से बहुत भिन्न हैं, लेकिन उनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। उन्हें श्री बजाज की गवाही से ही मालूम पड़ा है कि वे १९७६ की मुलाकात के बाद से उन्हें अपना दास्त भी नहीं मानते हालांकि उस भेंट में ऐसा कुछ कहा हुआ था कि वे इस तरह का खयाल अपनाते।

श्री शुक्ल ने यह भी बताया कि श्रीमती गांधी भी किसी समय केन्द्र की दृष्टी रही थी परन्तु बाद में उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह उन्होंने यह बताया कि वे केन्द्र के काम गाज़ करने के तरीके से खुश नहीं हैं। श्री शुक्ल ने इस बात से भी इकार किया कि श्रीमती गांधी ने उनसे कहा था कि केन्द्र के प्रबंध मंडल में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उन्होंने श्री खडालावाला के इस विचार को गलत बताया कि श्री सजय गांधी उनके मित्र थे

और उन्होंने उनसे नेट्र के मामले पर विचार विमर्श किया था।

मजबूती से जवाब

श्री शुक्ल व श्री लेखी और श्री खडालावाला के सवाल का बड़ा मजबूती से जवाब दिया। श्री खडालावाला के एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं मैं तो आपको सिर्फ वही बता सकता हूँ, जो मुझे याद है।' इसपर उनके वकील था राजे ट्रसिंह ने उठ सहारा देते हुए कहा यदि गवाह को इसी तरह बसकर जवाब देना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। श्री सिंह की इस तरफदारी पर श्री शुक्ल ने जस्टिस शाह से आप्रह किया कि उनके वकील की बात पर गौर किया जाए।

(ii) अवाड को एमरजेन्सी का 'अवाड'

मोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अनुसार सन् १९५८ में एक संस्था अवाड (ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन) का श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में गठन किया गया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना और उनकी जानकारी के लिए एक तरीके के किनरिंग हाउस का काम करना था। इसके अतिरिक्त इसका कार्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन और समान उद्देश्य वाली देशी एवं विदेशी संस्थाओं का संबंध स्थापित करना भी था।

देश में एमरजेन्सी की घोषणा के तुरन्त बाद संसद सदस्य श्री शशिभूषण ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी श्री सजय गांधी तथा तत्कालीन वरिष्ठ एवं राजस्व मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को अवाड तथा उसके पदाधिकारियों की कथित गैर कानूनी गति विधियाँ के बारे में पत्र लिखने शुरू कर दिए।

श्री शशिभूषण ने श्री सजय गांधी का लिख अपने पहले पत्र में कहा कि अवाड द्वारा एक पर्चा निवाला गया है जिसका शीर्षक है क्या एमरजेन्सी जरूरी थी? यह पर्चा दिल्ली के एक वकील

श्री पी० एन० लेखी ने, जो आयोग के सरकारी वकील भी है, तयार किया था।

उन्होंने इस पत्र में 'एमनस्टी इंटरनेशनल' के श्री मार्टिन एन्त्स द्वारा भारत में इसकी शाखा के सचिव को, जो अवाड व भी सचिव थे, लिखे गए पत्र का हवाला दिया। पत्र में कहा गया था कि 'हम उन वदियों के लिए काय करने को उत्सुक हैं जो पूरे रूप में 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' व लिए काय करते रहे हैं।' श्री शशि भूषण ने अपने पत्र में अवाड द्वारा तयार किए गए सीमावर्ती क्षेत्रों व कुछ नक्शों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि अवाड द्वारा यह नक्शे तयार कर व विदेशों को भेजे गए हैं। पत्र में कहा गया था कि निम्न सात व्यक्ति अवाड से सम्बद्ध हैं—श्री ए० सी० सेन (महासचिव), श्री जार० एल० गायल (अकाउंटेंट), श्री आई० व शर्मा (श्री सेन के निजी सचिव तथा जब श्री जयप्रकाश नारायण दिल्ली में होते हैं तब उनके सचिव), डा० ओम प्रकाश (जिओग्राफर) श्री एम० वी० शास्त्री (प्रशासनिक अधिकारी) श्री एस० डी० चापर (अनुसंधान निदेशक) तथा श्री एस० चक्रपाणी (सोशल जर्नेलिस्ट)।

पत्र में कहा गया था कि श्री ए० सी० सेन तथा डा० ओम प्रकाश को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और अवाड के दफ्तर पर छापा मारा जाना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया था कि अवाड को यू० एम० ए० आई० डी० से पहले सहायता मिल सकती थी, जो अब चर हो गई है। इसके अनिश्चित से परिचय जमनी की सस्या प्रोटेस्टेंट्स सेण्टल एजेंसी फार डेवलपमेंट एंड से अभी भी सहायता मिलती है।

श्री शशिभूषण ने श्री गांधी को अपने दूसरे पत्र में श्री जय प्रकाश नारायण का अवाड से संबंध होने का जिक्र करते हुए लिखा कि इस सस्या में श्री जयप्रकाश नारायण को धन दिया है। उन्होंने श्री गांधी को एक पत्र और लिखा।

श्री शशिभूषण ने श्रीमती गांधी को लिखे अपने पत्र में अवाड तथा 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' की मायवाहिया का जिक्र करते हुए कहा कि श्री जयप्रकाश ने 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' की भारत स्थित शाखा व सचिव श्री ए० सी० सेन को एक पत्र लिखा था जिसमें स्पष्ट होता है कि अवाड की मायवाहिया तथा इसमें कोष का

उपयोग राष्ट्र विरोधी कारवाइया के लिए किया जाता है।

श्री शशिभूषण ने श्री प्रणव मुखर्जी को लिखे एक पत्र में अवाइ से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम तथा पत्र देते हुए अनुरोध किया कि इन लोगों के यहाँ छापे मारकर तलाशी ली जानी चाहिए तथा संबंधित दस्तावेजों का जमा किया जाना चाहिए।

श्री मुखर्जी ने श्री शशिभूषण के इस पत्र को निदेशक (जांच) श्री एच० के० साहू का आवश्यक कारवाई के लिए भेज दिया, जिस भी सोधी ने निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहरनाथ के पास भेजा।

श्री लाल ने इस पत्र पर अपने नोट में लिखा था कि उन्होंने पोन करके श्री शशिभूषण को बुलाया था जो एक व्यक्ति श्री शशांतु देव के साथ आए थे। श्री देव पहले अवाइ में काम किया करते थे। उन्होंने श्री शशिभूषण से बातचीत के बाद श्री देव को उप निदेशक श्री शेण्डे के पास भेज दिया जिन्होंने पूछताछ के बाद एक नोट भेजा था जिसमें कहा गया था कि अवाइ एक धर्मार्थ सभा के रूप में प्रतीत हुई थी, परंतु उसमें कई वर्षों से अपने धर्म धर्म के रिटन नहीं भरे हैं। काफी विचार के बाद उन्होंने तलाशी के आदेश दिए। इन आदेशों के आधार पर अवाइ के धर्मार्थ की ५ परवरी १६७६ का तलाशी ली गई।

पुष्टि के बिना तलाशी

श्री लाल ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पुष्टि के बिना ही श्री शशिभूषण द्वारा बताया गए तथ्यों और श्री शेण्डे की टिप्पणी के आधार पर तलाशी के आदेश दे दिए थे। उनका कहना था कि चूंकि श्री शशिभूषण उस समय सतद-सदस्य के इसलिए उनके द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों पर विश्वास करके ही उन्होंने यह आदेश दिए। उन्होंने बताया कि श्री शशिभूषण के साथ आए श्री देव ने चर्चा के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा था।

श्री शेण्डे ने आयोग को बताया कि श्री देव ने उन्हें जो सूचनाएं दी थी वे काफी नहीं थी। उन्होंने इस तथ्य से श्री लाल को भी अवगत करा दिया था कि सिर्फ इन सूचनाओं के आधार पर धारा १३२ के अंतर्गत तलाशी के वारंट जारी नहीं किए जा सकते। श्री शेण्डे का कहना था कि श्री शशिभूषण से उनकी कोई बातचीत

नहीं हुई थी और उन्होंने जो कुछ किया, श्री साल के आदेश से किया।

गांधीवादी सस्यानो को सहायता बढ़

गृह मंत्रालय की फाइलों से पता चलता है कि तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता ने श्री सी० वी० नरसिम्हन (समुक्त सचिव) को पत्र लिखकर सभी मंत्रालयों तथा सभी राज्य सरकारों से अगले आदेश मिलने तक गांधीवादी सस्यानो को अनुदान बढ़ करने का निर्देश देने को कहा था। श्री नरसिम्हन के एक नोट के उत्तर में श्रीमती गांधी ने इन सस्यानो की कायवाहिया पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इनकी जाच कराने को कहा। श्रीमती गांधी का यह नाट प्रत्यक्ष कर छोड़ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस० आर० मेहता को भेजा गया तथा इस नोट को गृह-सचिव श्री सुन्दरलाल खुराना ने भी देखा। इस नोट के आधार पर ही अथाह, गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा गांधी अध्ययन संस्था का सभी प्रकार की सुविधाएँ तथा अनुदान बढ़ करने के निर्देश दिए गए।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई जाच के अनुसार सिर्फ यह पाया गया कि श्री जयप्रकाश तथा एक श्री गुलाबसिंह के दिल्ली में बसकत्ता तक के विमान टिकट का खर्चा तथा उनके टेलीफोन के तीन हजार रुपये का विल अवाह न चुकाया था। उन दिनों श्री जयप्रकाश अथाह के अध्यक्ष थे।

बाद में ७ अप्रैल को केन्द्रीय गृहमंत्री श्री चरणसिंह ने संसद में एक वक्तव्य देकर इन सस्यानो को फिर से अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

कारवाई संसदीय समिति की राय पर

श्री ओम मेहता ने आयोग को बताया कि अथाह तथा उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध कारवाई कांग्रेस संसदीय दल की कार्य-कारिणी तथा गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठकों में व्यक्त की गई राय के आधार पर की गई थी।

उन्होंने बताया कि इस संस्था तथा कुछ अन्य संस्थाओं को जाच पूरी होने तक दी जा रही अनुदान राशि को अस्थायी रूप से रोकने के आदेश के साथ-साथ जाच कराने के भी आदेश दिए गए

थे।

श्री मेहता ने बताया कि कांग्रेस ससदीय समिति की कार्यकारिणी में सदस्यों ने इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी कि गांधीजी के नाम पर चलाई जा रही कुछ सस्याएँ पिछले कुछ वर्षों से सरकार विरोधी प्रचार करने में लगी हुई हैं और दी जा रही सहायता का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय द्वारा पहले से ही सबसेवा सघ को अनुदान राशि देना बंद किया जा चुका था।

श्री शशिभूषण ने आयोग को बताया कि आयोग में चर्चा के दौरान श्री गांधी को लिखे शुरू के जिन दो तथाकथित पत्रों का उल्लेख किया गया है वे उन्होंने कभी लिखे ही नहीं तथा इन पत्रों पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रीमती गांधी को लिखे जिस पत्र की चर्चा की गई है वह भी उन्होंने नहीं लिखा तथा इसपर भी उनके हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्री गांधी को लिखे जिस तीसरे पत्र का उल्लेख किया गया है वह उन्होंने उल्टा लिखा है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग के पास काफी सक्षम स्टाफ होने के बावजूद सही पत्र पढ़ना तक गया नहीं पहुँच सके हैं।

शतान को भी पत्र

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि श्री गांधी की ऐसी क्या हैसियत थी जिसके कारण आपने उनको यह पत्र लिखा? श्री शशिभूषण ने कहा यह हैसियत की बात नहीं थी भी०आई० ए० का पर्दाफाश करने के लिए यदि उक्त शतान को भी पत्र लिखना पड़ता तो वे ऐसा करते।

सरकारा वकील श्री प्राणनाथ लेखी ने इसपर चुटकी लते हुए पूछा, क्या आपको शतान का पता मालूम है? इसपर जस्टिस शाह ने बीच में ही टोकते हुए कहा जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है उसकी आयोग के समक्ष चर्चा करना बकार है। जस्टिस शाह की इस टिप्पणी पर आयोग का कक्ष हसी के ठहाकों से गूँज उठा।

सी० आई० ए० के लिए चपरासी की भी सहायता

श्री शशिभूषण ने अपना वयान जारी रखते हुए बताया कि उन्होंने श्री गांधी को एक कार्ग्रेसी के नात ही पत्र लिखा था तथा सहायता करने का कहा था। श्री शशिभूषण ने कहा कि उन्होंने सहायता करने के लिए मभीरो कहा था, यहा तक कि वे एक चपरासी से भी कह सकते थे।

उन्होंने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि जहा एक और श्रीमती गांधी और श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा उनके पत्रों पर कारवाई की गई, वही श्री गांधी ने कोई कारवाई नहीं की। वे श्री गांधी की मदद लेना चाहते थे, परंतु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

सी० आई० ए० की कारवाइयो के लिए आयोग

श्री शशिभूषण ने सी० आई० ए० का जिक्र करते हुए बताया कि इस सस्या ने ही बंगला देश में राष्ट्रपति श्री मुजीबुररहमान तथा उनके साथियों की हत्या कराई थी। उनका कहना था कि वे शुरू से ही इस सस्या की कारगुजारियों का पदाफास करने में लगे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि 'अवाड एक स्वयंसेवी धर्माय सस्या है फिर भी उसमें मुजफ्फरनगर में लेती व औजार बनाने का एक कारखाना खोला और उसमें धन का दुरुपयोग राष्ट्र विरोधी कारवाइयो में किया।

अवाड में ब्लाउज

श्री शशिभूषण ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि छापी और तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला था। उन्होंने समाचारपत्रों में पढ़ा था कि तलाशी के दौरान बहुत कुछ बरामद हुआ है। यहा तक कि अवाड द्वारा ब्लाउजों की मिलाई के लिए किए गए भुगतान के बाउचर पकड़े गए थे जबकि इस सस्या का 'ब्लाउजों' से कोई संबंध नहीं होना चाहिए था।

श्री शशिभूषण ने इस बात पर सद प्रकट किया कि श्री देव को जिन्होंने उन्हें इस सस्या के संबंध में सूचना दी थी, आयोग

द्वारा यह मामला बनाने के लिए तय किया गया और मारा पीटा गया ।

(iii) बजाज उद्योग-समूह के प्रतिष्ठानों पर छापे

एमरजेन्सी के दौरान आयकर द्वारा जिस फुरती से काम किया गया, उसका एक उदाहरण है—बजाज उद्योग समूह पर मार गए छापे । इस उद्योग समूह के दश के विभिन्न भागों में स्थित ११४ कार्यालयों पर आयकर विभाग के ११०० अधिकारियों द्वारा एकसाथ छापे मारे गए और ये छापे सिर्फ कार्यालयों तक ही सीमित नहीं रहे गए बल्कि इनमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री जमनालाल बजाज की घमपरनी ८४ वर्षीया श्रीमती जानकीबाई के वर्धा स्थित निवास की भी तलाशी ली गई ।

बदले की भावना से

प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रामकृष्ण बजाज के अनुसार बजाज उद्योग समूह पर राजनीतिक बदले की भावना से छापे मारे गए थे । उनका कहना था कि इन सब छापों के पीछे और कोई 'मायिक' औचित्य नजर नहीं आता सिर्फ इसके बिना यह सब राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण किया गया क्योंकि हमारे परिवारजनों के आचायक विरोधी भावे श्री जयप्रकाश नारायण तथा सर्वोदय आंदोलन से काफी निवृत्त के सम्पर्क रहे हैं ।'

जस्टिस शाह द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि आयकर विभाग द्वारा मार गए छापों में बिना हिसाब का कोई धन नहीं मिला, हालांकि विभाग द्वारा ऐसा प्रचार किया गया जो पूर्णतया गलत था ।

श्री बजाज ने बताया कि 'एमरजेन्सी के दौरान तो बहुत सी गम्भीर बातें हुई थी हमारे महा मारा गया छापों तो उनके मुकाबले कम ही महत्वपूर्ण है । जिस बात ने हम सबसे अधिक परेशान किया वह था बजाज के नाम को बदनाम करने का प्रयास । उन्होंने हमारी ८४ वर्षीया माताजी के मकान तक को नहीं छोड़ा, जो १९४२ में ही पिताजी की मृत्यु के समय से सभी प्रकार के सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर चुकी थी ।'

श्री बजाज का कहना था कि छापा के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण नजर आता है, वह यह है कि उन्होंने अपने साले (स्वर्गीय) श्री श्रीमन्नारायण को आचार्य विनोबा भावे की इच्छानुसार आयोजित किए जाने वाले आचार्य-सम्मेलन के आयोजन से नहीं रोका था। जनवरी, १९७६ में वर्धा में हुए इस प्रथम आचार्य सम्मेलन में सबसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर एमरजेन्सी को समाप्त करने तथा सभी राजनीतिक नेताओं को रिहा करने की मांग की गई थी, जो निश्चित रूप से श्रीमती गांधी की इच्छा के अनुकूल नहीं थी।

सिफ एक व्यक्ति की सतुष्टि के लिए छापे

बजाज भाटो लिमिटेड के अध्यक्ष श्री राहुल बजाज ने एमर-जेन्सी के दौरान आयकर विभाग की काय पद्धति पर तीखी चोट परत हुए कहा कि उनके यहां सिफ एक व्यक्ति की सतुष्टि के लिए छाप मारे गए थे। उनके यहां छाप मारे जाने से १५ दिन पूर्व ही तत्कालीन बैंकिंग तथा राजस्व मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने ससद में आश्वासन दिया था कि सिफ सदेह के आधार पर कहीं भी छाप नहीं मारे जाएंगे। इसके बावजूद हमारे यहां छापे मारे गए जबकि आयकर विभाग के पास हम लोगों द्वारा की जा रही परीक्षाएं चोरी की कोई पक्की सूचना नहीं थी। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग के एक अधिकारी को हमारे सभी कार्यालयों के पते आदि नाट करने के लिए भारत दशन कराया गया था।

उन्होंने कहा 'हमपर करोड़ा रुपये की चोरी का आरोप लगाया गया, परंतु छापों में बिना हिसाब के सिफ ५८ लाख रुपये का पता लगा उसमें से भी ५२ लाख रुपये का विवाद एमरजन्सी की समाप्ति से पहले ही समाप्त हो गया तथा शेष छ लाख रुपये का विवाद सुलझने की आशा में है।'

छापे एस० आर० मेहता के निर्देश पर

निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहरलाल ने आयोग को अपनी सफाई में बताया कि बजाज उद्योग-समूह पर छापे प्रत्यक्ष कर-बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस० आर० मेहता के निर्देशानुसार मारे गए थे। उन्होंने बताया कि श्रीमती जानकीदेवी के घर की ही

विशय रूप से तलाशी के आदेश नहीं दिए गए थे, बल्कि सभी संप्रभित रिश्तेदारों के घरों की तलाशी में आदेश भी दिए गए थे। उनका कहना था श्रीमती जानकीदेवी का नाम तलाशी का फोड़ अलग से वारंट जारी नहीं किया गया था, उनके घर की तलाशी तो परम्परा का रिश्तेदारों का यहां की तलाशी के अंतर्गत ही आती थी।

उन्होंने स्वीकार किया कि तलाशी का निष्पत्ति लिए जान के समय उनका समक्ष ऐसी कोई विशिष्ट सामग्री नहीं थी जिसका आधार पर तलाशी का निष्पत्ति दिए गए।

इसपर जस्टिस शाहन आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आपने तलाशी के ११४ वारंट जारी किए और आप कह रहे हैं कि आपके सामने उस समय इस उद्योग-समूह का बिगड़ कोई विशिष्ट सामग्री नहीं थी।

श्री लाल ने अपने स्पष्टीकरण में आगे कहा कि आयकर अधिनियम की धारा १३२ अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का बिगड़ सद्व्यवहार के उचित कारण बनते हैं तो उसके यहां तलाशी ली जा सकती है और उसके अंतर्गत ही करदाता का रिश्तेदारों पर भी संदेह का उचित कारण बनता है।

मेहता द्वारा सडन

श्री लाल ने कहा कि वे छापे श्री मेहता के निर्देशानुसार मार गए थे लेकिन श्री मेहता ने इस बात का खटन किया कि उन्होंने ऐसा करने का बारे में कोई निर्देश दिए थे।

(iv) बडौदा रेयन पर छापे

सत्ताका दल द्वारा दलीय हितों के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना न सिर्फ अनुचित है बल्कि गैर कानूनी भी। एमरजेन्सी के दौरान कांग्रेस पार्टी को दिए गए चर्चा से संप्रभित कुछ कागजात निकालने के लिए जिस प्रकार से आयकर विभाग का उपयोग कर बडौदा रेयन कांफ्रेंस के सम्बन्ध में मुरत और बडौदा स्थित कार्यालयों पर छापे मार गए वह इस बात का एक उदाहरण है कि उन दिनों जो कुछ हुआ कम ही था।

२१ अप्रैल, १९७६ को दिन के लगभग ११ बजे निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहरलाल ने उप निदेशक श्री एम० एन० शेण्डे को अपने कमरे में बुलाकर कहा कि एक सप्ताह के अंदर अंदर बड़ोटा रेयन कापॉरेशन व सभी मामला में उनसे निदेशक तथा सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों व यहाँ तलाशी ली जानी चाहिए। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि श्री लाल ने इस निर्देश से पहले तक उनसे किसी अधीनस्थ अधिकारी का यह बात नहीं था कि बड़ोटा रेयन के किसी पदाधिकारी अथवा निदेशक द्वारा कर चोरी की कोई सूचना मिली है और न ही उन्हें द्वारा १३२ के अंतर्गत जांच करने का कोई औचित्य ही नज़र आ रहा था।

श्री लाल से बातचीत के बाद श्री शेण्डे ने इस सम्बन्ध में कुछ सूचनाएँ एकत्र की तथा श्री लाल के पास गए और उन्हें बताया कि बड़ोटा और सूरत जसी जगहों का पहले सर्वे किया जाना आवश्यक है। बाद में श्री लाल की अनुमति से दो सहायक निदेशकों श्री रंगाभास्कर और श्री भापुर को विमान से पहले बम्बई और बाद में सूरत भेजने की बात तय की गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि छाप मारने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इन दोनों अधिकारियों का उनके घरा के लिए रहना करने के पश्चात अभी शाम के पाँच भी नहीं बज पाए थे कि श्री लाल ने एक बार फिर श्री शेण्डे को बुलाया और कहा कि छापे मार जाने की कारवाई २७ अप्रैल को नहीं, जैसी कि पहले योजना थी, बल्कि २४ अप्रैल को ही की जाए। इससे अतिरिक्त कम्पनी के अध्यक्ष श्री फतहसिंह गायकवाड़ तथा प्रबंध निदेशक श्री बी० के० शाह के घरा की किसी भी हालत में तलाशी नहीं ली जाए। अंतिम समय में लिए गए इस निर्णय के बाद उसी दिन श्री भापुर के घर पर यह सूचना भेज दी गई।

तलाशी की कारवाई २४ अप्रैल को सूरत के पाम कम्पनी की फ़ैक्ट्री से शुरू हुई तथा उसी दिन वहाँ कुछ अधिकारियों के घरा की भी तलाशी ली गई। २४ अप्रैल को शनिवार होने के कारण बम्बई स्थित कार्यालय में छुट्टी थी, इसलिए उन्हें सील कर दिया गया, जिसके कारण वास्तविक तलाशी सोमवार २६ अप्रैल को ही हो सकी।

बम्बई स्थित कार्यालयों में तलाशी का कार्य २६ और २७

अप्रैल तक चला। २७ अप्रैल को जब तनाशिया जोर शोर से जारी थी तब सहायक निदेशक श्री एस० तलवार ने जो वहाँ तनाशी कार्यों के प्रमुख थे तलाशी कर रहे एक अधिकारी श्री सी० एस० परिदा से कहा कि श्री लाल के निर्देशानुसार उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेजों को खोजना है जिनमें श्री शाह द्वारा एकत्र किए गए चंदे का जिक्र है। इसके बाद श्री तलवार और श्री परिदा दोनों ही श्री शाह के निजी सचिव के पास गए और उनसे वे फाइलें प्रस्तुत करने को कहा जो चंदे से संबंधित थीं। निजी सचिव ने श्री शाह से विचार विमर्श के बाद 'कप बोर्ड' में कुछ फाइलें निकालकर उन्हें दीं। श्री परिदा द्वारा फाइलों को सरसरी नज़र से देखने पर मालूम पड़ा कि इनमें उन विभिन्न कम्पनियों तथा व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी के लिए धन लिया गया था।

इसी बीच श्री लाल ने जो दिल्ली से बम्बई चले गए थे बम्बई स्थित उप निदेशक श्री बी० आर० बघ का निर्देश दिए कि वे स्वयं बड़ीदा रयन के दफ्तर जाएं और अधिकारियों के साथ मिलकर श्री शाह के ग्रीफ़ेस की तलाशी लें। श्री लाल के निर्देशानुसार श्री बघ जब ग्रीफ़ेस की तलाशी ले रही रहे थे श्री तलवार और श्री परिदा आए और उन्होंने उन्हें चंदे से संबंधित कागज़ों के बारे में बताया।

विस्फोटक सामग्री

श्री बघ के अनुसार श्री शाह को जब ये कागज़ात दिखाए गए तो उन्होंने स्वीकार किया कि इन दस्तावेज़ों में दिखाई गई राशि व्यवसायियों तथा उद्योगपतियों से कांग्रेस पार्टी के लिए प्राप्त की गई थी तथा बाद में इसमें से कुछ राशि गुजरात के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को दे दी गई। श्री शाह के अनुसार वह 'विस्फोटक' सामग्री थी।

इन कागज़ों की बरामदगी के बाद आकर कार्यालय में इन कागज़ों को श्री लाल को दिखाया गया। श्री लाल ने इन्हें अपने पास रखते हुए श्री बघ से कहा कि वे एक घंटे बाद उनसे मिलें। बाद में जब श्री बघ श्री लाल के पास पहुँचे तो उनसे कहा गया कि इन कागज़ों का एक अलग पचनामा बनाया जाए क्योंकि वे

बड़ोदा रेयन के कर निर्धारण से संबंधित नहीं है। श्री परिदा न पहले तो अलग अलग पचनामे बनाने का विरोध किया, परन्तु बाद में श्री लाल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग पचनामे बना दिए। अलग से बनाए गए पचनामे के सभी कामजा के साथ सामान्य पचनामे का एक फाउंडर भी श्री लाल को दिया गया। श्री लाल ने अलग से बनाए गए पचनामे में दस चार आइटमों में से एक के कागज तो लौटा दिए और शेष तीन आइटमों और सामान्य पचनामे में दस फोल्डर को अपने पास रख लिया। अलग से बनाए गए पचनामे में एक फाइल का भी जिक्र था, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्मारिका समिति की बड़ोदा रेयन के नाम ३५१ रसीदें थीं जिनकी कुल राशि साढ़े तीस लाख रुपये के लगभग थी।

जब्त किए गए कामजा को लेकर श्री लाल २८ अप्रैल के आम-पाम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली रवाना होने से पूर्व उन्होंने श्री शेण्डे का फोन कर पश्चिम हवाई अड्डे पर बुलाया। उन्होंने श्री शेण्डे को बताया था कि वे अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण कागजात लेकर आ रहे हैं इसलिए वे पालम आ जाएं। दिल्ली आने के बाद श्री लाल ने जब्त किए गए कागजात प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री एस० आर० मेहता के सुपुर्ण कर दिए। श्री मेहता ने अलग से बनाए गए पचनामे के तीन आइटमों में से एक श्री लाल को वापस कर दिया और शेष दो अपने पास रख लिए।

कागज नहीं लौटाए

श्री मेहता ने श्री लाल से लिए व दो आइटम, जो श्री शाह की कविता से वसूला किए गए चार आइटमों में से थे अपने पास ही रखे। ये दोनो आइटम प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निदेशक (गुप्तचर) को वाद में भी नहीं लौटाए गए जबकि अधिनियम की धारा १३२ के अंतर्गत इसे १५ दिन के भीतर लौटा दिया जाना चाहिए।

छापे मेहता के निर्देशानुसार

श्री लाल ने जिरह के दौरान बताया कि उन्होंने बड़ोदा रेयन पर छापे श्री मेहता के निर्देशानुसार मारे थे तथा उसीके अनुसार

ता वह गलत है।

एमरजेंसी पर दृष्टिकोण

श्री लेखी द्वारा एमरजेंसी के बारे में श्री मेहता का दृष्टिकोण जानने पर उन्होंने कहा "एमरजेंसी के दौरान उहवातावरण मजबूत में बदला हुआ नहीं लगा। उन्हें केवल यही लगा कि जीवन में हर क्षण में सुधार हो रहा है।" लेकिन जब श्री लेखी ने यह पूछा क्या आप चाहेंगे कि एमरजेंसी फिर से लागू कर दी जाए, तो आयोग का कप्तान इसी से गुंज उठा। श्री मेहता ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'श्री लेखी एमरजेंसी के बारे में अपना राजनीतिक दुराग्रह छानने के लिए तयार नहीं हैं और मुझे स्वयं एमरजेंसी से कुछ लेना देना नहीं है।'

(v) पंडित ब्रह्मसं पर छापे

एमरजेंसी के दौरान दिल्ली की एक प्रतिष्ठित फर्म पंडित ग्राम' पर छापे मारे गए। इस कार्रवाई का लक्ष्य बनाया गया था, ताकि चीन प्रदानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी सचिव श्री पी० एन० हक्सर को। इस फर्म के हिस्सेदारों में श्री हक्सर की पत्नी, उनके चाचा तथा बहनोई शामिल थे।

नई दिल्ली के फर्निचर इत्यादि के बजार में स्थित इस फर्म की स्थापना सन १९२७ में हुई थी। यह फर्म बॉम्बे, काश्मीर, कपड़ा के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए वितरण का काम करती थी। इसके अतिरिक्त यह फर्म परलू साज-सज्जा के सामान बेचने का भी धंधा करती थी। इस फर्म की बाद में बादनी चौक में एक शाखा खोली गई।

इस फर्म के हिस्सेदारों में श्री हक्सर के ८२ वर्षीय चाचा श्री आर० एन० हक्सर थे जो एक विख्यात व्यवसायी के साथ-साथ भारत बना केन्द्र के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं और ७५ वर्षीय श्री क० पी० मुजरान, जो रेनव रोड के सदस्य रह चुके थे। श्री मुजरान पिछले में श्री पी० एन० हक्सर के बहनोई होते हैं। इनके अतिरिक्त श्री हक्सर की पत्नी श्रीमती उर्मिला हक्सर तथा

श्री मुशरान की पत्नी श्रीमती ए० मुशरान भी इस फम की हिस्सेदार थी।

फम की कनाट प्लेस स्थित दुकान पर १० जुलाई १९७५ की शाम को साठे पांच बजे दिल्ली प्रशासन के नवगठित प्रवतन विभाग द्वारा उनकी दुकान पर छापे मारे गए। ये छापे एक जुलाई से लागू किए गए मूल्य चिप्पी अधिनियम के अंतर्गत मारे गए थे। काफी खोजबीन के बाद भी छापामार दस्ते को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिल सकी जिसपर मूल्य चिप्पी नहीं लगी हुई थी, लिहाजा दो ऐसे रजिस्टर जप्त कर लिए गए, जिनमें इस विभाग के अनुसार ऐसी बित्री का जिक्र था जो दूसरे राज्यों को गई थी तथा जिनका कश मीमो में जिक्र नहीं था। श्री खन्ना का कहना था कि ये रजिस्टर कारसीट कवर की बित्री से संबंधित थे। इन छापे का नेतृत्व विशेष अधिकारी श्री अशोक कपूर ने किया था।

चूंकि इन छापों में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पकड़ी जा सकी थी इसलिए आगे की कारवाई पर विचार करने के लिए ११ जुलाई का राजनिवास में एक बैठक हुई, जिसमें फम पर पठोर कारवाई के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में श्री कृष्णचंद (उप-राज्यपाल), उनके निजी सचिव श्री नवीन चावला उप महानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर बिनी कर आयुक्त श्री बीरेन्द्र प्रसाद और श्री अशोक कपूर उपस्थित थे। बैठक में यह भी विचार प्रकट किया गया कि फम के हिस्सेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाए तथा मुकदमा चलाया जाए।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार फम की चादनी चौक स्थित दुकान पर १४ जुलाई को मूल्य चिप्पी अधिनियम के अंतर्गत छापा मारा गया। इस छापे का नेतृत्व उस इलाके के ए० डी० एम० श्री एस० एल० अरोड़ा ने किया। दुकान के मनेजर श्री एल० एस० माथुर के अनुसार इन छापों में पुलिस कास्टेबल का भी उपयोग किया गया था परंतु छापे में कोई ऐसा माल नहीं मिल सका जिस पर मूल्य चिप्पी नहीं लगी हुई थी। अचानक श्री अरोड़ा की नजर दुकान के ऊपर की रक़ा पर पड़े कुछ बहला पर पड़ी नज़्जम कुछ माल बचा हुआ था। बहल में रखे प्रत्येक माल पर तो मूल्य चिप्पी नहीं लगी हुई थी परंतु प्रत्येक बटल पर कीमत का काग़ज़ जरूर

लगा हुआ था। श्री अरोड़ा ने इन बड़लों को नीचे उतरवाकर सारा माल बाहर निकाल दिया और आरोप लगाया कि यह अधि नियम के अतगत अपराध है। श्री माधुर का कहना था कि उन्होंने श्री अरोड़ा से कहा कि अधिनियम में इस प्रकार से माल रखे जान पर कोई पावदी नहीं है तथा यह अधिनियम के अतगत ही है, परन्तु श्री अरोड़ा यही कहते रहे कि अधिनियम में परिवर्तन हो गया है तथा यह उसका उल्लंघन है जबकि अधिनियम एक जुलाई से ही लागू किया गया था। इसके बाद श्री अरोड़ा वहाँ से कुछ देर के लिए चले गए।

बिक्री-कर विभाग के भी छापे

श्री माधुर ने बताया कि अभी यह कायबाही चल ही रही थी कि बिक्री कर विभाग के इस्पेक्टर आ गए और उन्होंने भी अपनी पूछताछ जारी कर दी। उस समय दोपहर के लगभग एक बजे का समय रहा होगा।

गिरफ्तारी

उन्होंने बताया कि श्री अरोड़ा, जो बाहर चले गए थे थोड़ी देर बाद वापस आए और उनसे इन बड़लों के बारे में पूछताछ करने के लिए फर्म के हिस्सेदारों को दुकान पर बुलाने को कहा, परन्तु चूँकि श्री मुशरान बीमार थे और श्री हुक्मर भी ठीक नहीं थे इसलिए आ नहीं सक। इसके बाद लगभग दो बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। १५ तारीख को फर्म के हिस्सेदार श्री मुशरान और श्री हुक्मर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि १५ तारीख का उन्हें श्री मुशरान और श्री हुक्मर के तहोरी गेट थान में अगुलिया, अगूठा और हथेली के निशान लिए गए और तीनों को अदालत से जाया गया जहाँ काफी महन के बाद श्री हुक्मर और श्री मुशरान को तो २४ घंटे की जमानत पर छोड़ दिया गया परन्तु उन्हें नहीं छोड़ा गया। उसके बाद दूसरे दिन यानी १६ जुलाई का फिर अदालत में तीनों पेश हुए। एक बार फिर लम्बी बिरह हुई और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। श्री मुशरान और श्री हुक्मर को दोपहर तीन बजे के लगभग ही रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें रात्रि के ग्यारह

श्री मुशरान की पत्नी श्रीमती ए० मुशरान भी इस फम की हिस्सेदार थी।

फम की कनॉट प्लेस स्थित दुकान पर १० जुलाई, १९७५ की शाम को साठे पांच बजे दिल्ली प्रशासन के नवगठित प्रवर्तन विभाग द्वारा उनकी दुकान पर छापे मारे गए। ये छापे एक जुलाई में लागू किए गए मूल्य विष्पी अधिनियम के अंतर्गत मारे गए थे। काफी खाजबीन के बाद भी छापामार दस्ते को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिल सकी जिसपर मूल्य विष्पी नहीं लगी हुई थी, लिहाजा दो ऐसे रजिस्टर जब्त कर लिए गए, जिनमें इस विभाग के अनुसार ऐसी बिथी का जिक्र था जो दूसरे राज्यों को गई थी तथा जिनका कश भीमो में जिक्र नहीं था। श्री खन्ना का कहना था कि ये रजिस्टर फारमीट खबर की बिनी से संबंधित थे। इस छापे का नेतृत्व विशेष अधिकारी श्री अशोक कपूर ने किया था।

चूंकि इन छापों में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पकड़ी जा सकी थी इसलिए आगे की कारवाई पर विचार करने के लिए ११ जुलाई को राजनिवास में एक बैठक हुई जिसमें फम पर कठोर कारवाई के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में श्री कृष्णचंद (उप राज्यपाल), उनके निजी सचिव श्री नवीन चावला उप महानिरीक्षक (रेंज) श्री पी० एस० भिण्डर बिथी कर आयुक्त श्री बीरेन्द्र प्रसाद और श्री अशोक कपूर उपस्थित थे। बैठक में यह भी विचार प्रकट किया गया कि फम के हिस्सेदारा को गिरफ्तार कर लिया जाए तथा मुकदमा चलाया जाए।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार फम की चादनी चौक स्थित दुकान पर १४ जुलाई को मुख्य विष्पी अधिनियम के अंतर्गत छापा मारा गया। इस छापे का नेतृत्व उस इलाके के ए० डी० एम० श्री एस० एल० अराड़ा ने किया। दुकान के मनजर श्री एन० एम० माधुर के अनुसार इन छापों में पुलिस कास्टेबल का भी उपयोग किया गया था परन्तु छापे में कोई ऐसा माल नहीं मिल सका जिस पर मूल्य विष्पी नहीं लगी हुई थी। अचानक श्री अराड़ा की नजर दुकान के ऊपर की रकों पर पड़े कुछ बडला पर पड़ी निम्न कुछ माल बघा हुआ था। बडल भर रख प्रत्येक माल पर तो मूल्य विष्पी नहीं लगी हुई थी, परन्तु प्रत्येक बडल पर भीमत का कांड जरूर

लगा हुआ था। श्री अरोना न इन बडला को नीचे उतरवाकर सारा माल बाहर निकाल लिया और आरोप लगाया कि यह अधि नियम के अंतर्गत अपराध है। श्री मायुर का कहना था कि उन्होंने श्री अरोना से कहा कि अधिनियम में इस प्रकार से माल रखे जान पर कोई पावना नहीं है तथा यह अधिनियम के अंतर्गत ही है, परंतु श्री अरोना यहां कहते रहें कि अधिनियम में परिवर्तन हो गया है तथा यह उमका उल्लंघन है। जबकि अधिनियम एक जुलाई से ही लागू किया गया था। इसके बाद श्री अरोना वहां से कुछ देर के लिए चले गए।

बिन्नी-कर विभाग के भी छापे

श्री मायुर ने बताया कि अभी यह वायवाही चल ही रही थी कि बिन्नी-कर विभाग के इन्स्पेक्टर आ गए और उन्होंने भी अपनी पूछताछ जारी कर दी। उस समय दोपहर के लगभग एक बजे का समय रहा होगा।

गिरफ्तारी

उन्होंने बताया कि श्री अरोना जो बाहर चले गए थे, याड़ी दर बाद वापस आए और उनसे इन बडला के बारे में पूछताछ करने के लिए फर्म के हिस्सेदारों को दुकान पर बुलाने को कहा, परन्तु चूंकि श्री मुशरान बीमार थे और श्री हुस्सर भी ठीक नहीं थे इसलिए जा नहीं सक। इसके बाद लगभग दो बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। १५ तारीख को फर्म के हिस्सेदार श्री मुशरान और श्री हुस्सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि १५ तारीख को उन्हें श्री मुशरान और श्री हुस्सर के लाहारी गेट यान में अगुनियो खपूठा और हथेली के निशान दिए गए और तीनों को अदालत में जाया गया जहां काफी बहस के बाद श्री हुस्सर और श्री मुशरान को तो २८ घंटे की जमानत पर छोड़ दिया गया परन्तु उन्हें नहीं छोड़ा गया। उसके बाद दूसरे दिन यानी १६ जुलाई को फिर अदालत में तीनों पेश हुए। एक बार फिर लम्बी जिरह हुई और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। श्री मुशरान और श्री हुस्सर को दोपहर तीन बजे के लगभग ही रिहा कर लिया, लेकिन उन्हें रात्रि के प्यारह

बजे तिहाड़ जेल सरिहा लिया गया ।

श्री माथुर ने बताया कि रिहाई व तीन चार दिन बाद ही चादनी चौक पुलिस थान के सत्र इस्पक्टर श्री सतप्रकाश न उन्हें बुलाकर कहा कि फम व हिस्सदारा म जो दो महिलाए हैं उनकी अग्रिम जमानत करा ली जाए क्योंकि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है । उन्होंने जब इस बात से श्री मुशरान और श्री हक्मर को अवगत कराया तो उन्होंने थोड़ी दूर बाद फोन पर कहा कि 'आप इबार कर दीजिए कि महिलाए अग्रिम जमानत के लिए तयार नहा हैं और व उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं । उन्होंने इस बात से सतपाल को सूचित कर लिया था, परंतु बाद में ऐसी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं ।

श्री आर० एन० हक्सर न आयोग को बताया कि १५ जुलाई को जब वे सवेरे घूमने का कार्यक्रम समाप्त कर घर लौटकर चाय पी रहे थे कुछ पुलिसवाले आए और बोले कि 'आप गिरफ्तार हैं ।' उनके लिए यह आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि पिछले दिना हुई घटनाओं को देखते हुए इस बात की उन्हें पहले ही आशंका थी । उन्होंने पुलिसवाला से कहा कि उन्हें नहाने तथा नाश्ता करने का समय दिया जाए जिस मान लिया गया । उन्हें गिरफ्तार कर लाहोरी गेट पुलिस थाने ले जाया गया जहां उनकी अगुलिया, अगूठे और हथेली के निशान लिए गए ।

श्री मुशरान न बताया कि उन्हें भी १५ जुलाई को सवेरे गिरफ्तार कर लाहोरी गेट पुलिस थाने ले जाया गया जहां उनके भी निशान लिए गए ।

उन्होंने बताया कि मुख्य मद्रापालिटन मजिस्ट्रेट ने लगभग डेढ़ घंटे तक उनके वकील व तक सुनने के बाद २४ घंटे की जमानत देना मजूर किया और वह भी काफी आनाकानी के बाद । दूसरे दिन भी यही हाल रहा । इसपर जस्टिस शाह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा जहां एक ओर थोड़ी-सी बहस के बाद ही बड़ बड़ मामला म लागो को जमानत दे दी जाती है वहीं इतने छोटे स मामले म डेढ़ घंटे की बहस के बाद भी मजिस्ट्रेट को जमानत देने म आनाकानी हो रही थी ।

श्री मुशरान ने बताया कि १५ तारीख को उनकी तथा श्री हक्सर की गिरफ्तारी की खबर रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित

की गई, परंतु उन्हें जमानत पर छाड़न का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। इस प्रकार की खबर से उनके परिचितों का परेशान होता ज़रूरी था।

श्रीमती गांधी भी सजय से प्रसन्न नहीं थीं

श्री मुशरान का कहना था कि १५ तारीख की रात को उनकी पत्नी ने अपने भाई श्री हुस्मर का फोन कर इस बारे में सूचना दी, परंतु उन्होंने कहा कि वे इस मामले में शायद कुछ नहीं कर सकेंगे। श्री मुशरान ने बताया कि श्रीमती अरुणा आसफ़अली से उनका काफी निकटता था, इसलिए जब उन्हें इस बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने श्रीमती गांधी से बातचीत की। श्रीमती गांधी से उनकी क्या बातचीत हुई, इस बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, परंतु श्रीमता आसफ़अली ने उन्हें बताया था कि श्रीमती गांधी स्वयं भी सजय गांधी के काम करने के तरीके से प्रसन्न नहीं हैं क्योंकि उनके बारे में सनडा शिकायतें आती रहती हैं।

हथेली के निशान नहीं

बाद में लाहोरी गट थान के एस० एच० आ० श्री जगदीश न आयाग को बताया कि तीनों व्यक्तियों की अंगुलियाँ और अंगूठा के निशान उनमें निशान से नहीं लिए गए थे, बल्कि यह कार्य जाच अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया था। जाच अधिकारी ने इस बात से इन्कार किया कि उसने इन लोगों की हथेली के भी निशान लिए थे। उनका कहना था कि यदि ये लोग ऐसा कहते हैं तो झूठ बोलते हैं। उन्होंने बताया, निशान लेने की कार्यवाही वही सिनाह्त अधिनियम के अंतर्गत की गई थी तथा यह चालाक की आजापुरी लिए ज़रूरी था।

फम का तम्र किए जाने की कार्यवाही यहाँ समाप्त नहीं हो गई थी। फम की कनाट प्लस स्थित दुकान के मनेजर श्री आर० के० खन्ना ने बताया कि विन्नी-कर विभाग तथा मूल्य विषयी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई के बाद फम पर आयकर विभाग के दरिये भी पेशान करने की कार्रवाई कराई गई। फम को १६ जुलाई को एक नागम लिया गया जिसमें १६७३-७४ के खाता के संबंध में २२ जुलाई तक अपने जवाब दायित्व करने का कहा गया

था। काफी परशानिया के बाद ३० सितम्बर को फम क खिलाफ फैसला दे दिया गया। फम न ४,४३,३१२ रुपये की आय का आकलन दिया था लेकिन आयकर विभाग न उम वष के लिए ६ ३३ १८१ रुपये का निर्धारण कर २,४१ १३५ रुपये का कर लगा दिया। इसमें अतिरिक्त फम के हिस्मदारा की आय अलग से निर्धारित की गई। विभाग की ओर से इस राशि क पनत्नी वसूल करने का भी नोटिस दिया गया। फम द्वारा निम्नी उच्च न्यायालय में अपील की गई जिस स्वीकार नहा दिया गया परन्तु सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने पर उस स्वीकार कर लिया गया।

आयकर के छापे घबन के निर्देश पर

इस सबध में आयकर आयुक्त श्री ज० सी० सूधर का कहना था कि पटित घदस पर मार गए छापे सत्वालान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० व० घबन के निर्देशानुसार मारे गए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि यह निर्देश प्रधानमंत्री निवास से आए थे इसलिए इनका पानन किया गया।

बिभी-कर के सबध में मारे गए छापे के बारे में बिभी-कर आयुक्त श्री बीरेंद्र प्रसाद का कहना था कि उन्हें इस बारे में सूचित किया गया था कि फम की कमाट प्लस तथा चान्नी बौर स्थित दुकानों पर छापे मार जाते हैं परन्तु चूंकि इस विषय दुनान पर ही छापे मारे जाना उचित नहीं होता इसलिए अन्य दुकाना पर भी छापे मारे जाने को कहा गया।

'कठोर कार्रवाई' सजय के निर्देश पर

उन्होंने बताया कि राजनिवास में हुई बटक में उन्हें कहा गया था कि फम के विरुद्ध 'कठोर कार्रवाई' की जानी चाहिए क्योंकि श्री सजय गांधी ऐसा चान्ते हैं। इसके बाद उनकी श्री कण्णचद से काफी दूर तक उनके कमरे में इस सबध में बातचीत हुई।

दिल्ली के सत्वालीन उपराज्यपाल के निजी सचिव श्री नवीन चावला ने बताया कि प्रधानमंत्री निवास से उनके अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० व० घबन ने उन्हें फोन कर यह सदेश श्री कण्णचद को देने को कहा था कि श्री सजय गांधी को सूचना

मिली है कि कनाट प्लस स्थित दुकाना से भारी मात्रा में चारों की जा रही है। इसलिए वहां छापे मारे जाएं तथा इन छापों में पड़ित ब्रह्म को भी बरखा जाए हालांकि वं काफी प्रभावशाली है। श्री चावला का कहना था कि श्री कण्णबद का यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पड़ित ब्रह्म पर भी छाप मारने की बात कही गई है। श्री कण्णबद ने इसकी पुष्टि के लिए श्री धवन का फोन किया तो श्री धवन ने यही बात दोहराई। इसका बाद उपराज्यपाल ने उनसे अतिरिक्त मुख्य सचिव में इस मामले पर दूसरे दिन कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

श्री चावला का कहना था कि उपराज्यपाल ने उन्हें इन छापों में संबंध में एक प्रेस विज्ञापन जारी कराने को भी कहा था।

निर्देश धवन से नहीं, सीधे सजय से मिले थे

श्री कण्णबद ने श्री चावला के इस बयान का एकदम गलत बताया कि उन्होंने यह कहा था कि यह संदेश श्री धवन ने दिया है। जबकि सत्य यह है कि श्री चावला ने उनसे कहा था कि श्री सजय गांधी ने उन्हें ऐसा निर्देश दिया है। श्री चावला ने इस संबंध में कभी भी श्री धवन का जिक्र नहीं किया था।

उन्होंने जस्टिस शाह के एक प्रश्न का उत्तर में बताया कि 'जहां तक इसकी पुष्टि करने का मामला है श्रामान जब श्री गांधी ने स्वयं फोन कर श्री चावला से यह बात कही थी तब भरी यह एक बड़ी सुखता होती कि मैं श्री गांधी का फोन कर इसकी पुष्टि करता। उनका कहना था कि इस पूरे मामले में श्री चावला या गांधी से सीधे सम्पर्क में था तथा उन्हें सिर्फ छापों में संबंध में सूचित किया गया था गिरफ्तारिया के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। और न ही मैं इस बारे में कोई निर्देश ही लिए था।'

एस० जी० बनाम एस० जी०

श्री कण्णबद ने अपनी इस बात को पुन दोहराया कि उन निम्न निम्नी का प्रामाण्य सिर्फ वं चार या पांच व्यक्ति चला रहे थे जिनका श्री गांधी से सीधा सम्पर्क था। इन अधिकारियों में श्री चावला और श्री भिषदर भी शामिल थे। उन्होंने कहा श्रीमान सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उही मामले में पूछा जाता था जहां कोई वित्तिक

परशानी उठ खड़ी होती थी । वास्तव में यदि आप निल्ली प्रशमन के काम में एल० जी० (उपराज्यपाल) के स्थान पर एस० जी० (सजय गांधी) कर लें तो सब बात स्पष्ट हो जाएगी ।'

छापो की कार्रवाई श्रीमती गांधी की जानकारी में

श्री कृष्णचंद ने सरकारी वकील श्री प्राणनाथ 'नखी' के प्रश्न के उत्तर में बताया कि श्रीमती गांधी ने श्रीमता जरणा आमफजली का जिक्र करने हुए उनसे इस बारे में जानकारी चाही थी । उन्होंने स्वीकार किया कि श्रीमती गांधी का इस मामले की जानकारी तो रही ही होगी अन्यथा वे फोन करते ही उनपर बरस पड़ता कि ऐसा कैसे हुआ परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था ।

उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि उन्होंने श्री चावला से इस बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करने को कहा था ।

छाया तक पसंद नहीं

जहां श्री चावला यह कह रहे थे कि उन्हें छाप मार जान के बारे में श्री धवन ने निर्देश दिए थे वहां श्री धवन ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने श्री चावला को कोई निर्देश नहीं दिया । उनका कहना था कि श्रीमान श्री चावला उनका निर्देश लेना तो दूर, उनकी छाया तक को पसंद नहीं करते थे । उन्होंने कहा श्रीमान श्री चावला इस मामले में उन लोगों के नाम नहीं ले सकते जिनमें उन्होंने यह निर्देश दिया था इसीलिए उनका नाम लिया जा रहा है ।'

श्री धवन ने जस्टिस शाह की ओर भयातिव होकर कहा, श्रीमान क्या आप उन दिनों निल्ली में नहीं थे ?

इसपर जस्टिस शाह ने कहा हाँ आपका कहना सहाह मैं उन दिनों यहाँ नहीं था ।

तभी आप श्री चावला के शिकार हान में बच गए । श्रीमान् श्री चावला काफ़ी महत्वाकांक्षा यकिन थे और मर पद पर स्वयं जाना चाहते थे ।

(vi) दो ट्रेड यूनियन नेताओं के यहा छापे

एमरजन्सी में न सिर्फ सरकारी अधिकारियाँ और राज नीतियों को बल्कि ट्रेड यूनियन नेताओं को भी नहीं छाना गया। इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कारण यह था कि इन्होंने बैंक कमचारियों को बोनस दिलाने से संबंधित आंदोलन में बराबर भाग लिया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री राजेन्द्र कुमार धवन ने २७ जुलाई, १९७५ को बेद्रीय जाच ब्यूरो के तत्का लीन निदेशक श्री दशरथ सन का प्रधानमंत्री निवास बुलाया और उनसे कहा कि 'बम्बई के दो ट्रेड यूनियन नेता श्री डी० पी० चट्टा और श्री प्रभातकर लोगो को ऋण दिलाने का प्रस्तावन देकर उनसे यूनियनों के लिए चढ़ा बमूल कर रहे हैं तथा इस धन को छुद खर्च कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।'

श्री सन ने इस बारे में एक नोट लिखकर आयकर विभाग में निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहर लाल का भेजा। श्री लाल ने इस नोट पर कार्रवाई करते हुए श्री सन के निवास की तलाशी लेने का आदेश दिए और श्री चट्टा के सम्बंध में मामला बम्बई शाखा का सुपुर्न कर दिया।

तलाशी में जाच ब्यूरो का हाथ नहीं

श्री सन ने विरह के दौरान प्रश्नों के उत्तर में बताया कि क्रांतीय जाच ब्यूरो ने इन दोनों नेताओं के घरा की तलाशी लेने के सम्बंध में कोई निर्देश नहीं दिया था। उन्होंने आयकर विभाग को सिर्फ व सूचनाएँ ही दी थी जो उन्हें श्री धवन से प्राप्त हुई थी। तलाशी आदि का काम आयकर विभाग द्वारा कराया गया। उसमें जाच ब्यूरो का कोई हाथ नहीं था।

श्री धवन के वकील श्री के० जी० भगत के प्रश्नों के उत्तर में श्री सन ने बताया कि उन्होंने किसी अधिकारी से यह नहीं कहा था कि ये सूचनाएँ श्री धवन से मिली हैं क्योंकि हमारे यहा कभी भी सूचना-स्रोत का नाम नहीं बताया जाता।

सरकारी वकील श्री प्राणनाथ रेड्डी द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वे जानते थे कि उन्हें ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ

औजार के रूप में बाम मलिया जा रहा था श्री सन ने कहा, 'उह सिर्फ सूचना प्राप्त हुई थी, व नहीं वह मकते कि उह किसीके द्वारा औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया था अथवा नहीं।'

'क्या आपका मालूम है कि एमरजेसी के दौरान वानस सम्पत्ति करने के सम्बन्ध में कोई अध्यादेश जारी किया गया था ?'

श्री सन ने कहा 'मुझे मालूम नहीं।

श्री सन ने आयोग के प्रश्नों के उत्तर में बताया कि इस मामले में तो कोई प्रारम्भिक जांच ही करवाई गई थी और न ही कोई मामला दर्ज किया गया था। उनकी संस्था ने सिर्फ सूचनाएं एजन्स को और जब यह सद्ध हुआ कि मामले में आयकर की चोरी हुई है तो उस आयकर विभाग को भेज दिया गया और यही एक सामान्य प्रक्रिया थी।

उन्होंने बताया कि नेताओं के घरों की तलाशी लिए जाने के बाद श्री लाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का या तो उन्होंने श्री आम महुता को भेज दिया था या फिर श्री धवन के पास। उह ठीक तरह से माद नहीं आ रहा है कि उन्होंने यह रिपोर्ट किस भेजी थी।

जस्टिस शाह ने उनसे जानना चाहा क्या राष्ट्रीयकृत बका के कमचारी सरकारी कमचारी हात हैं जबकि उनका तो यही ख्याल है कि वधानिक नियमा के कमचारी सरकारी कमचारी नहीं हात।

जांच यूरों के पास राष्ट्रीयकृत बका के खिलाफ भारी सख्या में मामले पड़े हैं। उह सरकारी कमचारियों की तरह ही समझा जाता है।'

(vii) मारुति का मामला दबाया गया

एमरजेसी के दौरान आयकर विभाग द्वारा जो भेदभावपूर्ण नाति अपनाई गई उसकी एक शतक मारुति लिमिटेड के सम्बन्ध में की गई कारवाई सम्मिलित है। जहां अय फर्मों पर मात्र सद्ध के आधार पर छापे भारे गए और उनके परिवारजनों तक को तग किया गया यहा मारुति के शेयरों के सम्बन्ध में समझ में पूछे गए एक प्रश्न के सम्बन्ध में की गई जांच का दवा दिया गया।

संसद में भारत के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी कि उसमें शेयर होल्डरों के नाम कितना कितना कर बाकी है। इसके लिए आयकर अधिकारियों ने भारत के शेयर होल्डरों की सूची मांगी, परन्तु वह सूची नहीं दी गई। निदेशक (गुप्तचर) श्री हरिहर लाल द्वारा प्रत्यक्ष कर बोर्ड से निर्देश मांगने पर उह कहा गया कि भारत या उसके शेयर होल्डरों से कोई सूचना नहीं मांगी जाए। ऐसे ही निर्देश भारत के दावेनामी शेयर होल्डरों के बारे में भी दिए गए।

छद्म नाम

पश्चिम बंगाल के आयकर आयुक्त ने सूचित किया था कि बलकृष्ण में श्रीमती शारदादेवी और श्रीमती शांतीदेवी नाम की दो महिलाएँ नहीं हैं जिनके नाम से क्रमशः ३० हजार और २४ हजार रुपये मूल्य के शेयर खरीदे गए हैं। आयुक्त के अनुसार यह छद्म महिलाएँ थी अर्थात् ये शेयर छद्म नामों से खरीदे गए थे।

जिल्ला में श्री हरिहरलाल ने २४ जुलाई, १९७५ का इस सूचना पर नोट लिखा कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष चाहते हैं कि जब तक वे निर्देश न दें, आगे की कारवाई न की जाए।

अधिकारियों पत्र-व्यवहार की सूचनाओं के अनुसार प्राथमिक दृष्टि से यह एक मामला बनता था तथा सामान्य परिस्थितियों में इसपर कारवाई भी की जा सकती थी परन्तु प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देशानुसार ही ऐसा नहीं किया गया।

घाट में संसद में इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा गया कि मामला की जांच जारी है और शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। परन्तु मध्य रात यह भी कि इसपर प्रधानमंत्री सचिवालय में स्वीकृति नहीं आई थी, जांच तो हो ही चुकी थी।

मेहता द्वारा स्वीकार

श्री मेहता ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होंने ही यह निर्णय लिए थे कि बिना बोर्ड की पूर्ण अनुमति के भारत के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच नहीं कराई जाए।

नफा कहना था कि भारत का मामला इतना नाजुक हो गया था कि उन्होंने यह उचित नही समझा कि कोई ऐसी सूचना दी जाए

जो मरवारी रिकार्डों में नहीं है। अतः उन्होंने केवल सरकारी रिकार्डों के आधार पर ही सूचनाएँ देने का आदेश दिया।

जस्टिस शाह द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपन माहति के सम्बन्ध में सूचना एकाग्र करने पर रोक क्यों लगा दी थी श्री मेहता ने कहा 'उन्होंने दिमाग में यही बात थी कि कानून के अनुसार व्यक्तिगत मामला की जांच पर रोक है इसीलिए उन्होंने श्री लाल ने कहा था कि मैं इस बार में तत्काल कोई निर्देश नहीं दूँ सनता। उन्हें पूरे मामले का अध्ययन करने में एक महीना का समय लगा।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'क्या इसके बाद आपन कोई निर्देश दिए?'

नहीं मैंने समझा था कि मुझे इस बात में सूचित किया जाएगा।'

यानी जब तक आपकी कोई सूचित नहीं करता आप रोक बापस नहीं लत ?'

'हां' तो अभी तक बापस नहीं ली गई है यद्यपि मैं हट चुका हूँ।

श्री मेहता द्वारा सवालियों के जवाब घूमा फिराकर देने पर जस्टिस शाह ने किंचित रोष प्रकट करते हुए कहा 'आप ठिठाई न करें मैं आपको एक उच्चाधिकारी के रूप में पूरा जमाना प्रदान कर रहा हूँ और आप जानकारी देने के स्थान पर बहम कर रहे हैं और धोखी दलीलें दे रहे हैं। इसके बावजूद श्री मेहता अपनी बात दोहराते रहे। उन्होंने कहा 'आप जो चाहें अब लगा सकते हैं।'

श्री मेहता ने इस बात से अनभिज्ञता प्रकट की कि माहति सम्बन्धी किसी भी प्रश्न का उत्तर श्रीमती गांधी द्वारा अनुमोदित करार बिना समझ की भेजा जाना निषिद्ध था।

जहां श्री मेहता ने इस बात में इकार किया वहीं केन्द्रीय एक्साइज एंड कस्टम बोर्ड के अध्यक्ष श्री एम० जी० ए० ब्रोल ने स्वागत किया कि उन्होंने स्वयं वर्किंग एव राजस्व मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के निर्देशानुसार समझ के प्रश्नोत्तर सम्बन्धी उत्तरों का प्राप्ति तयार कर प्रधानमंत्री-सचिवालय भेजा था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री सचिवालय में एक निजी सहायक श्री

एम० एम० एन० जमाना भी इस बात की पुष्टि की तथा तत्संबंधी एक उत्तर के प्रारूप पर अपन हस्ताक्षर से निखित उम टिप्पणी की भी तत्संगीत की जिम्मे लिखा था कि प्रधानमंत्री ने यह प्रारूप देख लिया है।

श्री लाल ने जस्टिस शाह के इस प्रश्न पर कि उहान श्री महता से आदेश लेना क्या उचित समझा कहा 'मर पूर्ववर्ती अधिकारिया के समय में ही यह बात स्पष्ट हो चली थी कि बांड की जायत के बिना मारनि के घारे में कोई कारवाई न की जाए।

याद दिलाने पर मुसीबत

श्री महता ने श्री लाल ने कहा आपने बात में मुझे हम आदेश के सम्बन्ध में याद क्या नहीं दिलाया ?

आपसे जमी बात हुई थी उसमें स्पष्ट था कि यदि मैं याद दिलाया तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा।

कभी मुसीबत ?

मैं आपसे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था।

श्री महता ने कई बार जानना चाहा कि श्री लाल की किस तरह की मुसीबत में पड़ जान की आशंका थी। इसपर हसी के साथ जस्टिस शाह ने कहा वह मुसीबत क्या हो सकती थी यह तो आपपर ही निर्भर था।

श्री महता ने कहा इसका अर्थ यह है कि श्री लाल मुझ तक बात नहीं बता रहे हैं। इसपर जस्टिस शाह ने खुलासा करते हुए उन्हें स्मरण कराया कि एमरजेंसी के दुर्भाग्यपूर्ण समय में बहुत-से लोगों का आदेश न मानने के कारण मुसीबत का सामना करना पड़ा था।

(viii) रिश्तों का मामला रफा दफा

एमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री निवास में न सिर्फ बड़े-बड़े मामला ॥ श्री अग्रजजी की जानी थी बल्कि छोट अधिकारिया के छोट छोट मामला में भी अग्रज दिया जाता था। श्री प्रचार में एक मामला में एक समय कहर का रंग हाथा रिश्तों सेन पर पकड़े

जान के बावजूद उसके मामले का प्रधानमंत्री निवास के निर्देशों के आधार पर अदालत में नहीं भेजा और मामला रफा-दफा कर दिया गया।

श्री सुदर्शन वर्मा नामक इस व्यक्ति का श्री शापालदाम नामक एक अन्य व्यक्ति द्वारा यह शिकायत करने पर कि वह किसी काम को पूरा करने के लिए रिश्वत मागता है केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा जाल फलाकर २०० रुपये रिश्वत लेने पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

इस घटना के दो-तीन दिन बाद श्री वर्मा केन्द्रीय जाच ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक श्री देवदत्त सन से प्रधानमंत्री निवास में मिले और उनसे कहा कि वह एक क्लक है और जाच ब्यूरो द्वारा उनसे खिलाफ रिश्वत का जो मामला बनाया गया है वह झूठा है। श्री वर्मा ने मन से अनुरोध किया कि एक क्लक के नाते वह मुक्त दमा नहीं लड़ पाएंगे इसलिए यह मामला समाप्त कर दिया जाए। इसपर श्री सन ने उनसे कहा कि बेहतर यही होगा कि आप इस सम्बन्ध में अपना पापन भेज दें।

इसके बाद प्रधानमंत्री निवास में किमीन फान के श्री सन से इस मामले का जल्दी से जल्दी निपटान का वृत्त। बाद में श्री वर्मा के खिलाफ रेलवे को मुकदमा चलाने के लिए भेजी गई सिफारिश वापस मंगा ली गई।

श्री सन ने आयोग को बताया कि श्री वर्मा की उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री निवास में हुई थी। शायद वे प्रधानमंत्री के जन-दरबार में अपनी शिकायत लेकर गए थे। उन्होंने श्री वर्मा से हुई दूसरी भेंट में इस सम्बन्ध में एक लिखित पापन देने का कहा परन्तु उन्हें याद नहीं है कि उनका कार्यालय में वह आपन पहुंचा था या नहीं।

श्री सन ने कहा कि उन्हें याद नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री निवास से किसने फोन किया था। परन्तु उसने स्तना जरूर कहा था कि मामले का मयाशोध निपटाया जाए। उन्होंने साथ ही यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार के मामले उन तक सीधे नहीं आते बल्कि ग्राहक स्तर पर ही निपट जाते हैं।

उन्होंने बताया कि रंग हाथों पकड़ जाने के बावजूद सभी मामले अदालत में नहीं भेजे जाते क्योंकि बाद में अभियुक्त पिछली तारीख में लिखा प्रोन्नोट दिखाकर यह सिद्ध करने की कोशिश करते

है कि उधार दिया धन वापस लिया है।

श्री सेन ने बताया कि महमलालय के निर्देशों के अनुसार पहले इस प्रकार के मामले को विभागीय कारवाई के लिए भेजा जाता है और बाद में मुकदमा चलाया जाता है।

उन्होंने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री निवास से किसीन फोन कर मामले को जल्दी निपटाने की जरूरत कहा था, परन्तु उसमें दबाव जसी कोई बात नहीं थी।

रेलवे के सतकता अधिकारी श्री महेश्वर प्रसाद ने बताया कि श्री वर्मा के भाई ने जो रेलवे में ही सतकता अधिकारी थे, उनसे यह मामला वापस लाने को कहा था। इसके अतिरिक्त जांच ब्यूरो के एक अधिकारी ने उन्हें बताया था कि उनपर दबाव डाला जा रहा है किन्तु उन्होंने श्री वर्मा के संबंध में रसवे की मुकदमा चलान की जो सिफारिश की है उस वापस लिया जाए।

जांच ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक श्री एन० पी० मुखर्जी ने बताया कि रय हाथा पकड़े जाने के दो-तीन दिन बाद ही श्री सेन ने उनसे इस मामले में संबंधित फाइलें दिखाने को कहा था। श्री सेन ने फाइलें देकर पश्चात् कहा था कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए। श्री सेन के आदेशानुसार उन्होंने सम्बंधित पुलिस अधीक्षक को जिनमें मामला रेलवे को भेज दिया था, उस वापस मगाने को कहा।

बाजार बंद

आयाग के समक्ष श्री गोपालदाम भी जिहाने श्री वर्मा को पकड़वाया था उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को रवे हाथा पकड़े जाने के बाद जूद छोड़ दिया गया और एक तरीके से मामला भी समाप्त हो गया, परन्तु उनके व दो सौ रुपये अभी तक वापस नहीं किए गए हैं जिनके कारण यह सब हुआ। उन्होंने आयाग में प्रायना की कि उन्हें वे दो सौ रुपये वापस दिलवाए जाएं, क्योंकि जब भी वे इन रुपये को मागने के लिए जांच ब्यूरो के कार्यालय गए तब भी कहा गया कि 'हमने बाजार बंद कर दिया है यहां बार-बार क्या आन हो?'

७ एमरजेंसी में सफाई के नाम पर नादिरशाही

भारत की राजधानी नई दिल्ली की नई और आधुनिक इमारतों में थोड़ा-सा हटकर यदि पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके पर नज़र डालें तो वहाँ ऐसी पुरानी इमारतें पाएँगी जिन्होंने हिन्दुस्तान को न सिर्फ़ बनती बिगड़ती सल्तनत का ही देखा है बल्कि अपने गम में भारत के उस पुराने इतिहास का भी छिपा रखा है जिस इंसान हिन्दू और मुसलमान शासकों ने रचा है। पुरानी दिल्ली की ये पुरानी परन्तु शानदार इमारतें आज भी भारत की प्राचीन संस्कृति और कला का उजागर कर रही हैं।

पुरानी दिल्ली और उसके चारों ओर का नई दिल्ली का इलाका और उसमें जगह-जगह बड़ी आवासीय वस्तियाँ के कुछ पुराने और अवैध निर्माणों को एमरजेंसी के दौरान सिर्फ़ इसलिए गिरा दिया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के पुत्र श्री सत्य गांधी को यह सब दिल्ली की सुन्दरता पर बदनुमा दाग की तरह नज़र आता था।

ऐतिहासिक स्मारक भी गिराए गए

इमारतें गिराए जान के इस दौर में ऐतिहासिक स्मारकों को भी नहीं बचसा गया हालाँकि स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री यह दम भरा करती थी कि इनकी सुन्दरता को बरकरार रखा जाएगा परन्तु इस पाग़लपन में सुन्दरता को बनाए रखना तो दूर की बात शाहजहाँ के दिल्ली स्थित 'अस्यामी निवास कला महल' को भी गिरा दिया गया।

एमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार से अनधिकृत निर्माणों के नाम पर बनी-बनाई इमारतें दुकानें बच्चे मराना और झुग्गियों आदि को गिराया गया वह अपने-आपमें एक आश्चर्य है। एमरजेंसी के पूरे जहाँ १९७३ १९७४ और जून १९७५ तक कुल १८०० निर्माणों को गिराया गया था लेकिन एमरजेंसी के बाद २३ मार्च १९७७ तक एक लाख ५० हजार १०५ निर्माण गिराए गए।

इमारतें और दुकानें को गिराने का सिलसिला पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद और तुकमान गेट इलाके तक ही सीमित नहीं रहा, १९४

बकि नई दिल्ली में भी इसके नजारे देखे गए। दिल्ली-गुडगाव
महल पर स्थित कापमहेडा गाव, दक्षिण दिल्ली की एक बस्ती
अजुन नगर, महरोली रोड पर स्थित अघेरिया मोड पर बनी कुछ
पुरानी दुकानें तथा मकान और न जाने कितनी बस्तियां और मकान
मुम्बई के इस अभियान की भेंट चढ़ा दिए गए।

(1) जामा मस्जिद की सफाई तुर्कमान गेट की तबाही

पुरानी दिल्ली का एक पुराना और प्रसिद्ध स्मारक है जामा
मस्जिद। एमरजेंसी की घोषणा से पूर्व जामा मस्जिद के चारों ओर
के इलाके में मकानों की दुकानें बनी हुई थी जिनमें बहा के लोग की
न भिन्न आवश्यकताओं की ही पूर्ति होती थी बल्कि हजारा परि
वारों का राग रोनी भी चलती थी। एमरजेंसी के दौरान हम इनके
को यून्सूत बनाने के नाम पर यहां की दुकानों को उखाड़ तो दिया
गया, मस्जिद दुकानों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की
गई जबकि हमसे पूर्व हम इलाके के लोगों को पाईवास्तान योजना
में बसाया जाना था और शुरू में यह आश्वासन दिया गया था कि
पहले इस योजना को पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही हम
इलाके के लोगों का हनाया जाएगा। परंतु उस योजना पर अभी
काम शुरू भी नहीं हो पाया था, और लोगों को हटा भी दिया
गया।

इसी प्रकार जामा मस्जिद के चौड़ा-सा दक्षिण में चलने पर
आश्वासन की आशंकाओं की राह और पुराने अजमेरी गेट के बीच
स्थित है तुर्कमान गेट इलाका। मुस्लिम बाहुल्य वाले इस इलाके
का एमरजेंसी के बीच में बच नहीं बकि मकानों का पुराना है और
आज भी बहुत सारे पुराने घरों में समेटे हुए हैं। एमरजेंसी के
दौरान देश के अन्य भागों की तरह यहां भी परिवार नियोजन के
कार्य की गई जार-जबरन तरीके के कारण और कुछ इन पुराने मकानों
का निराधार जान के जोखिम में पड़ा हुए सजावट का परिणाम हुआ,
११ अप्रैल १९७६ का गोनी बाढ़। अभी निश्चय भी नहीं था
और सजावट में मरने वालों और घायलों की कसहें टट्टी भी नहीं

हो पाई थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने घड़घड़ाते बलदाज न इस इलाके के भवना को ध्वस्त करना प्रारम्भ कर दिया।

घायलों की कराहें और जहन

रोम जसता रहा और नीरो ठहाका लगाता रहा। बताया जाता है कि एक ओर तो यह कांड हो रहा था और दूसरी ओर आमफ मली रोड पर स्थित एक शानदार होटल में श्री सजय गांधी श्रीमनो दखसाना सुस्ततान और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन जहन मना रहे थे।

दिल्ली के भवनात गिराए जाने की इन घटनाओं के विरोध में कई सप्ताह सदस्यो सामाजिक कार्यकर्ताओं और अनेक राजनीतिक नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक अपना परि यात्रा पहुंचाने की चेष्टा की परंतु कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि उन दिनों तो श्री सजय गांधी का बहा पत्थर की लकीर हुआ करता था। उनके आदेश अथवा निर्देश के आगे किसीकी परियाद कैसे टिक सकती थी।

श्री गांधी की कोई सरकारी हैसियत न होने के बावजूद वे दिल्ली प्रशासन के उच्चाधिकारियों को सीधे आदेश दिया करते थे। यहाँ तक कि इन समस्याओं पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री निवास पर सम्पन्न बैठकों में भी वे भाग लेते थे। श्री गांधी अपने सभी आदेश मौखिक दिया करते थे। एक अवसर पर तो उन्होंने दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री बहादुरराम टमगा से कहा कि 'दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन उनके पास प्रतिदिन आते हैं वे भी आया करें।' एक अन्य अवसर पर उन्होंने श्री टमगा से कहा कि 'श्री जगमोहन विचार विमर्श के लिए फाइलें लेकर आते हैं आप भी लेकर आया करें। मैं आपसे भी दिल्ली नगर निगम के प्रत्येक मामले पर विचार विमर्श किया करूंगा।

इमारतें गिराने से जनता नाराज नहीं, प्रसन्न थी

इमारतें गिराए जाने की इन बारवादों के विरोध में श्रीमती गांधी को भी कई पापन दिए गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस सम्बंध में एक आपन दिया। दिल्ली के सप्ताह सदस्यो ने भी इस

बारे में अपनी नाराजगी प्रकट की थी, परन्तु श्रीमती गांधी का यही कहना था कि जनता इन सब बातों से नाराज नहीं बल्कि प्रसन्न है। निल्ली के दो भूतपूर्व कांग्रेसी सदस्या श्री शशिभूषण और श्रीमती सुमद्रा जोशी ने इस बारे में श्रीमती गांधी से कई बार भेंट की और उन्हें कई पत्र लिखे परन्तु उनका कोई नतीजा नहीं निकला।

मकान गिराने की इन कारवाइयों से स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री पखरुद्दीन अली अहमद भी प्रसन्न नहीं थे। विशेष तौर से जामा मस्जिद इलाके के मामले में। उनका मानना था कि इन लोगों को पाईवातान योजना पर काम पूरा होने से पहले उजागर नहीं जाए। जामा मस्जिद इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री शिराज पिरचा इस सम्बन्ध में स्वर्गीय राष्ट्रपति से मिले भी थे और उन्होंने (राष्ट्रपतिजी ने) आश्वासन भी दिया था कि वे इस सम्बन्ध में प्रधान-मन्त्री से बात करेंगे, परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

राष्ट्रपति भी सम्प्रदायवादी

श्रीमती सुमद्रा जोशी ने आयोग को बताया कि श्री सजय गांधी ने राष्ट्रपतिजी तक को सम्प्रदायवादी कहा था, क्योंकि उनका खयाल था कि राष्ट्रपतिजी नसबाने कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। श्रीमती जोशी का कहना था कि जब वह राष्ट्रपति से शिकायत करने गई कि सजय उन्हें (श्रीमती जोशी को) सम्प्रदायवादी और 'राष्ट्रविरोधी' कह रहा है तो राष्ट्रपतिजी ने कहा था कि 'तुम्हें क्या वह तो मुझे भी सम्प्रदायवादी' कहता है।

भूतपूर्व आवास और निमाणमन्त्री श्री के० रघुरमया तथा गृहमन्त्रालय में उपमन्त्री श्री पी० एच० माहसिन का भी कहना था कि स्व० राष्ट्रपति अहमद मकानात गिराए जाने की कार्यवाही से अप्रमत्न थे। उन्हें स्वयं इस कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी।

परन्तु निल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन ने श्री रघुरमया और श्री मोहसिन के इन बयानों को गलत बताया कि मकान गिराए जाने की कार्यवाही के संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि उन्होंने स्वयं इन दोनों

मंत्रिया को इससे अवगत कराया था ।

जामा मस्जिद क्षेत्र के एक अत्य सामाजिक कार्यकर्ता इमोहन् न इमारतें गिराए जान के बारे में प्रधानमंत्री को ता एक शायन दिया हो इस सम्बन्ध में श्री सत्य गांधी से भी भेंट की । श्री गांधी से भेंट करन की सलाह उह प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव श्री धवन न दी थी क्योंकि उनके अनुसार श्री गांधी ही इस मामले को दख रहे थे ।

श्री इद्रमाहन न श्री गांधी से भेंट के दौरान कहा था कि पहल पार्सवात्तान याजना पूरी कर ली जाए और इस बीच लोग का किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए । परन्तु श्री गांधी ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि एक बार एमरजेंसी हटी नहा और ये लोग थापस आए नही । मैं इस योजना पर समने चाते एक करो ५० लाख रुपये का रिस्क नही ले सकता ।' श्री गांधी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि इस इलाके के निवासिया और दुकानदारों को वही जाना होगा जहा हम उह बसाना चाहेंगे ।

दिल्ली में एक और पाकिस्तान

श्री इद्रमाहन ने इस सम्बन्ध में गृहराज्यमंत्री श्री ओम भट्टा और श्री जगमाहन से भी मुलाकात की । श्री जगमाहन न उह बताया था कि इस समुदाय को शहर के विभिन्न भागों में सितर बितर करना आवश्यक है । श्री इद्रमाहन के अनुसार श्री जगमाहन कहा करत थे कि दिल्ली में एक और पाकिस्तान बरदाश्त नही किया जा सकता ।

श्री जगमाहन ने इस सम्बन्ध में श्रीमती गांधी के विशेष दूत श्री मोहम्मद युनूस से दुई मुलाकात का भी खिन्न किया जिसमें उहने कहा था कि इन सभी मुसलमानों को जो जामा मस्जिद के इमाम का समयन करते हैं धक्का देकर शहर से बाहर निकाल देना चाहिए ।

श्री इद्रमाहन की इस दौड़ धूप का जो परिणाम सामने आया वह था भारत सुरक्षा बानून के अन्तगत उनकी गिरफ्तारी ।

एमरजेंसी के दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तगत की जा रही जबरन नसबन्दी और फिर भक्तान गिरान के नोटिसों ने तुकमान गेट इलाके के लोगों को

वेचन करने के साथ आघित भी कर दिया था। कुछ उसके फल स्वरूप और कुछ समाजविराधी तत्वाकी कारगुजारिया के कारण पुलिस को वहाँ १६ अप्रैल १८७६ को गोली चलाने पड़ी। शाम को चनी माली की घटना को अभी थोड़ी दूर ही हुई थी कि प्राधिकरण के बलबोज़रो ने अपना काय प्रारम्भ कर दिया जो शाम के घुघलके से प्रारम्भ होकर रात तक चलता रहा।

बिवादास्पद बयान

गोली चलाने की घटना और मकान गिराने के मामले पर आयाग में इतने बिवादास्पद बयान लिए गए जिनसे पता लगाना मुश्किल था कि क्या सही है और क्या गलत। गोली चलाने के मामले में दिए गए बयानों में यह पता लगाना मुश्किल था कि गोली चलाने के आदेश किसने दिए, वही मकान गिराए जाने के बारे में यह कहना मुश्किल था कि श्री टमटा सही बोल रहे हैं या श्री जगमाहन।

जहाँ तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक (रैंज) श्री पी० एस० भिण्डर ने इस आरोप से माफ़ इबार किया कि उन्होंने गोली चलाने का कोई आदेश दिया था तथा उन जिन वहाँ किसी पुलिस दल का मतलब किया था वही अपराध शाखा के पनिम उपअधीक्षक श्री अविनाश चद्र का कहना था कि श्री भिण्डर ने केवल वहाँ पुलिस दल का ही मतलब किया था बल्कि गोली चलाने का आदेश भी लिए। श्री भिण्डर का कहना था कि 'उस जिन तो मैं खोद लगने के कारण चलाने फिरने की स्थिति में भी नहीं था, वहाँ पहुँचने का तो सवाल ही नहीं था।'

सी० आर० पी० द्वारा अमानवीय व्यवहार

दिल्ली सशस्त्र पुलिस की पहली बटालियन के तत्कालीन कमांडेंट श्री एन० के० मिह ने इस बात से साफ़ इबार किया कि उन्होंने अपनी पिस्तौल से कोई गोली चलाई थी। उनका कहना था कि स्थिति उस समय इतनी तनावपूर्ण हो गई थी उनका अपने राइफलमन में हवा में गोली चलाने को कहना पड़ा। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सी० आर० पी० के जवानों द्वारा गोली से घायलों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था।

महिलाओं की बेइज्जती

मुकमान गेट इलाके के बहुत से नागरिका न आयाग को बताया कि किस प्रकार से उनके भवान गिराए जान के साथ-साथ उनका परिवारजनों को परेशान किया गया लूटा गया और महिलाओं की बेइज्जती की गई। इन निवासियों ने अतिरिक्त इस इलाके से चुने गए महानगर परिषद के सदस्य श्री राजेश शर्मा ने भी इस बात की पुष्टि की।

आमू यहाती कई महिलाओं ने बताया कि पुलिस ने घर घर में घुसकर मारपीट की औरता को बेइज्जत किया और कुछ महिलाओं के ऊपर तक छीन लिए गए।

महिलाओं के साथ अमरुत यवहार किए जान के बारे में जामा मस्जिद धान के सहायक सब इस्पेक्टर श्री गोविंदराम भाटिया ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि एक सिपाही श्री रविभानसिंह ने उन्हें बताया था कि उसने सी० आर० पी० के कुछ जवानों को एक महिला के साथ अमरुत व्यवहार करते देखा था परंतु उसके हस्तक्षेप करने पर वे उमम सफल नहीं हो सके।

योजना ही गरवानूनी थी

मुकमान गेट इलाके के सौ दयकरण की जिस योजना के नाम पर यह विनाशालीला की गई थी वह भी गरवानूनी थी। दिल्ली के भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य नगरनियोजक श्री सईदुल्लाह खान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस इलाके के विकास के लिए बनाई गई किसी भी योजना का पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली थी और ऐसे ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। उनका कहना था कि शाह जहाबा (जहां इमारतें गिराई गई) इलाके में प्रस्तावित ४४ मजिली इमारतें न केवल उस इलाके की बल्कि नई दिल्ली की पुरातन कला के भी अनुरूप नहीं थी।

आपत्ति न करने पर इमारतें गिराई गईं

प्राधिकरण के गद्दी बस्ती विभाग के एच० के० साल जस्टिस शाह द्वारा स्पष्ट नहीं कर सके कि किम

प्रमुख थी पर भी यह भी गिरा

निया गया जो प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई थी। श्री लाल इमका जवाब यही देने रहे कि उन्हें यही जानकारी थी कि य समस्त इमारतें प्राधिकरण में अतमत आती हैं और फिर इमारतें गिरात समय किसीने भी आपत्ति नहीं की थी कि यह इमारत प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नहीं है तथा उनकी है। इसपर जस्टिस शाह ने कहा आप बतल यहा बूलडोजर लेकर आएंगे ता क्या इस आधार पर इस पटियाला हाउस को गिरा देंगे कि कोई यह कहने वाला नहीं है कि यह उसका है ?'

श्री लाल इस बात का भी ठीक तरह से जवाब नहीं दे सके कि दिल्ली गेट में अजमेरी गेट तक की सात चरणा वाला इस योजना के कार्यावयन में पहले इसका सर्वे कराया गया था तथा इस बार में उपाध्यक्ष श्री जगमोहन की स्वीकृति भी ली गई थी।

जो कुछ किया, जनता की भलाई के लिए किया

श्री जगमाहन ने अपनी भलाई में तुक्मान गेट इलाके में पुनरुद्धार को सन १९२८ से १९७७ तक की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए यह बताने की चेष्टा की कि इस योजना पर जल्दबाजी में नहीं बल्कि काफी मोच विचार के बाद ही कार्य किया गया था। उन्होंने बताया कि १९२८ से ही इस योजना पर काम चालू हो गया था और इमारतों का अधिग्रहण हो गया था और जहां तक उनका प्रयास है सभी इमारतों का अधिग्रहण हो चुका था।

उनका कहना था कि प्राधिकरण ने जो कुछ किया जनता की भलाई के लिए किया। उन्होंने कहा कि रूस प्लाक में १९ अप्रैल १९७६ को हुए गोलीकांड के लिए प्राधिकरण नहीं, बल्कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा परिवार नियोजन कार्यक्रम दायी था। उस इलाके की जनता इसलिए भड़की क्योंकि वहां परिवार नियोजन शिविर में जबरन नमकदो की जा रही थी और फिर राजनीतिक नेताओं ने भी इस अवसर का गलत फायदा उठाया।

दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री टमटा ने आरोप लगाया कि तुक्मान गेट इलाके में प्राधिकरण की ओर से की गई कारवाई के बारे में निगम को कोई जानकारी नहीं थी जबकि श्री जगमाहन ने उनके आरोप का खंडन करते हुए कहा कि समस्त कार्य श्री टमटा की जानकारी में था।

(ii) कापसहेडा गांव

इमारतें गिरान का सिममिला यही ममाप्त नहा हुआ। तिला व दमिण म पालम-गुडगाव सडक पर एक गांव है कापसहेडा। यह गांव भारत की पहली छोटी कार बनान की तयारी म तगी था सजय गाधी की मारति फैक्टरी स दा-तीन किलामीटर दूर पहन स्थित है।

कार की रफ्तार धीमी करने के कारण

वहा जाता है कि श्री गाधी को यह भाव दो कारण म पम नही था पहला तो यह है कि उनके फक्टरी जात समय गांव वाला के धन्वे सतत-सतत सडक पर आ जाया करत थ जिसम उह अपनी तेज रफ्तार म धनी आ रही कार की गति को धीमी करना पहती थी और दूसरा यह है कि जहा इस गांव म इतने छोटे उद्याग पनप रहे थ वही उनकी फक्टरी के पास के इलाक म काई उद्योग नही लग रहे थे अत्रकि वे अपन उम इमाके को बड़ जीर छान उद्यागा के एक सम्पन्न म सम्प म देखना चाहते थ। इही कारण के फलस्वरु सितम्बर १९७६ म इस गांव के कई उद्यागा और मराना पर बुलडाडर चलवा दिया गया।

इस गांव की ममस 'यू पीम रबर इंडस्ट्री' नामक फम का जो सटेबल रबड का सामान बनाया करती थी ११ और १८ नितम्बर १९७५ को बिना नोटिस जीर चलावनी व गिरा दिया गया। इसत फम को ४ ३६ लाख रुपये का नुकसान हुआ। फैक्टरी के मालिको न जब इसके विरोध म श्री एम० एन० पन्ना की अगलन क दर बाजे छटपटाए और वहा स रोक के जादेश लाने म सफलता प्राप्त कर लो तो उह प्राधिकरण द्वारा धमकी दो गई कि यदि उहोन मामला वापस नही लिया तो उह मीसा के अन्तगत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मरता क्या न करता मामला वापस लेना ही पडा।

इसी प्रकार का घटना दिल्ली केपर प्राक्वटस नाम की फम के भाग भी हुई। इसे १७ नितम्बर को गिराया गया था और बा म उसे भी २३ तारीख को मामला वापस लेना पडा।

लेथ का काम करने वाले श्री रतिराम की वकशाप को भा

इसी तरह बिना नोटिस और चेतावनी के गिरा दिया गया। इसी तरह की घटनाएँ दुग्गल इजीनियरिंग और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के साथ भी हुई। इन फक्टोरिया के अतिरिक्त झुग्गी बापडिया और अनेक मकानों को भी गिराया गया।

करुण गाथा

इस गांव के कई निवासियों ने अपनी करुण गाथा सुनाई। ७५ वर्षीय श्री रामविशन ने बताया कि उसने १६ पक्के मकान ढहा दिए गए और मलवा टूटा म सदवाकर वहां से हटा दिया गया ताकि वहां मकान गिराने का नामोनिशान तक न रहे।

एक किसान श्री गंगादत्त ने रूढ़े हुए गले से कहा कि जब उनकी पारिवारिक मकान गिराया गया तो उनका बेटा यह देखकर बहोश हो गई। उनका कहना था श्रीमान् श्रीमती गांधी के फाम हाउस को बुलडोजर से गिरा देना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम न्याय मिल सकता है।

एक पैसे का भगडा

हरियाणा के बतमान शिक्षामंत्री कनल आर० एस० यादव ने बताया कि लगभग पचास बदमाशों के एक दल ने उनके ८२ वर्षीय पिता को गोली से मार दिया और उनके पेट में भी गोली लगी तथा पास खड़ा पुलिस का उड्डनदस्ता यह सब देखता रहा। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि उनके पेट्रोल पम्प से पेट्रोल लाने पर श्री सजय गांधी का पसा लीडर कमीशन चाहते थे, जबकि वे एक पैसा ही देना चाहते थे।

कनल यादव १९७५ की दीपावली की उस घटना को बताते हुए रो पड़े जब उन्हें अपनी पत्नी तथा बच्चा के साथ अपना फाम हाउस खाली करना पड़ा था। उन्होंने कहा श्रीमान जीवन भर अपनी मातृभूमि की सेवा करने का मुझे यह फन मिला था।

प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी श्री रणवीरसिंह ने ०१/०१/०१ का बताया कि कापमहडा में इमारतें गिराने का कार्य १९८१ में निगम द्वारा किया गया था हमने तो सिर्फ उनकी सहायता की थी। निगम की ओर से उन्हें कहा गया था कि आपको इन-इन इमारतों को गिराना है और हमने वही किया। हमने ३४ मं. १९८१

इमारतें ही गिराई थी ।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमाहू का कहना था कि श्री टमटा ने उन्हें फोन कर इस गांव में इमारतें गिराने के लिए प्राधिकरण का दस्ता भेजने को कहा था । इसपर आयोग में बड़े श्री टमटा ने तुरन्त उठते हुए कहा 'धीमान्' । यह सरासर झूठ है । श्री जगमोहन ने बाद में बताया कि 'हो सकता है, फोन श्री टमटा ने नहीं किया हो । इन्होंने नहीं तो इनके किसी अधिकारी ने किया होगा ।

सत्य के आदेश न मानने पर निलम्बन का डर

श्री टमटा ने बताया कि इस गांव में मकानात गिराए जान का काम श्री गांधी की इच्छानुसार किया गया था । उनका कहना था कि उनके तथा उनके अधिकारियों को धमकाया गया, तथा उन्हें स्वयं डर था कि यदि उन्होंने श्री गांधी के आदेशों का पालन नहीं किया तो उन्हें निलम्बित कर दिया जाएगा ।

उन्होंने बताया कि एमरजेंसी के दौरान व पूरा रूप से श्री गांधी की देख रेख तथा नियंत्रण में काम कर रहे थे । एमरजेंसी की घोषणा के तुरन्त बाद तत्कालीन उपराज्यपाल के निजी सचिव श्री चावला ने उनसे कहा था कि 'उपराज्यपाल चाहते हैं कि आप श्री गांधी के आदेशों का पालन करें ।'

मुगलियाई कानून

श्री टमटा के अनुसार, उन दिना 'मुगलिया' तरीके का कानून था । श्री गांधी द्वारा कई अधिकारियों का तग किया गया था तथा धमकिया दी गई थी । उन्होंने कहा 'श्रीमान वह सिर्फ मौखिकी का नहीं बल्कि जीवन मृत्यु का सवाल था । मुझे धमकी दी गई थी कि मुझे मौसा में गिरफ्तार कर लिया जाएगा ।' उन्हें तथा उनके अधिकारियों को बताया गया था कि दिल्ली के मामलों का नियंत्रण तथा देख रेख का काम श्री गांधी के उच्च पद पर जाते हेतु एक प्रशिक्षण व सम्मान है ।

(iii) अर्जुन नगर बनाम अर्जुनदास

दक्षिण दिल्ली में सफ़दरजग इलाके में एक बस्ती है/थी अर्जुन नगर। एमरजसी में मकान गिराने के लिये इस बस्ती का भी उजाड़ दिया गया था। दिल्ली में अनेक स्थानों पर गिराए गए मकानों के समान इस बस्ती-बसाई बस्ती का उजाड़ने में भी श्री सजय गांधी का अप्रत्यक्ष हाथ था।

इस बस्ती में लोगों ने १९५८ से ही मकान बनाने प्रारम्भ कर दिए थे। हालांकि यहाँ हो रहा समस्त निर्माण-कार्य ग़रबानूनी था परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस नियमित करने पर विचार किया जा रहा था। प्राधिकरण ने ८ फरवरी, १९६५ के अपने एक प्रस्ताव में इस बस्ती की योजना की रूपरेखा तैयार करवा स्वीकार कर लिया था तथा १९७०-७१ में यहाँ सीवर और पानी की लाइनें डाल दी थी। यहाँ के प्रत्येक मकान के लिए १५ रुपये प्रति गज की दर से विकास शुल्क भी वसूल किया गया था। इन सबके बावजूद इस सितम्बर-अक्तूबर १९७५ और ६ जनवरी १९७६ को उजाड़ दिया गया।

इस दौरान कुल १२१५ मकान गिराए गए, जिनमें पक्के कच्चे साथ पक्के मकान और झुगिया शामिल थी। यह कायदाहीन सिर्फ बिना नोटिस के की गई बल्कि अदालत द्वारा इसपर लिए गए रोक के आदेश की भी परवाह नहीं की गई।

पक्के मकान भी गिराए गए

साढ़े तीन लाख रुपये की लागत से बने एक तीन मंजिले मकान को भी इस कायदाहीन के दौरान गिरा दिया गया और जब मकान मालिक श्री रतन जाशी द्वारा अदालत से राक का आदेश लाया गया तो उसका भी पालन नहीं किया गया। इसपर श्री जाशी ने जो रेतव में काम करते थे प्राधिकरण तथा उसका उपाध्यक्ष पर अदालत की मानहानि का मुकदमा दायर किया जिसपर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। श्री जाशी के अनिरिक्त एक अन्य मकान मालिक श्री शर्मा का भी गिरफ्तार किया गया।

इस बस्ती को गिराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ श्री सजय गांधी के मित्र अर्जुनदास का बताया जाता है। श्री अर्जुनदास ने सचमें

पहले अपन रहन के मकान का गिरवाया और बाद में अय मकाना का गिरवान में भी सहायता दी। श्री अजुनदास जिस मकान में रहते थे वह उनका नहीं था बल्कि वह वहाँ किरायदार के रूप में रहते थे।

प्राधिकरण के अनुसार इस बस्ती में जिन १२१५ मकानों को गिराया गया था, उनमें से ३२७ परिवारों को दूसरी जगह मकान दिए गए थे। इनमें श्री अजुनदास भी, जिनका वहाँ कोई मकान नहीं था और जो किरायदार के रूप में रहते थे तथा उनके परिवार के मरम्मा का १३ मकान दिए गए। इनमें से ११ ता दक्षिण दिल्ली में और २ राजकोटी गाँवों में दिए गए। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि श्री अजुनदास उनके पिता तथा उनके भाइयों का जो मकान दिए गए वे किरायदार की हैसियत से दिए गए थे अथवा मकान मालिक की हैसियत से।

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मकान गिराए

प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी श्री एस० पी० सक्सेना के अनुसार मकानों को गिराए जाने की यह कार्यवाही सप्ताह मरम्मा श्री शशिभूषण तथा महानगर पापट श्री अजुनदास के बीच व्याप्त राजनीतिक विरोध के कारण हुई। श्री शशिभूषण ने इस बस्ती के निवासियों को आश्वासन दिया था कि उनके मकान नहीं गिरने दिए जाएंगे। श्री अजुनदास ने श्री सत्य गांधी का अपने विश्वास में लेकर यह कार्यवाही कराई।

मकान गिराने की इस कार्यवाही का निणय श्री जगमाहन का अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया था। श्री जगमाहन ने कहा था कि यह कार्यवाही जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है क्योंकि इससे वहाँ के निवासी जानूँगी कार्यवाही का सहारा नहीं ले सकेंगे। श्री जगमाहन ने बैठक में यह भी कहा था कि इसपर तुरंत कारवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए क्योंकि यह प्रतिष्ठा का सबान है तथा इसका निणय उच्च स्तर पर लिया गया है।

तीन घंटे का नोटिस

श्री सक्सेना ने बताया कि उन्होंने मकान गिराए जाने वाले दस्त का नतत्व किया था तथा निवासियों को सिर्फ तीन घंटे का

नोटिस दिया गया था, उनके अनुसार श्री अर्जुनदास द्वारा दवाव डाल जान के कारण ही उनको तथा उनके परिवारजनों का १३ मकान दिए गए। जस्टिस शाह ने उनसे जानना चाहा कि क्या यह घर कानूनी नहीं था इसपर श्रीसक्मना ने कहा, “श्री अर्जुनदास महानगर परिषद के अध्यक्ष थे उनकी बात तो माननी ही पड़ती यदि कोई मसद मदस्य भी कहता तो उसकी भी बात मानी जाती।”

जगमोहन मुखरे

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन इस बात से साफ़ मुकर गए कि श्री अर्जुनदास तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों का अर्जुन नगर में गिराए गए मकानों के एवज में १३ मकान दिए जाने में उनका कोई हाथ था। उनका कहना था कि जब तक वे प्राधिकरण में उपाध्यक्ष रहे उन्हें इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी।

उन्होंने इस बात में भी इकार बर दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से श्री अर्जुनदास को जानते हैं। पर वे इस बात से सहमत थे कि हाँ सकता है एक या दो बार उनकी भेंट प्रधानमंत्री निवास पर तथा किसी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई हो। उन्होंने स्वीकार किया कि मकान देने के संबंध में उनके हस्ताक्षरों से यह काम किया गया होगा परंतु उस सूची में अन्य १४५ लोगों के नाम भी थे और उन्होंने नाम नहीं देखे थे कि किम किमका मकान दिए जा रहे हैं। जहाँ तक एक ही मकान की एवज में तरह-तरह के मकान दिए जाने का मकान है, यह जमाघारण बात नहीं थी। श्री जाशी के बिना तीन मजिस्ट्रेट मकान गिरा दिया गया था किरायेदारा को भी १३ मकान दिए गए थे तथा दो अन्य मामलों में से एक में दो और एक में बाग़ मकान दिए गए।

(iv) अधेरिया मोढ़

एमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों की निगाहों में किसी चीज़ के खटवने का क्या परिणाम हो सकता है इसका पता महारौती के पास अधेरिया मोढ़ पर स्थित ७० दुकानों

तथा कुछ आवासीय मकानों को गिराए जाने की कामवाही स चल जाता है। कापसहेडा गांव में मकान गिराए जाने जस कारण की तरह यहां भी इन दुकानों तथा मकानों को श्री सजय गांधी की निगाहों का शिकार होना पड़ा।

रास्ते की रुकावट

श्री गांधी तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य जब महरोली स्थित अपने काम पर जाया करते थे तब अधरिया मोड़ पर स्थित एक निजी भूमि पर बनी ये पुरानी दुकानों और कुछ आवासीय मकानों एक तरीके से उनके रास्ते की रुकावटें थीं।

श्री गांधी के निर्देश पर दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री बहादुरराम टमटा ने उस क्षेत्र के सहायक आयुक्त (ग्रामाण) श्री ओ० पी० गुप्ता से २६ अक्टूबर १९७६ का इन्हें गिराने का कहा और २८ अक्टूबर और १ नवम्बर का इनको गिरा दिया गया।

श्री गुप्ता के अनुसार उन्होंने इसका विरोध किया था और श्री टमटा से कहा था कि बिना नोटिस उन्हें गिराना उचित नहीं होगा। इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी भी नहीं हो पाई थी कि २६ अक्टूबर को श्री टमटा ने पुनः उन्हें आदेश दिया कि यदि तीन दिन के भीतर इन मकानों को नहीं गिराया गया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

श्री टमटा ने आयोग को बताया कि उन्होंने यह कामवाही श्री गांधी के निर्देश से की। उनका कहना था कि जब कभी भी श्री गांधी किसी क्षेत्र का दौरा करके लौटते, बहुत नाराज होते और उनसे अपमानजनक भाषा में बात करतें। इसी प्रकार एक बार महरोली क्षेत्र के दौरे के बाद उन्होंने कहा कि इन निर्माणों को एक दिन में गिरा लिया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह कहने पर कि इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि कुछ औपचारिकताएं पूरी हामी। श्री गांधी ने यह स्पष्टीकरण पूरा सुना भी नहीं और बोल इस विशिष्ट तरीके तक यह काम हो जाना चाहिए अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त को नौकरी से हटा लिया जाएगा।

सजय की ग्रहण की सतुष्टि के लिए

श्री टमटा ने बताया कि इन निर्माणों का गिराए जाने की

कारवाई श्री गांधी के अहमकी सतुष्टि के लिए की गई थी। एक बार इसी तरह मैं उन्होंने पालम-गुडगाव सड़क पर स्थित मकानों का एक निश्चित समय तक गिराने के लिए कहा था और धमकी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शस्त्रीय सहायक आयुक्त को तो निलम्बित किया ही जाएगा और आपन (श्री टमटा) विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है।

जनसंघ को चंदे देने पर बरबादी

दुकानें बरबाद करने की कार्रवाई यही समाप्त नहीं हुई, बल्कि ऐसा ही हाल करील वाग के गफफार मार्केट का भी हुआ। इस मार्केट में जब बरबादी का जनाबा उठ रहा था, तब श्री सजय गांधी भी उसका मुआयना करने पहुंचे। व्यापारियों द्वारा विरोध प्रकट करने पर उन्हें लताड़ा गया और कहा गया कि तुम सचन जनसंघ का चंदे लिए और उसका उम्मीदवार को जिताया, अब उसका फल भुगतो। दुकानें गिराए जाने की इस कार्रवाई के विरोध में जिन पांच दुकानदारों ने अदालत से रोक के आदेश प्राप्त कर लिए थे उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी गई जिनमें से तीन को तो गिरफ्तार कर लिया गया और उन दो को छोड़ दिया गया जिन्होंने अदालत से अपनी दरवास्तों वापस ले ली थी।

इसी प्रकार की जोर जबरदस्ती कर चांदनी चौक में एसप्लेनेड क्षेत्र में साइरल विनोताभा का झंडेवाला जान पर मजबूर किया गया। इसके अतिरिक्त भगतसिंह मार्केट मुलतानपुर बाजार, सराय पीपलसला तथा समालखा गांव में मकान तथा दुकानें गिराने में साथ-साथ ग्रीन पार्क स्थित आय समाज मंदिर को भी मिट्टी में मिला दिया गया।

इंदिरा गांधी के राज में

मिल्ली विधाम प्राधिकरण के अधिकारी श्री रणवीरसिंह ने आयोग की अंतिम चरण की कार्रवाई में कहा कि उन्होंने जो कुछ किया अपने अधिकारियों के आदेश से किया।

उनका कहना था कि वे भी श्री वसीलाल के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, पीछे नहीं थे। उन्होंने भरे हुए गल से कहा कि यदि इस सरकार ने उन्हें नौकरी से हटा दिया अथवा

निलम्बित कर दिया तो व वही के नहीं रहेंगे । उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में उनका उद्धार सिर्फ तभी हो सकेगा जब श्रीमती गांधी सरकार में आएंगी, परन्तु यदि उनके साथ एक बार फिर श्री वसीलाल आ गए तो यह आशा भी नहीं रहेगी ।

श्री रणवीरसिंह का कहना था कि जाच ब्यूरो द्वारा आयोग के मामले तयार करने के लिए सभी फाइलें नहीं देखी गई और सिर्फ उही फाइलों को देखा गया तथा लोग की गवाहिया ली गई जिनसे मामला बन सके । उन्होंने इस सबब में दोषार जाच कराने का अनुरोध किया ।

प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री जगमोहन ने श्री सिंह की इस शिकायत का समर्थन करते हुए कहा कि जाच ब्यूरो द्वारा उचित तरीके से जाच-पड़ताल नहीं की गई ।

श्री जगमोहन ने श्री सिंह द्वारा किए गए सभी कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा कि श्री सिंह ने जो कुछ किया उनके कहने पर किया और व स्वयं उन कार्य के लिए जिम्मेदार है ।

८ जनप्रचार-साधनों का दुरुपयोग

चुनाव-घोषणा से पूर्व

तानाशाह हिटलर के प्रचारमंत्री गोब्ल्स का कहना था कि यदि एक झूठ का सौ बार बोला जाए तो वह भी सच नजर आने लगता है । सच और झूठ बोलने का काम प्रचार साधनों के जरिये किया जाता है । समाचारपत्र रेडियो दूरदर्शन और पत्रिकाएँ आदि प्रचार-साधन पर यदि एक ही व्यक्ति या संस्था का बोल चाला हो जाए तो वह जसा चाह जीर जितना चाहे सच को झूठ और झूठ को सच कर सकता है ।

देश में २५ जून १९७१ की मध्य रात्रि का एमरजेंसी लागू कराने के तुरन्त बाद समाचारपत्रों तथा अन्य प्रकाशन पर सेंसरशिप लागू कर दी गई जिसका मतलब था कि बिना सेंसरबोर्ड की स्वीकृति के कोई समाचार अथवा लेख आदि प्रकाशित नहीं किया जा सकता था । इस प्रकार के बान्ने की नियुक्ति केन्द्र तथा राज्यों में की गई । इससे अनिरीक्षित केन्द्र सरकार के सूचना और प्रसारण

मद्रास के जतगत आने वाले आकाशवाणी दूरदर्शन और पत्र सूचना कार्यालय पर तो पहले से ही सरकार का नियंत्रण था। एमरजेंसी की घोषणा के बाद इन सबपर सरकार का शिकजा और कसता गया और सरकार ने जसा चाहा इनका उपयोग किया।

एमरजेंसी के दौरान आकाशवाणी से थो सजय गांधी के प्रचार के लिए १ जनवरी, १९७६ में १८ जनवरी १९७७ के बीच १६२ समाचार प्रसारित किए गए। इसके अतिरिक्त जहां दिसम्बर १९७४ में सप्ताह दल की ५७१ तथा विपक्ष की ५२२ लाइनें प्रसारित की गई, वहीं दिसम्बर १९७६ में सप्ताह दल की २२०७ तथा विपक्ष की सिर्फ ३४ लाइनें प्रसारित की गई।

एमरजेंसी का लाभ उठाते हुए समाचारपत्रों पर न सिर्फ सेंसरशिप लागू कर लिया गया था, बल्कि उनको कुछ विशेष लेख और सम्पादकीय प्रकाशित करने पर भी दबाव डाले जाने लगा। इस सत्रके परिणामस्वरूप देश की ६० करोड़ जनता को वही मालूम पया जो सरकार ने उसको बताना चाहा, क्योंकि सूचना प्राप्ति का बाढ़ छात हो बचा नहीं था सिवाय गुप्त रूप से सूचनाएं प्रसारित करने के।

इन अतिरिक्त एमरजेंसी के दौरान ही देश की चार सभाद समितियां को मिलाकर एक सभाद समिति 'समाचार' का गठन किया गया। 'समाचार' के गठन में सरकार का खूबरा के वितरण पर शिकजा और भी बड़ा हो गया। एमरजेंसी के दौरान युवक शायम को आकाश की ऊचाइया पर पहुंचाने के लिए उसका पूरा प्रचार किया गया, यहां तक कि उसके लिए सरकारी गीत एवं नाटक प्रभाग का भी उपयोग किया गया। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक विशाख कुमार के गीतों के प्रसारण पर आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने में इकार कर दिया था।

(1) अखबारों पर शिकजा—विजली काटकर और सेंसरशिप लगाकर

प्रचार-भाषना पर शिकजा बमने का काम २५ जून को मध्य-रात्रि को एमरजेंसी की घोषणा के साथ ही प्रारम्भ हो गया था जब दिल्ली तथा कुछ राज्यों की राजधानियां स निकलने वाले

समाचारपत्रों की बिजली काट दी गई थी। इसके पीछे उस समय एक ही उद्देश्य था कि दूसरे दिन समाचारपत्रों में उस रात हुई गिरफ्तारियाँ के बारे में कोई समाचार नहीं निकल सके।

अखबारों की बिजली प्रधानमंत्री के निर्देश से काटी गई

निल्लीके उप राज्यपाल श्रीकृष्णचंद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अखबारों की बिजली काट देने का फैसला प्रधानमंत्री निवास पर हुई एक बैठक में लिया गया था। निल्ली स्थित तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री बी० एन० महरोत्रा के अनुसार २५ जून की रात्रि को उप राज्यपाल ने उनसे राजधानी के प्रमुख समाचारपत्रों की बिजली काटने का आदेश दिए थे। जब उन्होंने इसमें कुछ कठिनाई व्यक्त की तो उन्हें कहा गया कि रात्रि को दो बजे से पहले बिजली बंद जानी चाहिए, क्योंकि यह आदेश प्रधानमंत्री से मिले हैं।

चंडीगढ़ के तत्कालीन आयुक्त का भी यही कहना था कि उन्हें रात्रि को ट्रिब्यून अखबार की बिजली काटने के आदेश दिए गए थे।

सेंसरसिप लगाकर सरकार का प्रचार

सेंसर के अंतर्गत समाचारपत्रों में सरकार की नीति से असहमतिपूर्ण मन्त्रों और विचारों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। श्रीमती गांधी ने जुलाई १९७५ में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कुछ भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए थे। इस बैठक में श्रीमती गांधी ने यह भी कहा कि विदेशों में प्रचार के लिए वहाँ की पत्रिकाओं आदि में छपने के लिए लेख भेजे जाएँ और इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाए।

प्रधानमंत्री को प्रमुखता

तत्कालीन सूचना और प्रसारणमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने २६ जून १९७५ को हुई एक बैठक में यह आदेश दिए कि मंत्रियों के व्यक्तित्व पर जोर न दिया जाए बल्कि प्रधानमंत्री को ही अखबारों में प्रधानता दी जाए। तत्कालीन प्रधान सूचना अधिकारी श्री बाजी का निर्देश दिए गए कि वे अखबारों का प्रधानमंत्री के वस्तुओं

को ही प्रमुखता देने को बहें।

मन्त्रालय म तत्कालीन अतिरिक्त सचिव श्री के० एन० प्रसाद ने आयोग को बताया कि एमरजेन्सी के दौरान २५० पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। उनके अनुसार, यह भी निश्चय किया गया था कि पत्रकारों को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाए परंतु उनके बारे में सरकार को तुरंत सूचित किया जाए।

श्री प्रसाद का कहना था कि श्री शुक्ल के निर्देशों के अनुसार, फरवरी १९७६ के अंत में उन्हें पत्रकारों की एक सूची दी गई थी। इन पत्रकारों के रिवाजों को जांच कर यह पता लगाने को कहा गया था कि कहा इनका किसी प्रतिबंधित संगठनों से संबंध तो नहीं है या वे सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं। इससे अतिरिक्त कुछ विदेशी सवाददाताओं को भी देश से चल जाने को कहा गया था क्योंकि वे सेंसर के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

सजय राष्ट्रीय नेता

एमरजेन्सी के दौरान श्री सजय गांधी का रडियो और दूरदर्शन पर अत्यधिक प्रचार किया गया। दूरदर्शन पर उनकी कलकत्ता यात्रा के प्रचार पर ₹ ३३ लाख रुपये खर्च किए गए। उन्हें मुक्त नेता ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रकट करने की हिदायत दी गई थी।

विधि मन्त्रालय की सलाह के विपरीत तत्कालीन सूचना और प्रसारण सचिव श्री वर्मा ने आदेश दिए थे कि परिहार नियोजन संबंधी सभी खतरा का काट दिया जाए। 'यायाघीशों' के फैमलों को सेंसर करने के बारे में विधि मन्त्रालय ने सावधानी बरतने की सलाह दी थी परंतु इस मामले में भी मनमानी की गई।

गीता के उद्धरणों पर भी रोक

बम्बई की 'आपिनिपन' पत्रिका के सम्पादक श्री ए० डी० गोरे-वाला, साधना के सम्पादक श्री एस० एम० जाशी, हिम्मत के सम्पादक श्री राजमोहन गांधी, समित पानिक तुंगलक के सम्पादक श्री चो रामास्वामी, सेमिनार के सम्पादक श्री रामेश धापर, हिन्दुस्तान टाइम्स के भूतपूर्व सम्पादक श्री बी० जी० वर्गीज

तथा मेनस्ट्रीम के सम्पादक भी निखिल चक्रवर्ती ने आयोग को दिए अपने बयानों में बताया कि उन दिनों गीता के उद्धरणों तक पर रोक थी। महात्मा गांधी पंडित नेहरू तथा रवीन्द्र नाथ ठाकुर के ही नहीं बल्कि स्वयं श्रीमती गांधी के उद्धरणों तक को छपने में रोक दिया गया था। इन सम्पादकों का कहना था कि उन दिनों सम्पादकों वाला मंच खाली नहीं छोड़े जा सकते थे तथा खाली जगहों में देश आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता था।

संजय के खिलाफ कोई खबर न छपे

श्री चक्रवर्ती ने बताया कि श्री शुक्ल ने उनसे कहा था कि श्री संजय गांधी के विरोध में कोई खबर नहीं छपी जाए। मुख्य सेंसर अधिकारी श्री डी० पेहान तो यहाँ तक कहा था कि जो कागज़ी नेता श्री गांधी के विरुद्ध कोई बात कहें, उसका कोई समाचार नहीं छपा जाए।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी अखबारों में सम्पादकीय बातों को छाननी छोड़े जाने पर प्रतिबंध नहीं था परंतु एमरजेंसी के दौरान तो यह भी नहीं किया जा सकता था।

जासूसी और सुन्दरिया

श्री चक्रवर्ती ने बताया कि एमरजेंसी के दौरान पत्रकारों के आपसी बातचीतों को टैप करने के लिए सुन्दरिया का प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया कि जो भी पत्रकार श्रीमती गांधी के विरुद्ध सम्मेलन आदि में कोई बात कहता तो उनसे आसपास मंडरा रही सुन्दरिया अपने बैग में रखे टैप रिवाइटर से उनकी बातें टैप कर लेती और बाद में उस आधार पर उनको धमकाया जाता।

‘माफिया’ अभियान

श्री वर्गीज का कहना था कि सेंसरशिप का मुख्य उद्देश्य एमरजेंसी को स्थायी बनाना और पूरे सेंसरशिप का उद्देश्य दबित करना तथा डराना धमकाना था। उन्होंने कहा कि सेंसरशिप तथा खबरों का अपने हिसाब से प्रवर्धन करने का कार्य अवैध तो नहीं परंतु कुछ से आखिर तक मनमानीपूर्ण था। उनके अनुसार यह सब ‘माफिया’ जैसा अभियान था। उन दिनों मुख्य सेंसर-अधिकारी जो

कुछ कह देते थे वही कानून होता था।

जयप्रकाश का सम्भावित निधन और जीवन-चरित्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पालिका 'योजना के सम्पादक श्री के० जी० रामकृष्ण न आयोग को बताया कि श्री जयप्रकाश नारायण के अत्यधिक वामार पड़ जाने से उनके निधन की सम्भावनाओं को देखते हुए आकाशवाणी ने उनका जीवन चरित्र तयार कर लिया था, जिसका स्वयं श्री शुक्ल ने सम्पादन किया था। परंतु सौभाग्य से उसके प्रसारण का मौका ही नहीं आया। उनका कहना था कि जीवन-चरित्र में श्री जयप्रकाश को पुरानी बीमारी से जजरित बताने की चेष्टा की गई थी, ताकि श्रोताओं को यह प्रतीत न हो कि उनका निधन नजरबंदी के दौरान ही गद्द यातनाओं के कारण हुआ है।

शुक्ल की सफाई

श्री शुक्ल ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होंने भूत पूर्व प्रधान सूचना अधिकारी डा० ए० आर० बाजी से दिल्ली के समाचारपत्रों के सम्पादकों से मिलकर प्रधानमंत्री की खबरा तथा चित्रों के जरिये प्रचार करने को कहा था। उनका कहना था कि यह निर्देश मंत्रालय की सामान्य पद्धति के अनुसार ही दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह मंत्रालय का काय है कि वह प्रधानमंत्री तथा सरकार की छवि उभारने के लिए काय करे।

श्री शुक्ल ने कहा था कि आज तक कभी भी पत्र सूचना कार्यालय का उपयोग विपक्षी दलों का प्रचार करने के लिए नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसका काय सरकारी नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार करना है और इसी आधार पर सरकार तथा प्रधानमंत्री का प्रचार-काय किया जाता है। यह आज ही नहीं, बल्कि पहले से होता रहा है।

पत्रकारों को सी० आर्डी० ए० से घन

उन्होंने बताया कि देश के कई पत्रकारों तथा संस्थाओं को अमेरिका की गुप्तचर संस्था सी० आर्डी० ए० से घन मिलता था। उन्होंने कहा कि प्रेस इस्टीम्यूट आफ इंडिया के विरुद्ध कारवाइ

करने का भी एक कारण यही था कि इस बहा सघन मिनता था। उन्हें यह सूचना भारत के मुक्तचर संगठन 'रा' समिली थी। इसके अतिरिक्त अमरिणी कांग्रेस (ससन्) द्वारा इस संग्रध म एकत्र की गई जानकारी म भी इस सस्या तथा थी जनादन ठाकुर सहित कई पत्रकारो का सी० आई० ए० स सम्बद्ध हान का जिक्र किया गया था।

श्री शुक्ल ने स्वीकार किया कि उन्होंने यह निर्देश दिए थे कि पत्रा के सम्पादकीय कालमा को खाला नहीं छाड़ा जाए क्योंकि इसका तात्पर्य विरोध प्रकट करना हो सकता था। उन्होंने कहा कि वे समझत थे कि ये निर्देश कानूनसम्मत हैं।

उन्होंने बताया कि अखबारा पर सेंसर-सबधी मागदशन निर्देश उनके मधानय द्वारा तयार किए गए थे तथा उन्होंने स्वयं स्वीकृत किए थे। उन्होंने कहा कि मागदशन निर्देशा का कानूनी तौर पर कोई महत्व नहीं था। यदि ऐसा होता तो इह नियमा के रूप म जारी किया जाता। यह निर्देश अखबारा के सम्पादका की सहायता के लिए तयार किए गए थे तथा इह तयार करते समय विभिन्न पत्रा तथा कई पत्रकारा स विचार विमश किया गया था।

जस्टिस शाह न पूछा 'क्या सेंसरशिप को अवध ठहराने के लिए गुजरात उच्च 'यामालय के निणय को प्रकाशित नहीं किए जाने के निर्देश उन्होंने सेंसर-अधिकारी को दिए थे जबकि उच्च 'यामालय ने आदेश दिए थे कि फसले के प्रकाशन पर सेंसरशिप के अतगत रोक नहीं लगाई जाए ?'

श्री शुक्ल ने इसके जवाब म कहा सरकार ने उच्च 'यामालय के निणय क खिलाफ सर्वोच्च 'यामानय मे अपील करन का निश्चय किया था। मैंने अधिकारियों से कहा था कि मेरे निर्देशा का कानून के अतगत पालन किया जाए और यदि कानून का उल्लंघन हो ता उनपर अमल नहीं किया जाए।

श्री गांधी के प्रचार म सबध म श्री शुक्ल का कहना था कि उनकी कलकत्ता यात्रा के प्रचार के लिए उन्होंने ही दूरदशन महा निदेशक को निर्देश दिए थे। उस समय न सिर्फ आकाशवाणी और दूरदशन ही बल्कि निजी समाचारपत्र भी श्री गांधी का काफी प्रचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति म दूरदशन को भी उनकी यात्रा का पूरा ववरेज करने को कहा गया था।

(11) अखबारों पर शिकजा—विज्ञापनों के जरिये

एमरजेंसी के दौरान अखबारों का सरकारी विज्ञापन देने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया, जिससे अनुसार उन्हें तीन भागों में बांटा गया—मित्र, तटस्थ और विरोधी। मित्र पत्रों का छात्र अखबारों का विज्ञापन रोकेन अथवा बढ़ कर देने का आदेश दिया गया।

उद्योगिकीय का नग्न तांडव

विज्ञापन एक दृश्य प्रचार निष्ठाश्रय (सी० ए० बी० पी०) के एक अधिकारी (मीडिया एक्जक्यूटिव) श्री हरनाम सिंह ने अखबारों के इस प्रकार में वर्गीकरण किए जाने की पुष्टि करत हुए बताया कि एमरजेंसी के दौरान जनप्रचार-माध्याम के उपयोग में उद्योगिकीय का नग्न तांडव हुआ तथा हर क्षेत्र में दबाव डाला गया और मनमानी की गई।

उन्होंने बताया कि हर दिन उनका निदेशक स्वर्गीय श्री एन० के० सती कहा करत थे, 'यदि यह काम नहीं हुआ तो गदन बंट जाएगी।' सम्भवतः यह बात कमचारियों को भयभीत करने के लिए कही जाती थी। श्री सिंह का कहना था कि एमरजेंसी के दौरान कुछ पत्रों की विज्ञापन करें एकदम बंद दी गई। नई पत्र पत्रिकाओं का विज्ञापन जारी करने के बारे में कानून-बाधकों को उठाकर ताक पर रख दिया गया। जहाँ एक ओर नये पत्रों को उसके प्रकाशन के छ महीने बाद विज्ञापन लिए जाने थे तथा श्रीमती मेनका गांधी की पत्रिका सूर्य का उमर पहले अकेले ही विज्ञापन देने प्रारम्भ कर दिया गया।

सी० ए० बी० पी० के ही उपनिष्ठाक (विज्ञापन) श्री सी० एस० प्रेमाल ने आयोग का बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्मारिका के लिए एक हजार रुपये प्रति पृष्ठ की दर से २० पृष्ठों का विज्ञापन स्वीकृत किए गए थे परंतु स्मारिका की ओर ॥ बिल दो हजार रुपये प्रति पृष्ठ की दर से लिए गए। इस बारे में जय श्री शुक्ल का मुक्ति किया गया तो उनका सचिव श्री सी० के० शर्मा ने इस विषय में मन्त्रालय के निर्देश दिए जिसका पालन किया गया।

विजिटिंग कार्ड पर आदेश

विनापन देन के बारे में एक रोचक प्रसंग यह भी सामने आया कि विज्ञापन जारी करने के आदेश न केवल मौखिक, बल्कि विजिटिंग कार्डों पर भी लिखकर दिए जाते थे।

नेशनल गार्ड के प्रबन्ध निदेशक श्री अशोक वालिया श्री शुक्ल के पास विनापन लेने पहुँचे। श्री शुक्ल ने उन्हें श्री शर्मा के पास भेज दिया जो उहाने उन्हें डी० ए० बी० पी० के निदेशक श्री सेठी के पास भेजा। श्री सेठी ने श्री वालिया के विजिटिंग कार्ड पर ही निर्देश देत हुए लिखा 'सूचनामन्त्री के निजी सचिव की इच्छानुसार कृपया इन्हें विनापन दे दें।'।

शुक्ल ने जिम्मेदारी ली

बाद में श्री शुक्ल ने आयोग का दिए अपने बयान में कहा कि उन्होंने विनापना के सम्बन्ध में जो भी आदेश दिए वे फाइला में देखे जा सकते हैं। उन्होंने जो कुछ किया, अपने नियमानुसार किया। इसके अतिरिक्त वे और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जहाँ तक कांग्रेस स्मारिका के विनापना का स्वाल है, उन्हें बताया गया था कि दर दर हजार रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब में ही भेजी गई थी।

(III) समाचार का गठन

एमरजेन्सी की घोषणा के समय देश में चार सबाद समितियाँ काम कर रही थीं। अंग्रेजी भाषा में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड यूज ऑफ इंडिया तथा भारतीय भाषाओं में समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार।

एमरजेन्सी की घोषणा के बाद से ही इन चारों एजेंसियों पर तरह-तरह से दबाव डाले जाने लग जाँरे श्री शुक्ल की आर स कई बार कहा गया कि देश में इन चारों एजेंसियों की बिखरती हुई वित्तीय स्थिति का सुधारने का एकमात्र विकल्प इन्हें मिलाकर एक ही समाचार एजेंसी बना देना है।

इस दिशा में पहला कदम १३ दिसम्बर १९७५ को उठाया गया जब मन्त्रिमंडल में चारों एजेंसियों का ससद में बिल लाकर

एक एजेसी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, परन्तु मन्त्रिमंडल ने उस स्वीकार नहीं किया। ऐसा करने पर यह लगने की सम्भावना थी कि एमरजेन्सी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में रहेगी। श्री शुक्ल से इस मामले में कोई दूसरा तरीका ढूँढने को कहा गया।

इसके बाद चारों एजेंसियाँ का सूचित किया गया कि सरकार (आकाशवाणी) ने १ फरवरी १९७६ से उनकी सेवाएँ न लेने का फैसला किया है। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि इन चारों एजेंसियाँ की आय का प्रमुख स्रोत आकाशवाणी ही है। इसके बाद सचार मन्त्रालय से इन एजेंसियाँ के उन टेलीप्रिण्टर सचिटा को काट देने को कहा गया जिनका भुगतान नहीं हुआ था। इसके साथ ही इन एजेंसियाँ से यह कहा जाता रहा कि भविष्य में इस प्रकार के परिणामों में बचन के लिए वे स्वेच्छा से एक एजेसी का गठन करने पर सहमत हो जाएँ।

२३ जनवरी, १९७६ को साप्ताहिकी आफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत 'समाचार' का गठन किया गया, जिसमें इन चारों एजेंसियाँ को अपना विलय करना था। १ फरवरी से इन एजेंसियाँ ने अपनी छवों समाचार डेट लाइन में देना प्रारम्भ कर दिया।

सभी एजेंसियाँ के संचालक मंडल में देश में एक मुक्त राष्ट्रीय सवाद समिति के लिए एक ही सवाद समिति के निर्माण की आवश्यकता मजबूर की और २ अप्रैल, १९७६ से समाचार ने काम प्रारम्भ और अन्य गतिविधियों को अपने अंतर्गत ले लिया।

इस बीच श्री शुक्ल ने इस बात की तरफ इशारा किया कि इन चारों एजेंसियाँ के सर्वोच्च अधिकारियों को हटा दिया जाए। इस प्रक्रिया के रूप में प्रेस ट्रस्ट के श्री के० एम० रामचंद्रन तथा यू० एन० आई० के श्री जी० जी० भीरघदानी को हटा दिया गया। समाचार के गठन के बाद समाचार भारती के प्रमुख सम्पादक श्री धर्मवीर गांधी को भी अपने पद से स्वेच्छापूर्वक त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। हिंदुस्तान समाचार के सचिव श्री बालेश्वर अग्रवाल को समाचार में कोई स्थान नहीं दिया गया, यद्यपि यह कहा जात रहा।

यू० एन० आई० के अध्यक्ष डाक्टर राम तरनजी ने जायोग को बताया कि यू० एन० आई० के साथ आकाशवाणी का समझौता अप्रैल, १९७३ में समाप्त हो गया था। काफी विचार विमर्श के

बाद जून १९७५ में दोनों के बीच एक नया समझौता हुआ लेकिन उसमें बायां बय के पूरे ही एमरजेन्सी की घोषणा हो गई और जुलाई-अगस्त ॥ ही श्री शुक्ल ने एक सवाद समिति के लिए दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया ।

डॉक्टर तरनेजा का कहना था कि यू० एन० आई० को आकाशवाणी से गुलन के रूप में १५ लाख रुपये लाने थे, फिर भी बताया कि राय के बहाने उनकी टेलीप्रिण्टर लाइनें काट देने की धमकी दी गई जबकि यह बताया राशि बहुत ही कम थी । इस बीच था शकल उनपर निरंतर एक ही एजेन्सी बनाने के लिए दबाव डालते रहे । परंतु यू० एन० आई० के बोर्ड ने अपनी २१ नवम्बर की बैठक में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । ९ सितम्बर को मन्त्रालय ने एक पत्र निधर इस्पर पुन विचार करने को कहा जिसके उत्तर में १० दिसम्बर को हुई बोर्ड की बैठक में परिस्थितियां को ध्यान में रखते हुए एक एजेन्सी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया ।

विलय जोर-जबरदस्ती से

पी० टी० आई० के अध्यक्ष श्री पी० सी० गुप्ता ने बताया कि समाचार का गठन अनुचित दबाव तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की जोर जबरदस्ती से किया गया ।

समाचार के अध्यक्ष श्री जी० कस्तूरी ने आयोग को बताया कि उन्हें जनवरी में किसी समय श्री शुक्ल ने फोन कर समाचार के बारे में बताया था । उन्होंने इसका अध्यक्ष बनना इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उन्हें जाना था कि इससे देश को एक सुदृढ़ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समाचार एजेन्सी मिल सकती ।

उनका कहना था कि यह सही ॥ कि समाचार के गठन में सरकार का मुख्य हाथ रहा था परंतु यह कहना गलत होगा कि उन्होंने समाचार के प्रबंध के बारे में कभी भी सरकार से कोई आदेश लिए थे । कभी कभी सरकार द्वारा सुझाव ज़रूर दिए गए थे परंतु सभी को माना नहीं गया ।

सरकार का कोई दबाव नहीं

श्री शुक्ल ने आयोग को बताया कि आकाशवाणी तथा सरकारी

विभागा में एजेंसिया के टेलीप्रिण्टर इसलिए काट दिए गए थे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि एजेंसिया वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर निर्भर रहे। सरकार के एजेंसिया के साथ किए गए समझौते समाप्त हो चुके थे तथा नए समझौते हुए नहीं थे, इसलिए उन्हें सिर्फ तदर्थ राशि दी जा रही थी।

उनका कहना था कि समाचार के गठन से पूर्व इन एजेंसिया की हालत और भी खराब थी तथा वे प्रत्येक कार्य के लिए सरकार की आश्रय लेती रहती थी। श्री शुक्ल ने कहा कि श्री रामचन्द्रन तथा श्री गिरिचन्दानी का कार्यकाल तो पहले ही समाप्त हो चुका था तथा वे बर्खास्त हो अब भी काम कर रहे थे इसीलिए उन्हें हटा दिया गया था।

(iv) गीत एवं नाटक प्रभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकारों का उपयोग सरकारी कार्यक्रमों तथा सरकारी स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में ही किया जाता है परन्तु एमरजेंसी के दौरान इसके कलाकारों का उपयोग युवक कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी किया गया।

युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित कुछ शिविरों में इस प्रभाग के कलाकारों का ले जाया गया जहाँ उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

सत्तालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री शुक्ल ने आमोद के समक्ष इसका स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि कोई भी सरकारी सस्था मंत्रालय से अनुरोध कर इन कलाकारों की सेवाएं प्राप्त कर सकती है इसके लिए उसका कुछ भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार युवक कांग्रेस के शिविरों में इन कलाकारों का उपयोग से कोई सरकारी काम नहीं हुआ था।

(v) किशोरकुमार के गीतों पर प्रतिबन्ध

एमरजेंसी के दौरान ही हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक किशोरकुमार के गीतों पर भी आनाशबाणों और दूरदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इसका कारण यह था कि उन्होंने थामती गांधी के २० मूर्ती कार्यक्रम सहभाग्य दत्त तथा युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया था।

समयन में प्रत्येक समाचार लिया गया।

(I) 'त्यागपत्र' बनाम 'दल-बदल'

२ फरवरी १९७७ को रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम ने मन्त्रिमंडल तथा कांग्रेस से त्यागपत्र दे लिया। श्री जगजीवनराम ने इस बात का घोषणा एक सवाददाता सम्मेलन में की।

समाचार' द्वारा श्री जगजीवनराम के त्यागपत्र के सम्बन्ध में एक समाचार कुछ ही देर बाद जारी लिया गया कि 'श्री जगजीवनराम ने कांग्रेस तथा मन्त्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है' परंतु उसके बाद उनकी टेलीप्रिंटर मशीनें इस समाचार के बारे में काफी देर तक خامोश रही और जब यह समाचार पुनः लिया गया तो उसमें छपा था कि श्री जगजीवनराम ने दल बदल कर दिया है।

इसी प्रकार आकाशवाणी द्वारा अपने पहले बुलेटिन में इस त्यागपत्र ही बताया गया था, परंतु बाद के बुलेटिन में इसे 'दल बदल' कर दिया गया।

समाचार तथा आकाशवाणी द्वारा प्रारंभ में श्री जगजीवनराम के त्यागपत्र के उल्लेख के बाद 'समाचार' के जनरल मैनेजर श्री डब्ल्यू० लज्जाराज को तथा आकाशवाणी में समाचार सेवा के निदेशक श्री शंकर भट्ट को मंत्रालय में बुलाया गया जहां उनसे श्री शुक्ल ने त्यागपत्र शब्द पर आपत्ति करते हुए इसे दल बदल करने को कहा और उन्हींके निर्देशानुसार बाद के समाचारा और बुलेटिनों में यह शब्द दल बदल ही चला।

(II) 'बाँबी' का टीवी पर प्रदर्शन

६ फरवरी १९७७ को दिल्ली के रामलीला मदान में विरोधी दलों द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण तथा श्री मारारजी देसाई सहित कई अन्य विपक्षी नेता भी बोलने वाले थे। ५ फरवरी को श्री शुक्ल के विशेष सहायक श्री बी० एस० त्रिपाठी ने उनके निर्देशानुसार प्रदर्शन के सहायक महानिदेशक श्री एन० एन० चावला को फोन पर निर्देश दिया कि दूसरे दिन टीवी पर बस' के स्थान पर बाबा' फिल्म दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि फिल्म यहां उपलब्ध नहीं है तो

बम्बई से भगाने की व्यवस्था की जाएगी ।

दिल्ली दूरदर्शन के सहायक निदेशक श्री एम० पी० लल न बताया कि श्री त्रिपाठी के निर्देशानुसार पाच तारीख की रात्रि को दस बजे 'बाबी' फिल्म दिखाने के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी जबकि उस समय तक फिल्म की प्रिंट हमारे पास तक नहीं आई थी । काफी प्रयत्ना के बाद फिल्म दिखाए जाने के समय से लगभग एक घंटे पहले बादनी चौक स्थित एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहां फिल्म की प्रिंट ढकी जा सकी, और समय की कमी के कारण नियमानुसार उसकी पूर्ण जांच भी नहीं की जा सकी । उनका कहना था कि फिल्म दिखाने का समय छ के स्थान पर पाच बजे करने का निर्णय भी श्री त्रिपाठी के निर्देशानुसार ही किया गया था ।

दूरदर्शन निदेशालय में कार्यक्रम नियंत्रक श्री शिवशंकर शर्मा ने बताया कि उन्होंने सुना था कि 'वक्त के स्थान पर बाँबी' के प्रदर्शन को उचित ठहराने के लिए 'वक्त' की एक रील बर्बाद कर दी जाए । उन्होंने स्वयं श्री भावला के इस सुझाव का विरोध किया था कि बाबी के प्रदर्शन को छ के स्थान पर पाच बजे करने के लिए यह नोट लिख दिया जाए कि फिल्म के बर्बाद होने के कारण यह किया गया ।

सभा में कम लोगो के जाने के उद्देश्य से प्रदर्शन

श्री त्रिपाठी का इस सम्बन्ध में कहना था कि उन्होंने श्री शुक्ल के निर्देशानुसार ही श्री भावला से 'बाबी' फिल्म दिखाने को कहा था । उन्होंने स्वीकार किया कि सम्भवतः यह इसलिए किया गया था, ताकि लोग शाम को विरोधी दलों द्वारा आयोजित आम सभा में कम से कम संख्या में जाएं । परंतु उन्होंने इस बात से इंकार किया कि बाँबी दिखाए जाने को उचित ठहराने के लिए उन्होंने वक्त फिल्म की एक रील बर्बाद कर देने को कहा था ।

श्री शुक्ल ने स्वीकार किया कि 'वक्त' के स्थान पर 'बाबी' का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ही निर्देश दिए थे ।

इसकी सफाई में उनका कहना था कि कुछ लोग न उनसे शिकायत की थी कि 'वक्त' फिल्म में कुछ दृश्य ठीक नहीं हैं इसलिए इसका प्रदर्शन नहीं किया जाए यद्यपि यह सही है कि उन्होंने स्वयं यह फिल्म नहीं देखी थी । शिकायत करने वाले ही कुछ लोगो न

सुझाव दिया था कि 'वक्त' के स्थान पर 'बाबी' पिन्म लिखाई जाए, और इसीलिए उन्होंने यह निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि 'वक्त' पत्र के बाद में अन्य केन्द्रों पर भी नहीं दिखाया गया था।

(III) कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र का 'सरकारी' अनुवाद

१९७७ में माच में हुए लोकसभा के चुनाव के लिए एमरजेंसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस द्वारा अपने चुनाव घोषणापत्र का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए डी० ए० बी० पी० तथा आकाशवाणी के अनुवादकों का उपयोग किया गया।

७ फरवरी १९७७ का दोपहर में लगभग दो बजे श्री शुक्ल के विशेष सहायक श्री बी० एस० त्रिपाठी ने आकाशवाणी समाचार सेवा के निदेशक श्री शंकर भट्ट तथा डी० ए० बी० पी० के तत्कालीन निदेशक (स्वर्गीय) एन० के० सेठी को फोन कर कहा कि श्री शुक्ल चाहते हैं कि घोषणापत्र के अनुवाद के लिए उनके यहां के अनुवादकों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री महोदय चाहते हैं कि इस काम का तुरंत करान की व्यवस्था की जाए और उनके निर्देशों का तुरंत पालन हो।

श्री सेठी तथा श्री भट्ट ने एक दूसरे से बात कर यह तय किया कि किस किस भाषा के कितने कितने आत्मी आकाशवाणी अथवा डी० ए० बी० पी० के जाएंगे। इसके पश्चात् दोनों ओर के अनुवादकों की विश्व युवन केन्द्र में जाया गया जहां अनुवाद का काम कई-तीन बजे दोपहर में प्रारम्भ होकर रात्रि को साढ़े दस ग्यारह बजे तक चलता रहा। इस पूरे काम को गुप्त रखा गया। इससे कुछ दिनों बाद ही समाचारपत्रों में जनता पार्टी की एक खबर छपी कि डी० ए० बी० पी० तथा आकाशवाणी के अनुवादकों का कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र के अनुवाद के लिए दुरुपयोग किया गया है। चुनाव आयोग की किसी भी सम्भावित जांच से बचने के लिए जो-जो अनुवाद इस काम के लिए भेजे गए थे उनसे इस बात के छड़न पत्र लिखवाए गए कि उनका इस प्रकार के अनुवाद कायों से कोई सम्बन्ध नहीं था।

इस पूरे काम में आकाशवाणी के ११ तथा डी० ए० बी० पी० के भी इतने ही अनुवादकों ने भाग लिया। इसमें से आकाशवाणी के

अनुवादको को १२५ रुपया या इसके लगभग राशि का भुगतान किया गया, जबकि डी० ए० वी० पी० के अनुवादका को कुछ भी राशि नहीं दी गई।

जाकाशवाणी के विभिन्न अनुवादका ने (सहायक सम्पादको) आयोग को बताया कि उनमें से अधिकांश को उनके घरों से यह कहकर बुलाया गया था कि कोई बहुत ही जरूरी काम है। जब वे कार्यालय पहुँचे तो उन्हें स्टाफ कार और टैक्मिया में युवक केन्द्र से जाया गया।

डी० ए० वी० पी० के विभिन्न अनुवादका का कार्यालय से ही यह कहकर ले जाया गया कि उनकी संवाए एक जरूरी तथा गोपनीय कार्य के लिए चाहिए। लज्जाने से पूर्व निदेशक श्री सठी ने उनसे यह शपथ दिलवाई कि वे इस कार्य के बारे में किसीको भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही गोपनीय है। डी० ए० वी० पी० के कुछ लोग बसा और टैक्मिया से युवक केन्द्र पहुँचे।

अनुवाद करते समय रात को देरहाने की जाशका से सभीने अपने-अपने घरों पर सूचित करने को कहा, और अधिकांश न फोन के जरिये अपने घरों पर सूचना भी दी कि वे दरस आएंगे परन्तु किसीका भी यह नहीं बताया दिया कि वे कहाँ बान रहे हैं तथा क्या काम कर रहे हैं।

डी० ए० वी० पी० के जिन लोगों ने अनुवाद-कार्य में भाग लिया वे हैं—सबश्री डी० एन० स्वादिया जी० पी० सोहनी पी० के० त्रिपाठी वी० के० सोखिया, श्रीमती मुखर्जी एस० एन० सरना, कालन्वलू श्रीमती जे० मगम्मा, मी० आर० मडल कृष्णा दास, (सभी सहायक सम्पादक) तथा एक सीनियर कापी राइटर श्री श्रीनिवासन।

जाकाशवाणी के जिन मह-सम्पादका तथा यूज रीडर ने भाग लिया, वे हैं—सबश्री रामचन्द्र राव (समाचार-सम्पादक), एन० रहमान डी० के० दोलकिया, ए० आर० रंगाराव, एच० के० राम-कृष्ण श्रीमती इन्काले आर० एस० वैकट रमन, कुमारी सुरेन्द्र-बत्ता, कुमारी इवा नाग, श्रीमती एम० बत्ता तथा श्री शंकर-नारायणन।

शमिन्दगी का पारिश्रमिक

आकाशवाणी के समाचार-सम्पादक श्री राव न बताया कि उस समय वातावरण ही ऐसा था कि किसी काम के लिए इकार करने का सवाल ही पड़ा नहीं होता था। श्री राव ने बताया कि अनुवाद काय के पारिश्रमिक के रूप में उन्हें १२५ रुपये के लगभग राशि दी गई थी परन्तु वे उस समय इतने ज्यादा शमिन्दगी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने उस गिना भी नहीं और ज्यादा छुट्टियाँ मिली, वे सबसे पहले बट्टीनाथ की यात्रा पर गए और वहाँ वे रपय चढा आए।

इसपर आयोग के वकील कास खडातावाता ने कहा, क्या वे रुपये मंदिर में चढाने से आपके पाप धुल गए ?

‘पाप धुले हा या नहीं परन्तु इससे मेरी आत्मा का काफी शांति मिली है।’

भीड़ इकट्ठी करने के लिए बुलाया

आकाशवाणी के ही श्री डोलकिया ने बताया कि जब उन्हें कैद ले जाया गया तभी उन्होंने सोच लिया था कि कोई ऐसा बसा काम ही होया था फिर कांग्रेस की कोई सभा हागी, जहाँ लोगो की भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत पड गई होगी।

इसपर श्री शुक्ल के वकील श्री राजेन्द्रसिंह ने कहा, क्या इससे पूर्व भी आप इसी प्रकार से कांग्रेस की सभाओं में सख्या बढाने के लिए जाते रहते थे ?

‘नहीं मैं गया तो कभी नहीं लेकिन मैंने ऐसा ही अपना विचार बनाया था।’

एक वाक्य के अनुवाद में चार घंटे

डी० ए० बी० पी० ने श्री सरनाने आयोग को बताया कि उन्हें अनुवाद काय का ३० वष का अनुभव है, परन्तु यह काम काम पर निर्भर करता है कि उसपर कितना समय लगता है। उन्होंने इस सबंध में एक उदाहरण देते हुए बताया कि एमरजेंसी में उन्हें एक नारेका अनुवाद करना था— फारमट दी गवनमट एण्ड डू इट योर सेल्फ। इसका साधारण अनुवाद होता— सरकार को भूलिए अपना

काम स्वयं करिए।' उह इस अनुवाद में चार-पाच घंटे लग गए परन्तु जो अनुवाद हुआ, वह था, 'सरकार को राम राम, खुद सभालो अपना काम।'

जिरह के दौरान जहा आयोध के वकील सभी गवाहा से यह सिद्ध करा रहे थे कि उहोंने यह काम इसलिए किया था कि उहें भय था कि इकार कर देने पर नौकरी से हटाया जा सकता था तथा इससे उनके परिवार पर गम्भीर आर्थिक संकट आ सकता था वही थी शुक्ल के वकील श्री सिंह इन गवाहा से यही प्रश्न पूछकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि नौकरी के डर से ही वे अब भी झूठ बोल रहे हैं और उस समय भी उन्होंने जो कुछ किया, अपनी इच्छा से किया।

पूछताछ के कारण खडन-सम्बन्धी बयान

आकाशवाणी समाचार सेवा के निदेशक श्री शंकर भट्ट का कहना था कि चुनाव आयोग द्वारा किसी भी सभावित पूछताछ को ध्यान में रखते हुए ही अनुवादका से खडन-संबंधी बयान लिखवाए गए थे।

श्री भट्ट ने इस संव काय की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेत हुए कहा मैं जानूँ तो नहीं जानता फिर भी मैं उस समस्त काय की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, जो श्री मुशी तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने किए हैं।

मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री के० एन० प्रसाद ने इस बात से इकार किया कि उहोंने श्री भट्ट तथा श्री सेठी से अनुवाद के सम्बन्ध में खडन संबंधी बयान लिखवाने को कहा था।

श्री शुक्ल के विशेष सहायक श्री त्रिपाठी ने इस बात को एक हम गलत बताया कि उहोंने अनुवाद के संबंध में श्री भट्ट अथवा श्री सेठी को कोई निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि उन्होंने इस प्रकार की खबरें जब अखबारों में पढ़ी तो पहली बार उहें इस बारे में जानकारी हुई थी और उन्होंने इसमें श्री शुक्ल को रायपुर फोन कर सूचित किया था, परन्तु उहोंने कोई टिप्पणी नहीं की थी।

तीन दिन में पालन

एमरजेंसी के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने

सभी विभागा का इस बात के लिखित आदेश दिए थे कि मंत्री महोदय द्वारा स्वयं अथवा उनके किसी निजी सचिव और विशेष सहायक के जरिये दिए गए सभी मौखिक और लिखित आदेशों का तीन दिन में पालन होना चाहिए।

ये तथ्य आकाशवाणी के महानिदेशक के महानिदेशक श्री चटर्जी द्वारा ३० जून १९७६ को अपने सभी क्षेत्र निदेशकों को लिख गए एक पत्र की प्रतिलिपि में नात हुए। श्री चटर्जी ने लिखा था 'कुछ दिनों पूर्व मंत्रालय द्वारा एक केंद्र के कमचारी को निलंबी स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था, परंतु विभागाध्यक्ष यह कार्य नहीं कर सके और वे स्वयं भी भूल गए। तत्पश्चात् डा. महीने बाद मंत्रालय द्वारा इस बारे में जानकारी चाही गई और इससे उन्हें बड़ी कठिन स्थिति में गुजरना पड़ा।'।

श्री चटर्जी ने आगे लिखा था कि 'मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार मंत्री महोदय द्वारा स्वयं अथवा उनके निजी सचिव और विशेष सहायक के जरिये दिए गए सभी मौखिक तथा लिखित आदेशों का तीन दिन के भीतर पालन हो जाना चाहिए। आदेशों का पालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसके परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए।'।

चुनाव पोस्टर भी

कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र के अनुवाद के अतिरिक्त चुनाव पोस्टरों को तैयार करने में भी डी० ए० वी० पी० की सहायता ली गई थी। सीनियर कॉपोराइटर श्री धीनिवासन ने बताया कि उनसे श्री सत्य गांधी के विशाल आकार के फोटो चित्र और चुनाव पोस्टर तैयार करने को कहा गया था। इसने अतिरिक्त श्री मुकुल के निर्वाचन-संकेत के लिए भी पोस्टर बनाने का काम किया गया था।

इस सम्बन्ध में डी० ए० वी० पी० के मुख्य विजुनलाइजर श्री जे० भट्टाचार्य का कहना था कि तत्कालीन निदेशक श्री सैठी ने उनसे पांच पोस्टर बनाने का कहा था जो इस प्रकार थे—एक पोस्टर में श्री श्यामचरण शुक्ल के साथ श्रीमती गांधी को दिखाया गया था दूसरे में श्री विद्याचरण शुक्ल को श्रीमती गांधी के साथ तीसरे में श्री श्यामचरण शुक्ल अपने-अपने छोटे में, श्री विद्याचरण

शुक्ल अकेले और पाचवें में श्रीमती गांधी अकेली दिखाई गई थीं।

उन्होंने बताया कि उनको पोस्टर के सम्बन्ध में मौखिक और लिखित दोनों आदेश दिए गए थे जिनकी पूर्ण पालना की जा सकती है। पोस्टर बनने के बाद श्री सेठी उह तथा आठ एक्ज्यूक्यूटिव श्री दत्ता गुप्ता को लेकर श्री शुक्ल के घर गए थे और उह पोस्टर दिखाए थे। श्री शुक्ल ने इनमें कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। उन्होंने इन पोस्टरों को परिवर्तन के बाद श्री सेठी को दे दिया था। उसके बाद इनका क्या हुआ—उह मालूम नहीं।

(IV) हमला सजय गांधी और पुरुषोत्तम कौशिक पर

चुनाव घोषणा के बाद आकाशवाणी द्वारा जहा अमेठी में श्री सजय गांधी पर हुए कथित हमले के समाचार को तुरन्त दूसरे दिन सवेरे और उसके बाद के सभी समाचार बलटिना में स्थान दिया गया वहीं रायपुर में श्री पुरुषोत्तम कौशिक पर हुए हमले के समाचार का जिक्र तक नहीं किया गया। श्री गांधी पर हुए हमले के सम्बन्ध में तो नेताओं की प्रतिक्रियाएँ तक दी गई थीं।

शुक्ल के निर्देश में

आकाशवाणी में समाचार सत्र के निदेशक श्री भट्ट का इस सम्बन्ध में कहना था कि १५ १६ मार्च की रात्रि का लगभग १२ बजे के बीच उनके पास श्री शुक्ल की आर स पान आया था कि श्री गांधी पर हुए हमले का समाचार तुरन्त प्रसारित किया जाए तथा सवेरे तक उनपर हुए आक्रमण पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाओं को भी प्रसारित किया जाए जबकि दूसरी ओर श्री कौशिक पर हुए आक्रमण के बारे में उनके पास निर्देश आये थे कि इस समाचार को नहीं दिया जाए। उन्होंने जो कुछ किया श्री शुक्ल के निर्देशानुसार किया।

श्री शुक्ल ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने रायपुर में उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री पुरुषोत्तम कौशिक पर हुए हमले के समाचार को न देने का निर्देश दिए

थे ।

इसका स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की नीति है कि चुनावों के दिनों चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसक घटनाओं का प्रचार न किया जाए, क्योंकि इससे गलत वातावरण बनता है। इसके अतिरिक्त श्री कौशिक पर हुआ हमला वास्तव में उनपर नहीं हुआ था बल्कि उनके साथ बैठे एक राजनीतिक नेता पर किया गया था ।

अलग अलग स्टैंडर्ड क्या ?

इसपर श्री जस्टिस शाह ने जानना चाहा कि जमड़ी में श्री सजय गांधी पर हुए आक्रमण को तो इतनी प्रमुखता से प्रसारित किया गया और श्री कौशिक पर हुए आक्रमण को बिलकुल गोल कर दिया गया आखिर एक ही जैसे दो मामलों में अलग-अलग स्टैंडर्ड क्या ?

श्री शुक्ल ने इसके जवाब में कहा श्री गांधी के समाचार को हमें ही नहीं बल्कि निजी समाचारपत्रों तथा अन्य प्रचार साधनों ने भी प्रमुखता दी थी, जबकि उसके मुकाबले श्री कौशिक पर हुए आक्रमण को बहुत कम प्रमुखता दी गई थी । उनका कहना था कि जब निजी प्रचार तंत्र द्वारा श्री गांधी को इतनी अधिक प्रमुखता दी जा रही थी तब भी हमने उसके अनुसार ही ऐसा किया यह तो जनवर्षि की बात थी ।

(v) चुनावों की घोषणा और सेंसरशिप

जनवरी १९७७ में लोकसभा के चुनाव घोषित किए जाने के बाद से यद्यपि बहनों के लिए मेंबरशिप के नियमों में ढील दे दी गई थी परंतु उनपर लगातार नज़र रखी जा रही थी । इस सबके पीछे एक ही उद्देश्य था कि जो समाचारपत्र इन दिनों सरकार का विरोध करेंगे उनके विरुद्ध चुनाव समाप्त हो जाने के बाद कारबाई की जा सकती ।

चुनावों की घोषणा के बाद अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के साथ मिलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक आचार-महिता बनाई और यह तय किया गया कि समाचार पत्र इसका स्वेच्छा से पालन करेंगे । सम्मेलन की इस बैठक में नेश

नल हेराल्ड के श्री चेलापतिराव 'पट्रियट' के श्री एडता भारामणन, हिंदुस्तान टाइम्स के श्री हिरनमय कालेंकर और समाचार' के श्री डब्ल्यू० लजारम शामिल थे। इस बैठक में मन्त्रालय के अधिकारियों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की ओर से उनके सचिव श्री पा० एन० धर तथा प्रेस सचिव श्री शारदाप्रसाद भी शामिल थे।

पत्र-पत्रिकाओं पर नजर

श्री शुक्ल ने २१ जनवरी को अपने मन्त्रालय के वरिष्ठ अधि-
कारियों को एक बैठक बुलाकर निर्देश दिए कि देश के विभिन्न भागों
में निम्नलिखित बातें सभी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं पर सावधानी
पूर्वक नजर रखी जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कोई लिखित
आदेश तो नहीं दिया गया था परन्तु मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों
के जरिये समाचारपत्रों के सम्पादकों को इस सबंध में चेतावनी
जारी दी गई थी।

मुख्य सूचना अधिकारी डा० एस० दयाल इस सम्बन्ध में 'स्टेट्स-
मैन' के सम्पादक श्री एस० सहाय तथा टाइम्स आफ इंडिया के
संपादक श्री गिरिलाल जन से मिल गए तथा उनसे पत्रों में छप रही
कुछ खबरों के प्रति उन्हें चेतावनी दी।

प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री शारदाप्रसाद के निर्देशों
नुसार प्रतिदिन अखबारों में छपने वाली खबरों की समीक्षा तैयार
की जान लगी। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रेस के रख-रखाव पर नजर रखना
था।

मेंबरशिप में ढील बनाम मरों पर लटकी तलवार

स्टेट्समैन के श्री एस० सहाय 'टाइम्स आफ इंडिया' के श्री
गिरिलाल जन तथा 'हिंदुस्तान टाइम्स' के श्री हिरनमय कालेंकर के
अनुसार यद्यपि चुनावों की घोषणा के बाद मेंबरशिप में ढील दे दी
गई थी तथापि वह ढील उस सटकी हुई तलवार के समान थी,
जो कभी भी उनपर गिर सकती थी और ऐसा डर बराबर उन
लोगों के मन में बना रहा था। उनका कहना था कि वे जो कुछ छाप
रहे थे एक तरीके से अपनी जोखिम पर ही छाप रहे थे, क्योंकि मन्त्रा-
लय के अधिकारियों के व्यवहार से साफ लग रहा था कि यदि चुनाव
में सत्ताह्वित पार्टी पुनः सत्ता में आ जाती, जसी कि उस समय सभा

बना व्यक्त की जा रही थी, ता निश्चित रूप से उन्हें किसी भी हालत में नहीं बखशा जाता।

इंडियन एक्सप्रेस' के उप मुख्यसम्पादक श्री अजीत भट्टा चार्जी का कहना था कि लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद एक राजनयिक समारोह में श्री डी० पेहा ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि 'यद्यपि सरकार समाचारपत्रों में छप रही आपत्तिजनक खबरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही परंतु यह याद रखा जाना चाहिए कि इसपर आपत्तिजनक मामलों अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है और इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि चुनावों के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बार में अथवा बारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

श्री भट्टाचार्जी ने बताया कि उनके जनरल मैनेजर श्री आर० के० मिश्र ने बताया था कि श्री प्रसाद ने उन्हें सूचित किया है कि सरकार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हरियाणा के दो गांवों में हुए अत्याचारों से संबंधित खबर छापने पर खुश नहीं है।'

श्री दयाल ने इस सम्बन्ध में बताया कि सरकार का इंडियन एक्सप्रेस तथा स्टेट्समैन में छप रही खबरों तथा लघुओं पर काफी शिकायत थी। श्री शुक्ल ने उनसे कहा था कि 'स्टेट्समैन' के संपादक से मिलकर उन्हें उनकी मारामगी से अवगत करा दें। परंतु वे स्वयं नहीं समझते थे कि उनके इस प्रकार से सम्पादक से मिलने के बाद स्टेट्समैन अपनी सम्पादकीय नीति में परिवर्तन कर लेगा।

तीन फरवरी की बठक के बाद श्री शुक्ल के निर्देशानुसार मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों की एक बठक प्रतिदिन होती थी जिसमें समाचार के आ लजाव और आकाशवाणी के श्री भट्टा को भी बुलाया जाता था। इस बठक में प्रतिदिन की खबरों के मामले में समीक्षा की जाती थी तथा नीति निर्धारित की जाती थी कि किस प्रकार की खबरें देनी हैं और किस प्रकार की नहीं।

आकाशवाणी में समाचारों का मन्तव्य

चुनाव घोषणा के बाद से ही आकाशवाणी पर खबरें प्रसारित किए जाने के बारे में दवाव डाला जाने लगा था। २४ फरवरी का मंत्रालय के सचिव ने आदेश दिए कि कांग्रेस और बिपक्ष की खबरों का अनुपात दो के मुकाबले एक होना चाहिए परंतु यह अनुपात

बढ़ते-बढ़ते १२ से १५ मई के बीच साढ़े आठ के मुकाबले एक हा गया।

इस अवधि में आकाशवाणी के श्री भट्ट का कहना था कि जहाँ चुनावों की घोषणा के बाद समाचारपत्रों पर से संतर हटा दिया गया था वही आकाशवाणी पर यह और भी चल हो गया था। उन्होंने बताया कि जहाँ एक अवसर पर आकाशवाणी द्वारा कांग्रेस को ५५ प्रतिशत तथा विपक्ष को ४५ प्रतिशत समय दिया जाता था वही यह फरवरी १७ से २३ के बीच तीन के मुकाबले दो के अनुपात में हो गया था और मार्च १२ से १५ के बीच तो यह बढ़कर आठ के मुकाबले एक हो गया और अगले चार दिन तक यही चलता रहा।

कांग्रेस हरिजन और पिछड़े वर्गों के हितों की एकमात्र रक्षक ।

श्री भट्ट ने बताया कि इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे कि समाचारों को इस तरह पेश किया जाए जिसमें लगे कि सिर्फ कांग्रेस ही ऐसा दल है जो पिछड़े वर्ग तथा हरिजन के हितों की रक्षा करने में समर्थ है।

'समाचार के श्री लज्जारस का कहना था कि सिर्फ श्री जग जीवनराम के त्यागपत्र से सम्बन्धित अवसर ही ऐसा था जब उन्हें सरकार की ओर से कोई निर्देश लिए गए थे। जहाँ तक मंत्रालय की बैठक में उनसे शामिल होने का सवाल है उन्होंने ऐसा मंत्रालय के सचिव के कहने पर किया था। उस बैठक में मुख्यतः पत्र सूचना कार्यालय और आकाशवाणी के लिए ही निर्देश लिए जाते थे। उन्होंने इस बात को गलत बताया कि समाचार के लिए भी वहाँ कोई निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि वे १५ या २० बार उस बैठक में भाग लेने गए थे, उसके बाद नहीं गए।

श्री लज्जारस ने इस बात को गलत बताया कि उन्होंने अपने स्टाफ के लोगों का चुनाव समाचारों को देने से पहले उनसे स्वीकृत कराने को कहा था। उन्होंने कहा कि यह हो सकता है कि कुछ समाचारों को उनका दिखाकर दिया गया हो परन्तु यह तो पहले से ही होता आया था। उनकी पूर्ववर्ती एजेन्सी पी० टी० आई० में एसी परम्परा रही थी कि चुनाव आदिके समय किसी भी विवादास्पद

समाचार को दिल्ली की केन्द्रीय डेस्क पर भेजा जाता था।

इससे पूर्व 'समाचार' के विभिन्न सवाददाताओं ने आयोग को बताया कि उन्हें निर्देश दिए गए थे कि राजनीतिक समाचार संपादकीय विभाग में देन से पहले श्री लजारस से स्वीकृत कराए जाएं। कितनी ही बार तो समाचारों में भारी गद्दीबदली तक किए गए थे।

शुक्ल की सफाई

श्री शुक्ल का इस अवधि में कहना था कि जख्मों पर किसी प्रकार का दबाव डालने की बात गलत है। जहां तक आचार संहिता का संबंध है उसे समाचारपत्रों के सम्पादकों से विचार विमर्श के बाद ही बनाया गया था।

प्रचार के लिए सर्वे

समाचारों के बारे में जार खबरदस्ती के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा २० जनवरी को सलाहकार डा० एन० बी० राय को निर्देश दिए गए थे कि वे ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएं जहां विपक्षी दलों का प्रभाव है तथा यह भी सुचाएं कि इन क्षेत्रों के लिए किस प्रकार से प्रचार कार्य किया जा सकता है।

मत्तारूढ़ दल और सरकार में अन्तर नहीं

इस सम्बन्ध में श्री राय का कहना था कि उन्हें इस प्रकार के निर्देश मंत्रालय के सचिव श्री वर्नी ने दिए थे। उन्होंने बताया कि उन दिनों मत्तारूढ़ दल और सरकार में कोई अन्तर नहीं रह गया था। इसलिए मत्तारूढ़ दल के लिए किया जाने वाला कार्य एक तरीके से सरकार के लिए किए जाने जैसा ही था।

गुस्ताखी का फल

चुनाव घोषणा के बाद रायपुर स्थित आकाशवाणी के अश कालिक सवाददाता श्री बोग को हटाने के भी आदेश दिए गए। श्री बोग के अनुसार उन्हें इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की एक सभा की खबर भेजने की गुस्ताखी की थी।

श्री शुक्ल ने इस सम्बन्ध में स्वीकार किया कि उन्होंने श्री बोरा को हटाने के निर्देश दिए थे, परन्तु इस बात से इकार किया कि यह इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने श्रीमती पट्टि की सभा का समाचार दिया था। उनके अनुसार सच तो यह है कि छत्तीसगढ़ इलाके में रायपुर के महत्त्व का देखते हुए वहाँ एक पूण-कालिक सवाददाता नियुक्त किया जाना था श्री बोरा को इसलिए नियुक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह पहले से ही एक समाचारपत्र में काम कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी यह बात इसीसे मिट्ट हो जाती है कि जनता सरकार ने भी श्री बोरा को नहीं रखा है और वहाँ एक पूणकालिक सवाददाता की नियुक्ति की गई है।

शुक्ल की लाचारी

आयोग द्वारा अपनी कायवाही में अंतिम चरण में श्री शुक्ल से १३ अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने का कहा गया था, परन्तु श्री शुक्ल ने अपनी सफाई में कुछ भी कहने में असमर्थता प्रकट करने हुए कहा कि वे इस समय अपनी सफाई में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि इस समय वे एक अन्य मुकदमे में (विस्मा कृमी का) फंसे हुए हैं और उसके कारण समय नहीं निवान पा रहे हैं।

उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि वह मामले पर सुनवाई स्थगित कर दे, ताकि उन्हें अपनी सफाई के लिए समय मिल सके परन्तु जस्टिस शाह ने उनका अनुरोध अस्वीकार करत हुए जन-प्रचार-साधना के दुरुपयोग वाले सभी मामलों में, जिनमें कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र का अनुवाद और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए डी० ए० वी० पी० के ऊपरि पास्टर बनाने का मामला भी शामिल है उनका पक्ष मुन बिना ही मरकारी वकील और आयाग के वकील से अपने तक रखने को कहा।

आयाग के वकील श्री छटानावाला और सरकारी वकील श्री सेखी का कहना था कि जनप्रचार साधना के दुरुपयोग में श्री शुक्ल का पूरा हाथ रहा है तथा उन्होंने यह कार्य तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की तस्वीर उभारने के लिए किया जो उचित नहीं था।

भुगतना पड़ा। उन्होंने बताया, 'हैदराबाद में इण्डियन एयर लाइंस ने अपना बुकिंग ऑफिस बनाने के लिए एक जमीन खरीदी थी। परंतु बाद में इस विचार को त्याग दिया गया और बाड की बैठक में विचार विमर्श के बाद उस भूमि का एक निजी पार्टी को बेच दिया गया। सरकारी ऑडिटर भी किसी ऐसी बात का पता नहीं लगा सके कि श्री मूर्ति का इस जमीन को बिकवान में या किसी विशेष व्यक्ति को दिलवाने में कोई हाथ था।'

श्री लाल ने बताया कि उन्होंने श्री मूर्ति को हटाए जान के बाद ही त्यागपत्र देन का निश्चय कर लिया था। उन्होंने साधा था कि वे अप्रैल में श्री मेहता को अपना त्यागपत्र दे देंगे, परन्तु जब उन्होंने एक व्यक्ति को अपने कमरे के बाहर मड़रात हुए देखा और पूछने पर पता चला कि एक पुलिस अधीक्षक तथा जाब ड्यूरो के चार अन्य अधिकारी मुख्यालय पर निगरानी रख रहे हैं, तो उन्होंने अपना इस्तीफा और पहले ही दे दिया।

जब वे श्री राजवहादुर से मिलकर अपने कमरे में लौटे और श्रीफ केस उठाकर जाने ही लगे कि एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोककर श्रीफ केस की तलाशी देने को कहा। पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा कि आप इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करें कि आप माघ कोई गुप्त कामजात नहीं ले जा रहे हैं।

श्री लाल ने भरे गले से कहा श्रीमान् जब मैं वामुननाथ्यक्ष था तब इण्डियन एयर लाइंस के कामजाता से भी कीमती और गोपनीय कामजात मेरे पास आत थे।

राजवहादुर की स्वीकारोक्ति

बाद में श्री राजवहादुर ने स्वीकार किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दाना एयर लाइंस के निदेशक मंडला के नामा के सुमाव उनके अनुरोध पर ही दिए थे।

उन्होंने बताया कि निदेशक मंडला का गठन मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ही किया करती थी परंतु उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि गठन के समय में सावजनिक उद्योग चयन बाड की राय लिया जाना जरूरी था अथवा नहीं। उनका कहना था कि यह जरूरी नहीं कि एयर लाइंस के अध्यक्षों से मंडला के गठन के बारे में राय ली हो जाए।

सत्कालीन प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव श्री घवन ने स्वीकार किया कि उन्होंने श्री राजवहादुर के विशेष सहायक श्री भटनागर को फोन कर दोनों निदेशक मंडला के सदस्यों के नाम बताए थे। उनका कहना था कि यह नाम श्रीमती गांधी ने स्वीकृत किए थे। उन्होंने बताया कि श्री भटनागर को जिस दिन उन्होंने नाम बताए थे उसी दिन श्री राजवहादुर व हस्ताक्षरों से निदेशक मंडलों की सूची प्रधानमंत्री सचिवालय को प्राप्त हो गई थी।

(II) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर पद पर श्री के० आर० पुरी की नियुक्ति

सत्कालीन वित्तमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने २६ जुलाई, १९७५ को सत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक अत्यंत गोपनीय पत्र लिखा जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया का जिक्र किया गया था। पत्र में उन चार नामों का भी उल्लेख था, जिनमें से किसी एक को गवर्नर पद के लिए चुना जाना था।

पुरी की नियुक्ति सुब्रह्मण्यम की इच्छा के बिना

श्रीमती गांधी ने श्री के० आर० पुरी का इस पत्र पर नियुक्त किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने जावन बीमा निगम जमीं बड़ी संस्था के अध्यक्ष के रूप में काफी अच्छा काम किया था। श्रीमती गांधी की इच्छानुसार श्री सुब्रह्मण्यम ने श्री पुरी की १८ अगस्त १९७५ का एक बयान के लिए नियुक्ति कर दी, जबकि वे स्वयं इससे सहमत नहीं थे।

श्री पुरी की नियुक्ति जहां १८ अगस्त का की गई वही मंत्रि मंडलीय नियुक्ति समिति के सचिव के पाम इसकी सूचना २० अगस्त को भेजी गई।

नियुक्ति समिति की कोई औपचारिक बैठक नहीं

इस सम्बन्ध में श्री सुब्रह्मण्यम का कहना था कि किसी भी

नियुक्ति पर विचार विमर्श करने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुआ करती थी। नियुक्ति के सम्बन्ध में जब भी कोई सिफारिश की जाती थी उस समिति के सम्स्या को भेज दिया जाता था और उनकी सहमति ली जाती थी। इस तीन सदस्यीय समिति के दो सम्स्या में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री हुआ करते थे जबकि तीसरा सम्स्या सम्बन्धित मंत्रालय का मंत्री हुआ करता था।

(III) पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० तुली की नियुक्ति

बकिंग मंत्रालय में सचिव ने 12 मई को रिजर्व बैंक के गवर्नर को एक पत्र लिखकर पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहे श्री टण्डन के स्थान पर नये व्यक्ति का नाम सुझाने को कहा। रिजर्व बैंक ने उस पत्र में जवाब में बैंक के उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० गुप्ता का नाम सुझाया। इस नाम पर तत्कालीन वित्तमंत्री ने भी अपनी सहमति व्यक्त की।

श्री गुप्ता के नाम पर मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति की स्वीकृति लेने के लिए एक पत्र ३० मई को लिखा गया परन्तु काफी लम्बे समय तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एम० जी० बाल मुग्रहाण्यम ने उक्त फाइल पर १५ जुलाई को एक नोट लिखा जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री सचिवालय से यह फाइल वापस जा गई है तथा इसमें कोई और नया नाम सुझाने को कहा गया है तथा उन्होंने इस संबंध में रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी बात कर ली है।

सिर्फ मट्रिक पास फिर भी बैंक चेयरमैन

श्री बाल मुग्रहाण्यम ने अपने इस नोट के बाद २१ जुलाई को एक और नोट लिखा, जिसमें कहा गया था कि मेरी १६ जुलाई को बलवत्ता में रिजर्व बैंक के गवर्नर से मुलाकात हुई थी तथा मैंने उनसे सरकार द्वारा यू.बी.आफ इंडिया के श्री टी० आर० तुली को पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने से

सबधित प्रस्ताव पर बातचीत थी। श्री बाग मुद्राध्यक्ष म १६ जुलाई को हुई इस बातचीत के तुरन्त पश्चात् २७ जुलाई का रिजर्व बैंक के गवर्नर ने लिखा, आपने जमी इच्छा व्यक्त की थी, मैं श्री तुनी के बारे में पूछताछ कराई है। श्री तुनी का जन्म १ अक्तूबर १९१३ को हुआ था और इस हिसाब में वह ६१ वर्ष पूर्ण भी कर चुके हैं। वे सिर्फ मद्रिब पाम हैं परन्तु उन्होंने अपने बैंक (यू बैंक आफ इंडिया) में काफी अच्छा काम किया है। इस बैंक की पूरी उन्नति का श्रेय श्री तुनी के नेतृत्व और कामकुशलता को ही जाता है। डा० हजारी द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच करा जा गई है और उन्होंने भी उनकी नियुक्ति के बारे में कोई आपत्ति नहीं की है।

गवर्नर के इस पत्र पर २२ जुलाई को ही वित्तमन्त्री श्री गी० सुब्रह्मण्यम ने एक नोट लिखकर कहा, "श्री तुनी का एक बरस के लिए सीधे अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसपर प्रधानमंत्री की अनुमति ले ली जाए। प्रधानमंत्री ने २४ जुलाई का अपनी अनुमति प्रदान कर दी और ३१ जुलाई का एक अधिमूचना के जरिये श्री तुनी की नियुक्ति भी कर दी गई। नियुक्ति के बाग औपचारिकता के नाम पर मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति-समिति का इस बारे में अवगत करा दिया गया।

श्रीमती गांधी ने सुझाव दिया था, आदेश नहीं

श्री सुब्रह्मण्यम का इस मामले में कहना था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सुझाव दिया था कोई आदेश नहीं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि श्री तुनी की नियुक्ति के बाद पत्राव नशानन बैंक द्वारा मादति निमित्त का कोई कृण दिया गया था अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक श्री गुप्ता का संबंध है रिजर्व बैंक ने कुछ साच-समझ पर ही अपनी राय बनाई होगी।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'फिर आपने रिजर्व बैंक का सुझाव क्यों नहीं माना ?

उस समय तक तो सिर्फ नाम पर ही विचार चल रहा था इस बीच प्रधानमंत्री ने श्री तुनी का नाम सुझाया और उसे मान लिया गया।'

“एक छोटे बैंक के अध्यक्ष को, जिसकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत कम थी, किस प्रकार एक बड़े बैंक के लिए उपयुक्त समझ लिया गया ?”

श्री मुन्नाहाण्यम ने इसके जवाब में कहा कि शैक्षणिक योग्यता तो केवल नौकरी पाने के समय काम में आती है बाद में उनति के लिए तो व्यक्ति का अनुभव ही काम में आता है और इसी आधार पर उन्होंने रिजर्व बैंक से श्री तुली के अनुभव के बारे में पता लगाने को कहा था। उन्होंने बताया कि नियुक्ति से पहले रिजर्व बैंक ने श्री गुप्ता के साथ साथ श्री तुली के नाम पर भी विचार किया था और हमने उसमें से श्री तुली को चुना।

(12) स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर श्री टी० आर० बरदाचारी की नियुक्ति

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री तलवार का कार्यकाल समाप्त होने में अभी लगभग ६ महीने शेष थे कि उनको हटाकर श्री टी० आर० बरदाचारी को नियुक्त कर दिया गया। श्री बरदाचारी श्री तलवार के बाद सबसे अधिक विरोध थे परंतु श्री बरदाचारी की नियुक्ति से पहले ही श्री तलवार उनके विरोध अनियमितताओं के आरोप लगा चुके थे। परंतु सरकार का कहना था जांच के बाद इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं मिली थी। स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा १६ (ए) (१) के अनुसार इस बैंक के अध्यक्ष पद पर केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक की अनुमति से ही किसीकी नियुक्ति की जा सकती है परंतु इस मामले में रिजर्व बैंक तथा मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति की भी अनुमति नहीं ली गई। बाद में श्री बरदाचारी की नियुक्ति के संबंध में जारों की गई अधिसूचना पर ही समिति के सचिव सहस्ताक्षर करार कर यह खानापूरी कर दी गई।

नियुक्ति के लिए सजय गांधी की सिफारिश

श्री बरदाचारी का अपनी नियुक्ति के संबंध में कहना था कि भूतपूर्व बंकिम तथा राजस्वमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी ने उन्हें इस

सबध मे श्री सजय गाधी से मिलने को कहा था और इस निर्देशानुसार वे उनसे मिले भी थे। इसके अतिरिक्त कई अन्य मौकों पर भी वे श्री गाधी से निर्देश लेने गए थे।

श्री मुखर्जी ने श्री वरदाचारी के इस बयान को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने श्री वरदाचारी से बभी भी श्री गाधी से मिलने को नहीं कहा था।

उन्होंने श्री वरदाचारी की नियुक्ति का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि श्री तलवार के बाद श्री वरदाचारी ही सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय श्री तलवार और श्री वरदाचारी में काफी खींचतान चल रही थी और इससे बक का वातावरण भी खराब हो रहा था। श्री मुखर्जी का कहना था कि उन्होंने इस सबध में रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी बात की थी परन्तु वह मौखिक ही थी इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसके रिकार्ड रक्षे गए हैं या नहीं।

मन्त्रालय में तत्कालीन सचिव श्री एन० पी० सेन का इस सबध में कहना था कि श्री तलवार के स्थान पर श्री वरदाचारी की नियुक्ति के बारे में उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से बैंक के गवर्नर से बात की थी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया था। उन्होंने इस बात से पूर्व भी गवर्नर से इस सबध में चर्चा की थी।

श्री सेन ने बताया कि उनके विचार से तो श्री वरदाचारी और श्री तलवार दोनों को ही हटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इनके बीच भयंकर रूप से वापसी प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, परन्तु वे क्या कर सकते थे, सचिव का काम तो अपने उच्चाधिकारी के आदेशों को पूरा करना होता है और इस मामले में उन्होंने मंत्री के निर्देशों का पालन कर अपना काम पूरा किया था।"

**(१) भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं
प्रबध निदेशक के पद पर ले० जनरल
जे० पी० सतारावाला की नियुक्ति**

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबध निदेशक
२४३

पद पर नियुक्ति के लिए सावजनिक उद्योग चयन बोर्ड द्वारा श्री अजीतसिंह तथा श्री बी० एस० दास के नामों की सिफारिश किए जाने के बावजूद पयटन एव नागरिक उद्बोधनमंत्री श्री राजवहादुर के निर्देश पर ले० जनरल जे० पी० सतारावाला की नियुक्ति कर दी गई।

इस नियुक्ति के संबंध में श्री राजवहादुर ने अपनी पूरी जिम्मेदारी लते हुए कहा कि उनके अधीनस्थ मंत्री न जनरल सतारावाला का नाम सुझाया था, जिस उन्होंने उपयुक्त समझते हुए स्वीकार कर लिया।

उनका कहना था कि जनरल सतारावाला अपनी पत्नी उषा के बावजूद काफी अनुभवी थे। उन्होंने अशोक होटल के प्रबंधक के रूप में बहुत ही अच्छा काम किया था और उनके प्रयत्ना से ही होटल को १९७३-७४ में ६३ लाख का लाभ हुआ था।

श्री राजवहादुर ने बताया कि उन्होंने श्री अजीतसिंह और श्री दास के स्थान पर जनरल सतारावाला के नाम के लिए प्रधानमंत्री को कहा था क्योंकि उनको नजर में वही सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार थे। प्रारम्भ में काम देखने के लिए उन्होंने जनरल सतारावाला को सिर्फ एक वर्ष के लिए ही नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था। इन सब बातों के अतिरिक्त जनरल सतारावाला न दो महीने के तन्त्र अध्यक्ष के रूप में निगम के काम को अच्छी तरह सभाला था जबकि दूसरी ओर श्री दाम जी श्री सिंह को इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था।

(VI) भारत के अन्तराष्ट्रीय हवाई पत्तन में प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर एयर मार्शल एच० सी० दीवान की नियुक्ति

एयर मार्शल वाई० बी० मात्से का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए सावजनिक उद्योग चयन बोर्ड द्वारा एयर मार्शल एच० सी० दीवान तथा श्री बी० एस० दास सहित कुछ व्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया और उसमें

श्री दास को उपयुक्त ठहराते हुए उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई।

चयन बोर्ड की सिफारिश के बावजूद मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति ने श्री दास के नाम को नहीं माना और श्री दीवान के नाम पर स्वीकृति दी। समिति का यह निर्णय मतानय और पयटन एवं नागरिक उद्वेगन सचिव के लिए आश्चर्यजनक था।

श्री राजबहादुर ने आयोग को बताया कि चयन-बोर्ड द्वारा दीवान के अतिरिक्त श्री दास श्री ए० के० मरकार और श्री मुलगाव कर के नामों पर भी विचार किया था परन्तु बाद में श्री दास में मुकाबले सभीको अनुपयुक्त ठहराया गया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि श्री दीवान ही इन लोगों में सर्वाधिक उपयुक्त नहीं थे।

श्री राजबहादुर ने यह भी स्वीकार किया कि चयन-बोर्ड द्वारा सुझाए गए नामों को ताल पर रखकर दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति वास्तव में एक अच्छी परिपाटी नहीं कही जा सकती।

(VII) दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर श्री यू० एस० श्रीवास्तव की नियुक्ति

दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर जून, १९७६ में श्री ए० एन० चावला काय कर रहे थे परन्तु उनके द्वारा पूरा समय न दे पाने के कारण दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल श्री कृष्णचंद ने श्री यू० एस० श्रीवास्तव जैसे जूनियर अधिकारी को अध्यक्ष बनाने के संवध में प्रधानमंत्री से सिफारिश की, जिसपर उन्होंने अपनी सहमति दे दी।

उप-राज्यपाल द्वारा अधिकार-क्षेत्र के बाहर काय

उप राज्यपाल द्वारा यह काय अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर किया गया था क्योंकि इसपर केन्द्रीय परिवहनमंत्री की सिफारिश आवश्यक थी, परन्तु परिवहनमंत्री उन बिना दिल्ली से बाहर थे और उनके आन का इतनाार किए बिना ही यह काय पूरा कर लिया गया।

उप राज्यपाल ने जब यह प्रस्ताव तत्कालीन गृहमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेडडी के पास भेजा तो उन्होंने इसपर कोई आपत्ति तो नहीं की, परन्तु इसपर यह लिखा कि 'श्री श्रीवास्तव सिर्फ निदेशक स्तर के ही अधिकारी हैं। परन्तु जब उप राज्यपाल न सिफारिश कर ही दी है, तब चाह जैसा भी स्तर हो क्या अन्तर पड़ता है फिर भी प्रधानमंत्री जैसा चाह, निश्चय से।'

तत्कालीन परिवहनमंत्री श्री जी० एस० डिल्लो जब दिल्ली वापस आता उन्हे ये बातें आश्चर्य में तो डालती ही। वे इसपर नाराज भी बहुत हुए और उन्होंने इस प्रकार के कार्य के विरोध में प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा परन्तु प्रधानमंत्री ने इस सार काय से अपनी अनभिन्नता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने अनभिन्नता प्रकट करने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक पत्र लिखकर सूचित किया कि 'श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए।'

श्री डिल्लो का कहना था कि श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री ने उनसे तो अपनी अनभिन्नता व्यक्त की थी और उसके कुछ दिनों बाद ही अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए थे सब बातें उनके लिए आश्चर्यजनक थी। परन्तु उन्होंने न चाहते हुए भी प्रधानमंत्री के निर्देशों की अवमानना करना उचित नहीं समझा और अधिसूचना जारी कराई।

श्री कृष्णचंद ने इस सम्बन्ध में अपनी मर्माई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री निवास में एक बार श्रीमती गांधी न जिक्र किया था कि श्री चावला अब आगे कार्य नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाता है। इसपर उन्होंने श्रीमती गांधी से श्री श्रीवास्तव के बारे में बात की जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

उन्होंने सेद प्रकट किया कि उनके इस कार्य से श्री डिल्लो ने अपना अपमान महसूस किया। श्री कृष्णचंद ने स्वीकार किया कि इस मामले में जल्दयाज्ञा की गई और श्री श्रीवास्तव की वरिष्ठता के बारे में नहीं सोचा गया।

(VIII) दिल्ली और बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावनति और पुनर्नियुक्ति

एमरजेन्सी के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश की मिसरिंग के बावजूद बम्बई उच्च न्यायालय के अनिरीक्त न्यायाधीश श्री यू० आर० ललित तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के अनिरीक्त न्यायाधीश श्री आर० एन० अग्रवाल को बचाव की आग पुष्टि नहीं की गई। श्री अग्रवाल का तो बापस भत्र तथा जिला न्यायाधीश के पद पर भेज दिया गया। बाद में बताया गया कि श्री अग्रवाल की पदावनति के पीछे राजनीतिक बदल की भावना थी क्योंकि वे भीमा के मामले सुनने में संबंधित बच में थे और उन्होंने एक मामले में वेद सरकार के विरुद्ध निषेध दिया था।

भूतपूर्व विधिमंत्री स्वर्गीय एच० आर० गोयल का कहना था कि न्यायाधीश श्री ललित में सख्खिन फाइल बाकी लम्बे समय तक प्रधानमंत्री के पास पड़ी रही। फाइल पर निम्ने नोट में पता चला कि बाबू में विभाग के सचिव का फोन पर कहा गया था कि न्यायाधीश श्री ललित की आगे पुष्टि नहीं की जाए।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सचिवालय में जब फाइल उनके पास आई तो उसमें निम्नी कुछ टिप्पणियां पायी थी बाद में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से बात की ललित उन्होंने स्पष्ट रूप में यह कहा कि वे न्यायाधीश श्री ललित की पुष्टि करने वाली नहीं हैं। न तो प्रधानमंत्री ने ही उन्हें इस बात के कारण बताया और न ही उन्हें स्वयं श्री ललित के खिलाफ कोई ऐसी बात मालूम थी जिससे अनुसार प्रधानमंत्री ने यह निषेध दिया।

न्यायाधीश श्री अग्रवाल के बारे में श्री गोयल का कहना था कि उनके बारे में मन्त्रालय के सचिव ने एक गोपनीय नोट भेजा था परन्तु वह उसमें सम्मन नहीं थे यद्यपि प्रधानमंत्री उसमें महमत जान पड़ती थी।

राज्य विभाग में तत्कालीन सचिव श्री सुंदर लाल धुराना ने जस्टिस शाह के प्रश्न के उत्तर में कहा कि न्यायाधीश अग्रवाल को हटाए जाने के संबंध में यह कहना उचित नहीं होगा कि मोमा के मामले में सरकार के विरुद्ध निषेध देने के कारण उन्हें हटाया गया

था। उनका कहना था कि श्री अग्रवाल द्वारा निणय दिए जाने से पूर्व ही सरकार ने सबधित मामल में मीसा आदश वापस ले लिए थे। इसपर जस्टिस शाह ने कहा, जब सरकार का लगन लगा कि निणय उनके विरोध में जाएगा उन्होंने मामला वापस ले लिया।'

जस्टिस शाह के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री पुराना ने कहा कि 'यायाधीश श्री अग्रवाल पर लगाए गए आरोप से सबधित फाइल की उद्धान कोई जांच नहीं की थी, क्योंकि ज्योंही यह फाइल उनके पास आई थी उन्होंने उस मंत्री के पास भेज दिया था।

जस्टिस शाह ने इसपर कहा क्या आपने 'याय मचिव के रूप में अपना विभाग इस बारे में उगाया था कि जब एक 'यायाधीश उच्च 'यायालय के लिए उपयुक्त नहीं समझा जा रहा है तो क्या वह तब और जिला 'यायालय के रूप में उपयुक्त रहेगा ?

नहीं इस सबध में विचार नहीं किया गया था।

दिल्ली उच्च 'यायालय के एक अन्य 'यायाधीश श्री एम० रंगराजन का भी जो कुरादीप नायर मामले में बच के प्रमुख थे दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया क्या यह सही है ?

'यह सही है कि उनका स्थानांतरण कर लिया गया था।'

इसपर जस्टिस शाह ने 'यग्य से कहा जहां तक कुरादीप नायर के मामले का सबध है यह तो एक दुषटना ही होनी चाहिए।'

श्री पुराना ने कहा यह तो वास्तव में एक दुषटना थी।

उनका कहना था कि 'यायाधीशों के स्थानांतरण के सबध में मुख्य 'यायाधीश तथा विधिमन्त्री में विचार विमर्श के बाद ही निणय लिया जाता है। यह काम निचले स्तर पर नहीं होता।

१० ऋण जो चुकाए नहीं गए

प्रधानमंत्री के निर्देश पर किसी बक के अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना तो स्वाभाविक है। सक्ता है परंतु उसके लिए कुछ फर्मों को बिना किसी गारंटी के ऋण देना अनियमित तो है ही निश्चित रूप से बक को साखा रूपय की हानि की आशंका भी है।

श्री टी० आर० तुली ने इसी तरह पंजाब नेशनल बक का

अध्यक्ष बनाए जान के कुछ दिना बाद ही एसोसिएटेड जनल्स तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेन्ता के एक सवधी की फर्म ब्रम्मा कमिक्स तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री के पुत्र श्री मजय गांधी की फर्म मासुति लिमिटेड को बिना किसी उचित गारंटी के ऋण उपलब्ध कराए या उनके भुगतान मरियायत निकाई । दिलाए गए अधिकांश का बाद में भुगतान भी नहीं किया गया ।

(1) एसोसिएटेड जनल्स

एसोसिएटेड जनल्स लिमिटेड न जा लखनऊ और दिल्ली में अंग्रेजी दैनिक नेशनल हर्षल्ड, हिन्दी दैनिक 'नवजीवन' और उर्दू दैनिक 'कौमी आवाज' प्रकाशित करता है विजय बक की गारंटी पर छपाई की मशीन आयात की थी । उस वक़्त और विलम्ब शुल्क के रूप में दस लाख रुपये में अधिक का भुगतान करना था । मार्च, १९७६ में तत्कालीन केन्द्रीय उवरक और रसायनमंत्री श्री प्रकाशचंद सेठी ने श्री तुली से इस सवधि में कम्पनी की सहायता करने का आग्रह किया । श्री तुली ने बक की पालियामेंट स्ट्रीट स्थित शाखा के मनेजर श्री एल० डी० अथलखा से प्राथमिकता के आधार पर इस काय को निपटाने को कहा ।

कम्पनी के इस ऋण के लिए दिल्ली स्थित अपन भवन हर्षल्ड हाउस का गिरवी रखने का प्रस्ताव किया । बक ने ऋण के रूप में कम्पनी को ₹ २६५०० रुपये की राशि का एक डाफ्ट दिया और शेष ₹ ७०,५०० रुपये की राशि की कम्पनी ने स्वयं व्यवस्था की ।

श्री अघनखा के अनुसार जो आजकल छ बक के क्षेत्रीय मनेजर हैं श्री तुली ने मार्च १९७६ में एसोसिएटेड जनल्स के प्रबंध निदेशक बनल दशरथ हुसेन जदी से उनका परिचय कराते हुए कहा था, 'कम्पनी को १५ लाख रुपये के ऋण की आवश्यकता है और उनकी एवज में वह अपने दिल्ली स्थित हर्षल्ड-हाउस को गिरवी रखने को तयार है और जब तक गिरवी रखने की कायवाही पूरी नहीं हो जाती सिंडिकेट बैंक उसका निए गारंटी देन का तयार है । इसके अतिरिक्त सिंडिकेट बैंक से भी इसी शत पर १५ लाख रुपये ऋण लेने की बात चल रही है । श्री तुली ने उनसे कहा कि चूंकि इन्हें कुछ भुगतान तुरत करने हैं इसलिए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऋण दे दिया जाए ।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद ऋण

बैंक के केंद्रीय जाच विभाग द्वारा बाद में की गई जाच से पता चला कि कम्पनी की स्थिति गिरनुल खराब है तथा उस पिछले दो वर्ष में कुल १६ लाख १६ हजार रुपये का नुकसान हो चुका है।

बाद में जान हुआ कि मिडिवेट बैंक ने हंगल हाउस की गिरवी रखकर १५ लाख रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है परन्तु श्रीमती गांधी के विशेष दूत श्री मुहम्मद युनुस द्वारा, जो बाद में इस कम्पनी के प्रबंध निदेशक बनाए गए थे, मिडिवेट बैंक को भेज एक दलबल सदेश में इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने पर बैंक ने इस स्वीकार कर लिया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि फर्म को ऋण दत्त समय में तो उसकी बलव शक्ति दग्री गई और न ही उसके ऋणदाताओं की सूची ही। इससे अतिरिक्त कम्पनी द्वारा अभी तक बैंक के ऋण के भुगतान के रूप में उसका पूरा व्याज भी नहीं चुकाया गया है।

दो महीने का काम दो दिन में

श्री अद्यतना का कहना था कि बैंक मैनेजर के रूप में उन्हें दस हजार रुपये में अधिक का ऋण देने की अनुमति नहीं थी। साधारणतया किसी भी प्रकार का ऋण देने से पहले ऋण लेने वाले की आर्थिक क्षमता आदि की जाच की जाती है परन्तु इस मामले में श्री तुली के आन्तर् मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने ३४ वर्ष के बैंक अनुभव में कभी भी ऐसा कोई मामला नहीं देखा था जिसमें बिना कम्पनी की स्थिति देखे और जाच कर बिना किसी जमानत के इतना अधिक ऋण दिया गया हो। उन्होंने बताया कि यह कमीशन आकर ड्राफ्ट दो ही दिन में दे भी दिया गया जबकि साधारणतया ऐसे काम में एक या दो महीने तक का समय लग सकता था।

जस्टिस ग्राह के प्रश्नों के उत्तर में श्री अद्यतना ने बताया कि पार्टी को ऋण देने संबंधी औपचारिकताएं बाद में बैंक के ऋण विभाग ने पूरी कर ली थी हालांकि पार्टी द्वारा इसके बदले 'हेराल्ड हाउस' गिरवी रखने में आना-जानी की जाती रही, जबकि उसको ऋण इसी शर्त पर दिया गया था। यद्यपि बाद में बैंक के प्रबंध मंडल ने

इस ऋण की स्वीकृति दे दी थी।

अधलखा भी मजबूती की सिफारिश परक्षे गीय मैनेजर ने

श्री तुली के वकील श्री डी० एम० डाग ने आयाग के समक्ष एक पत्र पढ़कर सुनाया जो आयोगवा एक व्यक्ति ने एमरजेसी के दौरान हुई ज्यादातियों के संबंध में लिखा था। पत्र में कहा गया था कि श्री मजबूती गांधी की सिफारिश पर ही श्री अधलखा का महा-राष्ट्र का क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया गया था। श्री डाग यह पत्र दिखाकर सिद्ध करना चाहते थे कि चूंकि श्री अधलखा स्वयं श्री गांधी के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने उनका परिचिता से संबंधित कम्पनी को ऋण देने में जल्दी दिखाई। परंतु श्री अधलखा ने इस बात से इंकार किया कि वे कभी भी श्री गांधी से मिले थे।

श्री अधलखा ने यह जरूर स्वीकार किया कि वे एक बार प्रधान मंत्री निवास अवश्य गए थे जहां उन्होंने श्री धवन से मुलाकात की थी परंतु वे कहा श्री मजबूती गांधी से भेंट के मिलमिले में नहीं, बल्कि श्री राजीव गांधी का बंब में छाता खाने जान के मध्य में कुछ कागजात देने गए थे। इसपर श्री डाग ने कहा 'यह काम तो एक क्षणभी भी कर सकता था। आप जस वरिष्ठ अधिकारी को इतने-से काम के लिए कहा जान की क्या आवश्यकता थी?'

"मैंने श्री तुली ने निर्देश लिए थे कि श्री राजीव को वधत छाता के बारे में कुछ जानकारी देनी है।

श्री तुली ने जिरह के दौरान स्वाभार किया कि कम्पनी का जल्दी से जल्दी ऋण देने के पीछे एक कारण यह भी था क्योंकि यह प्रतिष्ठित लागा की मर्यादा थी तथा इसमें कई अवलगावा भी शामिल थे।

श्री तुली ने कहा कि बहुत से संबंधित कागजात के बारे में पुष्टि करने की जिम्मेदारी श्री अधलखा पर थी क्योंकि वे ही प्राच मनजर थे। अब वे अधलखा के मान यह काम उनका नहीं था कि वे पार्टी की बैठकें और बैठकों की सूची देखते। उनका कहना था कि श्री अधलखा द्वारा महमनि देने पर उन्होंने यह समझा था कि उन्होंने संबंधित कागजात देकर अपनी पुष्टि कर ली होगी। था अधलखा से उनका जो भी विचार विमर्श हुआ वह निश्चित ही हुआ था,

उहाने लिखित में कोई आदेश नहीं दिए थे ।

उहान बताया कि कज की स्वीकृति देते समय उनके दिमाग में यही बात थी कि हाराल्ड हाउस की कीमत कम से कम साठ सत्तर लाख रुपये तो होगी ही और उसको गिरवी रखकर आठ-नौ लाख रुपये का कज देना कोई विशेष बात नहीं थी । चूकि कम्पनी को धन की तुरन्त आवश्यकता थी और वे मिडिवेक बैंक से भी ऋण ले रहे थे इसलिए हमने उन्हें एक तरीके से ब्रिजिंग ऋण दिया था । इसपर जस्टिस शाह ने मुस्कराते हुए कहा 'और वह ब्रिज (पुल) कभी नहीं बना ।' इसपर आयोग का कस हसी के ठट्ठाका से गुंज उठा ।

श्री तुली ने आयोग का बताया कि चूकि श्री सेठी ने उहे यह ऋण मजूर करने को कहा था उन्होंने इसीलिए ऐसा किया आखिर श्री सेठी एक मंत्री थे ।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'यदि कम्पनी इस ऋण का भुगतान नहीं करगी तो क्या मंत्री (श्री सेठी) इसका भुगतान करेंगे ?'

'नहीं ।'

तो क्या आपने फिर इस ऋण की इसलिये स्वीकृति दी कि प्रधानमंत्री ने आपको नियुक्त कराया था ? आपने यह काय किसी न किसी रूप में उनको खुश करने के लिए किया होगा । श्री तुली ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया ।

आपमें ही ऐसी क्या बात थी कि आपको ही पंजाब नेशनल बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ?

इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ ।

क्या आपको अपनी नियुक्ति के बारे में सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ ?'

उस समय मैं बाहर था और मुझे यह सुनकर घाबरे बहुत आश्चर्य हुआ था ।

जांच की जिम्मेदारी अघलखा पर

श्री तुली ने जिरह के दौरान आयोग के वकील श्री खडाला-वाला द्वारा यह पूछे जाने पर कि गिरवी रखे जाने का दस्तावेज आखिर पूरा क्या नहीं किया गया कहा कि गिरवी रखे जाने का यह करार न किया जाना एक गम्भीर खामी थी लेकिन इसकी जिम्मेदारी उस समय के जांच मनेजर श्री अघलखा पर थी उनपर नहीं ।

श्री तुनी बार-बार पूछे जाने व बाद भी यही कहत रहे कि उहनि ऋण दन व बारे म था अधलखा का कभी आदेश नही दिए । उन्हाने श्री अधनखा को मनल जदी से मिला दिया था और कहा था कि उनकी सहायता करें ।

दम नाख के ऋण मे से दस हजार का भुगतान

उहास बताया कि कम्पनी न अभी तक इस ऋण के भुगतान क रूप म सिर्फ दस हजार रुपये चुकाए हैं जा व्याज भी पूर नही पडते ।

तत्कालीन रसायन एव उबरक मंत्री श्री सटी ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उहाने श्री तुनी का फोन कर बुलाया था तथा उनम एमोमिएटेड जनल्स की सहायता करने को कहा था । उहाने बताया कि कम्पनी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक कनल जनीन उनम कहा था कि उनकी मशीनों बदरगाह पर पड़ी हैं और व श्री तुनी म यह धाम जल्दी स निपटान को कह दें ।

श्री सटी ने कहना था कि यह अनुरोध करने के पीछे उनके मन म सिर्फ यही बात थी कि इस पत्र को पन्ति नहू न स्थापित किया था इमलिए सबट व समय इसकी सहायता की जानी चाहिए । उहाने श्री तुनी म कहा था कि व दस मामले को दक की गतों तथा नियमा व अंतगत निपट दें व आभारी रह्य । उनका इस मामले म कोई व्यक्तिगत हित नही था ।

उनका कहना था कि उहाने श्री तुनी म मामले को जल्दी से निपटान का कहा था न कि ऋण मद्धर करने का ब्यापि दस मामले म पहल म ही वैक व माय बातचीत हो रही बताई गई थी ।

उहाने स्वीकार किया कि उहाने यह अनुरोध करने म पूर कम्पनी की विनीय स्थिति तथा उसकी सम्पत्ति आदि के बारे म जाच नह की थी । उनका निमाण म यही बात थी कि कम्पनी क पाम स्थिती और लगनऊ दोना ही जगह अपने भवन हैं ।

राजनीतिक दबाव मे ऋण

आयाज व वकील श्री गृहानावाना न जिरह व बात कहा कि कम्पनी क ऋण दन के लिए राजनीतिक दबाव का उपयोग किया गया । उनका कहना था कि इस मामले म श्री तुनी भी बराबर के

जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके निर्देशानुसार ही ऐसा किया गया था, जबकि श्री तुली व वकील श्री डांग का कहना था कि इसका जिम्मेदारी थी तुली के अधीनस्थ अधिकारियों की है। श्री तुली न तो सामान्य प्रक्रिया का पालन किया था इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते।

(11) फ़रमा केमिकल्स

२३ अक्टूबर १९७५ को फरीदाबाद की एच फ़र्म फ़रमा केमिकल्स प्रा० लिमिटेड का कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया। इस फ़र्म की प्रारंभिक पूंजी भिफ़ धार साध रुपये थी तथा इसने एक निदेशक तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री ओम मेहता के भाई श्री सत मेहता थे।

कुछ ही दिनों बाद फ़र्म गम्भीर आर्थिक संकट से गुजरने लगी और उसका सामान सहायता के लिए बच के पास जान के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इसी संकट के दौरान इस फ़र्म के एक निदेशक श्री एस० पी० मेहता (जो श्री सत मेहता के ससुर भी थे) बैंकिंग और राजस्वमंत्री के निजी सहायक श्री कुमार के साथ बच व अग्रस्त श्री टी० आर० तुली के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने फ़र्म का ६ लाख ३० हजार रुपये के तीन ऋण पत्र ज़माने का अनुरोध किया ताकि फ़र्म इस संकट की घड़ी से उबर सकें।

श्री तुली द्वारा फ़र्म की आर्थिक स्थिति देख बिना ही यह स्वीकृति भी दे दी गई जिससे बच को बाद में ४५० लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

उसके दिल्ली दफ़्तर के मनजर श्री डी० पी० नायर ने बताया कि श्री तुली ने उन्हें बुलाकर श्री मेहता की ओर इशारा करते हुए कहा था कि आप उनका पैसा दें और बिना बच मार्जिन के ऋण पत्र जारी करा दीजिए। इनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

बच की पालियामेंट शाखा के मनजर श्री के० एन० वाली का कहना था कि इस फ़र्म का मूल आवेदन श्री तुली ने स्वयं ही प्राप्त किया था और फिर उसने वाच कार्यालय में भेज दिया था। बूझ ही तुली ने स्वयं ही इस फ़र्म का परिचय दिया था, इसलिए उसकी ऋण देने संबंधी आर्थिक क्षमता की जांच नहीं की गई।

एक महीने का काम एक दिन में

बक की विदेशी मुद्रा शाखा के मनेजर श्री एस० एस० जौली ने बताया कि इन ऋणपत्रों को सिर्फ एक दिन में जारी कर दिया गया था जबकि सामान्यतया ऐसे काम में लगभग एक महीने का समय लग जाता है।

श्री तुली ने जिरह के दौरान इस सबध में अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह एक सामान्य मामला था और इसे सिर्फ शीघ्रता से निपटाया गया था। उन्होंने कहा 'यह सही है कि मैंने कभी इस पत्र की अथवा इसके निदेशकों की आर्थिक क्षमता के बारे में कोई जांच नहीं कराई थी परन्तु चूंकि यह मामला स्वयं श्री कुमार द्वारा लाया गया था इसलिए मैंने यह किया।

परन्तु श्री कुमार ने इस बात से साफ इकार किया कि उन्होंने कभी बैंक के अध्यक्ष श्री तुली से श्री एस० पी० मेहता का परिचय कराया था अथवा उनके कार्यालय गए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने श्री तुली को श्री मेहता के सबध में फोन जरूर किया था, परन्तु क्या लेन देन हुआ इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

श्री तुली ने बाद में बताया कि ऋण पत्रों के सबध में किसी प्रकार की जमानत लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि माल अपने-आपमें एक जमानत हाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के ७० से ७५ मामले में बिना बैंक मार्जिन लिए ही काम होता है, इसलिए इस विशेष मामले में कोई अति विशिष्टता वाली बात नहीं थी।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'चूंकि श्री मेहता श्री मुखर्जी के निजी सहायक श्री कुमार के साथ आए थे इसलिए आपने सामान्य प्रक्रिया में अपनात हुए इसे जल्दी करा दिया?'

मैं यह नहीं कह सकता कि वह किसी मंत्री की सिफारिश लेकर आए थे। हा श्री कुमार ने उनसे परिचय जरूर कराया था।

'आपने उसके अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं किया जसा श्री कुमार ने कहा था ?

वह एक सामान्य लेन देन था।

मंत्री के निजी सहायक आपके पास इस प्रकार की सिफारिशें लेकर और कितनी बार आ चुके थे ?'

मैं जब तक पंजाब नेशनल बैंक में रहा—दो, तीन या फिर

चार बार आए हाने । कभी किसीको नौकरी ढिनाने के सबध म और कभी किसीका स्थानांतरित कराने के लिए ।'

क्या बर्किंग लेन देन क सबध म व सिर्फ इसी मामल म आए थे ?'

मुझे कुछ याद नहीं ।'

क्या आप समझत है कि यह एक बुद्धिमत्तापूण लेन-देन था ?'

जी हा । इस लेन देन म कोई गलत बात नहीं थी ।

राजनीतिक दबाव का उदाहरण

बाद मे इस मामले पर हुई जिरह के बाद आयाग के वकील श्री खड्गालावाला और सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लखी न कहा कि यह मामला भी राजनीतिक दबाव का एन उदाहरण है ।

(III) मादति लिमिटेड

श्री सजय गाधी की छोटी कार बनान कीतयारी म नगी कम मार्गति लि० को मई १९७४ म पजाब नेशनल बैंक की ओर स ३० लाख और ५० लाख रुपय की दो ऋण सुविधाए मिली हुई थी परंतु इसम शतयही थी कि इन दोनों मामला म यह ऋण सुविधा एक समय मे कुल ७५ लाख रुपय म अधिक नहा होगी । इसके बावजूद माघ १९७५ म यह राशि बन्द कर ६० लाख तक पहुच गई थी ।

श्री तुली द्वारा अगस्त १९७५ म बक के अध्यक्ष पद का काम सभालते समय मार्गति का यह ऋण-आता बहुत ही अनियमित चल रहा था । इसनिए बक ने मार्गति म पनल स्थान लेना शुरू कर निया । इसपर मार्गति ने बक को लिखा कि इस समय उनकी कम्पनी घाटे म चल रही है इसलिए जितना सम्भव हो इस पनल ँयाज को कम कर निया जाए । इसके अतिरिक्त उहने खान को नियमित करने के लिए एकमुस्त राशि के रूप म पाच लाख रुपये का भुगतान निया और इसके अतिरिक्त एक लाख रुपया महीना देते रहने का वादा भी निया ।

श्री तुली की अध्यक्षता म हुई बक के निष्पक्ष मन्त्र की बैठक म महापत्र जनरल मनजर (उधार) की सिफारिश पर ँयाज की राशि म ७० २४७ रुपय ६५ पस की कटौती कर दी गई तथा

ब्याज का भी डेढ़ प्रतिशत घटा दिया गया ।

श्री तुली न बाद में आयोग को जिरह के दौरान बताया कि एमरजेन्सी के १५ महीने के दौरान व २१ बार १ सफ़रजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री निवास गए थे । इसमें स व नौ बार श्री सजय गांधी स मिने और १० बार श्रीमती गांधी के अतिरिक्त सचिव श्री आर० के० धवन स बैंक द्वारा दिए गए ऋण को वसूल करने के संबंध में उहाने कहा 'श्रीमान भारति के मालिकों जसी ऊंची प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों स धन वसूल करना आसान नहीं था ।' उहाने कहा 'श्रीमान् भारति के व्यक्तियों के स्तर को देखते हुए उसकी सम्पत्ति को कुर् करके बैंक के ऋण की वसूली करना बड़ा मुश्किल काम था ।'

उहाने बताया कि भारति का एक बीमार खाता था । उहाने पार्टी के साथ यह समझौता इसलिए किया था ताकि दिए गए ऋण का कम से कम कुछ भाग तो वसूल हो और इसी सिलसिले में वे श्री गांधी से कई बार मिल थे ।

इसपर जस्टिस शाह न पूछा क्या भारति सयंत्र की मशीनों का कुर् नहीं किया जा सकता था ? क्या वे बहुमूल्य नहीं थी ?

श्री तुनी ने इसके जवाब में कहा, 'हा कम से कम कागजों पर तो थी ही ।

श्री तुनी न स्वीकार किया कि बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए वे श्रीमती गांधी को धन्यवाद देने उनके घर पर गए थे ।

इसपर जस्टिस शाह ने कहा, क्या इसीलिए कि आपकी नियुक्ति आपके स्तर के हिसाब से ऊंची थी ?

श्रीमान वह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी । मैं श्री सुब्रह्मण्यम को भी धन्यवाद देने गया था ।'

श्री तुली ने बताया कि बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के कुछ दिन बाद से ही वे श्री आर० के० धवन को जानने लगे थे । वे अपनी नियुक्ति के कुछ दिन बाद ही श्री धवन से मिलने गए थे, क्योंकि उहाने उन्हें बुलाया था । उनका कहना था कि उनकी नियुक्ति के कुछ दिन बाद के २० अगस्त १९७५ का श्रीमती गांधी से मिलने गए थे ।

श्री तुनी जस्टिस शाह के प्रश्न स कुछ परेशान महो गए थे,
२५६

और उन्होंने सवालो का जलटा-सीधा जवाब दिया। जब जस्टिस शाह न उनसे पूछा 'क्या वे वहाँ श्री सजय गांधी से भी मिले थे ?' उन्होंने जवाब दिया, 'हाँ मैं प्रधानमंत्री से भी मिला था।'

जिरह के बाद आयोग के वकील श्री काल खड्गालावाला और सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लेखी ने सिद्ध करना चाहा कि श्री तुली ने मारुति को दिए गए ऋण पर पनल्टी व्याज में इसलिए छूट दी क्योंकि उनसे ऐसा करने को कहा गया था। इसपर जस्टिस शाह ने कहा कि यह ऋण श्री तुली की नियुक्ति से पूर्व ही दे दिया गया था तथा एक बरकर के नात उन्होंने इसकी बमूली के लिए एक तरीका यह भी अपनाया था कि 'इस प्रकार से छूट देकर जितना ऋण वापस लिया जा सके ले लिया जाए' इसलिए इस मामले में हम देखना होगा कि ज्यादाती कहा हुई है। परन्तु दाना वकीला का मानना था कि श्रीमती गांधी द्वारा नियुक्त कराए जाने के कारण ही श्री तुली ने यह नरमी दिखाई थी परन्तु जस्टिस शाह इस विचार से सहमत नहीं जान पड़े।

११ गैर-सरकारी हैसियत

यह सही है देश का प्रधानमंत्री का काफी अधिकार होना है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनके परिवारजना और परिचितों को भी बिना किसी सरकारी हैसियत के ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जिनके अन्तर्गत वे सरकारी बठका में भाग ले सकें या अपन प्रभाव का उपयोग कर निजी काम करा सकें।

एमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के दोना पुत्र श्री राजीव और श्री सजय गांधी तथा उनके निवटस्थ स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा जिस प्रकार से गैर-सरकारी हैसियत का उपयोग किया गया वह अपन-आपम एक उदाहरण है।

(१) सजय की आगरा-यात्रा

एमरजेंसी के दौरान न सिर्फ छोटे-बड़े सरकारी अधिकारियों में बल्कि राज्या के मुख्यमंत्रियों में भी श्री सजय गांधी का प्रसन करने की हाड-सी सगी हुई थी। उनकी इस गैर-सरकारी हैसियत

के बावजूद उनसे निर्देशों के प्रति सहमति न रखने वाले अधिकारियों का हटाया जा रहा था या फिर स्थानांतरित किया जा रहा था। इसी सप्ताह में एक छोटी-सी घटना है उनकी आगरा-यात्रा की, जब उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने सभी बापद-बानूना को ताल पर रखकर उनकी यात्रा-दारी में अपने को बिछा दिया था।

जिस्मा २ मई १९७६ का है जब श्री गांधी श्री तिवारी के साथ आगरा गए। उन्होंने दिल्ली से आगरा तक की यात्रा कार से की। उनके साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार के कुछ अधिकारी भी थे। भारत सरकार में अतिरिक्त पयटन महानिदेशक श्री बी० एस० गिडवान्नी को, जो होनोलूलू में 'पाटा' के एक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे २ मई को आगरा पहुँचने के निर्देश दिए गए थे।

श्री गांधी आगरा जाते समय बीच रास्ते में कौमी स्थित भारतीय पयटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्तरा पर रुके। यह रेस्तरा बहुत धाटे में चल रहा था तथा इसे लाभ में चलाने के लिए कई योजनाएँ विचाराधीन थीं। इन योजनाओं में से एक यह भी थी कि राज्य सरकार या तो स्वयं रेस्तरा से आगरा-दिल्ली सड़क के बीच की भूमि की दृष्यावली को सुंदर बनाए या फिर यह भूमि निगम को दे दे ताकि वह यह काम कर सके। यह मामला कई महीने से यूँही पड़ा था। २ मई की इस विशेष यात्रा के दौरान पयटन विभाग द्वारा यहाँ एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता की रिपोर्ट में पता चलता है कि श्री सत्य गांधी ने सहमति प्रदान की तथा मुख्यमंत्री ने आदेश प्रदान किए कि इस क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए बोसी रेस्तरा के आसपास की भूमि का पयटन विकास निगम को दे दिया जाए। वास्तव में मुख्यमंत्री ने वहाँ उपस्थित पयटन निगम के अधिकारियों से कहा कि आप यह समझिए कि यह भूमि आज ही स आपकी है।

निगम की उप महानिदेशक श्रीमती विभा पाणी के अनुसार पयटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री को इसकी जानकारी दे दी गई तथा उन्होंने स्वयं इस योजना में अपनी विशेष रुचि दिखाते हुए इस कार्य पर काम चालू कराने के मौखिक आदेश दे दिए

जबकि अभी औपचारिकताएं भी पूरी नहीं हो पाई थी। बाद में १९७७-७८ के वार्षिक पयटन योजना में काफी विचार विमर्श के बाद भी योजना सचिव इस योजना पर सहमत नहीं हो सके। परन्तु इस बीच इस योजना पर निर्देशानुसार काम प्रारम्भ भी हो चुका था इसलिए बाद में मन्त्रीजी को स्वयं इसकी स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी।

जब तिवारी सजय की कुर्सी के चक्कर लगाते रहे

आगरा पहुंचने के बाद वहां के सैक्रेट हाउस में केन्द्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में आगरा में पयटन की सुविधा के बारे में विचार विमर्श हुआ। बैठक प्रारम्भ होने ही थी गांधी कमरे में आए तथा मुख्य कुर्सी पर बैठ गए और श्री तिवारी उनके चारों ओर घूमकर लगाते रहे। वास्तव में श्री गांधी द्वारा ही बैठक संचालित की गई जबकि श्री तिवारी अधिकारियों का बुझाने तथा निर्देश देते हुए उनकी सहायता करते रहे। इस पूरी बैठक की कामवाही राज्य सरकार के सचिव द्वारा रिवाइज की गई। बैठक की कामवाही के अनुसार श्री सजय गांधी ने भी बैठक में हुए विचार विमर्श में भाग लिया तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उचित निणय तक पहुंचने में अपने सुझाव दिए।

इस बैठक में जिन योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया, उनमें से एक थी मधुरा रोड पर टामपोट नगर बसाने की। इस योजना के अंतर्गत यमुना किनारे पर बसे ट्रंक ऑपरेटरों का इस नये स्थान पर बसाना था। श्री गांधी ने बैठक में कहा कि यह योजना ३० जून १९७६ तक समाप्त हो जानी चाहिए। इसपर आगरा विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता श्री एस० एन० पी० अग्रवाल ने बताया कि मधुरा रोड वाले प्रस्तावित स्थान पर जगह जगह गहरे गड्ढे हैं तथा पूरी चेष्टा के बावजूद इस योजना को ३० जून तक समाप्त करना संभव नहीं हो पाएगा।

यदि काम नहीं कर सके तो हटा दो

श्री गांधी ने इस बात को पसंद नहीं किया और श्री तिवारी से कहा कि यह इंगीनियर यह काम नहीं कर सकता है तो इस

दूमर स्थान पर भेज दो।' वाद म श्री गाधी ने घोषणा भी कर दी कि यह योजना ३० जून तक पूरा हो जाएगी और श्री तिवारी एक जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। इस योजना का पूरा करने के लिए भारतीय चलसना की जमीन साफ करने की भारी मशीना का भी उपयोग किया गया तथा एक ले० बनल को इस पूरे काय का इंचाज बनाया गया, ताकि काम ३० जून तक पूरा हो सके।

श्री गाधी द्वारा इस बठक म एक नही कई निणय लिए गए। उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि छावनी क्षेत्र म गाच स्टार होटलो के लिए जगह तलाश की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गाधी रोड बहुत ऊटपटाग बनी हुई है उसे सुधारा जाए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि आगरा विकास निगम द्वारा सभी प्रमुख स्मारका पर दो रुपये का प्रवेश शुल्क लगा देना चाहिए।

राजनीति के आकाश मे नये सितारे का उदय

बठक के बाद शाम को सात बजे एक सावजनिक सभा हुई, जिसमे मुख्यमन्त्री तथा श्री गाधी ने भाषण दिए। मुख्यमन्त्री ने अपने भाषण मे कहा कि राजनीति के आकाश म एक नये सितारे का उदय हुआ है। मुख्यमन्त्री ने कहा कि श्री सजय गाधी ने आगरा की लम्बे अर्से से चली आ रही कई समस्याओं का समाधान कर दिया है। उन्होंने यह भी वायदा किया कि वे तथा उनकी सरकार भविष्य मे श्री गाधी द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करगी।

सजय के सुझाव न मानने पर स्थानांतरण

आगरा सभाग के तत्कालीन आयुक्त श्री के० किशोर ने आयोग का दिए अपने बयान म बताया कि उनका बिना कोई कारण बताए स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी गलती सम्भवत यही थी कि उन्होंने आगरा के विकास कार्यों म श्री गाधी द्वारा सुझाए गए तरीका के प्रति असहमति व्यक्त की थी।

मैं नहीं, वे मेरे साथ गए थे

जस्टिस शाह ने आश्चर्य व्यक्त करत हुए पूछा आप श्री गाधी के साथ आगरा जान के लिए विशेष रूप से दिल्ली आए

थे ?' श्री तिवारी ने कहा, श्री गांधी मेरे साथ गए थे, मैं उनके साथ नहीं गया था। (इसपर हाल हसी के ठहाका से गूज उठा)

उन्होंने कहा, 'मुझे कुछ वैदेशीय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। अगले दिन मैं आगरा के लिए रवाना हुआ। श्री गांधी को भी वहाँ युवक कांग्रेस तथा गुरु तगबहादुर के एक सौ वर्ष समारोह समिति की ओर से बुलाया गया था।

श्री तिवारी ने बताया कि आगरा के रास्ते कासी में हुई बैठक कोई औपचारिक बैठक नहीं थी तथा इस बैठक में श्री गांधी ने कुछ सुझावों के प्रति सिर्फ सहमति व्यक्त की गई थी। इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'जब यह बैठक औपचारिक ही थी, तब इसकी कार्यवाही क्या लिखी गई ?'

मैंने किसीसे कार्यवाही लिखने को नहीं कहा था तथा पयटन विकास निगम को भूमि दिए जाने के आदेश मैंने दिए थे श्री गांधी ने नहीं।'

श्री गांधी की पयटन विकास निगम तथा उत्तरप्रदेश सरकार में क्या हैसियत थी ?

'वे भारत के युवकों के एक प्रमुख गैर सरकारी प्रतिनिधि थे।

श्री तिवारी ने बड़ी मासूमियत से कहा 'लगता है पयटन मंत्रालय ने कार्यवाही बहुत ही हलके तरीके से लिखी है।'

उन्होंने इस बात से इकार किया कि आगरा के सफिट हाउस में हुई बैठक की अध्यक्षता श्री गांधी ने की थी। उन्होंने कहा कि बैठक की अध्यक्षता श्री गांधी ने नहीं बल्कि उन्होंने की थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि श्री किशोर ने किस प्रकार ने यह कहा कि मैं उनकी कुर्सी के आगे पीछे घूम रहा था। वे तो एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं।

फिर उनका क्या स्थानांतरण किया गया ?'

'हम वहाँ और अच्छे अधिकारी चाहते थे।'

परंतु अभी-अभी आपने कहा है कि वे एक अच्छे अधिकारी हैं ? (श्री तिवारी इसका कुछ जवाब नहीं दे सके।)

श्री तिवारी ने बताया कि इतने कम समय में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने पर हम बधाई दी जानी चाहिए, यह एक आवश्यक था। इसपर जस्टिस शाह ने कहा 'मैं काम की निंदा नहीं कर

रहा हू। मैं आपको आपके उस व्यवहार के लिए बधाई भी दे रहा हूँ जो आपने उस बठक में किया था।'

(11) बोइंग विमानों की खरीद

एमरजेंसी के दौरान सरकारी बठका में विचार विमर्श के समय सजय गांधी ता. भाग लिया ही करते थे इसी प्रकार की एक बठक में उनके बड़े भाई श्री राजीव गांधी ने भी भाग लिया था और वह अवसर था इंडियन एयरलाइंस के लिए बोइंग ७३७ विमानों की खरीद के सम्बन्ध में हुई बठक का।

अक्टूबर १९७६ के प्रारम्भ में इंडियन एयर लाइंस के तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री ए० एच० मेहता के कमरे में हुई एक बठक में एयर लाइंस के निदेशक (वित्त) श्री कृपालचंद के अतिरिक्त निदेशक (आपरेटिंग) कप्टन ए० एन० कपूर ने भी भाग लिया। इस बठक में कप्टन कपूर के साथ श्री राजीव गांधी भी आए थे तथा वे विचार विमर्श के पूरे समय वहाँ मौजूद थे। बठक में कुछ विमानों की क्षमताओं के बारे में चर्चा हुई जिसमें बोइंग ७३७ विमान भी शामिल था। बठक में बोइंग ७३७ से सम्बंधित वित्तीय प्रावधानों जैसी गोपनीय फाइल दिखाई गई। ३०-२५ करोड़ रुपये की लागत के इन विमानों की खरीद जाने के सम्बन्ध में मन्त्रालय द्वारा बिना किसी सिस्टम स्टेडी के मोर्चे ही स्वीकृति दे दी गई। इसके बारे में बताया गया कि बोइंग कम्पनी ने इन विमानों की खरीद के सम्बन्ध में अंतिम तारीख ८ अगस्त, १९७७ दी थी और उस समय तक कोई फमला न हान के कारण ही इतनी जल्दी की गई, क्योंकि इसमें देर होने पर इन विमानों का और अधिक मूल्य देना पड़ सकता था।

इस बीच ऐसा पता चला था कि एयर लाइंस के प्रबंध निदेशक श्री मेहता इन विमानों के म्यान पर कोई अन्य विमान खरीद जाने के इच्छुक थे और इसी आधार पर ५ अक्टूबर १९७६ का केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक श्री देवेन्द्र सेन ने श्री मेहता के भ्रष्टाचार में निपट होने के बारे में एक गुप्त नोट लिखा था। उसके बाद १२ नवम्बर १९७६ को लिखे दूसरे नोट में उन्होंने लिखा था कि श्री मेहता के बारे में एक विमान बनाने वाली फर्म

म रवि निखान के सम्बन्ध में जा आरोप लगाया गया था, उसमें कुछ मत्पता नजर आती है।

श्री मन न श्री मेहता से सम्बन्धित यह फाइल तत्कालीन प्रधान मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री धवन के पास भेज दी थी।

श्री मेहता ने आयाग का लिए अपने बयान में बताया कि कप्टन कपूर ने उन्हें पान पर कहा था कि वह एवरो जस कुछ विमानों के सम्बन्ध में उनकी सलाह चाहते हैं। उन्होंने इस मामले में निदेशक (इंजीनियरिंग) से मिलने को कहा परन्तु कप्टन कपूर का कहना था कि निदेशक (इंजीनियरिंग) उपलब्ध नहीं है और उन्हें उनकी सलाह की तुरन्त आवश्यकता है। इसपर उन्होंने उन्हें बुला लिया।

श्री मेहता ने बताया कि इस बैठक में कपूर के साथ श्री राजाव गांधी भी आए थे। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार की बैठक (विचार विमर्श) में श्री गांधी जस जूनियर पाइलट का क्या काम था? परन्तु चूंकि कप्टन कपूर के साथ आए थे इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। बैठक में विचार विमर्श के दौरान कप्टन कपूर ने बोइंग ७३७ विमानों की खरीद के प्रस्ताव पर हुई प्रगति के बारे में जानकारी चाही थी। जहां तक उन्हें याद है उन्होंने श्री कृपानन्द से बोइंग विमानों के वित्तीय प्रावधानों से सम्बन्धित फाइल श्री गांधी को दिखाने को नहीं कहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि श्री गांधी इस बैठक के दौरान एक शर्त भी नहीं बताए थे।

सरकारी वकील श्री प्राणनाथ लेखी के एक प्रश्न के उत्तर में श्री मेहता ने बताया कि बोइंग विमानों के वित्तीय प्रावधानों से सम्बन्धित फाइल नाई गोपनीय दस्तावेज नहीं थे परन्तु उनपर विश्वसनीय अवश्य लिखा था।

श्री मेहता ने बताया कि उन्हें उस समय इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ कोई जाच की जा रही है। उन्हें एक अधिकारी ने याद में बताया था कि मर जिनाफ इस प्रकार की कोई जाच चर रहा है।

केन्द्रीय जाच ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक श्री रेवेन्द्र मन न स्वीकार किया कि उन्होंने श्री मेहता के सम्बन्ध में दो नोट बनाए थे तथा उनमें से एक गोपनीय नाट तत्कालीन प्रधानमंत्री के

अतिरिक्त सचिव श्री आर० के० घवन का भेता था। उस नोट में लिखा था कि श्री मेहता के विरुद्ध सरमरी नज़र में मामला बनता है।

श्री कृपालचंद ने जस्टिस शाह द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में आयोग की इस बात से सहमति व्यक्त की कि श्री गांधी की एयर लाइंस में कोई हैसियत नहीं थी तथा एक जूनियर पइलट के रूप में उनका संगठन के वित्तीय मामला से कोई लेना-देना भी नहीं था।

श्री कृपालचंद ने इस बात से इकार किया कि उन्होंने श्री गांधी से बोइंग विमानों की खरीद से सम्बंधित किसी भी पहलू पर कुछ विचार विमर्श किया था।

जस्टिस शाह ने कहा जब मल्लिमण्डल ने बोइंग विमानों की खरीद पर अपनी स्वीकृति दे दी थी तब इन विमानों के बारे में आपन ६ फरवरी, १९७७ को ही हस्ताक्षर करने में इतनी जल्दी क्या दिखाई? इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने भी कहा था कि उनके अधिकारी से इस मामले में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व सहमति ली जाए। इससे पूर्व कि मंत्रालय को इस सम्बंध में सूचित किया जाता आपन हस्ताक्षर भी कर दिए।

श्री कृपालचंद ने इसके उत्तर में बताया कि मैंने इतनी जल्दी हस्ताक्षर इसीलिए किए क्योंकि मुझे ऐसा करने का कहा गया था इसके अतिरिक्त यदि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में देर हो जाती तो विमानों की सप्लाय में देर हो जाती। बोइंग कंपनी ने सप्लाय के लिए ७ फरवरी अंतिम तारीख दी थी तथा इसके बाद १५ तारीख से इनकी कीमत में बढ़ि हो जाती।

श्री कृपालचंद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि ८ फरवरी को मंत्रीजी ने उन्हें बुलाया और कहा कि बोइंग विमानों की खरीद में सम्बंधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी है। मंत्रीजी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संपुक्त सचिव श्री ए० एस० भटनागर को निर्देश दिए कि इस सम्बंध में औपचारिक स्वीकृति से निगम को अवगत करा दिया जाए तथा अनुबंध पर तुरंत हस्ताक्षर करवा लिए जाए। मंत्रालय द्वारा इन विमानों की बुक नागत ३०-२५ फरवरी के तुरंत स्वीकृति दे दी गई।

उन्होंने बताया कि नव विमानों की खरीद बहुत ही जल्दी की

क्याकि यातायात दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा था और यदि और देरी हाती तो इससे निगम का काफी हानि उठानी पड़ सकती थी।

बिना सिस्टम स्टेडी के खरीद

इंडियन एयर लाइंस में योजना आयोग के सलाहकार श्री नितिन देसाई ने आयोग को बताया कि विमानों की खरीद के लिए उनकी सिस्टम स्टेडी के बारे में स्वयं इंडियन एयर लाइंस ने मायता दे रखी है। उनका कहना था कि इस मामले में भी इंडियन एयर लाइंस ने सिस्टम स्टेडी की आवश्यकता को स्वीकार किया था परन्तु वे इस बहुत जल्दी पूर्ण कराना चाहते थे क्योंकि उनके अनुसार एक तो विमानों की कीमत बढ़ने वाली थी और दूसरे १९७७-७८ को मंत्रियों के लिए काफी विमान चाहिए थे।

श्री देसाई ने बताया कि कीमत बढ़ने के सम्बन्ध में योजना आयोग की मायता थी कि कभी हुई कीमतों उस बचत से बहुत कम होती जो सिस्टम स्टेडी के बाद बचती। जहां तक १९७७-७८ तक यातायात में बढ़ि की बात थी, योजना आयोग के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं थी कि ६ महीने अथवा एक वर्ष में यातायात पर ऐसा कोई विशेष दबाव पड़ने वाला है।

उन्होंने कहा कि इन सबके बावजूद यदि सिस्टम स्टेडी कराई जाती तो उसमें अधिक से अधिक दो महीने का समय लगता जा बहुत अधिक नहीं होता। इन सब बातों के अतिरिक्त बिना सिस्टम स्टेडी के विमानों की खरीद का निष्पत्ति योजना आयोग तथा सांख्यिकीय पूँजी बोर्ड को भी स्वीकार नहीं था।

घबरे के कहने पर

तत्कालीन उड्डयनमन्त्री श्री क० रघुरमैया तथा उनसे पूर्व इस मन्त्रालय के मन्त्री श्री राजबहादुर ने आयोग को बताया कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० घबरे ने उनसे बोझ विमानों की खरीद के सम्बन्ध में बातचीत की थी। उन दिनों कायना ही यह था कि जा कुछ घबरे कहते थे उसने लिए ऐसा माना जाता था कि श्रीमती गांधी कह रही हैं।

श्री रघुरमैया ने बताया कि श्रीमती गांधी की जानकारी में अमेरिका के कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित यह खबर थी जिसमें

कहा गया था कि बोइंग कम्पनी ने भारत सरकार के कुछ अधिकारियों को तीन विमान खरीदे जान के सम्बन्ध में कमीशन दिया है। श्रीमती गांधी ने मंत्रिमण्डल की एक बैठक में स्वयं यह बात उनसे कही थी, इसपर उन्होंने उनसे कहा था कि आप ही देखिए, इस मामले में क्या करना है।

इसपर जस्टिस ने कहा 'अमेरिका के समाचारपत्रों में जिन १३ सलाहकारों के नाम छपे थे, उनमें भारतीय प्रतिनिधियों के भी नाम थे। बोइंग कम्पनी के अधिकारियों का भी कहना था कि वास्तविकता में कुछ कमीशन दिया गया है। आपने इस मामले में क्या सोचा था?'

श्री रघुरमया ने इसके जवाब में कहा 'मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया था क्योंकि इस मामले में बारबार्ड प्रधानमंत्री को करना था, मुझे नहीं।

स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए राज्यपाल नहीं बनना चाहता

श्री रघुरमया ने बताया कि वे नहीं जानते कि इस मामले में सिस्टम स्टेडी क्या नहीं कराई गई, क्योंकि जब यह बात ही रही थी, व मंत्री नहीं थे। इसपर श्री राजबहादुर ने कहा कि उन्होंने श्रीमती गांधी से सिस्टम स्टेडी कराने की बात कही थी तब उनसे कहा गया कि आप यह पद छोड़ दें तथा त्यागपत्र दे दें। इसके बाद उनसे किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर जान का प्रस्ताव किया गया परंतु उन्होंने यह कहकर इकार कर दिया कि अभी मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है।'

उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि विमान का खरीदना में कोई जल्दबाजी की गई थी तथा यह कहना भी गलत है कि उन्होंने बोइंग ७३७ खरीदना में ही कोई विशेष दिलचस्पी ली थी। कौन-सा विमान खरीदा जाना है यह बात उन्होंने तबनी नियमों पर छोड़ दी थी।

श्री राजबहादुर ने इस बात में इशारा किया कि श्री राजीव गांधी एयर माइम व प्रशासनिक मामलों में कोई हस्तक्षेप किया करते थे।

क्योंकि यातायात दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा था और यदि और दूरी हाती तो इससे नियम को काफी हानि उठानी पड़ सकती थी।

बिना सिस्टम स्टेडी के खरीद

इंडियन एयर लाइंस में योजना आयोग के सलाहकार श्री नितिन देसाई ने आयोग को बताया कि विमानों की खरीद के लिए उनकी सिस्टम स्टेडी के बारे में स्वयं इंडियन एयर लाइंस ने मायता दे रखी है। उनका कहना था कि इस मामले में भी इंडियन एयर लाइंस ने सिस्टम स्टेडी की आवश्यकता को स्वीकार किया था, परन्तु वे इस बहुत जल्दी पूरा कराना चाहते थे, क्योंकि उनके अनुसार एक तो विमानों की कीमत बढ़ने वाली थी और दूसरे १९७७-७८ की सदियों के लिए काफी विमान चाहिए थे।

श्री देसाई ने बताया कि कीमत बढ़ने के सम्बन्ध में योजना आयोग की मायता थी कि बढ़ी हुई कीमतों उस वृषत से बहुत कम हाती जो सिस्टम स्टेडी के बाद वचती। जहां तक १९७७-७८ तक यातायात में वृद्धि की बात थी योजना आयोग के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं थी कि ६ महीने अथवा एक वर्ष में यातायात पर ऐसा कोई विशेष दबाव पड़ने वाला है।

उन्होंने कहा कि इन सबके बावजूद यदि सिस्टम स्टेडी कराई जाती तो उसमें अधिक से अधिक दो महीने का समय लगता जो बहुत अधिक नहीं होता। इन सब बातों के अतिरिक्त बिना सिस्टम स्टेडी के विमानों की खरीद का निणय योजना आयोग तथा सावजनिक पूंजी बोर्ड को भी स्वीकार नहीं था।

ध्वन के कहने पर

तत्कालीन उद्योगमन्त्री श्री के० रघुरमया तथा उनसे पूर्व इस मन्त्रालय के मन्त्री श्री राजबहादुर ने आयोग को बताया कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० ध्वन ने उनसे वाइय विमानों की खरीद के सम्बन्ध में बातचीत की थी। उन दिनों कायदा ही यह था कि जो कुछ ध्वन कहते थे उसके लिए ऐसा माना जाता था कि श्रीमती गांधी कह रही हैं।

श्री रघुरमया ने बताया कि श्रीमती गांधी की जानकारी में अमेरिका के कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित यह खबर थी जिसमें

विमान को आयात करने खरीदने और हवाई पट्टी के निर्माण की अनुमति भी भिन्न चुकी थी जबकि इस मामले में सामान्यतः कितना समय लग सकता है इसकी सट्टा ही कल्पना की जा सकती है।

विमान खरीदने की अनुमति

स्वामीजी ने सबसे पहले जम्मू काश्मीर सरकार का २६ मार्च १९७६ का एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मतलाई में निजी हवाई पट्टी बनाने की अनुमति देने तथा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न हाने का प्रमाण पत्र चाहा। राज्य के मुख्यमन्त्री ने दो दिन के भीतर ही इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए लिखा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

स्वामीजी ने उसी दिन वैमानिक निरीक्षण निदेशक श्री बी० एन० कपूर का एक पत्र लिखकर आवेदन किया कि वे कृषि के कार्य के लिए अमेरिका की मौले कम्पनी द्वारा बना गया 'एम ५' किस्म का विमान आयात करना चाहते हैं तथा यह विमान कम्पनी द्वारा अपनी आवश्यकता का उपहारस्वरूप दिया जा रहा है।

जांच करने पर पता चला कि मौले कम्पनी 'एम ५' श्रेणी में कृषिकाय के लिए कोई विमान बनाती ही नहीं है। श्री कपूर ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक श्री रामअमृतम से विचार विमर्श कर ३१ मार्च को स्वामीजी का एक पत्र लिखकर कहा कि आप एक दूसरा आवेदन करें जिसमें इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए कि विमान का उपयोग किस काम में किया जाएगा। इसके बाद २ अप्रैल १९७६ को महानिदेशक नागरिक उड्डयन ने 'व्यक्तिगत उपयोग' दिखाते हुए विमान की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी दिन स्वामीजी का आवेदन जम्मू-काश्मीर सरकार की स्वीकृति तथा श्री कपूर के नोट के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय भेज दिया गया।

श्री कपूर का कहना था कि उन्होंने कृषि के वजाय व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान का इसी आधार पर मंजूरा दिया था कि इसमें नागरिक उड्डयन में विकास होगा। श्री कपूर के अनुसार उपहारस्वरूप दिए गए विमान के लिए अनुमति देना असाधारण नहीं था जम्मू पूर्व महर्षि महेश योगी का भी जम्मू आधार पर विमान आयात करने की अनुमति दी गई थी।

श्री रामअमृतम ने आयोग को बताया कि चूंकि आवेदन पर

(III) स्वामीजी और विमान

नई दिल्ली में अशोक रोड पर गालि हाइस्कोन के एक किनारे पर स्थित विश्वायतन यागाश्रम और उसके संचालक स्वामी धीमन्त्र ब्रह्मचारी एमरजेसी के दौरान काफी चर्चित रहे थे। कहा जाता है कि स्वामीजी का तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनके परिवारजनों से बड़ा निकट का सम्बन्ध था और उनका उन लोगों पर काफी प्रभाव भी था। इस प्रभाव का उपयोग करते हुए तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार के साथ उनके निकट के सम्बन्धों के कारण वे राज्या तक प्रभावों से और उनके एक पत्र लिखन मात्र से ही कई काम हो जाया करते थे।

अपर्णा आश्रम

स्वामीजी ने जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिन में मतलाई में अपना एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखा 'अपर्णा आश्रम'।

६३०० फुट की ऊंचाई पर ५० एकड़ भूमि में बना यह आश्रम तीन ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर देवदार के वृक्ष लगे हैं। आश्रम में ५०० विभिन्न किस्मों के सब्जियों के पौधे लग चुके हैं। इसके अतिरिक्त बेल्जीकोनिया के बादाम इटली की लीची तथा अच्छी किस्म के नींबू और माल माल्टा भी लगे हुए हैं। आश्रम के बीच में स्थित बाग में ७५ फुट चौड़ा ३५ फुट लम्बा और ११ फुट गहरा आम की आकार का तरने का एक तालाब है जिसमें निम्न किन्मीटर दूर से पानी लाया जाता है।

यह आश्रम पूर्ण रूप से सीमेंट-बनीट का बना हुआ है। इसके कमरे वातानुकूलित साउंड प्रूफ तथा डेम्प प्रूफ हैं। आश्रम में एक विशेष गुफा बनाई गई है जिसपर किसी चीज का अमर नहीं हो सकता। कहा जाता है कि यह विश्व में अपनी किस्म की एक ही गुफा है। इस गुफा में शिष्यों को योग सिखाने का प्रवर्ध है।

इस खूबसूरत आश्रम तक सड़क के रास्ते जाना असम्भव नहीं तो मुश्किल जरूर है। इसीलिए स्वामीजी ने एक विमान आयात कराने का काम प्रारम्भ कराया। स्वामीजी ने इसके बार में पहला पत्र २६ मार्च १९७६ को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को लिखा था। कई मंत्रालयों की धाना पूरी के बाद ३१ नवम्बर १९७६ को इस

विमान का आयात करन खरीदने और हवाई पट्टी के निर्माण की अनुमति भी मिल चुकी थी जबकि इस मामले में सामान्यतः कितना समय लग सकता है इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

विमान खरीदने की अनुमति

स्वामीजी ने सबसे पहले जम्मू काश्मीर सरकार को २६ मार्च १९७६ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मतलाई में निजी हवाई पट्टी बनाने की अनुमति देने तथा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न होने का प्रमाण पत्र चाहा। राज्य के मुख्यमंत्री ने दो दिन के भीतर ही इस स्वीकृति प्रदान करत हुए लिखा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

स्वामीजी ने उसी दिन कमानिक निरीक्षण निदेशक श्री बी० एन० कपूर का एक पत्र लिखकर जावदन किया कि वह कृषि के काम के लिए अमेरिका की मौले कम्पनी द्वारा बना गया 'एम ५' किस्म का विमान आयात करना चाहते हैं तथा यह विमान कम्पनी द्वारा अपना आश्रम को उपहारस्वरूप दिया जा रहा है।

जाच करने पर पता चला कि मौले कम्पनी 'एम ५' श्रेणी में कृषिकाम के लिए कोई विमान बनाती ही नहीं है। श्री कपूर ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक श्री रामअमृतम से विचार विमर्श कर ३१ मार्च को स्वामीजी को एक पत्र लिखकर कहा कि आप एक दूसरा आवदन करें जिसमें इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए कि विमान का उपयोग किस काम में किया जाएगा। इसके बाद २ अप्रैल, १९७६ को महानिदेशक नागरिक उड्डयन ने व्यक्तिगत उपयोग दिखाते हुए विमान की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी दिन स्वामीजी का आवदन जम्मू काश्मीर सरकार की स्वीकृति तथा श्री कपूर के नोट के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय भेज दिया गया।

श्री कपूर का कहना था कि उन्होंने कृषि के वजाय व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान का इसी आधार पर मुंशाव दिया था कि इसमें नागरिक उड्डयन में विकास होगा। श्री कपूर के अनुसार उपहारस्वरूप लिए गए विमान के लिए अनुमति देना असाधारण नहीं था इसमें पूर्व महर्षि महेश योगी का भी इसी आधार पर विमान आयात करने की अनुमति दी गई थी।

श्री रामअमृतम ने आयात का बताया कि चूँकि आवदन पर

मौने सम्पत्नी से पत्र यह लिखा लिया था कि विमान उपहार स्वरूप दिया जा रहा है ताकि सभी प्रकार की तकनीकी आपत्तियां से बचा जा सक।

सूचना मिलने पर भी कारवाई नहीं

प्रवतन निदेशालय में २८ अप्रैल का एक व्यक्ति एक पत्र लेकर आया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के विश्वायतन योगाथम के स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दो-तीन दिन में एक प्रति तिथि मण्डल के साथ लंदन रवाना होने वाले हैं। उन्होंने कहा एक व्यक्ति धीरेन्द्र जन के खर्च साठे तीन लाख रुपये मूल्य के खालर खरीदे है तथा जाग और भी खरीदे जाने वाले हैं। सूचना देने वाले ने इस पत्र में अपना नाम, पता और टेलीफोन नम्बर भी लिखा था ताकि बाद में उससे सम्पर्क किया जा सके।

यह पत्र प्रवतन अधिकारी श्री आर० एस० सेठ को दिया गया था और उन्होंने उप निदेशक श्री ए० एम० सिन्हा को इस बारे में सूचित कर दिया था। श्री सिन्हा ने निदेशक श्री एस० बी० जन से उसी दिन फोन पर बात कर कहा कि यह सूचना अस्पष्ट लगती है इसलिए इसपर कोई कारवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में १२ मई को कारवाई न करने के निर्देश दिए गए जबकि स्वामीजी २७ अप्रैल का ही दिल्ली से रवाना होकर लंदन के रास्ते ३० अप्रैल को अमेरिका पहुँच चुके थे और बाद में २४ मई को वहाँ से दिल्ली लौट आए थे।

अस्पष्ट सूचना के कारण कारवाई नहीं

श्री सिन्हा ने इस बारे में अपनी सफाई देते हुए कहा कि चूंकि प्राप्त सूचना बहुत ही अस्पष्ट थी इसलिए उसपर कोई कारवाई नहीं की गई। उन्होंने उस व्यक्ति को जिसने सूचना दी थी, उसी दिन शाम को बुलाने को कहा था परन्तु वह आया नहीं। इस बीच वे इस मामले में और सूचनाएं प्राप्त करना चाहते थे। इसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि स्वामीजी लंदन के लिए रवाना भी हो गए हैं उसके बाद कोई कारवाई करना बेकार था।

श्री जन का कहना था कि इस प्रकार के मामले को श्री सिन्हा ही देखते थे और जब उन्होंने उन्हें फोन कर कहा कि 'सूचना के

स्पष्ट होन के कारण वे उमपर कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं, ता उनके द्वारा स्वयं इस मामले में कोई कारवाई करने का सवाल ही नहीं था। यदि श्री सिंहा उनमें कोई सुझाव मांगते तो वे जरूर कोई कारवाई करने का कहते।

चुगी में छूट

स्वामीजी द्वारा आयातित विमान के लिए चुगी में छूट देने सम्बन्धी आवेदन पर भी सिर्फ छ मिनटों के भीतर ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई जबकि वित्तमन्त्रालय के एक अधिकारी ने इस उचित नहीं बताया था।

स्वामीजी ने विमान के लिए चुगी में छूट देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय एक्साइज एवं कस्टम बोर्ड के सचिव को एक जुलाई को पत्र लिखा। पत्र का जवाब न आने पर उन्होंने दूसरा पत्र १२ जुलाई का श्री प्रणव मुखर्जी को तथा उसकी प्रतिलिपि श्री धवन को भेजी। २३ जुलाई को बांड के सम्बन्धित विभाग ने आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया क्योंकि उनके अनुसार यह आश्रम एक मायताप्राप्त संस्था नहीं था तथा खरीदे जाने वाले विमान के बारे में यह नहीं बताया गया था कि वह शक्षणिक कार्यों में ही काम आएगा। विभाग के एक दस नोट पर अवर सचिव श्री ए० क० मरकार ने भी अपनी महमति प्रदान की थी। अवर सचिव ने यह नोट उन्नीस दिन उपसचिव श्री बी० के० गुप्ता को भेज दिया था।

श्री गुप्ता ने दस आवेदन पर बात करें टिप्पणी लिखकर इसे श्री सरकार के पास वापस भेज दिया। २६ जुलाई का श्री गुप्ता ने इसपर लिखा कि इस मामले पर गहराई से विचार करने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व उन्होंने शिदा मन्त्रालय के पास भी उक्त नोट सुझाव के लिए भेजा।

शिदा मन्त्रालय ने २७ जुलाई को लिखे अपने नोट में कहा कि मन्त्रालय के पास इस आश्रम की गतिविधियों के बारे में कोई सूचना नहीं है। ऐसी स्थिति में मन्त्रालय इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

शिदा मन्त्रालय से इस प्रस्ताव के वापस आने पर श्री गुप्ता ने इसपर वित्त सचिव श्री एच० एन० रे सदस्य (टारिफ) श्री के०

नरसिम्हन, मदस्य (बस्टम) थी एम० ए० रणास्वामी, तथा बकिंग और राजस्वमन्त्री थी प्रणव मुयर्जो से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद श्री गुप्ता ने २८ जुलाई को इस प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य लोगो को योग का निःशुल्क प्रशिक्षण देना है विमान उपहारस्वरूप दिया जा रहा है तथा उसके लिए बस्टम विभाग की स्वीकृति भी ली जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आश्रम जिस ऊँचाई पर बना हुआ है उसको देखते हुए आने जाने के लिए विमान की आवश्यकता महसूस की जा सकती है।

हवाई पट्टी की अनुमति

विमान धरौदन के लिए समस्त गानापूरी भी हा गई और विमान खरीद लिया गया परन्तु जब तक मतलाई स्थित आश्रम में विमान उतरने के लिए हवाई पट्टी नहीं हो तो विमान का आयात करना ही बेकार था। इसलिये हवाई पट्टी बनाने का काम भी शुरू हुआ और उसके साथ ही उसकी अनुमति के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को आवेदन किया गया।

स्वामीजी ने २० अगस्त १९७६ को महानिदेशक को लिखे एक पत्र में हवाई पट्टी बनाने की अनुमति देने की प्रार्थना की तथा उस स्थान पर किसी अधिकारी को भी निरीक्षण हेतु भेजने का निवेदन किया। इस काम के लिए एमरोडम अधिकारी श्री के० सी० दुग्गल बहा गए। उन्होंने पाया कि हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू हो गया है तथा भूमि को समतल किए जाने तक का काम भी हो चुका है। श्री दुग्गल ने इस बार में २३ अगस्त को एक रिपोर्ट बनाकर अपने विभाग का दी। यह रिपोर्ट अनुमति के लिए वायु सेना मुख्यालय भेजी गई जहाँ से उस इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रस्तावित हवाई पट्टी सना के सामरिक महत्व के स्थान के बहुत पास ही स्थित है और उक्त स्थल से १५ मील दूर ही सनिक हवाई अड्डा है।

स्वामीजी ने २७ नवम्बर को एक बार फिर महानिदेशालय में इसकी अनुमति प्रदान करने के लिए पत्र लिखा जिस एक बार फिर वायुना मुख्यालय भेजा गया जहाँ ने उसपर अस्वीकृत कर दिया गया।

रक्षामंत्री से अनुरोध

स्वामीजी न २३ दिसम्बर का तत्कालीन रक्षामंत्री श्री ब्रसी-लाल को एक पत्र लिखा और पत्र के साथ उप निदेशक (याजना) श्री एस० के० बोम द्वारा वायुसेना मुख्यालय को निम्न पत्र की वह प्रतिलिपि भी भेजी, जिसमें उन्होंने इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। (यह आश्चर्य की बात थी कि मन्त्रालय के इस गौणनीय पत्र की प्रतिलिपि स्वामीजी के पास कम पहुँची।) स्वामीजी ने रक्षामंत्री की निम्ने पत्र में हवाई पट्टी बनाने की अनुमति निलान के लिए व्यक्तिगत रूप में गति लेकर यह कार्य करने का अनुरोध किया था, परन्तु इस सब से वाकजूत मुख्यालय ने श्री बोम को निम्न में कोई परिवर्तन न करने का कारण मंगूचित कर दिया।

सामरिक महत्व के स्थान से निष्पटता के कारण अनुमति नहीं

मुख्यालय में इस बार में हुए पत्राचार में पता चलता है कि एयर कमांडर श्री पी० पी० सिंह ने जा निम्न (गुप्तचर) का भी कार्य कर रहे थे ३० दिसम्बर की एक नोट लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मतनाई क्षेत्र की सामरिक महत्व के स्थान के साथ निष्पटता को देखते हुए अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री सिंह ने ३१ दिसम्बर का निम्न एक डूमेर नाट में कहा था कि प्रस्तावित स्थान सामरिक महत्व के स्थान से सिर्फ ७ मील दूर तथा सैनिक हवाई अड्डे में १५ मील दूर है। यहाँ पहुँचना के लिए सिर्फ एक ही ओर में रास्ता है क्योंकि शेष तीन ओर पट्टाईयाँ हैं। इससे अतिरिक्त विमान का उपयोग विदेशी शिप्या का जान-लेजाने में भी किया जाएगा जो सुरक्षा के विहाय से उचित नहीं है।

श्री सिंह के ये दोना नोट मन्त्रालय में गयुका सचिव (वायु सेना) के पास पहुँचा दिए गए, परन्तु ये नोट श्री सिंह का फौज दिए गए और बाद में उठ खूँ भी कर लिया गया। श्री सिंह ने बाद में ३० दिसम्बर की तारीख में ही एक अन्य नाट लिखा जिसमें कहा गया था कि बहुत हिता को देखते हुए कड़ी शर्तों के साथ मतनाई में हवाई पट्टी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। श्री

सिंह न यह नाटलिया सपूव वायुसनाध्यक्ष म भी मुसारात की थी ।

जासूसी की आशका का सडन

श्री सिंह न आपाग की इस आशका का निमून बताया कि इस विमान के अरिय विन्नेशी नोम भारत पर जासूसी कर मरते थे या फिर इस हवाई पट्टी का उपयोग इसी प्रकार की किसी कारवाइ के निण किया जा सकता था ।

जस्टिस शाह न इस बात पर खेद प्रकट किया कि 'एक' शक्ति के हित के लिए देश के हिता को ध्यान म नही रखा गया तथा ऐस स्थाना पर हवाई पट्टी बनान की अनुमति दे दी गई जो सामरिक महत्व का स्थान था और जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पदा हो सकता था ।

श्री सिंह न जस्टिस शाह को इस बारे म सतुष्ट करने की काफी चेष्टा की रि मतलाई हवाई पट्टी बनाने की इजाजत बहुत मोच ममनकर तथा बड़ी शर्तों के साथ दी गई थी ।

उद्घातन कहा कि जहा तक स्वामीजी के विमान के जासूसी का मवाल है उसम आधुनिक इलेक्ट्रोनिक यंत्र नही लगाए जा सकते थे । सिर्फ छोटे क्रिस्म के कमर ही लगाए जा सकते थे । इसके अतिरिक्त राडार म विमान का निरीक्षण भी किया जा सकता था, इसपर जस्टिस शाह ने पूछा क्या राडार यह पता लगा सकता था कि विमान के अन्दर शत्रु बठा है या भित्त जराकि आपने स्वय निष्ठा था कि विमान को विन्नेशी शिप्या को लाने ल जाने म भी काम म लिया जाएगा । इसपर श्री सिंह यही जवाब दे सके कि यह देखना नागरिक उड्डयन विभाग का काम था ।

कोई दबाव नहीं

श्री सिंह न इस बात को भी गलत बताया कि इस काय को करने के लिए उनपर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला गया था या कोई निर्देश दिए गए थे । श्री सिंह ने हवाई पट्टी बनाने की अनुमति देने के पीछे एक और कारण बतात हुए कहा कि युद्ध के समय इसका उपयोग वायुसेना के लिए किया जा सकता था इस पर जस्टिस शाह न कहा फिर ता एक तरीके से आपने ही स्वामीजी का पट्टी बनान के लिए आमन्त्रित किया था ।

श्री मिह ने गरवारो बनीन व विचार म अगहमति स्थित की नि वायुमनाध्यक्ष एयर चीफ माशल मुलगावकर म इस मामले पर विचार विमल व बात उहने अपना निणय बदला था ।

उप महानिष्ठाव (नागरिक उद्बोधन) श्री जी० आर० पट पात्रिया न आयोय के समक्ष इस बात का दावा किया कि स्वामीजी का मतनाई म हवाई पट्टी बनान की अनुमति दाता जमाधारण बाल नगी थी, भन हो वह सनित हवाई अड्डे व १५ मीन के अन्दर ही रही हो । उहने बताया कि दिल्ली म पात्रिम गगनपर जग हवाई अड्डे व बीन की दूरी १० मीन स भी कम है । इसी प्रकार बम्बई मातापुर हवाई अड्डे म जुहू हवाई पट्टी भी इसत अधिक दूरी पर नही है ।

रक्षामत्रालय म सदुवा सचिव श्री त्रिनय व्यास न आयाम का बताया कि उहने श्री सिंह म फोन कर पूछा था कि स्वामीजी को हवाई पट्टी बनाने की अनुमति किन शर्तों पर दी जा रही है । श्री व्यास का कहना था कि रक्षामत्री स सम्बद्ध समुक्त सचिव श्री एस० के० मिश्र ने उनस पूछा था कि पट्टी बनान की अनुमति की क्या शर्तें हा सकती हैं ?

श्री मिश्र का कहना था कि रक्षामत्री ने उनसे जानकारी चाही थी कि स्वामीजी को हवाई पट्टी बनान मरघी आवदन पर कारवाई म क्या प्रगति है । इसपर उहने श्री व्यास स इस शर म बात की थी । श्री व्यास ने उह फाइल भेजी थी जिनम वायु सेना ने आपत्ति कर रखी थी । य कारण उहने रक्षामत्री को दिखाए थ और उहने जानना चाहा था कि किन शर्तों पर अनुमति दी जा सकती है आप माजूम करिए ।

श्री मिश्र ने कहा कि रक्षामत्री द्वारा शर्तें पूछे जान का कारण नीति संबंधी निणय लेना था । व निजा हवाई पट्टिया व संबंध म एवं निश्चित नीति तय करना चाहते थ । उहने इस बात का मतल बताया कि अनुमति देने के लिए रक्षामत्री की ओर स किसी प्रकार का कोई दबाव डाला गया था ।

रक्षामत्रालय की विलचस्पी के कारण अनुमति

वायुमनाध्यक्ष एयर चीफ माशल एच० मुलगावकर न आयाम के समक्ष स्वीकार किया कि हवाई पट्टी बनान के संबंध मे अनुमति

र मामला को विशेष नित्यचस्पी के कारण दी गई थी परन्तु उन्होंने इस बात से साफ इन्कार किया कि अनुमति देने के लिए उन पर किसीने कोई दबाव डाला था।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि रक्षामन्त्रालय इतना उत्सुक नहीं होता ता सुरक्षा के हिता का ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने कहा 'जब मन्त्रालय को ही आपत्ति नहीं थी तो हम राकन वाले क्यों हाने थे।'

श्री मुनगावकर का कहना था कि जहाँ तक सैनिक हवाई पट्टी के पास नागरिक हवाई अड्डे होने की बात है ता इसमें गलत कुछ नहीं है क्योंकि आज भी जामरा के सैनिक हवाई अड्डे से कुछ शतों के साथ नागरिक विमानों को उत्तम की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा 'यदि आज भी उस क्षेत्र में कोई हवाई पट्टी बनती है तो हम कोई आपत्ति नहीं होगी।' एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि केंद्र में नई सरकार के आने के बाद मतलाई हवाई पट्टी के उपयोग के आदेश को रद्द करन संबंधी आदेश भी मन्त्रालय की ओर से ही दिए गए हैं और उनका पालन किया गया।

स्वामीजी भी उसी रास्ते पर

स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी आयोग द्वारा भेजे गए समन के जवाब में आयोग के समक्ष पेश ता हुए, परन्तु उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। उनका सिर्फ यही कहना था कि उन्होंने जा विमान आयात किया था वह उन्हें उपहार में मिला था न कि खरीना था। स्वामीजी द्वारा जपथ लेकर बंधात न देने के आरोप में उनका मामला भी भारतीय दंड संहिता की धारा १७८ तथा १७९ के अंतर्गत नित्य के मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया गया। साथ ही अदालत में देश हान का गारंटी के रूप में आयोग ने उनसे दो हजार रुपये की जमानत भी ली जा वहाँ उपस्थित स्वामीजी के एक शिष्य ने उसी समय जमा करवाई। जमानत देने के बाद ही स्वामीजी को आयोग से जाने की अनुमति दी गई।

○○○

